रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274543
CG-DL-E-16072026-274543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948
No. 174] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

मामला सं. - सीवीडी(ओआई) - 03/2024

विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयात के संबंध में प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. संख्या 6/39/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रति संतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के

निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. कम्पाउंड्स एण्ड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे "सीएमएमएआई" कहा गया है) और मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे "एमएमए" कहा गया है) (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने भारत के घरेलू उत्पादकों की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष अधिनियम और सीवीडी नियमावली के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के वियतनाम (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयात के संबंध में प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच शुरूआत करने के लिए आवेदन दायर किया।

2. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग विखंडित है और इसमें भारत भर में स्थित बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं, इसलिए प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच के लिए आवेदन दो संगठनों, अर्थात् सीएमएमएआई और एमएमए द्वारा अपने सदस्य इकाइयों की ओर से दायर किया गया था। व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021, यथा-संशोधित व्यापार सूचना सं. 11/2021 दिनांक 18 नवंबर 2021 (सामूहिक रूप से "व्यापार सूचना 9/2021") के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

3. निम्नलिखित बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने विखंडित उद्योगों के लिए व्यापार सूचना 9/2021 के अनुलग्नक-I के अनुसार अपेक्षित जानकारी दायर की:

i. कंडुई इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
ii. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
iii. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
v. बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड
vi. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
vii. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. सिद्ध केमीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
ix. श्री अंबिका पॉलीफिल
x. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
xi. आलोक इंडस्ट्रीज़
xii. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

4. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस (21) घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया और निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराए:

i. सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. एस.पी. पॉलीमर

v. 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड
vi. एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
vii. सत्य पॉलीअलॉयज एलएलपी
viii. एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड
ix. रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
x. भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. स्वस्तिक प्लास्टोअलॉयज
xii. मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xiii. आदित्य पॉलिसपिन प्राइवेट लिमिटेड
xiv. जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड
xv. स्पेशियलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी
xvi. सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड
xvii. एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xviii. मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xix. डॉल्फिन पॉलीफिल
xx. जेजे प्लास्टअलॉय
xxi. प्रभु पॉलीकलर

5. आवेदकों द्वारा विधिवत दायर किए गए सत्यापित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 की अधिसूचना फा. सं. 6/39/2024-डीजीटीआर, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित सब्सिडी के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रति संतुलनकारी शुल्क की राशि, जो अगर लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसार संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच शुरू की गई।

ख. ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले, वर्तमान प्रति संतुलनकारी शुल्क आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसार अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रति संतुलनकारी उपायों पर करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार स्थिति को स्पष्ट करने और आपसी सहमति से समाधान पर पहुंचने के उद्देश्य से वियतनाम सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम सरकार के साथ दिनांक 03.12.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श आयोजित किए गए। इन परामर्शों में वियतनाम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

iii. प्राधिकारी ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 की सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच आरंभ की गई।

iv. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को, साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने दृष्टिकोण लिखित रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर अवगत कराएं।

v. प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

vi. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वे निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें। संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति उनके नाम और पते के साथ दूतावास को भी भेजी गई।

vii. प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र. सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
1.	पी एम जे जॉइंट स्टॉक कंपनी
2.	सी पी आई वियतनाम प्लास्टिक लिमिटेड
3.	यू बी मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
4.	मेगा प्लास्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी
5.	ए डी सी प्लास्टिक जे एस सी
6.	एच पी केमिकल्स जॉइंट स्टॉक कंपनी
7.	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी
8.	फू लाम ट्रेड कंपनी लिमिटेड
9.	यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी
10.	सन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
11.	हून्धी प्लास्टिक कंपाउंड्स जे एस सी
12.	थान जुआन स्टोन मिनरल्स जे एस सी
13.	फाइव कॉन्टिनेंट्स प्लास्टिक जे एस सी
14.	वी एस वी ग्रुप कॉर्पोरेशन
15.	विनारेस वियतनाम जॉइंट स्टॉक कंपनी

16.	फिलप्लास कंपनी लिमिटेड
17.	बाओ लाई मार्बल वन मर्मर कंपनी लिमिटेड
18.	प्लास्टेक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी
19.	मास्का ग्लोबल कंपनी लिमिटेड
20.	विना प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
21.	सनशाइन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
22.	कैपोट वियतनाम कंपनी लिमिटेड
23.	फाले प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी
24.	वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल जॉइंट स्टॉक कंपनी
25.	प्लास्टिक हा नोई ट्रेडिंग जॉइंट स्टॉक
26.	फिल्टर मास्टर बैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
27.	बीनप्लास्ट कंपनी लिमिटेड
28.	वियतनाम कलर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बीन ए एंड टी कंपनी लिमिटेड
29.	ग्लोबल मिनरल्स जेएससी
30.	एनबायो जॉइंट स्टॉक कंपनी
31.	टीएलडी वियतनाम जॉइंट स्टॉक कंपनी
32.	एन थान बिकसोल जॉइंट स्टॉक कंपनी
33.	मिन्ह खांग केमिकल ट्रेडिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी
34.	यू एस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
35.	होआंग जिया मिनरल ग्रुप जे एस सी
36.	दाई ए इंडस्ट्री जॉइंट स्टॉक कंपनी
37.	वियतनाम हनोटेक जॉइंट स्टॉक कंपनी
38.	एन टिएन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी
39.	विटाप्लस जॉइंट स्टॉक कंपनी
40.	रेनफॉरेस्ट एक्सपोर्ट गुड्स होलसेलर्स एल एल सी
41.	एशिया प्लास्टिक इंडस्ट्री जॉइंट स्टॉक कंपनी

42.	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल इंटरनेशनल
43.	यू एस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी-हंग येन यू एस मास्टरबैच जेएससी
44.	कॉन्ग टी एन एच एच मिन्ह हिएन एल एस डैप्लास्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी
45.	जी सी सी मिनरल्स जॉइंट स्टॉक कंपनी
46.	एन ओ एम एम ए प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
47.	डुक फोंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
48.	फिलर मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
49.	पॉली प्लॉय यू एस सोंग मिन्ह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी

viii. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया:

क्र. सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
1.	एन जी एच ई एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी
2.	येन बाइ यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी
3.	यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी
4.	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी
5.	एन टीएन इंडस्ट्रीज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी
6.	ए डोंग प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी
7.	वीटाप्लस जॉइंट स्टॉक कंपनी
8.	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल जॉइंट स्टॉक कंपनी
9.	जी सी सी मिनरल्स जेएससी
10.	वियम ट्रंग प्लास्टिक केमिकल जे एस सी
11.	यू एस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
12.	फिलर मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी
13.	मेगाप्लास्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी

ix. जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसरण में, उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, वियतनाम सरकार ने भी वियतनाम के व्यापार उपचार प्राधिकारी के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी दायर की।

x. प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को आवश्यक जानकारी देने की मांग करते हुए आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावलियां भेजीं।

क्र. सं.	आयातक का नाम	क्र. सं.	आयातक का नाम
1	एशियन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	136	श्री दक्षिणेश्वरी माँ पॉलीफैब्स लिमिटेड
2	डीवीएम प्रोटेक	137	श्रीजा पॉलिमर्स
3	पारिख पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	138	एमवीएस एसीएमईआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	प्रीमियर पॉलिमर्स	139	एसडीआर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	स्पिनपैक इंडस्ट्रीज कंपनी	140	राठी एंटरप्राइजेज
6	नीलमगम गणपति राम	141	शिवम एग्री पाइप्स
7	पद्मा पॉलिमर्स	142	बीना प्लास्टिक्स
8	यूफोरिया पैकेजिंग एलएलपी	143	बोहरा सेल्स सर्विसेज लिमिटेड
9	रॉप्लास्ट इम्पेक्स	144	सुपर पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड
10	जंबो बैग लिमिटेड	145	जुपैक्स वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
11	जीएसवी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	146	रुचक केमिकल्स
12	डॉलर सेंस	147	मेगाप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	दक्षिणी जैव प्रौद्योगिकी पॉली उद्योग	148	श्री श्याम एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
14	मिथिला प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड	149	मोहन कुमार अग्रवाल
15	इंडो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	150	पॉलीस्पिन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
16	पारशनाथ पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड	151	गोविंद अग्रवाल एचयूएफ
17	प्रगति पॉलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	152	रुषभ प्लास्टिक
18	निर्मल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	153	नेशनल प्लास्टो कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	गोथी इम्पेक्स	154	राजेश कलर कंपनी
20	प्रमुख एजेंसियां	155	भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	विर्गो पॉलिमर्स आई लिमिटेड	156	सन एंटरप्राइज
22	एएम ट्रेडर्स	157	ओरेकल पॉलीप्लास्ट
23	अतुल्य फैब्रिक्स एलएलपी	158	कावेरी ग्लोबल
24	पूजा सेल्स	159	एनके इम्पोर्ट्स
25	टॉपसैक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	160	पार्क शेल्ड्रेक
26	राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड	161	प्यारे लाल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
27	विश्वा पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड	162	श्रीवारी इंडस्ट्रीज

28	श्री लकोशा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड	163	इनऑटो फिल्टर
29	आरजीके पॉलीकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	164	अजय लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
30	श्री आदित्य पॉलिमर्स	165	कावेरी इम्पेक्स
31	शिव इंटरनेशनल लिमिटेड	166	नागिंदास हीरालाल भयानी
32	एयरो प्लास्ट लिमिटेड	167	जाखोटिया पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
33	जे वसंत एक्सपोर्ट्स	168	वीजीआर फूडटेक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
34	सर्वो पैकेजिंग लिमिटेड	169	मारुति एंटरप्राइज
35	गगन पॉलिमर्स	170	एवरेस्ट पॉलीफिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	टेक्सबॉन्ड नॉनवोवन्स	171	अल्पाइन एफआईबीसी प्राइवेट लिमिटेड
37	पीयूष पॉलीटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	172	वैभव मिनरल्स केमिकल्स
38	डेल्टा सिंचाई इंडिया एलएलपी	173	महाशक्ति पॉलीकोट
39	बल्क लिक्विड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	174	श्री कृष्ण सेल्स एजेंसी
40	निर्मल फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	175	एनएवी - डिव इंडस्ट्रीज
41	तिरुमलाई एजेंसी	176	प्लास्टेन इंडिया लिमिटेड
42	ऑलविन पाइप्स	177	राणासरिया पॉली पैक प्राइवेट लिमिटेड
43	ब्रोकेड इंडिया पॉलीटेक्स लिमिटेड	178	कोंकण स्पेशलिटी पॉलीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
44	एच और एच पॉलिमर	179	थानिगाई इंटरनेशनल
45	आर्क नॉनवोवन	180	आल्प्स पॉलीटेक्स
46	गिरिवर्या नॉन वोवन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	181	सिंगला प्लास्टिक उद्योग
47	विराट इम्पेक्स	182	ज़ील पैकेजिंग
48	साई कंदन एजेंसी	183	ओम्या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49	प्रताप सिंथेटिक्स लिमिटेड	184	प्रगति पेपर एंटरप्राइजेज
50	कृष्णा लैमिकोट प्राइवेट लिमिटेड	185	श्रीजी पॉलीमिक्स इंडस्ट्रीज
51	अल्ट्रा नॉनवोवन	186	विबग्योर पॉलीएडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
52	ए-वन टेक्स टेक प्राइवेट लिमिटेड	187	केआईके प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
53	राजश्री फैब्रिक्स	188	ओरियाना ग्लोबल ट्रेड एलएलपी
54	मैट्रिक्स इम्पेक्स	189	नियोटेक्स पॉलिमर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
55	प्राइमो इंडस्ट्रीज	190	के के पॉलीकलर एशिया लिमिटेड
56	श्री माँ पॉलीफैब्स लिमिटेड	191	मधु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
57	प्राकृत इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	192	बालाजी पॉली उद्योग
58	बिग बैग्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	193	क्रिसेंट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	पीके एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	194	सराफ फैबट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

60	प्रोटॉन बहुलक	195	फॉर्मोसा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
61	एपी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	196	बैंगलोर पॉलीकॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	सिग्नोड इंडिया लिमिटेड	197	मेहुल कलर्स मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
63	अग्रवाल टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	198	कश्यप यूनिटेक्स कॉर्पोरेशन
64	नाद नॉनवोवन प्राइवेट लिमिटेड	199	सूरज लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
65	भूमि प्लास्टिक	200	सूरज जायसवाल
66	इलेक्ट्रो पॉलीकेम लिमिटेड	201	एचजे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
67	मिली एक्सपोर्ट्स	202	केसी संस
68	सूर्य लक्ष्मी इंडस्ट्रीज	203	मास्टर एक्सट्रूज़न
69	वर्ना बैग	204	पिनेकल पॉलिमर्स
70	कैपस्टोन पॉलीवीव प्राइवेट लिमिटेड	205	झुनसंस केमिकल्स
71	जेमिनी इम्पेक्स सॉल्यूशंस	206	सेय्योन हाई-टेक पॉली फैब्स प्राइवेट लिमिटेड
72	सुवर्णा एक्सपोर्टर्स	207	एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73	हरिओम पॉलीपैक्स लिमिटेड	208	साई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
74	डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड	209	आयुष्मान मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड
75	लिंगम पॉलिमर्स	210	त्रिमूर्ति पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
76	गिरधर रोल रैप प्राइवेट लिमिटेड	211	अदिशा मोल्ड्स
77	राजगुरु इंडस्ट्रीज	212	ओसवाल इंडस्ट्रीज
78	एसकेपी एंटरप्राइजेज	213	सिडविन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड
79	कोवई पॉलिमर ट्रेडर्स	214	दर्शन प्लास्टिक
80	प्रीत फ्लेक्स	215	ग्लोबेकेम इम्पोर्ट्स
81	एमको एंटरप्राइजेज	216	एसयूवीजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
82	ब्लो पैकेजिंग आई प्राइवेट लिमिटेड	217	स्टैंडर्ड पैकेजिंग
83	एवी एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	218	एस्क्वायर मल्टीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
84	डीबी पॉलिमर्स	219	भीम पॉलीफैब इंडस्ट्रीज
85	पोलस्टार	220	भुयान एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
86	स्किल डाई केम पी लिमिटेड	221	अंजनी इंटरव्यू
87	विडवर कंपनी	222	फास्ट्रैक्स पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
88	मानसरोवर एग्रो सैक्स प्राइवेट लिमिटेड	223	श्याम केमिकल एंड मिनरल्स
89	वर्धमान पॉलीपैक्स	224	मेरिट पॉलिमर्स
90	समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड	225	इशोम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
91	सुनील फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	226	मनिका मोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
92	आरएल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	227	चूड़ीवाल टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड

93	लचीले बैग	228	सुप्रभा प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
94	कुल पैकेजिंग सेवाएँ	229	केएनके ओवरसीज
95	मैरिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	230	पॉलीस्क्वेयर एलएलपी
96	सर्वो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	231	माइको प्लास्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
97	मित्तल टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड	232	विजय पॉलिमर्स
98	नेक्सा कंपाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड	233	तिरुपति हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड
99	बिल्डमेट फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	234	मल्लिनाथ टेक्सटाइल मिल्स
100	पोलिवेक्स ओवरसीज	235	दमन पॉलीफैब्स
101	साई सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	236	टिबरीवाल प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
102	भागीरथी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	237	बड़ौदा पैकेजिंग
103	सिमंधर इम्पेक्स	238	प्रियदर्शिनी पॉलीसैक्स लिमिटेड
104	रचना पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	239	विशाल सिंथेटिक्स
105	बल्कपैक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	240	पैटको पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
106	ड्यूरा प्लास्टसॉल्यूशंस एलएलपी	241	ऋषि एफआईबीसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
107	उत्कृष्ट तकनीकी उद्योग	242	माइको पॉली पैक
108	सिंथेटिक पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड	243	सन मास्टरबैच प्राइवेट लिमिटेड
109	कलरप्लास पॉलीएडिटिव्स एलएलपी	244	भवानी प्लास्टिक्स
110	गौतम सिंघल	245	केबी उद्योग
111	प्लास्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड	246	सन टेक्स मिल्स
112	एमडीपी ट्रेडिंग	247	आस्था प्लास्टिकॉन
113	हुगली एक्सट्रूज़न्स लिमिटेड	248	अनन्या इम्पेक्स
114	डीप केम इंडस्ट्रीज	249	अल-सा अद एंटरप्राइजेज
115	पेकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	250	विजयनेहा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
116	गिरिराज पॉलीपैक	251	नवकार पैकेजिंग
117	सराफ फिनकॉम प्राइवेट लिमिटेड	252	कंडोई फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
118	केटी पायरोकेम	253	शंकर पैकेजिंग्स लिमिटेड
119	आरडीबी रसायन लिमिटेड	254	एसएनजी माइक्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड
120	ध्वनि पॉलीप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड	255	श्री सालासर ट्रेडिंग कंपनी
121	मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	256	वाइब्रेंट पॉलिमर्स एलएलपी
122	चंद्रा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड	257	सीलियन वर्ल्ड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
123	सावित्रीदेवी पॉलीफैब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	258	श्री राम पॉलिमर्स
124	पॉलीजेन ट्रेडिंग कंपनी	259	अमित ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	एनएस फैब्रिक्स	260	एसजी पॉलिमर्स

126	कुलोडे प्लास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	261	वीएम पॉलीटेक्स लिमिटेड
127	पर्ल पॉलीफिल्म निर्माता	262	कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
128	परिवर्तन मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	263	क्रिएटिव पॉली पैक्स पी लिमिटेड
129	अमोरा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	264	वेन पैक
130	पैराडाइज एंटरप्राइजेज	265	वीआर एफआईबीसी जाम्बो बैग इंडस्ट्रीज
131	बड़ौदा रैपिड्स	266	शक्ति पॉली केम
132	श्री अंगिरा एंटरप्राइजेज	267	डीप पॉलिमर्स लिमिटेड
133	पायनियर एंटरप्राइजेज आई प्राइवेट लिमिटेड	268	मेहरासंस कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
134	विवा पेट्रोकेमिकल एलएलपी	269	लिंकन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
135	राजेंद्र केमिकल्स	270	बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
		271	पद्मजा पॉली पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

xi. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातक/उपयोगकर्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया:

क्र. सं.	आयातक/उपयोगकर्ता
1	ऋषभ कलर्स प्राइवेट लिमिटेड

xii. जांच शुरूआत अधिसूचना और आवेदन का एक अगोपनीय संस्करण ज्ञात संगठनों को भेजा गया।

xiii. जांच शुरूआत अधिसूचना के जवाब में, किसी भी ज्ञात संगठन ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया।

xiv. जो निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच में प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं या प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें असहयोगी के रूप में माना गया है।

xv. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदक को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया।

xvi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("जांच की अवधि" या "पीओआई") 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 माह) है। क्षति की अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 शामिल हैं।

xvii. महानिदेशक प्रणाली (डीजी सिस्टम्स) से क्षति जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त आंकड़े प्राधिकारी को प्राप्त हुए और संबद्ध जांच के लिए विचार किए गए। वर्तमान प्रकटीकरण वक्तव्य के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

xviii. प्राधिकारी ने वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित हाल ही में संपन्न पाटनरोधी जांच में फाइल संख्या फा. सं. 06/38/2024 – डीजीटीआर में मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024 के माध्यम से दिनांक 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन

कार्यप्रणाली का निर्धारण किया। चूंकि पाटनरोधी जांच और वर्तमान सीवीडी जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा एक ही है, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान सीवीडी जांच में भी पाटनरोधी जांच मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024 में अपनाई गई वही पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाना उचित समझा।

xix. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अभ्यावेनों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

xx. व्यापार सूचना सं. 09/2021 के पैराग्राफ 7 के अनुसार, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच सीमित की। सांख्यिकीय रूप से वैध तकनीकों का उपयोग करते हुए, प्राधिकारी ने नमूने के भाग के रूप में निम्नलिखित इकाइयों का चयन किया:

क सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड.
ख आलोक मास्टरबैच प्रा. लिमिटेड
ग आलोक इंडस्ट्रीज
घ कंदुई इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड

xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटीकरण विवरण में उचित रूप से विचारित किए गए हैं।

xxii. प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार समझी गई सीमा तक अतिरिक्त जानकारी मांगी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का स्थल-सत्यापन उस सीमा तक किया गया जो वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xxiii. प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार समझी गई सीमा तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त जानकारी मांगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जो वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई।

xxiv. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों/सूचनाओं के आधार पर किया गया है। इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री की लागत के आधार पर एनआईपी, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और सीवीडी नियमावली के अनुसार तैयार की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबसिडी मार्जिन से कम प्रति संतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

xxv. सीवीडी नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 दिसंबर 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें, इसके बाद, यदि कोई हो, तो प्रतिउत्तर अभ्यावेदन दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने अभ्यावेदनों का अगोपनीय रूपांतरण अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

xxvi. प्रकटन विवरण दिनांक 20.03.2026 को जारी किया गया था। तत्पश्चात, प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों में, इच्छुक पक्षों ने जांच के कई पहलुओं पर मुद्दे उठाए, जिनमें योजनाओं की प्रतिकारी योग्यता, विभिन्न योजनाओं के लिए विचार किए गए मानक, विशिष्टता, क्षति, कार्य-कारण संबंध, प्रश्नावली प्रतिक्रिया की अस्वीकृति आदि शामिल हैं। प्राधिकरण ने इन प्रस्तुतीकरणों की जांच की

और इस जांच से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों के प्रकटीकरण में उन्हें सम्मिलित करना उचित समझा। अतः, 20.03.2026 को पूर्व में जारी किए गए प्रकटीकरण वक्तव्य को अधिक्रमित करते हुए, प्राधिकरण ने व्यापक सार्वजनिक हित में सीमा शुल्क प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, यथासंशोधित, के नियम 18 के अनुसार दिनांक 16.06.2026 का एक संशोधित/अतिरिक्त प्रकटीकरण वक्तव्य जारी किया, जिसमें इस जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया। तत्पश्चात, दिनांक 16.06.2026 के प्रकटीकरण वक्तव्य पर घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों को इन अंतिम निष्कर्षों में सम्मिलित किया गया है।

xxvii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित समझा, वहां गोपनीयता दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया। जहां संभव हो सका, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

xxviii. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहुंच से मना कर दिया हो या अन्यथा प्रदान नहीं किया हो, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की हो, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xxix. प्राधिकारी ने इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, उस सीमा तक जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं।

xxx. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी को दर्शाता है और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा उसे इसी प्रकार माना गया है।

xxxi. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = रु. 83.82 है।

ग. ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

7. आरंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच' है, जिसे 'फिलर मास्टरबैच' या 'कैल्शियम कार्बोनेट कम्पाउंड' के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) आयतन के अनुसार 50% से अधिक प्रमुख घटक है।"

"4. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच कैल्शियम कार्बोनेट (एक खनिज), पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीइथाइलीन जैसी आधार प्लास्टिक सामग्री और अन्य योजकों का मिश्रण है। उक्त मिश्रण को एक निश्चित तापमान पर बाहर निकाला जाता है, जिससे कम्पाउंड कणिका रूप में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच बनता है। पीयूसी में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, शेष में प्लास्टिक और अन्य योजक होते हैं।"

"5. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच एक विशेष सामग्री है जिसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक वस्तुओं के गुणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल फिलर के रूप में कार्य करना है जो विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण प्रदान करता है।"

"6. पैकेजिंग, निर्माण, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कई उद्योग कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक में मिलाने पर, कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच उन्हें मजबूत, कम भंगुर, बेहतर आकार-बनाए रखने वाला और कम सिकुड़ने वाला बना सकता है।"

"7. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच यह भी बदल सकता है कि प्लास्टिक सतह पर कैसा महसूस होता है, यह गर्मी को कैसे संभालता है और इसके साथ काम करना कितना आसान है। इसका उपयोग अक्सर प्लास्टिक फिल्म, शीट, पाइप, आकार की वस्तुओं और अन्य प्लास्टिक सामान बनाने के लिए किया जाता है।"

"8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के प्रशुल्क मद 3824 99 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख आयात प्रशुल्क मद 3824 99 00 के तहत निकासी की जाती है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

"9. आवेदकों ने प्रस्तावित किया है कि वर्तमान जांच के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) वैसी ही मानी जाए जैसी फा. सं. 06/38/2024 – डीजीटीआर, मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024 में वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित चल रही पाटनरोधी जांच में अपनाई गई है। प्राधिकारी ने उपर्युक्त पाटनरोधी जांच में दिनांक 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन कार्यप्रणाली का निर्धारण किया है। चूंकि पाटनरोधी जांच और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा एक ही है, इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच में भी वही पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाना उचित समझता है, अर्थात् कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों के साथ:"

मानदंड	***पीसीएन कोड***
75% $CaCO_3$ से कम	*A*
75-85% $CaCO_3$	*B*
85% $CaCO_3$ से अधिक	*C*

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में कोई अनुरोध या टिप्पणी नहीं की है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का दायरा और पीसीएन कार्यप्रणाली, वियतनाम से उसी उत्पाद के आयातों से संबंधित हाल ही में संपन्न पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दी गई के समान ही बनी रहनी चाहिए। पाटनरोधी जांच में उत्पाद का विवरण और संबद्ध देश एक ही था। उसमें किए गए निर्धारण वर्तमान जांच के लिए सीधे प्रासंगिक हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली का मुद्दा पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी की विस्तृत जांच के बाद अंतिम रूप ले चुका है।

iii. पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें निर्यातक, आयातक, उपयोगकर्ता और घरेलू उद्योग शामिल हैं, के व्यापक अनुरोधों की जांच की। लिखित अनुरोधों के कई दौर दायर किए गए और प्राधिकारी ने अपना निर्धारण करने से पहले पीयूसी और पीसीएन पर एक समर्पित बैठक आयोजित की।

iv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच का उपयोग पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को पुनः खोलने या पुनः विवाद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिनकी पहले से ही पूर्व जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों की पूर्ण भागीदारी के बाद जांच की जा चुकी है और उन्हें तय किया जा चुका है।

v. उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच में, आधार बहुलक प्रकार, अंतिम उपयोग अनुप्रयोग और उत्पादन प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पाद नियंत्रण संख्या वर्गीकरण के प्रस्तावों की जांच की थी और उन्हें अस्वीकार कर दिया था।

vi. प्राधिकारी ने उत्पाद नियंत्रण संख्या वर्गीकरण को केवल कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री के आधार पर स्वीकार किया, क्योंकि यह मानदंड बाजार में लागत और मूल्य अंतर को प्रतिबिंबित करता है। यह निष्कर्ष लागत आंकड़ों की जांच और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में रखे गए अनुरोधों के निकाला गया।

vii. उपरोक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि जांच के अंतर्गत उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति को, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच में अंतिम रूप दिया गया है, वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में बिना किसी संशोधन के अपनाया जाए।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी और पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा फा. सं. 06/38/2024–डीजीटीआर, मामला संख्या एडी (ओआई)-36/2024 में वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली की विस्तार से जांच की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया।

12. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उक्त पाटनरोधी जांच (मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024) में उसी संबद्ध देश से उत्पाद का वही विवरण था। उस जांच में पीयूसी के दायरे और पीसीएन पर निर्धारण इसलिए सीधे प्रासंगिक और वर्तमान जांच पर लागू होता है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पीयूसी के दायरे या पीसीएन कार्यप्रणाली में किसी संशोधन की मांग करते हुए कोई टिप्पणी नहीं की है।

13. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी वर्तमान प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच के प्रयोजन के लिए पाटनरोधी जांच में अपनाए गए पीयूसी के उसी दायरे और उसी पीसीएन कार्यप्रणाली को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं। पीयूसी का दायरा निम्नानुसार निर्धारित है:

> *"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच' है, जिसे 'फिलर मास्टरबैच' या 'कैल्शियम कार्बोनेट कम्पाउंड' के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) आयतन के अनुसार 50% से अधिक प्रमुख घटक है।"*

14. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के प्रशुल्क मद 38249900 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख आयात प्रशुल्क मद 382499 00 के तहत निकासी की जाती है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

15. इसके अलावा, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी जांच (मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024) में दिनांक 04 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित पीसीएन को वर्तमान जांच में बनाए रखना उचित है, जो कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों के साथ था:

मानदंड	**पीसीएन**
75% $CaCO_2$ से कम	A
75-85% $CaCO_2$	B
85% $CaCO_2$ से अधिक	C

घ. घ. <u>घरेलू उद्योग की स्थिति एवं नमूनाकरण प्रक्रिया</u>

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत अपर्याप्त आधारों पर आधारित है, क्योंकि याचिका में घरेलू उत्पादकों के उत्पादक-वार उत्पादन मात्रा का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसी जानकारी के अभाव में, हितबद्ध पक्षकार यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि आवेदक उत्पादक सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं।

ii. जहाँ अनेक घरेलू निर्माता विद्यमान हों, वहाँ घरेलू उद्योग को विश्वसनीय और सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ अपनी अधिकार स्थिति स्थापित करना आवश्यक है। याचिका में प्रत्येक उत्पादक का

व्यक्तिगत उत्पादन डेटा प्रदान नहीं किया गया है, जिससे यह सत्यापित करना संभव नहीं हो पाता कि आवेदक उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनाते हैं या नहीं।

iii. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक है कि उत्पादक सामूहिक रूप से समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के एक प्रमुख अनुपात के लिए जिम्मेदार हों। याचिका में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया कि यह आवश्यकता पूरी होती है।

iv. यद्यपि याचिका में कुछ उत्पादकों के समर्थन पत्र शामिल हैं, तथापि यह स्थापित नहीं किया गया है कि आवेदक उत्पादक और समर्थक उत्पादक मिलकर कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनाते हैं। यह दावा किया गया कि आवश्यक जानकारी को रोकने के लिए अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया गया।

v. इक्कीस समर्थक उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी अत्यंत अपर्याप्त है। समर्थक उत्पादकों ने उत्पादन, क्षमता, बिक्री या वित्तीय प्रदर्शन पर किसी सार्थक डेटा के बिना केवल संक्षिप्त, एकल-पृष्ठ विवरण दायर किए हैं।

vi. समर्थक उत्पादकों के अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण लगभग पूरी तरह से संपादित हैं, जिनमें कोई सूचीबद्ध, सारांशित या प्रवृत्ति-आधारित डेटा नहीं है। परिणामस्वरूप, हितबद्ध पक्षकार समर्थक उत्पादकों के उत्पादन मात्रा, बिक्री प्रवृत्तियों, लागत संरचनाओं या लाभप्रदता का आकलन नहीं कर सकते।

vii. यह व्यापार सूचना संख्या 05/2021 के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत समर्थक उत्पादकों से साक्ष्य सहित स्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा, तथा घरेलू बिक्री, निर्यात और स्वयं के उपभोग के लिए अलग-अलग संबद्ध वस्तु की बिक्री मात्रा एवं मूल्य प्रदान करना आवश्यक है।

viii. सूचीबद्ध या सारांशित अगोपनीय डेटा की पूर्ण अनुपस्थिति व्यापार सूचना संख्या 14/2018 का भी उल्लंघन करती है, जो यह अनिवार्य करती है कि गोपनीयता के दावों के साथ सार्थक अगोपनीय सारांश भी प्रस्तुत किए जाएं जो प्रस्तुत जानकारी की उचित समझ की अनुमति दे सकें।

ix. इक्कीस समर्थक उत्पादकों से अनुपालन योग्य और सत्यापन योग्य डेटा के अभाव में, घरेलू उद्योग की अधिकार स्थिति निर्धारित करने के लिए उनके समर्थन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

x. प्राधिकारी ने गैर-भागीदारी घरेलू उत्पादकों या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से जानकारी मांगकर घरेलू उद्योग की अधिकार स्थिति का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है, जैसा कि पिछली जांचों में प्राधिकारी की निरंतर प्रथा रही है।

xi. पिछली जांचों का संदर्भ दिया गया जहाँ ऐसा स्वतंत्र सत्यापन किया गया था। इसी प्रकार के अभ्यास की अनुपस्थिति से विकृत डेटा पर निर्भरता का जोखिम उत्पन्न होता है।

xii. यह प्रस्तुत करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की न्यायिक व्याख्या पर भी भरोसा किया गया कि प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा आर्थिक डेटा को तिरछा करने और क्षति विश्लेषण को विकृत करने का भौतिक जोखिम उत्पन्न न करे।

xiii. संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादकों के अस्तित्व को देखते हुए, "प्रमुख अनुपात" परीक्षण केवल एक गणितीय अभ्यास नहीं है और इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलुओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

xiv. यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि आवेदक प्रमुख अनुपात परीक्षण को पूरा करते हैं, तो भी प्राधिकारी अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकते, जब तक कि वे कानूनी रूप से घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार किए जाने के अयोग्य न हों।

xv. क्षति विश्लेषण में उद्योग की समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ जांच होनी चाहिए और इसे उद्योग के केवल कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

xvi. नमूना चयन के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि वे नमूना चयन पद्धति की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुसार आवश्यक जांच अवधि के लिए आवेदक कंपनियों का उत्पादक-वार डेटा प्रकट नहीं किया गया है।

xvii. यह प्रस्तुत किया गया कि नमूना चयन किए जाने और चार घरेलू उत्पादकों को नमूना कंपनियों के रूप में चुने जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग अनिवार्य क्षति प्रारूपों (प्रारूप छह-एक से छह-पाँच) के अगोपनीय संस्करण प्रदान करने में विफल रहा है।

xviii. केवल एक समेकित अगोपनीय गैर-क्षति मूल्य का परिसंचरण व्यापार सूचना संख्या 09/2021 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि दायित्व स्वयं क्षति प्रारूपों के प्रकटीकरण तक विस्तारित होता है।

xix. अगोपनीय क्षति प्रारूपों तक पहुँच के बिना, हितबद्ध पक्षकार उत्पादन लागत, कच्चे माल की खपत के मानदंड, कार्यशील पूंजी, क्षमता उपयोग, संयंत्र-वार इष्टतम उत्पादन और लागू समायोजन जैसे प्रमुख तत्वों की सार्थक जांच या सत्यापन नहीं कर सकते।

xx. कथित पिछली प्रथाओं पर निर्भरता या पृथक नमूना अधिसूचना की आवश्यकता की अनुपस्थिति, व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों को रद्द नहीं कर सकती।

xxi. प्राधिकारी ने नमूना उत्पादकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कुल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया है, जो यह आकलन करने के लिए आवश्यक है कि नमूना प्रतिनिधिक है या नहीं।

xxii. क्षति प्रारूपों के गैर-प्रकटीकरण और नमूने के उत्पादन हिस्से के गैर-प्रकटीकरण का संचयी प्रभाव उनके बचाव के अधिकारों को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

xxiii. प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वह अधिकार स्थिति निर्धारण के उद्देश्य से अपर्याप्त समर्थक डेटा को अस्वीकार करे, घरेलू उद्योग को नमूना उत्पादकों के लिए प्रारूप छह-एक से छह-पाँच के सार्थक अगोपनीय संस्करण दायर करने का निर्देश दे, नमूने द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले उत्पादन हिस्से का खुलासा करे, तथा घरेलू उद्योग की अधिकार स्थिति और नमूना पद्धति पर स्वतंत्र रूप से जांच करके एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

xxiv. याचिकाकर्ता सत्यापन योग्य साक्ष्य के माध्यम से अधिकार स्थिति स्थापित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं, वर्तमान आवेदन प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6(3) और सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 11.4 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, और इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत के लिए अधिकार स्थिति, सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 11.4 और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 के अंतर्गत संगत सीमा परीक्षण द्वारा शासित होती है।

ii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि अधिकार स्थिति परीक्षण में दो शर्तें हैं: पहली, वे घरेलू उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन भारत में समान उत्पाद के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो; और दूसरी, जहाँ समर्थन और विरोध दोनों विद्यमान हों, वहाँ समर्थक

उत्पादकों को समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले कुल उत्पादकों के उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

iii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन दो संघों अर्थात् कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों सदस्यों की ओर से दायर किया गया था।

iv. कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उनकी सदस्य कंपनियाँ/संस्थाएँ भारत में संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक का गठन करती हैं। ये दोनों संघ भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र दो संघ हैं।

v. याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के दौरान जांच अवधि सहित संबद्ध वस्तु के उत्पादन मात्रा के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ के सदस्यों की सूची प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे उत्पादक की स्थिति (अर्थात् वह समर्थक है, विरोधी है या तटस्थ है) भी प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता ने देश में कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ की गैर-सदस्य अज्ञात कंपनियों/संस्थाओं के अनुमानित उत्पादन सहित भारतीय उत्पादन के विवरण का समेकित विवरण भी प्रदान किया है।

vi. निम्नलिखित बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 9/2021 के अनुलग्नक-एक में आवश्यक जानकारी दायर की, जो जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 35 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं।

क्रम संख्या	**विवरण**	**कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी**
1.	सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	***%
2.	आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड	***%
3.	कंडुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	***%
4.	सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	***%
5.	बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
6.	बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	***%
7.	आलोक इंडस्ट्रीज	***%
8.	बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड	***%
9.	सिद्ध केमीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	***%
10.	बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड	***%
11.	ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
12.	श्री अंबिका पॉलीफिल	***%

vii. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस संस्थाओं ने आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया।

क्रम संख्या	**विवरण**	**कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी**
1.	सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
2.	मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***%
3.	श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
4.	एस.पी. पॉलीमर	***%
5.	365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड	***%
6.	एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	***%
7.	सत्य पॉलीअलॉयज एलएलपी	***%
8.	एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड	***%
9.	रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड	***%
10.	भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
11.	स्वस्तिक प्लास्टोअलॉयज	***%
12.	मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
13.	आदित्य पॉलिसपिन प्राइवेट लिमिटेड	***%
14.	जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड	***%
15.	स्पेशियलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी	***%
16.	सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड	***%
17.	एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
18.	मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	***%
19.	डॉल्फिन पॉलीफिल	***%
20.	जेजे प्लास्टअलॉय	***%
21.	प्रभु पॉलीकलर	***%

viii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुलग्नक-एक में आवश्यक जानकारी दायर की और ये बारह आवेदक जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 35 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि इक्कीस (21) संस्थाओं ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया और समर्थकों के प्रारूप में आवश्यक डेटा प्रदान किया।

ix. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि बारह आवेदक उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का 35% से अधिक हैं, जबकि आवेदक उत्पादक इक्कीस सहायक उत्पादकों के साथ मिलकर 55% से अधिक हैं; तदनुसार, वैधानिक स्थायी आवश्यकता पूरी होती है। घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि सीएमएमएआई और एमएमए की कोई सदस्य कंपनी/इकाई और पीयूसी का कोई अन्य घरेलू उत्पादक याचिका का विरोध नहीं करता है; इसलिए, नियम 6 (3) की व्याख्या के तहत 50% परीक्षण भी पूरा होता है।

x. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" पद में या तो समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादक शामिल हैं, या वे उत्पादक शामिल हैं जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" गठित करता हो। इसने प्रस्तुत किया कि आवेदक और समर्थक सामूहिक

रूप से कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए नियम 2(ख) को संतुष्ट करते हैं।

xi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के हिस्से को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के लिए निम्नलिखित उत्पादन और हिस्सेदारी के आंकड़े प्रस्तुत किए:

क्र. सं.	विवरण	कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी	पीओआई में उत्पादन
1.	बारह आवेदक घरेलू उत्पादक	35	2,50,893 मीट्रिक टन
2.	इक्कीस सहयोगी घरेलू उत्पादक	20	1,43,525 मीट्रिक टन
3.	अन्य भारतीय उत्पादक	45	3,21,306 मीट्रिक टन
कुल		**100**	**7,15,724 मीट्रिक टन**

xii. वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में अधिकार स्थिति पर निर्धारण वही होना चाहिए जो प्राधिकारी द्वारा हाल ही में संपन्न पाटनरोधी जांच में पहले से किया जा चुका है, जो उसी देश से उसी उत्पाद के आयात से संबंधित है।

xiii. पाटनरोधी जांच में निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के पश्चात अधिकार स्थिति की जांच की गई और निर्णय लिया गया। मामला संख्या एडी(ओआई)-36/2024 में अंतिम अंतिम जांच परिणाम फाइल संख्या 06/38/2024-डीजीटीआर में, प्राधिकारी ने दर्ज किया कि घरेलू उद्योग ने 25 प्रतिशत अधिकार स्थिति सीमा और "प्रमुख अनुपात" परीक्षण दोनों को संतुष्ट किया।

xiv. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में अधिकार स्थिति के लिए कानूनी परीक्षण, पाटनरोधी जांच में लागू किए गए परीक्षणों के समान हैं। यह दोहराया गया कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6(3) के साथ पठित सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 11.4 के अंतर्गत अधिकार स्थिति के लिए (एक) कुल उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत समर्थन; और (दो) जहाँ समर्थन और विरोध दोनों विद्यमान हों, वहाँ समर्थन या विरोध व्यक्त करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक समर्थन आवश्यक है, और यह प्रस्तुत किया गया कि इन सिद्धांतों को पहले से ही संपन्न पाटनरोधी जांच में लागू और पुष्टि किया जा चुका है।

xv. घरेलू उत्पादन आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आवेदक उत्पादकों और समर्थक उत्पादकों की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत सत्यापित अधिकार स्थिति गणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xvi. वर्तमान जांच में जांच अवधि मोटे तौर पर वही है, जिसमें पाटनरोधी जांच की तुलना में तीन महीने की वृद्धि की गई है।

xvii. चूँकि तथ्यात्मक आधार और कानूनी परीक्षण समान हैं, इसलिए वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में अधिकार स्थिति का निर्धारण, संपन्न पाटनरोधी जांच में हुए अधिकार स्थिति निर्धारण का अनुसरण करना चाहिए, और अधिकार स्थिति के मुद्दे को पुनः खोलने के प्रयासों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xviii. नमूना चयन पर, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुच्छेद 7 के अनुसार किया गया था, जो प्राधिकारी को क्षति मार्जिन निर्धारण के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच को सीमित संख्या तक सीमित करने की अनुमति देता है। व्यापार सूचना में सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना चयन विधियों की आवश्यकता है, किंतु नमूना चयन के लिए पृथक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

xix. विस्तृत जांच के लिए चुने गए चार नमूना उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, जो उन्हें लागत और बिक्री सत्यापन के लिए प्रतिनिधिक बनाता है, और वे मिलकर कुल घरेलू आवेदकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xx. चार नमूना उत्पादक भौगोलिक और परिचालन दृष्टि से विविध हैं, और यह विविधता सुनिश्चित करती है कि नमूना व्यापक घरेलू उद्योग का प्रतिबिंब है।

xxi. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों या सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते के अंतर्गत नमूना घरेलू उद्योग के चयन के लिए पृथक अधिसूचना जारी करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। पारदर्शिता के लिए, घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रारूपों में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हुए एक प्रस्तुतीकरण दायर किया और यह प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी की प्रक्रिया और प्रथा के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया।

xxii. प्राधिकारी ने अनेक पिछली जांचों में पृथक नमूना अधिसूचना जारी किए बिना घरेलू उत्पादकों के प्रतिनिधि समूह का चयन किया है, और घोषणा के स्वरूप के बजाय डेटा की पूर्णता, सत्यापन योग्यता और प्रतिनिधित्वता पर जोर दिया जाता है।

xxiii. नमूना चयन का विरोध करने वाले प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए नमूना चयन में कोई प्रक्रियागत त्रुटि या कानूनी दोष स्थापित नहीं करते।

xxiv. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उसने व्यापार सूचना संख्या 09/2021 का अनुपालन किया, यह कहते हुए कि अगोपनीय प्रकटीकरण का उद्देश्य क्षति दावों की उचित समझ की अनुमति देना है, न कि संवेदनशील संयंत्र-वार लागत डेटा प्रकट करना। कंपनी-वार गोपनीय प्रारूपों को प्रकट करने के बजाय समेकित अगोपनीय गैर-क्षति मूल्य परिचालित करना इस आवश्यकता को संतुष्ट करता है।

xxv. प्रारूप छह-एक से छह-पाँच में संवेदनशील जानकारी शामिल है, जिसमें उत्पादन लागत, कच्चे माल की खपत के मानदंड, कार्यशील पूंजी, क्षमता उपयोग और संयंत्र-वार इष्टतम उत्पादन शामिल हैं, और विस्तृत स्तर पर प्रकटीकरण से व्यक्तिगत उत्पादकों की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी उजागर होगी और अपूरणीय क्षति होगी।

xxvi. एन आई पी की गणना उत्पादन लागत, क्षमता उपयोग, कच्चे माल की खपत, उपयोगिताओं, कार्यशील पूंजी और उचित प्रतिफल पर गोपनीय डेटा से की जाती है, और यह संपूर्ण डेटा प्राधिकारी के पास उपलब्ध है तथा उसके द्वारा सत्यापित है। अंतर्निहित प्रारूपों की गोपनीयता एन आई पी की शुद्धता या सत्यापन योग्यता को प्रभावित नहीं करती।

xxvii. हितबद्ध पक्षकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि उन्हें बारह आवेदक घरेलू उत्पादकों के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभप्रदता और अन्य क्षति मानकों में प्रवृत्तियों को दर्शाने वाली अगोपनीय क्षति जानकारी प्रदान की गई है। इस आधार पर, हितबद्ध पक्षकार क्षति और कार्य-कारण पर प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई क्षति, यदि है, तो वह सब्सिडीयुक्त आयात के कारण है।

xxviii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियम हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उत्पादकों के गोपनीय लागत या उत्पादन डेटा तक पहुँच का अधिकार प्रदान नहीं करते, और घरेलू उद्योग का दायित्व प्राधिकारी के समक्ष संपूर्ण डेटा प्रस्तुत करना है, जिसका अनुपालन किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्राधिकारी की जांच और सत्यापन के माध्यम से तथा सार्थक अगोपनीय सारांशों के प्रकटीकरण के माध्यम से सुरक्षित हैं।

xxix. व्यापार सूचना में प्राधिकारी को नमूना चयन के मानदंड या विस्तृत औचित्य प्रकट करने या नमूना उत्पादकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सटीक उत्पादन हिस्से को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिनिधित्वता का मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा गोपनीय डेटा के आधार पर किया जाता है, और सार्वजनिक प्रकटीकरण की अनुपस्थिति नमूना चयन अभ्यास को अवैध नहीं बनाती।

xxx. घरेलू उद्योग ने इस आरोप को अस्वीकार किया कि नमूना चयन याचिकाकर्ता के विवेक से संचालित था और प्रस्तुत किया कि नमूना चयन व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुच्छेद 7 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, और घरेलू उद्योग को नमूने का चयन करने का अधिकार नहीं है।

xxxi. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुपालन न करने के आरोप कानूनी या तथ्यात्मक आधार के बिना हैं; कि नमूना चयन प्राधिकारी द्वारा व्यापार सूचना और स्थापित प्रथा के अनुसार किया गया है; कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण दायित्वों का अनुपालन किया गया है; और कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के प्रकटीकरण की मांग करते हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

18. यह आवेदन भारत में घरेलू उत्पादकों की ओर से कम्पाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे इसके पश्चात "सीएमएमएआई" कहा जाएगा) और मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे इसके पश्चात "एमएमए" कहा जाएगा) द्वारा दायर किया गया था।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में पीयूसी उद्योग विखंडित है और इसमें भारत भर में स्थित अत्यधिक बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं, इसलिए प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच के लिए आवेदन दो संगठनों, अर्थात् सीएमएमएआई और एमएमए द्वारा अपनी सदस्य इकाइयों की ओर से दायर किया गया था। दिनांक 29 जुलाई 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में व्यापार सूचना सं. 11/2021 दिनांक 18 नवंबर 2021 द्वारा यथा-संशोधित सभी प्रासंगिक जानकारी निम्नलिखित बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर की गई:

i. कंडुई इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
ii. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
iii. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
v. बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड
vi. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
vii. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. सिद्ध केमीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
ix. श्री अंबिका पॉलीफिल
x. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
xi. आलोक इंडस्ट्रीज़
xii. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

20. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस (21) घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया:

i. सोनाली पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. श्री मणिराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. एस.पी. पॉलीमर
v. 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड
vi. एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
vii. सत्य पॉलीअलॉयज एलएलपी
viii. एडेक्स पॉलीब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड
ix. रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
x. भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. स्वस्तिक प्लास्टोअलॉयज
xii. मनन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xiii. आदित्य पॉलिसपिन प्राइवेट लिमिटेड
xiv. जे के पारस पॉलीकोट्स लिमिटेड
xv. स्पेशियलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी
xvi. सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड
xvii. एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xviii. मनहर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xix. डॉल्फिन पॉलीफिल
xx. जेजे प्लास्टअलॉय
xxi. प्रभु पॉलीकलर

21. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत के लिए स्थिति आवश्यकता एससीएम करार के अनुच्छेद 11.4 के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 6(3) द्वारा शासित होती है। सीवीडी नियमावली के नियम 6(3) के लिए आवश्यक है कि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हों। इसके अलावा, जहां घरेलू उत्पादक आवेदन का स्पष्ट रूप से विरोध करते हों, ऐसा विरोध उन घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए जिन्होंने आवेदन के प्रति समर्थन या विरोध व्यक्त किया हो।

"(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन के आधार पर जांच तब तक प्रारंभ नहीं करेंगे जब तक कि —

(क) वह समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए आवेदन के समर्थन या विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित न कर ले कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है: परंतु यह कि यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान उत्पाद के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से कम के लिए जिम्मेदार हों तो कोई जांच प्रारंभ नहीं की जाएगी, और

(ख) वह आवेदन में प्रदान किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करे और स्वयं को संतुष्ट करे कि निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं —

(i) सब्सिडी,

(ii) क्षति, जहाँ लागू हो; और

(iii) जहाँ लागू हो, ऐसे सब्सिडीयुक्त आयात और कथित क्षति के बीच कार्य-कारणात्मक संबंध, जो जांच प्रारंभ करने को उचित ठहराते हों।

स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजन के लिए, आवेदन को "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" किया गया माना जाएगा यदि इसे उन घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त हो जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है जो आवेदन के समर्थन या विरोध में, यथास्थिति, अभिव्यक्ति कर रहा हो।"

23. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" को समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान वस्तु के निर्माण में संलग्न हैं, या वे घरेलू उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात गठित करता हो। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

24. प्राधिकारी कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क पर ध्यान देते हैं कि याचिका में घरेलू उत्पादकों के उत्पादक-वार उत्पादन मात्रा और बाजार हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया गया है और इसलिए अधिकार स्थिति के सत्यापन की अनुमति नहीं मिलती। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 6(3) के अंतर्गत अधिकार स्थिति निर्धारण के लिए समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए आवेदन के समर्थन या विरोध की मात्रा की जांच आवश्यक है। प्राधिकारी ऐसी जांच आवेदन में और उसके पश्चात की प्रतिक्रियाओं में अभिलेख पर रखी गई जानकारी के आधार पर करते हैं, जिसमें आवेदकों और समर्थकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय जानकारी तथा लागू नियमों के अनुसार अगोपनीय सारांश शामिल हैं।

25. प्राधिकारी जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर रखी गई उत्पादन और हिस्सेदारी की जानकारी नोट करते हैं:

विवरण	**कुल भारतीय उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी**	**जांच अवधि में उत्पादन (क)**
बारह आवेदक घरेलू उत्पादक	35	2,50,893 मीट्रिक टन
इक्कीस समर्थक घरेलू उत्पादक	20	1,43,525 मीट्रिक टन
अन्य भारतीय उत्पादक	45	3,21,306 मीट्रिक टन
कुल	100	7,15,724 मीट्रिक टन

26. पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि बारह आवेदक घरेलू उत्पादक, इक्कीस समर्थक उत्पादकों के साथ मिलकर, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन के

55 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं। प्राधिकारी ने आगे दर्ज किया कि अभिलेख पर सत्यापित जानकारी के आधार पर 25 प्रतिशत सीमा आवश्यकता और "प्रमुख अनुपात" परीक्षण दोनों संतुष्ट हुए।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 11.4 के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6(3) के अंतर्गत अधिकार स्थिति के लिए कानूनी परीक्षण, पाटनरोधी जांच में लागू अधिकार स्थिति परीक्षणों के समान हैं। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम के पश्चात से आवेदक उत्पादकों, समर्थक उत्पादकों या घरेलू उत्पादन आधार की पहचान में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

28. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में जांच की अवधि, पाटनरोधी जांच में परीक्षित अवधि के साथ काफी हद तक अतिव्यापी है, जिसमें केवल तीन महीने की वृद्धि की गई है। वर्तमान जांच में अभिलेख पर रखी गई जानकारी की जांच पर, प्राधिकारी को पिछली कार्यवाही में विस्तृत परीक्षण के पश्चात पहले से पहुँचे गए अधिकार स्थिति निर्धारण से हटने का कोई आधार नहीं मिलता।

29. प्राधिकारी इसलिए यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग की अधिकार स्थिति का मुद्दा, जिसे पाटनरोधी जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों की पूर्ण भागीदारी के पश्चात विस्तार से जांचा और निर्णायक रूप से निर्धारित किया जा चुका है, एक सुलझा हुआ मुद्दा है। तथ्यों या कानूनी ढाँचे में किसी भौतिक परिवर्तन की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी पहले से पहुँचे गए अधिकार स्थिति निर्धारण पर निरंतरता बनाए रखना और उस पर निर्भर रहना उचित मानता है।

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान शीर्षक के अंतर्गत उठाई गई कई आपत्तियाँ मुख्यतः गोपनीयता, अगोपनीय सारांशों की पर्याप्तता और आवेदक तथा समर्थक उत्पादकों द्वारा अभिलेख पर रखी गई जानकारी की पारदर्शिता के मुद्दों से संबंधित हैं।

31. प्राधिकारी मानते हैं कि गोपनीयता दावों, व्यापार सूचनाओं के अनुपालन और अगोपनीय प्रकटीकरणों की पर्याप्तता से संबंधित मुद्दे प्रक्रियागत मामले हैं जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 और प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं द्वारा शासित हैं। ऐसे मुद्दे, स्वयं में, नियम 6(3) के अंतर्गत अधिकार स्थिति सीमाओं की संतुष्टि या नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा को नकारते नहीं हैं।

32. कथित अत्यधिक गोपनीयता, अगोपनीय सारांशों की पर्याप्तता और प्रकटीकरणों की पारदर्शिता से संबंधित प्रस्तुतीकरणों की अलग से जांच की गई है और इन्हें प्रकटीकरण वक्तव्य के संबंधित परवर्ती खंडों में संबोधित किया गया है जो गोपनीयता और प्रकटीकरण दायित्वों से संबंधित हैं।

33. प्राधिकारी यह नहीं मानते कि गैर-भागीदारी उत्पादकों से जानकारी प्राप्त करने के पृथक अभ्यास की अनुपस्थिति, अपने आप में, अधिकार स्थिति निर्धारण को अवैध बनाती है, जहाँ अधिकार स्थिति सीमाएँ और घरेलू उद्योग के मानदंड अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संतुष्ट हों और प्राधिकारी द्वारा जांचे गए हों।

34. नमूना चयन पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार सूचना संख्या 09/2021 का अनुच्छेद 7, प्राधिकारी को क्षति मार्जिन निर्धारण के लिए घरेलू उत्पादकों के एक नमूने तक विस्तृत जांच सीमित करने की अनुमति देता है और नमूने का चयन सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना चयन तकनीकों का उपयोग करके किए जाने की आवश्यकता है। व्यापार सूचना में विस्तृत नमूना चयन औचित्य निर्धारित करते हुए पृथक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का प्रावधान नहीं है।

35. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विस्तृत जांच के लिए चार घरेलू उत्पादकों का चयन किया गया था। नमूना उत्पादक संबद्ध वस्तु के बड़े उत्पादकों में से हैं और वे भौगोलिक तथा परिचालन दृष्टि से विविध हैं। प्रतिनिधित्वता का मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा गोपनीय जानकारी सहित अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है, और प्राधिकारी यह नहीं मानते कि किया गया नमूना चयन केवल इसलिए दूषित है क्योंकि नमूना चयन औचित्य की व्याख्या करते हुए पृथक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई।

36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नमूना चयन और प्रतिनिधित्वता का मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के आधार पर किया जाता है, और सटीक उत्पादक-वार उत्पादन हिस्सेदारी के प्रकटीकरण में व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय जानकारी शामिल हो सकती है। प्राधिकारी मानते हैं कि उचित प्रक्रिया, अनुमेय सीमा तक अगोपनीय जानकारी के परिसंचरण और प्रस्तुतीकरण दायर करने के अवसर के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

37. प्राधिकारी का मानना है कि क्षति और कार्य-कारणात्मक संबंध पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणी करने की क्षमता, व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करते हुए, समेकित अगोपनीय प्रवृत्ति जानकारी तक पहुँच के माध्यम से संरक्षित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विस्तृत लागत डेटा और क्षति प्रारूप प्राधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन के लिए उपलब्ध रहते हैं।

38. प्राधिकारी, जांच और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यह मानना है कि जांच की शुरुआत और निरंतरता, घरेलू उद्योग की अधिकार स्थिति या नमूना चयन प्रक्रिया के आधार पर दूषित नहीं है, क्योंकि नियम 6(3)/अनुच्छेद 11.4 के अंतर्गत अधिकार स्थिति सीमाएँ संतुष्ट हैं, परीक्षित उत्पादन संरचना के आधार पर नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकता पूरी होती है, और नमूना चयन व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुच्छेद 7 के अनुसार किया गया है तथा जांच अभिलेख के आधार पर प्राधिकारी द्वारा जांचा गया है।

39. इस प्रकार, निम्नलिखित बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादक, खंडित उद्योगों के लिए व्यापार सूचना 9/2021 के अनुबंध-I के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं:

i. कंदुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
ii. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
iii. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. बजाज मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड
v. बजाज सुपरपैक इंडिया लिमिटेड
vi. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
vii. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. सिद्ध केमीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
ix. श्री अंबिका पॉलीफिल

x. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
xi. आलोक इंडस्ट्रीज
xii. आलोक मास्टरबैचेस प्राइवेट लिमिटेड

40. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित इक्कीस (21) घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया और निर्धारित प्रारूप में आवश्यक डेटा प्रदान किया:

i. सोनाली पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. श्री मनीराम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. एस.पी. पॉलीमर
v. 365 प्लास्टियम प्राइवेट लिमिटेड
vi. एन.पी. एग्रो (इंडिया) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
vii. सत्य पॉलीएलॉयज एलएलपी
viii. एडेक्स प्लॉयब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड
ix. रामा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
x. भाग्यश्री कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. स्वस्तिक प्लास्टोएलॉयज
xii. मनन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xiii. आदित्य पॉलीस्पिन प्राइवेट लिमिटेड
xiv. जे के पारस प्लॉयकोट्स लिमिटेड
xv. स्पेशलिटी मास्टरबैचेस एलएलपी
xvi. सचदेवा पॉलीकलर प्राइवेट लिमिटेड
xvii. एवरप्लस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xviii. मनहर पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xix. डॉल्फिन पॉलीफिल
xx. जेजे प्लास्टएलॉय
xxi. प्रभु पॉलीकलर

ङ. ङ. गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दे

ङ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

41. गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. जांच शुरू करने की सूचना और उसके बाद की कार्यवाही विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि जांच 18 महीने की अस्वीकार्य रूप से बढ़ाई गई जांच अवधि के साथ शुरू की गई, जो कथित तौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 की व्याख्या (ii) का उल्लंघन है।
ii. व्याख्या (ii) के अनुसार चूक जांच अवधि बारह महीने होती है, और केवल प्राधिकारी द्वारा "लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों" से न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने की अवधि अपनाने की छूट दी गई है।
iii. "लिखित रूप में कारण दर्ज करने" की आवश्यकता अनिवार्य है, जैसा कि "होगा" शब्द से स्पष्ट है। यह आवश्यकता क्षति विश्लेषण में निरंतरता, समान तुलना और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और इसलिए इसके लिए प्राधिकारी द्वारा दिमाग लगाने का प्रदर्शन करने वाला एक स्वतंत्र, तर्कपूर्ण औचित्य आवश्यक है।

iv. जांच शुरू करने की सूचना में केवल आवेदक के कथन को दोहराया गया है और इसमें प्राधिकारी का स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल नहीं है।

v. जांच शुरू करने की सूचना में यह दर्ज नहीं है कि प्राधिकारी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थिति या संसाधन की कमी के बारे में आवेदक के दावों की पुष्टि की या स्वीकार किया; यह नहीं बताया गया कि बताई गई व्यावहारिक कठिनाइयाँ असाधारण परिस्थितियाँ क्यों हैं जो 12 महीने के मानक से विचलन को उचित ठहराती हैं; और यह संबोधित नहीं करती कि क्या विचलन के कारण जांच शुरू होने के बाद दिए जा सकते हैं।

vi. आवेदक की सुविधा या प्रशासनिक कठिनाई, प्राधिकारी के अपने कारणों को दर्ज करने के वैधानिक दायित्व का विकल्प नहीं बन सकती, और आवेदक के कथन का यांत्रिक रूप से समर्थन करने से "लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों" की आवश्यकता अर्थहीन हो जाएगी।

vii. याचिका व्यापार सूचना संख्या 14/2018 का पालन न करने के कारण दोषपूर्ण है, जो आवेदकों को सार्थक सत्यापन और खंडन की अनुमति देने के लिए विस्तृत अगोपनीय समर्थक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।

viii. समर्थकों के प्रस्तुतीकरण में खाली प्रारूप शामिल हैं जिनमें मूल जानकारी को व्यापक गोपनीयता के दावों के तहत काट दिया गया है, जिससे आंकड़े अनुपयोगी हो गए हैं और मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, क्षति और समर्थन के दावों का आकलन नहीं हो पा रहा है।

ix. अनुपालन योग्य अगोपनीय समर्थक आंकड़ों के अभाव में, प्राधिकारी को समर्थकों के योगदान को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए और याचिका को समर्थन रहित मानना चाहिए। जांच शुरू करना प्रदर्शित समर्थन के अभाव में विफल होना चाहिए और कार्यवाही को शुरुआत में ही खारिज/समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

x. व्यापार सूचनाएं प्राधिकारी और पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकारी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, बंबई (सिविल अपील संख्या 6600/1985) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला यह प्रस्तुत करने के लिए दिया गया कि एक व्यापार सूचना सीमा शुल्क प्राधिकारियों को बांधती है और, यदि गलत है, तो इसे वापस लिया जाना चाहिए या संशोधित किया जाना चाहिए।

xi. आवेदक उद्योग जांच शुरू करने की सूचना में अपनाई गई जांच अवधि के अनुरूप पूर्ण और अद्यतन आंकड़े प्रदान करने में विफल रहा। आवेदन मूल रूप से अप्रैल 2023-मार्च 2024 के आंकड़ों के आधार पर दायर किया गया था, जबकि प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2023-30 जून 2024 के लिए जांच शुरू की।

xii. एक बार जब प्राधिकारी ने विस्तारित जांच अवधि अपना ली, तो आवेदक केवल मार्च 2024 तक के आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, संपूर्ण अधिसूचित अवधि को कवर करने वाली सूचना का एक पूर्ण अद्यतन सेट और संशोधित क्षति विश्लेषण प्रस्तुत करके अपने आवेदन को अधिसूचित जांच अवधि के साथ संरेखित करने के लिए बाध्य था।

xiii. आवेदकों ने पूर्ण अद्यतन आवेदन दायर नहीं किया और इसके बजाय, सभी आवेदक उत्पादकों की सूचना को समेकित करने वाला केवल एक पृष्ठ का "अद्यतन" प्रोफार्मा IV-क दायर किया।

xiv. इससे कमी दूर नहीं होती क्योंकि आवेदक ने सभी व्यक्तिगत आवेदक कंपनियों के लिए अद्यतन जांच अवधि के लिए कंपनी-वार जानकारी प्रदान नहीं की, जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के तहत अनिवार्य है, और अधिसूचित जांच अवधि के लिए संशोधित क्षति तालिकाएँ, प्रवृति या विवरणात्मक विश्लेषण दायर नहीं किया।

xv. यह खंडित अद्यतनीकरण हितबद्ध पक्षकारों के अपने हितों की रक्षा करने के अधिकारों में बाधा डालता है, पक्षकारों और प्राधिकारी को क्षति मापदंडों की सुसंगत समझ से वंचित करता है, और इसके परिणामस्वरूप जांच एक ऐसे आवेदन और क्षति विश्लेषण पर आगे बढ़ती है जो जांच अवधि के अनुरूप नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया क्षति और कारण-निर्धारण मूल्यांकन कमजोर होता है।

xvi. आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि में क्षति को सिद्ध करने का अपना भार पूरा नहीं किया है।

xvii. संपूर्ण जांच अवधि के लिए प्रमाणपत्रों/वचनबद्धताओं/घोषणाओं/प्राधिकरणों की अनुपस्थिति कार्यवाही को अवैध बनाती है। आवेदन 1 अप्रैल 2023-31 मार्च 2024 की जांच अवधि के साथ दायर किया गया था, लेकिन प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2023-30 जून 2024 के साथ जांच शुरू की, और आवेदक ने जांच शुरू करने की सूचना में प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच अवधि के अनुरूप प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए।

xviii. प्राधिकारी को आवेदक के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में योग्य होने का आकलन करने के लिए, आयातकों/निर्यातकों के साथ संबंध और स्व-आयात के बारे में प्रमाणपत्रों सहित, जांच शुरू करने की सूचना में अपनाई गई जांच अवधि के लिए प्रमाणपत्र मांगने चाहिए थे, और यह जांच शुरू करने की सूचना जारी करने से पहले एक पूर्व-शर्त के रूप में किया जाना चाहिए था।

xix. जांच शुरू करने की सूचना नियम 2(ख) के तहत पूर्व-शर्तों का पता लगाए बिना प्रकाशित की गई थी और इसलिए कार्यवाही विधि में दोषपूर्ण है, जिसमें नियम 5 और नियम 6(3) का उल्लंघन भी शामिल है, जो प्रावधान करता है कि प्राधिकारी तब तक जांच शुरू नहीं करेगी जब तक पूर्व-शर्तें पूरी न हो जाएं। चूंकि दोष जांच शुरू होने से पहले हुआ, इसे बाद में वर्तमान चरण में प्रमाणपत्र प्रदान करके ठीक नहीं किया जा सकता और यह एक घातक अधिकार-क्षेत्र संबंधी त्रुटि है।

xx. यहां तक कि अद्यतन जांच अवधि के लिए बाद में दायर की गई अद्यतन क्षति सूचना में भी अद्यतन अवधि के लिए अनिवार्य प्रमाणपत्र/वचनबद्धताएं/घोषणाएं या प्राधिकारी शामिल नहीं हैं। आवेदन दायर करने की पात्रता और सब्सिडी, क्षति और कारण-संबंध के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर निर्णय पूर्ण जांच अवधि के आंकड़ों और प्रमाणपत्रों के बिना लिए गए हैं, जिससे आंकड़ों की सत्यता पर संदेह होता है।

xxi. आवेदक उद्योग ने याचिका में कई प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया, जिससे उत्तरदाताओं की क्षति मापदंडों की जांच करने और अपने हितों की रक्षा करने

की क्षमता प्रभावित हुई। आवेदक ने न तो गोपनीयता के लिए अच्छा कारण स्थापित किया और न ही उचित समझ के लिए पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रदान किए।

xxii. जहां कोई पक्ष यह दावा करता है कि जानकारी सारांश के योग्य नहीं है, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुसार यह बताने वाले कारणों के विवरण की आवश्यकता होती है कि सारांश बनाना संभव क्यों नहीं है, और केवल यह कह देना कि सारांश बनाना संभव नहीं है, इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता।

xxiii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों और व्यापार सूचना के अनुसार, याचिका के अगोपनीय संस्करण में उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में सूचीबद्ध और सारांशित आंकड़े प्रदान करने चाहिए, और व्यापार सूचना प्रावधान करती है कि सार्थक अगोपनीय संस्करणों के बिना प्रस्तुतियाँ अभिलेख पर नहीं ली जानी चाहिए।

xxiv. याचिका के उचित अगोपनीय संस्करण प्रदान किए जाने चाहिए और प्रभावी बचाव को सक्षम करने के लिए सार्थक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

xxv. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के विपरीत, याचिका बिक्री मूल्य, प्रति इकाई कर पूर्व ब्याज लाभ, कुल कर पूर्व ब्याज लाभ, घरेलू बिक्री ब्याज/वित्त लागत, और मूल्यह्रास/परिशोधन व्यय के लिए प्रवृति प्रदान करती है, जबकि समग्र वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता थी, और यह पारदर्शिता को कमजोर करता है।

xxvi. घरेलू उद्योग की इस स्थिति का संदर्भ दिया गया कि व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिशानिर्देश-आधारित है और अच्छा कारण दिखाने पर मामला-दर-मामला आधार पर विचलन की अनुमति देता है, और इसके अनुसार गोपनीयता का दावा किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि ऐसा भरोसा गलत है क्योंकि विचलन केवल अच्छा कारण प्रदर्शित करने पर ही स्वीकार्य है, जो वर्तमान मामले में सिद्ध नहीं किया गया है।

xxvii. कई उत्पादकों के लिए समग्र वास्तविक आंकड़ों का खुलासा करने से व्यक्तिगत कंपनी की जानकारी का पता नहीं चलता और इसलिए इससे वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने यह नहीं दिखाया है कि ऐसा समग्र खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता, और इसलिए केवल प्रवृति प्रदान करने का कोई अच्छा कारण मौजूद नहीं है।

xxviii. व्यापार सूचनाएं बाध्यकारी हैं और घरेलू उद्योग का यह औचित्य कि पहले के मामलों में इसी तरह के खुलासे की आवश्यकता नहीं थी, व्यापार सूचना आवश्यकताओं की अवहेलना का वैध आधार नहीं है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वह घरेलू उद्योग को पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अगोपनीय संस्करण में समग्र वास्तविक आंकड़े प्रदान करने का निर्देश दे।

xxix. सहायक उत्पादकों ने केवल न्यूनतम विवरण दायर किए जिनमें मूल जानकारी को काला कर दिया गया, कोई सूचीबद्ध या प्रवृति-आधारित आंकड़े नहीं दिए, जिससे उत्पादन, बिक्री, लागत प्रवृति, लाभप्रदता और समर्थन की सीमा का आकलन नहीं हो पाया। घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना संख्या 05/2021 और व्यापार सूचना संख्या 14/2018 का अनुपालन नहीं किया, और ऐसे दोषपूर्ण समर्थन की अवहेलना की जानी चाहिए।

xxx. आवेदक द्वारा उपयोग किया गया आयात आंकड़ा अविश्वसनीय द्वितीयक/निजी स्रोतों से है और प्रामाणिक या विश्वसनीय नहीं है। प्राधिकारी को आयातों की जांच के लिए वाणिज्य

मंत्रालय के अधीन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का आयात आंकड़ा मंगाना और उस पर भरोसा करना चाहिए, जैसा कि प्राधिकारी ने पिछले मामलों में उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xxxi. आवेदक ने जांच शुरू करने के आधार के रूप में उपयोग किए गए आयात आंकड़ों के स्रोत का नाम तक उजागर न करके, ऐसी गोपनीयता के कारण बताए बिना, अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया। आयात आंकड़े निर्यातकों से संबंधित हैं और इसलिए इसे जवाब देने वाले निर्यातकों से गोपनीय नहीं रखा जा सकता।

xxxii. कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच (जांचाधीन उत्पाद) और रंग मास्टरबैच (गैर-जांचाधीन उत्पाद) के बीच अंतर बनाए रखा जाना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच आमतौर पर कम कीमत वाला होता है, जबकि रंग मास्टरबैच की कीमतें और लाभ अंतर अधिक होते हैं।

xxxiii. प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वह जांचाधीन उत्पाद और रंग मास्टरबैच के लिए अलग-अलग उत्पादन और वित्तीय आंकड़े प्राप्त करे; यह पहचाने कि 12 आवेदकों में से कौन मुख्य रूप से जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे हैं; यह निर्धारित करे कि क्षमता का कितना अनुपात जांचाधीन उत्पाद बनाम रंग मास्टरबैच के लिए समर्पित है; और सुनिश्चित करे कि आवेदक की स्थिति और क्षति मूल्यांकन का आकलन केवल जांचाधीन उत्पाद उत्पादन के संदर्भ में किया जाए।

xxxiv. नमूना चयन से संबंधित प्रकटीकरण पर आपत्तियाँ दोहराई गईं, यह प्रस्तुत करते हुए कि केवल समेकित गैर-क्षति मूल्य का प्रकटीकरण व्यापार सूचना संख्या 09/2021 को संतुष्ट नहीं करता है और सार्थक परीक्षण को सक्षम करने के लिए नमूना चयनित उत्पादकों के लिए प्रारूप VI-1 से VI-5 के अगोपनीय संस्करणों की आवश्यकता है।

xxxv. क्षति विश्लेषण की समीक्षा केवल गैर-क्षति मूल्य के आधार पर नहीं की जा सकती और इसके लिए अंतर्निहित क्षति प्रारूपों तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जिसमें लागत आवंटन पद्धतियाँ, खपत मानदंड, उपयोगिताएँ, कार्यशील पूंजी अनुमान, क्षमता उपयोग और संयंत्र-वार इष्टतम उत्पादन स्तर, और समायोजन/सामान्यीकरण शामिल हैं।

xxxvi. प्राधिकारी ने नमूना चयनित उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया है, जो पारदर्शिता को कमजोर करता है और प्रतिनिधित्वशीलता के आकलन को रोकता है।

xxxvii. आवेदक द्वारा दायर किसी भी प्रस्तुतीकरण को अभिलेख पर नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि एक उचित अगोपनीय संस्करण साझा नहीं किया गया हो। आवेदक को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए कि किन पिछले प्रस्तुतीकरणों पर भरोसा किया जा रहा है, और प्राधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि प्रत्येक गोपनीय प्रस्तुतीकरण के साथ एक उचित अगोपनीय संस्करण है और जो प्रस्तुतियाँ इस आवश्यकता को पूरा नहीं करतीं उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए।

xxxviii. समर्थकों ने जांच शुरू करने की सूचना में विचार की गई जांच अवधि के अनुरूप विवरण प्रदान नहीं किए और व्यापार सूचनाओं का पालन किया जाना चाहिए और गैर-अनुपालन को अनदेखा किया गया है।

xxxix. भले ही कुछ दस्तावेज व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हों, कम से कम सूचकांक-आधारित अगोपनीय जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। समर्थन पत्रों को बिना कारणों के नहीं रोका

जाना चाहिए और, कम से कम, जानकारी प्रतिशत के रूप में प्रदान की जानी चाहिए ताकि उत्तरदाता निष्पक्ष तरीके से समर्थन का विश्लेषण कर सकें।

xl. अत्यधिक गोपनीयता क्षति मापदंडों सहित सार्थक प्रस्तुतियाँ देने में बाधा डालती है, और सभी अगोपनीय आंकड़े और सार्थक सारांश प्रभावी बचाव की अनुमति देने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

xli. सब्सिडी नियम, 1995 का नियम 18 अपेक्षित करता है कि प्राधिकारी, अपने अंतिम अंतिम जांच परिणाम देने से पहले, सभी हितबद्ध पक्षकारों और इच्छुक देशों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचित करेगा जो उसके निर्णय का आधार बनते हैं और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हित की रक्षा करने की अनुमति देगा। इस संदर्भ में हमारे दावे की पुष्टि के लिए नियम 18 के अंश नीचे दिए गए हैं।

नियम 18. सूचना का प्रकटन

प्राधिकारी, अपने अंतिम अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले, सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देशों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचित करेंगे जो उसके निर्णय का आधार बनते हैं और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हित की रक्षा करने की अनुमति देगा।

xlii. जैसा कि प्रकटीकरण विवरण से देखा जा सकता है कि नियम 18 की आवश्यकताओं और दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने और अपने हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने के उचित अवसर से वंचित किया गया है। इसलिए, हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि एक नया प्रकटन विवरण जारी किया जाए ताकि हम अपनी सार्थक टिप्पणियाँ दायर कर सकें और अपने हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा कर सकें।

ङ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी को गोपनीयता का आकलन विभिन्न कारकों के आधार पर करना चाहिए, जिनमें सूचना की प्रकृति और यह कि क्या ऐसी सूचना को संबंधित क्षेत्र में कानून, रिवाज, उपयोग या व्यवहार द्वारा गोपनीय माना जाता है, शामिल हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 09/2021 का पालन करने में विफलता से इनकार किया, जो खंडित उद्योगों में सभी उत्पादकों से पूरी जानकारी एकत्र करने की चुनौतियों को मान्यता देता है और प्रारंभिक दायर करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। आवेदकों ने बारह आवेदक उत्पादकों के लिए अनुबंध-I के तहत सभी आवश्यक जानकारी दायर की, जो क्षति अवधि के दौरान अपेक्षित उत्पादन और क्षति आंकड़ों द्वारा समर्थित थी।

iii. घरेलू उद्योग ने इस बात से इनकार किया कि केवल प्रोफार्मा IV-क और एक पृष्ठ का गैर-क्षतिपूर्ति मूल्य विवरण प्रदान किया गया था, यह कहते हुए कि उत्पाद नियंत्रण संख्या-वार लागत और मूल्य आंकड़े और लागत पत्रक सहित पूर्ण गोपनीय आंकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत

किए गए थे। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में काम कर रहे नमूना चयनित उत्पादकों के वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी का खुलासा किए बिना, यथासंभव अगोपनीय संस्करण प्रस्तुत किए गए।

iv. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 और व्यापार सूचना 14/2018 का पालन करने में विफलता से इनकार किया, यह कहते हुए कि व्यापार सूचना के अनुसार, उत्पादकों को उचित अगोपनीय सारांश या स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है जहाँ सारांश संभव नहीं है। सभी मामलों में जहाँ आंकड़ों को गोपनीय चिह्नित किया गया था, या तो सूचीबद्ध रूप में सारांश प्रस्तुत किया गया या स्पष्टीकरण दिया गया कि खुलासा कंपनियों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित क्यों करेगा।

v. अगोपनीय संस्करण व्यापार सूचना के अनुसार उचित गोपनीयता संकेतकों के साथ चिह्नित आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए गए। घरेलू बिक्री, लाभ अंतर, ब्याज लागत और मूल्यह्रास में सारांश प्रवृति सूचीबद्ध रूप में प्रदान किए गए, जो गोपनीयता उपचार आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करते हैं।

vi. अत्यधिक गोपनीयता के आरोप निराधार हैं क्योंकि प्राधिकारी ने लगातार उन गोपनीय दाखिलों को स्वीकार किया है जहाँ कंपनियाँ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक हानि का जोखिम दिखा सकती हैं। जांचाधीन उत्पाद का बाजार प्रतिस्पर्धी है और लागत और मूल्य निर्धारण के खुलासे से नमूना चयनित उत्पादकों को भौतिक रूप से हानि होगी। गोपनीयता के दावे व्यापार सूचना और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुसार किए गए हैं।

vii. सार्वजनिक संस्करण में वास्तविक संख्याओं का खुलासा करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है जब इस तरह के खुलासे से वाणिज्यिक हानि होगी। प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में कोई कमी नहीं उठाई है और कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं है।

viii. प्राधिकारी पूर्णता, गोपनीयता और प्रक्रियात्मक अनुपालन का आकलन करने के लिए सक्षम निकाय है। सभी अनिवार्य जानकारी अभिलेख पर रखी गई है और प्राधिकारी के पास अभिलेख पर सभी आंकड़ों को सत्यापित और मूल्यांकन करने और यदि आवश्यक हो तो आगे की जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश देने का विवेकाधिकार बरकरार है।

ix. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसने कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ के सदस्यों की सूची, समर्थकों या विरोधियों के रूप में उनकी स्थिति सहित, और कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन का हिस्सा दर्शाने वाला एक विवरण अभिलेख पर रखा है।

x. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि सहायक उत्पादकों के समर्थन की अवहेलना करने का अनुरोध अस्थिर है और अभिलेख में लागू ढांचे के तहत आवश्यक अगोपनीय रूप में समर्थक-वार जानकारी शामिल है।

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना को गलत तरीके से पढ़ा है, यह दावा करके कि यह कई घरेलू उत्पादकों से जुड़े सभी मामलों में समग्र वास्तविक आंकड़ों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।

xii. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि गोपनीयता दिशानिर्देश निरपेक्ष नहीं हैं और प्राधिकारी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 8 के अनुरूप, अच्छे कारण के प्रदर्शन पर मामला-दर-मामला आधार पर विचलन की अनुमति दे सकता है।

xiii. समग्र बिक्री मूल्य और लाभप्रदता के आंकड़ों पर गोपनीयता का दावा करने के लिए वर्तमान मामले में अच्छा कारण मौजूद है। अगोपनीय संस्करण में समग्र बिक्री मात्रा का खुलासा किया गया है, और समग्र बिक्री मूल्य और लाभप्रदता का खुलासा, जब मात्राओं के साथ पढ़ा जाता है, तो घरेलू उत्पादकों की अनुमानित बिक्री कीमतों और लाभ स्तरों का खुलासा करेगा।

xiv. जांचाधीन उत्पाद के लिए घरेलू बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और खंडित है, जिसमें कई भारतीय उत्पादक आपस में और निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समेकित बिक्री मूल्य और लाभप्रदता के आंकड़ों का खुलासा प्रतिस्पर्धियों और निर्यातकों को मूल्य निर्धारण मानक प्रदान करेगा, जिससे कीमत कटौतीसंभव होगा और गंभीर वाणिज्यिक हानि होगी।

xv. यह आरोप कि कई उत्पादकों के लिए समग्र प्रकटीकरण से वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाजार की वास्तविकताओं की अनदेखी करता है, क्योंकि समग्र आंकड़े अभी भी तुलनीय लागत संरचनाओं और उत्पाद विशेषताओं वाले उद्योगों में संवेदनशील मूल्य निर्धारण और अंतर की जानकारी प्रकट कर सकते हैं।

xvi. ब्याज और मूल्यह्रास आंकड़ों के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि ब्याज व्यय और मूल्यह्रास और परिशोधन से संबंधित समग्र जानकारी याचिका के अगोपनीय संस्करण में प्रदान की गई है।

xvii. गोपनीयता का दावा केवल साधारण दावों के माध्यम से नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के औचित्य को स्पष्ट रूप से समझाया है, जिसमें मूल्य न्यूनीकरण, सौदेबाजी की शक्ति का नुकसान और प्रतिस्पर्धा के विरूपण के जोखिम शामिल हैं।

xviii. प्राधिकारी की पिछली प्रथा पर भरोसा किया गया, जिसमें तुर्की, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान से सोडा ऐश के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शामिल है, जहाँ प्राधिकारी ने संभावित वाणिज्यिक हानि को देखते हुए बिक्री मूल्य और लाभप्रदता के लिए समग्र वास्तविक आंकड़ों के बजाय प्रवृतियों के प्रकटीकरण को स्वीकार किया था।

xix. प्राधिकारी ने सोडा ऐश के अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि वास्तविक बिक्री मूल्य, लागत और लाभप्रदता की जानकारी के प्रकटीकरण से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं और अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है, और इसलिए ऐसे मापदंडों पर गोपनीयता की अनुमति दी।

xx. वर्तमान जांच में तथ्यात्मक स्थिति सोडा ऐश मामले के भौतिक रूप से समान है, क्योंकि यहाँ घरेलू उद्योग में भी कई उत्पादक शामिल हैं जो आपस में और निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और समग्र वास्तविक आंकड़ों का खुलासा इसी तरह संवेदनशील मूल्य निर्धारण और अंतर की जानकारी प्रकट करेगा।

xxi. प्रवृति-आधारित प्रकटीकरण की स्वीकृति पारदर्शिता को कम नहीं करती। अगोपनीय प्रवृति क्षति मापदंडों को समझने, क्षति अवधि में पद्धति की जांच करने और गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की रक्षा करते हुए सार्थक प्रस्तुतियाँ देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं।

xxii. प्राधिकारी ने कई उत्पादकों से जुड़ी जांचों में लगातार बिक्री मूल्य और लाभप्रदता से संबंधित जानकारी की गोपनीयता की अनुमति दी है, जिनमें मुद्रित परिपथ पटल, पीवीसी निलंबन रेजिन, सौर सेल, टायर, पॉलिएस्टर धागा और कास्टिक सोडा से संबंधित जांचें शामिल हैं।

xxiii. हितबद्ध पक्षकार अपने बचाव के अधिकार में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं और अभिलेख पर रखी गई अगोपनीय जानकारी के आधार पर मात्रा प्रभाव, मूल्य प्रभाव, लाभप्रदता प्रवृति और कारण-निर्धारण पर प्रस्तुतियाँ देने में सक्षम हैं।

xxiv. सहायक उत्पादकों द्वारा अपर्याप्त प्रकटीकरण के आरोपों के संबंध में, वर्तमान जांच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रभुत्व वाले खंडित उद्योग से संबंधित है, और व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के तहत विशेष प्रक्रियात्मक ढांचा लागू होता है।

xxv. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुसार आवेदक घरेलू उत्पादकों को अनुबंध-I में बुनियादी क्षति जानकारी दायर करने की आवश्यकता है और सहायक उत्पादकों को विस्तृत क्षति, लागत, बिक्री या वित्तीय जानकारी दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

xxvi. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 का उद्देश्य खंडित उद्योगों के लिए जांच शुरू करना सरल बनाना और उन प्रक्रियात्मक बाधाओं से बचना है जो अन्यथा ऐसे उद्योगों को व्यापार उपचार संरक्षण प्राप्त करने से रोकतीं।

xxvii. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुपालन में, कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच निर्माता संघ और मास्टरबैच निर्माता संघ के सदस्यों की एक पूर्ण सूची, जो समर्थकों, विरोधियों और तटस्थ उत्पादकों को इंगित करती है, घरेलू उद्योग की उत्पादन संरचना को समझने के लिए पर्याप्त समग्र उत्पादन आंकड़ों के साथ पहले ही दायर और परिचालित की जा चुकी है।

xxviii. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह दोहराया गया कि केवल बारह आवेदक घरेलू उत्पादक ही जांच अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा रखते हैं, जो समर्थक आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से, नियम 6(3) के तहत 25% की सीमा को स्वतंत्र रूप से संतुष्ट करता है।

xxix. किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है, और इसलिए नियम 6(3) के तहत स्थिति परीक्षण का दूसरा पहलू, जिसके अनुसार समर्थकों को समर्थन या विरोध व्यक्त करने वालों में से 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है, स्वतः संतुष्ट हो जाता है।

xxx. व्यापार सूचना संख्या 14/2018 के उल्लंघन के आरोपों का मूल्यांकन व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के साथ सामंजस्य में किया जाना चाहिए, जो समय में बाद में जारी किया गया था और विशेष रूप से खंडित उद्योगों के लिए दायर करने की आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

xxxi. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत क्षति निर्धारण आवेदक घरेलू उत्पादकों के आंकड़ों पर आधारित होता है, जिसमें जहाँ लागू हो, नमूना चयनित उत्पादक शामिल हैं, और सहायक उत्पादकों को विस्तृत क्षति जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

xxxii. समेकित प्रोफार्मा IV-क प्रमुख क्षति मापदंडों को शामिल करता है और हितबद्ध पक्षकारों के पास क्षति और कारण-निर्धारण पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त अगोपनीय क्षति जानकारी तक पहुंच है।

xxxiii. प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है और हितबद्ध पक्षकारों को अभिलेख पर रखी गई जानकारी के आधार पर क्षति की जांच और टिप्पणी करने का पूरा अवसर दिया गया है।

xxxiv. विस्तारित जांच अवधि के लिए पूर्ण अद्यतन आवेदन पुनः दायर करने में विफलता के आरोपों के संबंध में, प्राधिकारी के पास जांच शुरू करते समय जांच अवधि निर्धारित करने का विवेकाधिकार है और जांच शुरू करना प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर आधारित है। एक बार जांच अवधि बढ़ा दिए जाने के बाद, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा निर्देशित तरीके से अतिरिक्त अवधि के लिए अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की, और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत संपूर्ण याचिका को फिर से दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxxv. हितबद्ध पक्षकारों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि विस्तारित जांच अवधि सहित क्षति अवधि में प्रवृतियों को दर्शाने वाली अगोपनीय जानकारी अभिलेख पर रखी गई है।

xxxvi. विस्तारित जांच अवधि के लिए प्रमाणपत्रों या घोषणाओं की अनुपस्थिति के आरोपों के संबंध में, आवेदन में दायर करने के समय आवश्यक प्रमाणपत्र शामिल थे और जांच अवधि का विस्तार पहले से अभिलेख पर मौजूद प्रमाणपत्रों को अमान्य नहीं करता।

xxxvii. कोई भी कथित प्रक्रियात्मक कमी सुधारी जा सकती है और जांच शुरू करने को शून्य या अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं बनाती।

xxxviii. व्यक्तिगत आवेदक उत्पादकों के लिए कंपनी-वार जानकारी व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुसार दायर करने के समय प्रदान की गई थी और विस्तारित जांच अवधि के लिए अद्यतन कंपनी-वार जानकारी भी प्राधिकारी के पास दायर की गई है। अद्यतन जांच अवधि के लिए व्यक्तिगत कंपनी-वार जानकारी के अगोपनीय संस्करण भी दायर किए गए हैं और अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए हैं।

xxxix. जांच की शुरुआत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के तहत साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच पर आधारित थी।

xl. जिन आयात प्रवृतियों पर भरोसा किया गया है, वे क्षति अवधि में वियतनाम से आयात में लगातार वृद्धि दिखाते हैं, जो जांच अवधि के दौरान एक उछाल में परिणत हुई, और इन प्रवृतियों की पुष्टि प्राधिकारी द्वारा जांचे गए सत्यापित आयात आंकड़ों से हुई है।

xli. जांच शुरू करने के चरण में द्वितीयक आयात आंकड़ों पर भरोसा करना प्राधिकारी की एक स्थापित प्रथा है जहाँ आधिकारिक आंकड़े समकालीन रूप से उपलब्ध नहीं होते, और ऐसे आंकड़ों को बाद में जांच के दौरान सत्यापित किया जाता है।

xlii. जांचाधीन उत्पाद के आंकड़ों को रंग मास्टरबैच आंकड़ों के साथ मिलाने के आरोपों के संबंध में, प्रस्तुत सभी जानकारी विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच से संबंधित है और समेकित प्रोफार्मा IV-क केवल जांचाधीन उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों को दर्शाता है।

xliii. यह तथ्य कि कुछ आवेदक उत्पादक रंग मास्टरबैच का भी निर्माण कर सकते हैं, क्षति विश्लेषण को अमान्य नहीं करता, जब तक विश्लेषण जांचाधीन उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है, जो कि यहाँ मामला है।

xliv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता और विविध प्रक्रियात्मक मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ खारिज कर दी जाएँ।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

i. प्राधिकारी इस आपत्ति पर ध्यान देते हैं कि जांच 15 महीने की जांच अवधि के साथ शुरू की गई थी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 की व्याख्या (ii) में 12 महीने की जांच अवधि को मानक के रूप में निर्धारित किया गया है, जो केवल "लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों" से न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने की अनुमति देता है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 की व्याख्या (ii) इस प्रकार प्रावधान करती है:

(ii) बारह महीने की अवधि के लिए होगी और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकते हैं।

ii. प्राधिकारी का मानना है कि जांच शुरू करने के चरण में, प्राधिकारी को चयनित जांच अवधि के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, और ऐसे कारण चुने गए विकल्प के आधार को समझाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि जांच 18 महीने की जांच अवधि के साथ शुरू की गई थी, गलत है और इसे अस्वीकृत किया जाता है। 27.12.2024 की जांच शुरू करने की सूचना में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जांच 15 महीने की जांच अवधि के साथ शुरू की गई थी।

iii. प्राधिकारी वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की संरचना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-संचालित खंडित उद्योग के लिए आंकड़े संकलित करने की व्यावहारिक संभाव्यता से संबंधित कारणों पर ध्यान देते हैं। प्राधिकारी इन विचारों को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 की व्याख्या (ii) के तहत प्रदान की गई सीमा के भीतर एक उपयुक्त जांच अवधि का चयन करने के लिए प्रासंगिक मानते हैं।

iv. प्राधिकारी का मानना है कि अनुमेय वैधानिक सीमा के भीतर एक उपयुक्त जांच अवधि के चयन के लिए तुलनीयता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है, और जांच शुरू करने की सूचना में दर्ज किए गए कारण प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 6 की व्याख्या (ii) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं।

v. तदनुसार, प्राधिकरण ने इस प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया है कि जांच अवधि 12 महीने से अधिक होने के आधार पर जांच क्षेत्राधिकार रहित है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि का चुनाव अनुमेय वैधानिक सीमा के भीतर है।

vi. प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 7(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय संस्करण सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:

(1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

vii. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि समर्थकों ने उत्पादन, क्षमता, बिक्री, लाभप्रदता या क्षति पर सार्थक अगोपनीय आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, अगोपनीय संस्करणों को भारी रूप से काट दिया गया है, और इसलिए समर्थकों के समर्थन को स्थिति के प्रयोजनों के लिए अवहेलना कर देना चाहिए।

viii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बारह (12) आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के तहत अनुबंध-I में आवश्यक जानकारी दायर की, जो घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और इक्कीस (21) उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया।

ix. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, किसी भी स्थिति में, केवल बारह आवेदक उत्पादक ही कुल घरेलू उत्पादन का 25% से अधिक का गठन करते हैं। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि नियम 6(3) के तहत 25% की सीमा की संतुष्टि समर्थकों पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदन पर विरोध व्यक्त नहीं किया है। नियम 6(3) की व्याख्या के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि समर्थन या विरोध व्यक्त करने वालों में समर्थन की मात्रा से संबंधित स्थिति की आवश्यकता वर्तमान मामले के तथ्यों पर संतुष्ट होती है।

x. प्राधिकारी इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि व्यापार सूचना संख्या 14/2018 में विस्तृत अगोपनीय सारांशों की आवश्यकता है और समर्थकों के आंकड़े अनुपालन योग्य नहीं हैं। प्राधिकारी का मानना है कि गोपनीयता दायित्व सभी अनुरोधों पर लागू होते हैं, और अगोपनीय सारांशों की पर्याप्तता का आकलन दायर की जाने वाली सूचना के संदर्भ में और उस सूचना की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसके लिए गोपनीयता मांगी गई है।

xi. प्राधिकारी इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में कई घरेलू उत्पादकों से जुड़े मामलों में वास्तविक आंकड़ों में समग्र आंकड़ों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है, और घरेलू उद्योग ने बिक्री मूल्य, लाभप्रदता, ब्याज/वित्त लागत, और मूल्यह्रास/परिशोधन जैसे मापदंडों के लिए केवल प्रवृति प्रकट किए।

xii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस औचित्य की जांच की है कि समग्र बिक्री मात्रा का खुलासा किया गया है और समग्र बिक्री मूल्य और लाभप्रदता का खुलासा, जब मात्राओं के साथ पढ़ा जाता है, प्रतिस्पर्धी और खंडित बाजार में घरेलू उत्पादकों की अनुमानित बिक्री कीमत और लाभ स्तरों को प्रकट कर सकता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस प्राधिकारी अनुरोध पर नोट करते हैं कि ऐसा प्रकटीकरण प्रतिस्पर्धियों और निर्यातकों को मूल्य निर्धारण मानक प्रदान कर सकता है और वाणिज्यिक हानि का कारण बन सकता है।

xiii. प्राधिकारी मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत गोपनीयता व्यवस्था पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया को गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। प्राधिकारी का मानना है कि प्रवृति-आधारित प्रकटीकरण अनुमेय हो सकता है जहाँ यह संवेदनशील आंकड़ों की रक्षा करते हुए सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देता है, बशर्ते सारांश सार्थक हों और हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हों।

xiv. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे तरीके से अगोपनीय जानकारी प्रदान की है जो हितबद्ध पक्षकारों को क्षति अवधि के प्रवृतियों को समझने और क्षति, मूल्य प्रभाव, लाभप्रदता प्रवृति और कारण-निर्धारण पर प्रस्तुतियाँ देने में सक्षम बनाती है, जबकि उस जानकारी की रक्षा करती है जो स्वभाव से गोपनीय है।

xv. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों दोनों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता दावों की विस्तृत जांच की है। समीक्षा करने पर, प्राधिकारी पाते हैं कि ये दावे, सामान्यतः, उपयुक्त रूप से प्रमाणित थे और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थे।

xvi. तदनुसार, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों को, जहाँ भी उचित था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xvii. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि आवेदन मूलतः अप्रैल 2023-मार्च 2024 के लिए दायर किया गया था, जबकि प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2023-30 जून 2024 की विस्तारित जांच अवधि के साथ जांच शुरू की, और आवेदक कथित तौर पर अधिसूचित जांच अवधि के लिए पूर्ण अद्यतन आवेदन और संशोधित क्षति विश्लेषण पुनः दायर करने में विफल रहा।

xviii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू करते समय जांच अवधि निर्धारित कर सकते हैं और बाद में जांच के दौरान अद्यतन सूचना या अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं। घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसने निर्देशित तरीके से सभी आवश्यक अद्यतन जांच अवधि के आंकड़े प्रस्तुत किए, और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों में ऐसे अद्यतनों के लिए याचिका को पूर्णतः पुनः दायर करने की आवश्यकता नहीं है। इसने निर्धारित प्रारूपों में

कंपनी-वार जानकारी भी प्रस्तुत की, जिसमें अद्यतन जांच अवधि के लिए, परिचालित अगोपनीय संस्करण के साथ शामिल है। विस्तारित जांच अवधि के लिए नए प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए जाने के आरोप के संबंध में, घरेलू उद्योग का कहना है कि आवेदन के साथ दायर मूल प्रमाणपत्र वैध बने रहते हैं और केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाते क्योंकि जांच अवधि बढ़ा दी गई थी।

xix. प्राधिकारी का मानना है कि प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या जांच के लिए आवश्यक सूचना अपनाई गई जांच अवधि के लिए अभिलेख पर उपलब्ध है, और क्या प्राधिकारी के पास जांच के दौरान सूचना की जांच और सत्यापन करने की क्षमता रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच प्रक्रिया में अद्यतन सूचना मांगने और प्रदान करने के अवसर शामिल हैं, और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुधार योग्य प्रक्रियात्मक पहलुओं को अधिकार-क्षेत्र संबंधी दोष न मानते हुए, एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

xx. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों की विस्तारित जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए अगोपनीय जानकारी तक पहुंच रही है और उन्हें प्रस्तुतियाँ दायर करने का अवसर दिया गया है। इसलिए प्राधिकारी इस प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं करते कि कार्यवाही उस रूप के कारण शुरुआत में ही दूषित हो गई है जिसमें अद्यतन जांच अवधि की जानकारी प्रदान की गई थी या प्रमाणपत्रों के संबंध में आरोपों के कारण, विशेष रूप से जहाँ जानकारी अभिलेख पर रखी गई है और उसकी जांच की गई है।

xxi. प्राधिकारी इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि आवेदक ने आयात आंकड़ों के लिए द्वितीयक/निजी स्रोतों पर भरोसा किया और प्राधिकारी को जांच शुरू करते समय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़े मंगाने चाहिए थे, और आयात आंकड़ों के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया।

xxii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के लिए जिन आयात प्रवृतियों पर भरोसा किया गया था, उनकी तर्कसंगतता और निरंतरता के लिए जांच की गई थी और प्राधिकारी के पास सत्यापन के लिए जांच के दौरान आधिकारिक आयात आंकड़ों तक पहुंच है।

xxiii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के प्रयोजन के लिए, उन्होंने महानिदेशालय प्रणाली के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xxiv. प्राधिकारी इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि नमूना चयनित कंपनियाँ कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच (जांचाधीन उत्पाद) और रंग मास्टरबैच दोनों का निर्माण कर सकती हैं, और रंग मास्टरबैच की लाभप्रदता क्षति विश्लेषण को विकृत कर सकती है जब तक कि जांचाधीन उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों का उपयोग न किया जाए।

xxv. जांच केवल कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच से संबंधित है और आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी, जिसमें कंपनी-वार और समेकित प्रोफार्मा IV-क के आंकड़े शामिल हैं, विशेष रूप से जांचाधीन उत्पाद से संबंधित है, और इसमें रंग मास्टरबैच या अन्य गैर-संबद्ध उत्पादों से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत या लाभप्रदता शामिल नहीं है।

xxvi. प्रासंगिक मुद्दा यह है कि क्या क्षति विश्लेषण जांचाधीन उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है। अभिलेख के आधार पर, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने निर्धारित प्रारूपों में जांचाधीन उत्पाद से संबंधित उत्पाद-विशिष्ट जानकारी दायर की है। इसलिए

प्राधिकरण ने इस प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया है कि क्षति विश्लेषण केवल इसलिए दूषित है क्योंकि कुछ उत्पादक अन्य उत्पादों का भी निर्माण कर सकते हैं, जहाँ भरोसा किए गए आंकड़े उत्पाद-विशिष्ट हैं और प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हैं।

xxvii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दोहराया कि नमूना चयनित उत्पादकों के लिए क्षति प्रारूप VI-1 से VI-5 के अगोपनीय संस्करण परिचालित किए जाने चाहिए और केवल समेकित अगोपनीय गैर-क्षतिपूर्ति मूल्य का प्रकटीकरण अपर्याप्त है, और नमूना चयनित उत्पादकों की उत्पादन हिस्सेदारी का गैर-प्रकटीकरण प्रतिनिधित्वशीलता को प्रभावित करता है।

xxviii. प्राधिकारी दोहराते हैं कि क्षति विश्लेषण और गैर-क्षतिपूर्ति मूल्य नमूना चयनित उत्पादकों द्वारा अभिलेख पर रखी गई और प्राधिकारी द्वारा जांची गई पूर्ण जानकारी पर आधारित है, और गोपनीयता दावों का आकलन पारदर्शिता और गोपनीय सूचना की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू ढांचे के तहत किया जाता है।

xxix. उपरोक्त जांच के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि उपरोक्त मुद्दों की जांच लागू कानूनी ढांचे के अनुसार की गई है और ये वर्तमान जांच की शुरुआत या जारी रहने को दूषित नहीं करते।

च. <u>सबसिडी और सबसिडी मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. सबसिडी और सबसिडी मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि याचिका में लगाए गए सब्सिडीकरण के आरोप निराधार हैं और साक्ष्य से असमर्थित हैं।

ii. उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया कि याचिका में सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 तथा भारतीय प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के संगत प्रावधानों के तहत अपेक्षित सब्सिडीकरण के "पर्याप्त साक्ष्य" का अभाव है। याचिका प्रत्येक कथित कार्यक्रम के लिए सब्सिडी के संघटक तत्वों को स्थापित किए बिना, सरकारी नीतियों के दावों और सामान्य विवरणों पर निर्भर करती है।

iii. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत सब्सिडी के अस्तित्व के लिए वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता का प्रमाण आवश्यक है, और घरेलू कानून के तहत किसी कार्यक्रम की मात्र उपलब्धता या अस्तित्व कानूनी रूप से अपर्याप्त है।

iv. विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र पर भरोसा किया गया है, जिसमें चीन – जीओईएस में पैनल रिपोर्ट शामिल है, यह तर्क देने के लिए कि जांच प्राधिकारी को जांच शुरू करने से पहले साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करनी चाहिए और ऐसे आवेदनों को छांटना चाहिए जो पर्याप्तता मानक को पूरा नहीं करते। तर्क दिया गया है कि "प्रथम दृष्टया" साक्ष्य "पर्याप्त साक्ष्य" के समकक्ष नहीं है और बाद वाले के लिए कानूनी रूप से संतोषजनक प्रमाणीकरण आवश्यक है।

v. हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने प्रस्तुत किया कि याचिका में कथित तेरह सब्सिडी कार्यक्रमों में से, उन्होंने एक मामूली निवेश-संबद्ध कॉर्पोरेट आयकर छूट को छोड़कर कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं किया है, जो वियतनामी कानून के तहत एक सामान्य उपाय और गैर-विशिष्ट प्रकृति का होने का दावा किया गया है।

vi. उक्त कॉर्पोरेट आयकर छूट पंद्रह महीने की जांच अवधि के दौरान केवल छह महीने की सीमित अवधि के लिए उपलब्ध थी और इससे नगण्य लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे सीमित और सामान्य कर उपाय को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं माना जा सकता।

vii. कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि वे या तो संबंधित योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उन्होंने ऐसी योजनाओं में भाग नहीं लिया है, या बाजार-निर्धारित दरों पर संचालित विशुद्ध वाणिज्यिक लेन-देन में संलग्न रहे हैं। गैर-पात्रता, गैर-प्राप्ति, या किसी अधिमान्य उपचार की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

viii. याचिका और जांच शुरू करने की सूचना में केवल तेरह कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया गया है, बिना साक्ष्य के यह प्रदर्शित किए कि किसी निर्यातक ने वास्तव में एक परिमाणात्मक लाभ प्रदान करने वाला वित्तीय अंशदान प्राप्त किया।

ix. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करते हैं कि याचिका स्थापित करने में विफल रही: (i) वियतनाम सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान; (ii) प्रदान किया गया लाभ; और (iii) कथित कार्यक्रमों की विशिष्टता। इन तत्वों को स्थापित करने में विफलता जांच की शुरुआत को दूषित करती है और बाद के चरण में इसे ठीक नहीं किया जा सकता।

x. वीटाप्लस ने प्रस्तुत किया है कि विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय की विधिशास्त्र ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि घरेलू कीमतें प्राथमिक और वरीय मानक हैं, और देश से बाहर के मानकों का सहारा प्रकृति में पूर्णतः अवशिष्ट है। यूएस – सॉफ्टवुड लम्बर IV में, अपीलीय निकाय रिपोर्ट, डब्ल्यूटी/डीएस257/एबी/आर (17 फरवरी 2004 को अंगीकृत), पैरा 90-103, अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि प्रावधान वाले देश में निजी कीमतें प्राथमिक मानक हैं, और देश से बाहर के मानकों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब घरेलू कीमतें विकृत हों। अपीलीय निकाय ने घरेलू कीमतों की किसी भी स्वचालित या अनुमानित अस्वीकृति को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। यह स्थिति यूएस–प्रतिसंतुलनकारी उपाय (चीन)-डब्ल्यूटी/डीएस437/एबी/आर, यूएस–कार्बन स्टील(भारत)- डब्ल्यूटी/डीएस436/एबी/आर में सुदृढ़ की गई।

xi. प्राधिकारी ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उन्होंने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते के अनुच्छेद 11.3 और भारतीय प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों की धारा 6 के तहत अपेक्षित, जांच शुरू करने से पहले साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता का आकलन किया। उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उस आधार को स्पष्ट करें जिस पर याचिका में पर्याप्त साक्ष्य माना गया।

xii. उत्पादकों/निर्यातकों ने आगे विश्व व्यापार संगठन के पैनल जांच परिणामों पर भरोसा किया, जिसमें मेक्सिको – पाइप्स एंड ट्यूब्स और जापान – ड्रैम्स शामिल हैं, यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क केवल वहीं लगाया जा सकता है जहाँ चल रहे सब्सिडीकरण

का साक्ष्य हो और सामान्य दावे, नीति विवरण, या अप्रमाणित दावे साक्ष्य की सीमा को पूरा नहीं करते।

xiii. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित सब्सिडियों के अस्तित्व, लाभ, या विशिष्टता के संबंध में कोई भी निर्धारण निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और वियतनाम सरकार द्वारा दायर प्रतिक्रिया की संयुक्त जांच पर आधारित होना चाहिए। ऐसी सहसंबद्ध जांच के बिना कोई प्रतिकूल अंतिम जांच परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

xiv. उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर न करने के आधार पर उसकी प्रतिक्रिया की अस्वीकृति अनुचित है, क्योंकि उसने पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर कर दी थी और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी या तो मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी या कंपनी पर लागू नहीं थी।

xv. कैल्शियम कार्बोनेट विवरण के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि कैल्शियम कार्बोनेट ही जांचाधीन वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र कच्चा माल था, और इसके उपभोग और खरीद का विवरण मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया की धारा I(सी) में पहले ही प्रदान किया जा चुका था। निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन, अनुदान या वापसी के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि जांच अवधि के दौरान जांचाधीन वस्तुओं के निर्यात के लिए ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, और इसकी पुष्टि मूल प्रतिक्रिया की धारा I(ए)(7) में पहले ही की जा चुकी थी।

xvi. उत्तरदाता ने आगे प्रस्तुत किया कि उसे कच्चे माल की खरीद पर कोई छूट प्राप्त नहीं हुई थी। कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी आयातित कच्चे माल वियतनामी कानून के तहत सामान्य आयात-निर्यात शुल्क अनुसूची के अधीन थे, और जांचाधीन वस्तुओं के निर्माण में संलग्न उद्यमों को विशेष रूप से कोई विशिष्ट आयात शुल्क छूट या अधिमान्य उपचार प्रदान नहीं किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात शुल्क रियायतें प्रतिसंतुलनकारी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी रियायतें सामान्यतः निर्धारित उत्पत्ति और मुक्त व्यापार समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध हैं और उद्योग-विशिष्ट या जांचाधीन वस्तुओं के लिए अनन्य नहीं हैं।

xvii. पूंजीगत वस्तुओं और स्पेयरों के संबंध में, उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि उसने किसी भी पूंजीगत वस्तु या भंडार/स्पेयरों का आयात नहीं किया था और इसलिए, ऐसी किसी योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया। भूमि-संबंधित लाभों के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उसने भूमि नहीं खरीदी थी और बाजार दरों से कम पर भूमि प्रदान करने या भूमि-संबंधित छूट प्रदान करने वाले किसी सरकारी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। परिसर एक निजी पक्ष से किराए पर लिए जाने का उल्लेख किया गया था।

xviii. उत्तरदाता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह जांचाधीन वस्तुओं के निर्माण में जल या गैस का उपयोग नहीं करता है। बिजली के संबंध में, उसने प्रस्तुत किया कि बिजली सामान्यतः सभी कंपनियों पर लागू बाजार-आधारित कीमतों पर खरीदी जाती है और कोई बिजली सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है।

xix. कॉर्पोरेट कर के संबंध में, उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने जांच अवधि के दौरान 20% की दर से नियमित कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान किया। उसने आगे प्रस्तुत किया कि यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – हंग येन शाखा ने 2023,

2024 और 2025 में 50% कॉर्पोरेट आयकर कटौती प्राप्त की, और उत्पादक और संबंधित व्यापारी के संगत आयकर रिटर्न की प्रतियाँ मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया के साथ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थीं।

xx. ऋणों के संबंध में, उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि सभी ऋण वाणिज्यिक बैंकों से बाजार-आधारित शर्तों पर और सामान्य बैंकिंग दरों पर प्राप्त किए गए थे। उसने आगे प्रस्तुत किया कि वियतनाम स्टेट बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया था और इसलिए, कथित योजना कंपनी पर लागू नहीं थी। उत्तरदाता ने यह भी कहा कि ऋणों का विवरण मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया के पृष्ठ 28 से 30 पर पहले ही प्रदान किया जा चुका था।

xxi. उत्तरदाता ने अंत में प्रस्तुत किया कि निर्यात प्रोत्साहन, कच्चे माल की खरीद की छूट, पूंजीगत वस्तुओं की रियायतें, और जल/गैस लाभों सहित कई कथित योजनाओं पर 20 मार्च 2026 के प्रकटीकरण विवरण में प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई नहीं की गई।

xxii. उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि संपूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया की अस्वीकृति प्राधिकारी की सतत प्रथा के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया गया कि कई जांचों में, जहाँ सूचना का एक भाग अपर्याप्त पाया गया या स्वीकार नहीं किया गया, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना को केवल अपर्याप्त भाग पर लागू किया और फिर भी व्यक्तिगत शुल्क अंतर प्रदान किए।

xxiii. समर्थन में, उत्तरदाता ने चीन, वियतनाम और कोरिया से एल्यूमीनियम और जिंक लेपित फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया, जिसमें प्राधिकारी ने अभ्यासरत लेखाकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के बावजूद मैसर्स नाम किम स्टील की पूर्ण प्रतिक्रिया को अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय, प्राधिकारी ने केवल दावा किए गए सामान्य मूल्य को अस्वीकार किया और इसे उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया।

xxiv. तदनुसार, उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए भी कि कोई अनुपलब्ध या अपर्याप्त सूचना है, यूएस मास्टरबैच समूह की पूर्ण प्रतिक्रिया को समग्र रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी, सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते, प्राधिकारी की पिछली प्रथा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, अधिक से अधिक केवल विशिष्ट अनुपलब्ध सूचना पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना लागू कर सकते हैं।

xxv. उत्तरदाता ने आगे प्रस्तुत किया कि यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – हंग येन शाखा दोनों जांचाधीन वस्तुओं के निर्माता हैं और इसलिए, अनुरोध किया कि दोनों कंपनियों को व्यक्तिगत शुल्क अंतर प्रदान किए जाएं।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. सबसिडी और सबसिडी मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान जांच में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों का निर्धारण विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते तथा सीमा शुल्क

अधिनियम, 1975 की धारा 9 के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों में निहित घरेलू कानूनी ढांचे द्वारा शासित होता है।

ii. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, सब्सिडी का अस्तित्व तब माना जाता है जब निर्यातक देश की सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान किया जाता है और इसके द्वारा प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। किसी सब्सिडी पर प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई के लिए विशिष्टता की आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए।

iii. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि वित्तीय अंशदान, अन्य बातों के साथ-साथ, निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण, सरकारी राजस्व का त्याग या गैर-संग्रहण, सामान्य अवसंरचना के अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान, वस्तुओं की खरीद, या निर्यात बढ़ाने या आयात घटाने के लिए संचालित आय या मूल्य समर्थन का रूप ले सकता है, बशर्ते लाभ प्रदान किया गया हो।

iv. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का नियम 12 प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की राशि की गणना के लिए पद्धति प्रदान करता है। नियम यह अनिवार्य करता है कि प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों की गणना जांच अवधि के दौरान विद्यमान पाए जाने वाले प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ के संदर्भ में की जाएगी।

v. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर, घरेलू उद्योग ने वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग करते हुए याचिका में विस्तृत और कार्यक्रम-विशिष्ट प्रस्तुतियाँ दीं। इन अनुरोधों में कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रकृति, वियतनामी कानून के तहत कानूनी आधार, वियतनाम सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान किए जाने का तरीका, और जांचाधीन वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान किया गया लाभ चिह्नित किया गया।

vi. याचिका और मानक अनुरोध सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों, सरकारी अधिसूचनाओं, नीतिगत दस्तावेजों और द्वितीयक साक्ष्य से समर्थित थीं, और जांच शुरू करने तथा जांच के प्रयोजनों के लिए वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थीं।

vii. जांच शुरू करने के चरण से आगे बढ़ चुकी है और सब्सिडीकरण का निर्धारण अब प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुसार, निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं, वियतनाम सरकार द्वारा दायर प्रतिक्रिया, और अभिलेख पर मौजूद सूचना के सत्यापन की विस्तृत जांच पर आधारित होना चाहिए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सब्सिडियों और सब्सिडी अंतर के निर्धारण के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के तहत, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के साथ पठित, सब्सिडी का अस्तित्व तब माना जाता है जब सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान किया जाता है, जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, किसी सब्सिडी पर प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई के लिए, उसे विशिष्टता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडीकरण और सब्सिडी अंतर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उन्होंने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

(i) घरेलू उद्योग द्वारा याचिका और बाद की अनुरोधों में दायर सूचना और साक्ष्य, जिसमें मानक अनुरोध शामिल हैं;

(ii) भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं/अतिरिक्त प्रश्नावली प्रतिक्रिया और सहायक दस्तावेज; और

(iii) वियतनाम सरकार द्वारा वियतनाम व्यापार उपचार प्राधिकारी के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिक्रिया और सूचना, साथ ही जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन और परीक्षण।

48. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के अभिलेख में सभी सहयोगी पक्षकारों से सब्सिडीकरण के संघटक तत्वों की जांच के लिए प्रासंगिक सूचना शामिल है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम-वार गैर-पात्रता, गैर-प्राप्ति, बाजार-आधारित लेन-देन, और कुछ योजनाओं की कथित गैर-प्रतिसंतुलनकारी प्रकृति के संबंध में निर्यातकों के तर्क ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके लिए कार्यक्रम-विशिष्ट जांच की आवश्यकता है। प्राधिकारी का मानना है कि इन मुद्दों का अंतिम जांच परिणाम सामान्य दावों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता और इनका आकलन अभिलेख पर मौजूद सत्यापित सूचना के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

50. तदनुसार, प्राधिकारी ने कथित सब्सिडी कार्यक्रमों, घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सूचना, और वियतनाम व्यापार उपचार प्राधिकारी द्वारा दायर प्रतिक्रिया की जांच की है, इसका निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियाँ सब्सिडी अंतर के परिमाणीकरण के लिए विद्यमान हैं। प्राधिकारी की कार्यक्रम-वार जांच, जिसमें मानकों और लाभ गणनाओं की जांच शामिल है, संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के अंतर्गत आगामी पैराग्राफों में रखी गई है।

51. प्राधिकारी ने इसलिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, उपलब्ध सूचना के आधार पर सब्सिडीकरण और सब्सिडी अंतर का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया की है।

52. प्राधिकारी पाते हैं कि जहाँ भी वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सहयोग का स्तर संतोषजनक रहा है, प्राधिकारी ने व्यक्तिगत सब्सिडी अंतरों के निर्धारण के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया है।

53. यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – हंग येन शाखा (निर्यातकों) ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि निर्यातकों ने अपनी मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कच्चा माल, भूमि, बिजली, कॉर्पोरेट आयकर और ऋण से संबंधित सूचना दायर की है। निर्यातकों ने अपनी मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में यह भी दावा किया है कि उन्होंने कोई निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया, आयातित कच्चे माल/पूंजीगत वस्तुओं पर कोई विशिष्ट आयात शुल्क छूट प्राप्त नहीं की और पूंजीगत वस्तुओं/भंडार का आयात नहीं किया। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया की जांच की है और नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई की गई योजनाओं के

अंतरों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक सूचना निर्यातकों द्वारा मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दायर की गई थी। इसलिए, निर्यातकों को व्यक्तिगत अंतर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

I. कम पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर वस्तुओं/सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों की सूची

- **कार्यक्रम 1 –** एलटीएआर पर चूना पत्थर की आपूर्ति
- **कार्यक्रम 12 –** एलटीएआर पर बिजली खपत के लिए प्राकृतिक गैस/बिजली/कोयले का प्रावधान
- **कार्यक्रम 13 –** एलटीएआर पर भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि तथा जल किराए से छूट/कमी

II. कर छूट और छूट के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों की सूची

- **कार्यक्रम 3 –** उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर छूट
- **कार्यक्रम 4 –** कच्चे माल, मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क छूट

III. ब्याज दर सब्सिडी के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों की सूची

- **कार्यक्रम 5 –** निवेशकों के लिए तरजीही ऋण
- **कार्यक्रम 7 –** निर्यातकों को तरजीही ऋण
- **कार्यक्रम 8 –** निवेश ऋण ऋणों की ब्याज दर
- **कार्यक्रम 9 –** लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने वाले निवेशकों को निवेश सहायता
- **कार्यक्रम 10 –** वियतनाम विकास बैंक (वीडीबी) से निर्यात ऋण
- **कार्यक्रम 11 –** विएटिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

IV. अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों की सूची

- **कार्यक्रम 2 –** वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान
- **कार्यक्रम 6 –** निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

54. जांच शुरू होने के पश्चात, जांचाधीन वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित प्रपत्र और रीति में प्रश्नावली और अतिरिक्त प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की सलाह दी गई थी और उन्हें कथित सब्सिडी कार्यक्रम के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव पर सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था ताकि ऐसी सब्सिडियों, यदि कोई हो, के अस्तित्व और परिमाण का उचित निर्धारण किया जा सके।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं:

i) यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

ii) पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

iii) न्घे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी

iv) येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

v) ए डोंग प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

vi) वीटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

vii) आन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

viii) फिलर मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

ix) वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

56. शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("गैट") का अनुच्छेद VI, सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समझौते ("एससीएम") के अनुच्छेद 19 के साथ पठित, आयातक देशों को पाटित आयातित वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

57. तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 केंद्र सरकार को पाटित आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की अनुमति देती है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) इस प्रकार कहती है:

(1) जहाँ कोई देश या राज्य क्षेत्र, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी वस्तु के वहाँ निर्माण या उत्पादन या वहाँ से निर्यात पर कोई सब्सिडी देता या प्रदान करता है, जिसमें ऐसी वस्तु के परिवहन पर कोई सब्सिडी शामिल है, तब ऐसी किसी वस्तु के भारत में आयात पर, चाहे वह सीधे निर्माण, उत्पादन वाले देश से या अन्यथा आयात की गई हो, और चाहे वह उसी स्थिति में आयात की गई हो जिसमें वह निर्माण या उत्पादन के देश से निर्यात की गई थी या निर्माण, उत्पादन या अन्यथा द्वारा स्थिति में परिवर्तित कर दी गई हो, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सब्सिडी की राशि से अनधिक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगा सकती है।

58. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) की व्याख्या में एससीएम के अनुच्छेद 1 की ही भाषा शामिल है, जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के प्रयोजनों के लिए 'सब्सिडी' को परिभाषित करती है। यह कहती है कि सब्सिडी का अस्तित्व तब माना जाएगा यदि:

"(क) निर्यातक या उत्पादक देश या राज्यक्षेत्र में सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान है, अर्थात्, जहाँ –

(i) किसी सरकारी प्रथा में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (अनुदान, ऋण और इक्विटी अंतर्वेशन सहित), या निधियों या देयताओं का संभावित प्रत्यक्ष अंतरण, या दोनों शामिल हों;

(ii) सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है, त्याग दिया जाता है या संग्रहीत नहीं किया जाता (राजकोषीय प्रोत्साहनों सहित);

(iii) कोई सरकार सामान्य अवसंरचना के अतिरिक्त वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करती है या वस्तुओं की खरीद करती है;

(iv) कोई सरकार किसी निधियन तंत्र को भुगतान करती है, या किसी निजी निकाय को ऊपर खंड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रकार के कार्यों को करने के लिए न्यस्त या निर्देशित करती है जो सामान्यतः सरकार में निहित होते हैं और वह प्रथा, किसी वास्तविक अर्थ में, सरकारों द्वारा सामान्यतः अनुसरित प्रथाओं से भिन्न नहीं होती; या

(ख) कोई सरकार किसी भी प्रकार का आय या मूल्य समर्थन अनुदानित या अनुरक्षित करती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके राज्यक्षेत्र से किसी वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के लिए, या उसके राज्यक्षेत्र में किसी वस्तु के आयात को कम करने के लिए कार्य करता है, और इसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है।"

59. इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) और धारा 9(2) के साथ पठित धारा 9(3) यह संकेत देती है कि किसी सब्सिडी के प्रतिसंतुलनकारी होने के लिए, वह वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन या निर्यात में संलग्न सीमित संख्या में व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए।

60. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का नियम 7(8) प्राधिकारी को 'उपलब्ध तथ्यों' पर भरोसा करने की अनुमति देता है यदि निर्यातक जांच में सहयोग करने में विफल रहते हैं। इस संबंध में, यह कहता है:

"ऐसे मामले में जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार पहुँच से इनकार करता है, या अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, प्राधिकारी अपने जांच परिणामों को अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभिलेखित कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझते हैं।"

च.3.1 प्रतिसंतुलनकारी पाई गई योजनाएं

अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं/सेवाओं के प्रावधान के रूप में चिह्नित योजनाओं की सूची

योजना 1 - अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर की आपूर्ति

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. "अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर की आपूर्ति" का आरोप या तो तथ्यों पर व्यक्तिगत संस्थाओं पर लागू नहीं होता या कानून में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं है।

ii. घरेलू उद्योग ने प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के आवश्यक तत्वों, अर्थात् वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता को स्थापित करने का भार नहीं उठाया है, और पारिश्रमिक की पर्याप्तता की जांच के लिए एक गलत मानक भी प्रस्तावित किया है।

iii. एक उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने प्रस्तुत किया कि कथित योजना उस पर लागू नहीं होती क्योंकि वह डली के रूप में चूना पत्थर बिल्कुल नहीं खरीदता। उसने प्रस्तुत किया कि वह स्वतंत्र आपूर्तिकर्ताओं से बाजार मूल्यों पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) पाउडर खरीदता है, जो खरीद प्रपत्रों, दीर्घकालिक खरीद समझौतों और आपूर्तिकर्ता प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित है। उसने प्रस्तुत किया कि उसके पास चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) पाउडर में बदलने की कोई सुविधा नहीं है और इसलिए, कथित "चूना पत्थर निर्यात कर" को उसकी कच्चे माल की खरीद या उत्पादन विधियों से नहीं जोड़ा जा सकता।

iv. उक्त पक्ष ने आगे प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद एचएस 2517.41.00.10 के तहत वर्गीकृत कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) पाउडर है, जबकि चूना पत्थर एचएस 2521 00 00 के अंतर्गत आता है।

v. उसने प्रस्तुत किया कि कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) पाउडर 5% के निर्यात कर के अधीन है, जो जांच अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहा है, और तर्क दिया कि यह मान लेना तर्कसंगत नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) पाउडर पर ऐसा निर्यात कर अनुप्रवाह उत्पादकों के लाभ के लिए घरेलू कीमतों को कम कर सकता है।

vi. उसने यह भी प्रस्तुत किया कि उसे आपूर्ति किया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर सफेद पत्थर/संगमरमर से उत्पादित होता है न कि चूना पत्थर से, और इसलिए वियतनाम सरकार ने उसे अपर्याप्त पारिश्रमिक पर संगत इनपुट उपलब्ध नहीं कराया है। इस आधार पर, उसने प्रस्तुत किया कि यह योजना उस पर लागू नहीं मानी जानी चाहिए।

vii. अन्य पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है कि वियतनाम का चूना पत्थर पर निर्यात कर एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1 के तहत सब्सिडी का गठन करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सब्सिडी के लिए (i) सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान और (ii) प्रदान किया गया लाभ आवश्यक है, और इसके अलावा प्रतिसंतुलनकारी होने के लिए सब्सिडी अनुच्छेद 2 के तहत विशिष्ट होनी चाहिए।

viii. उन्होंने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला साक्ष्य प्रदान नहीं किया है और विशेष रूप से, यह स्थापित नहीं किया है कि निर्यात कर को सरकारी वित्तीय अंशदान के समकक्ष माना जा सकता है।

ix. उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्यात कर या उपकर एक नियामक राजकोषीय उपाय है और इसमें निधियों का कोई अंतरण, सरकारी राजस्व का त्याग, या उद्यमों को वस्तुओं का सरकारी प्रावधान शामिल नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत कि निर्यात कर कथित रूप से अतिरिक्त घरेलू आपूर्ति उत्पन्न करता है और इसलिए घरेलू कीमतों को कम करता है, सरकारी "वित्तीय अंशदान" नहीं माना जा सकता और एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत वित्तीय अंशदान के समकक्ष सरकारी कार्रवाई के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता।

x. समर्थन में, विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया कि सरकारी उपाय के प्रति निजी संस्थाओं की प्रतिक्रिया, या विनियमन के आर्थिक प्रभाव (निर्यात प्रतिबंध/करों सहित), स्वयं एससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के तहत "न्यस्तीकरण या निर्देशन" या "वित्तीय अंशदान" स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने अपने द्वारा उद्धृत विश्व व्यापार संगठन विवादों, जिनमें

यूएस – निर्यात प्रतिबंध (डीएस194) और यूएस – सॉफ्टवुड लम्बर शामिल हैं, के तर्क पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि निर्यात प्रतिबंधों या करों को सरकार-न्यस्त या निर्देशित वस्तुओं का प्रावधान नहीं माना जा सकता और न्यस्तीकरण/निर्देशन के लिए निजी आचरण से प्रदर्शन योग्य सरकारी संबंध आवश्यक है, न कि केवल बाजार प्रभाव।

xi. उन्होंने अपने द्वारा उद्धृत विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्टों पर भी भरोसा किया, जिनमें यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से बायोडीजल के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (डीएस618) और यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर प्रतिसंतुलनकारी और पाटन रोधी शुल्क (डीएस616) शामिल हैं, यह प्रस्तुत करने के लिए कि न्यस्तीकरण/निर्देशन के लिए सरकारी कार्रवाई के साक्ष्य की आवश्यकता है जो आपूर्तिकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से बेचने की स्वतंत्रता से प्रभावी रूप से वंचित करे और केवल नियामक हस्तक्षेप या घरेलू मूल्य निर्धारण या आपूर्ति को प्रभावित करने वाले निर्यात उपाय अपर्याप्त हैं।

xii. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वियतनाम में चूना पत्थर के आपूर्तिकर्ता घरेलू स्तर पर बेचने या निर्यात करने, अनेक क्षेत्रों को बेचने का वाणिज्यिक विवेक रखते हैं, और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को या किसी विशेष मूल्य पर चूना पत्थर प्रदान करने के लिए अधिदेशित नहीं किया गया है, जिससे "प्रदर्शन योग्य संबंध" परीक्षण विफल हो जाता है।

xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि, केवल तर्क के लिए वित्तीय अंशदान का अस्तित्व मानते हुए भी, घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि जांचाधीन वस्तुओं के उत्पादकों को कोई लाभ प्रदान किया गया था। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाना प्रदर्शित होना चाहिए और प्रकृति और सीमा दोनों में जांचा जाना चाहिए।

xiv. उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने यह दिखाने वाला साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि जांच अवधि के दौरान किसी उत्पादक ने उपयुक्त मानक की तुलना में बाजार से कम कीमतों पर चूना पत्थर खरीदा, या निर्यात कर के परिणामस्वरूप जांचाधीन वस्तुओं के उत्पादकों के लिए इनपुट लागत में वास्तविक कमी आई।

xv. विशिष्टता के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर एक बहु-उपयोगी खनिज है जो अनेक क्षेत्रों (सीमेंट, इस्पात, खनन, कागज, जल उपचार और अन्य उद्योगों सहित) में उपयोग किया जाता है और इसलिए किसी निर्यात कर उपाय को जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों के लाभ के लिए सीमित या अभिकल्पित नहीं माना जा सकता।

xvi. उन्होंने तर्क दिया कि एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के अर्थ में कुछ उद्यमों या उद्योगों तक किसी कथित लाभ की पहुंच की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 8.1 के अनुसार, एक गैर-विशिष्ट सब्सिडी कार्रवाई योग्य नहीं है और प्रतिसंतुलनकारी नहीं की जा सकती।

xvii. वियतनाम सरकार ने भी, वियतनाम व्यापार उपचार प्राधिकारी के माध्यम से, प्रस्तुत किया है कि यह आरोप एससीएम समझौते के तहत सब्सिडी कार्यक्रम नहीं बनता। उसने प्रस्तुत किया कि निर्यात कर एक राजकोषीय नियामक उपाय है और अनुच्छेद 1.1(क)(1) के तहत "वित्तीय अंशदानों" की विस्तृत सूची में नहीं आता और सरकार चूना पत्थर प्रदान नहीं करती, घरेलू मूल्य निर्धारण नियंत्रित नहीं करती, या छूट पर चूना पत्थर की आपूर्ति नहीं करती।

xviii. उसने प्रस्तुत किया कि वित्तीय अंशदान के अभाव में, कोई सब्सिडी नहीं हो सकती, और इसलिए कथित कार्यक्रम के तहत कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता। उसने आगे प्रस्तुत किया

कि किसी भी विश्व व्यापार संगठन सदस्य जांच प्राधिकारी ने सब्सिडी रोधी जांच में निर्यात कर को सब्सिडी नहीं माना है।

xix. कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि उनकी कच्चे माल की खरीद प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धी बातचीत के माध्यम से निर्धारित कीमतों पर, निजी आपूर्तिकर्ताओं से बाजार आधारित शर्तों पर होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खरीद लेन-देन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है और इसलिए, अनुच्छेद 14(घ) के तहत लाभ का परीक्षण संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि महानिदेशालय की पिछली प्रथा यह मान्यता देती है कि बाजार-आधारित खरीद को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं माना जा सकता।

xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग का मानक प्रस्ताव दोषपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग ने एचएस 2521 के लिए मलेशिया एफओबी निर्यात कीमतों का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है, जो चूनेदार उत्पादों के एक विषम समूह को शामिल करता है और आवश्यक रूप से उत्पादकों के इनपुट के लिए प्रासंगिक तुलनीय चूना पत्थर की डलियाँ नहीं है।

xxi. उन्होंने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग के स्वयं के मानक आंकड़ों में विभिन्न गंतव्यों में चरम बाह्य बिंदु शामिल हैं, जो उत्पाद मिश्रण, गलत वर्गीकरण, या अन्य विकृतियों को इंगित करता है, और इसे अनुच्छेद 14(घ) के तहत "प्रचलित बाजार स्थितियाँ" नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग द्वारा कथित निर्यात कर चूना पत्थर (एचएस 2521) पर लागू होता है न कि प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादों (एचएस 2517/3824) पर, और इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट कीमतों का उपयोग करके मानक निर्धारण या लाभ परिकलन का कोई प्रयास कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

xxii. मलेशिया एफओबी मानकों के स्थान पर, एक उत्तरदाता निर्यातक ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर की डलियों के भारतीय आयात मूल्य एक उपयुक्त मानक होंगे, जो एक उत्तरदाता निर्यातक द्वारा खरीदा गया सटीक रूप बताया गया है।

xxiii. इस प्रयोजन के लिए, हितबद्ध पक्षकार ने जांच अवधि के दौरान भारत में आयातों का लेन-देन-वार सारांश प्रदान किया है, जो संयुक्त अरब अमीरात से औसत आयात मूल्य दिखाता है, जो आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, साथ ही अन्य देशों से छोटी मात्रा में आयात दर्शाता है। इस आधार पर, उसने प्रस्तुत किया कि संयुक्त अरब अमीरात की कीमतें प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों की प्रतिनिधि हैं।

xxiv. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वियतनाम के चूना पत्थर पर निर्यात शुल्क का घोषित तर्क संसाधन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के अति-दोहन की रोकथाम है, न कि अपर्याप्त पारिश्रमिक पर आपूर्ति सुनिश्चित करना। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार स्वयं चूना पत्थर की आपूर्ति नहीं करती और चूना पत्थर की आपूर्ति निजी विक्रेताओं द्वारा की जाती है।

xxv. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और भारत में भी उपलब्ध है, और भारत अनेक देशों से चूना पत्थर का आयात करता है, जो एक सत्यापन योग्य मानक के रूप में कार्य कर सकता है, और तीसरे देश के निर्यात मूल्य आंकड़ों पर भरोसा अनुचित है।

xxvi. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर पर अपस्ट्रीम उपायों से कैल्शियम कार्बोनेट या मास्टरबैच के अनुप्रवाह मूल्य निर्धारण पर संचरण का अनुमान लगाने का कोई प्रयास काल्पनिक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्यात कर, बाजार स्थितियों के आधार पर, भिन्न मूल्य परिणामों की ओर ले जा सकता है और उचित समायोजनों के बाद एक अविकृत मानक के सापेक्ष निरंतर घरेलू ह्रास को

प्रदर्शित करने वाला कोई अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कोई भी संचरण विश्लेषण स्वचालित नहीं है और साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए, जो अनुपस्थित है।

xxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि लाभ परिकलन के प्रयोजन के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के विरुद्ध लाभ की गणना करना अनुज्ञेय नहीं है जब कथित उपाय केवल चूना पत्थर से संबंधित है, और लाभ, यदि कोई है, का परीक्षण केवल चूना पत्थर की डलियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रत्यक्ष प्रावधान के संबंध में कोई आरोप नहीं है और इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के विरुद्ध कोई लाभ परिकलित नहीं किया जा सकता।

xxviii. उपरोक्त के आधार पर, अन्य हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस योजना के तहत घरेलू उद्योग के आरोपों को अस्वीकार करें, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित मानक को अस्वीकार करें, और निर्धारित करें कि कथित उपाय प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी का गठन नहीं करता और/या उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू नहीं होता।

xxix. वियतनाम सरकार सादर प्रस्तुत करती है कि महानिदेशालय के जांच परिणाम एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1, 2 और 14(घ) के साथ असंगत हैं। वियतनाम सरकार इस अंतिम जांच परिणाम से सादर असहमत है कि कथित कार्यक्रम चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले अनुप्रवाह उद्योगों के लिए विशिष्ट है। चूना पत्थर एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला बहु-उद्देश्यीय खनिज है जो सीमेंट, इस्पात, कागज, प्लास्टिक, पेंट, रबर, जल उपचार, खनन, निर्माण, उर्वरक, खाद्य, औषधि और अन्य क्षेत्रों सहित अनेक उद्योगों में उपभुक्त होता है। डिक्री संख्या 26/2023/एनडी-सीपी एक सामान्यतः लागू संसाधन प्रबंधन उपाय है जो चूना पत्थर के अंतिम जांच परिणाम और निर्यात में संलग्न सभी संस्थाओं पर लागू होता है और मास्टरबैच या जांचाधीन उत्पाद क्षेत्रों को विशेष रूप से कोई लाभ प्रदान नहीं करता।

xxx. इस उपाय का नीतिगत उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अनवीकरणीय संसाधनों के अति-दोहन और क्षरण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास है, न कि अनुप्रवाह उद्योगों को लक्षित सहायता का प्रावधान। तदनुसार, वियतनाम सरकार सादर प्रस्तुत करती है कि कार्यक्रम एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के अर्थ में न तो विधिक और न ही तथ्यात्मक विशिष्टता प्रदर्शित करता है।

xxxi. वियतनाम सरकार आगे सादर प्रस्तुत करती है कि एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के अर्थ में कोई "वित्तीय अंशदान" विद्यमान नहीं है। महानिदेशालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या निर्यात शुल्कों और नियामक उपायों को निजी निकायों के "न्यस्तीकरण या निर्देशन" के समकक्ष मानती प्रतीत होती है और स्थापित विश्व व्यापार संगठन विधिशास्त्र का सीधा खंडन करती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स – निर्यात प्रतिबंध और यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से बायोडीजल पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क शामिल हैं। ये विश्व व्यापार संगठन रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि निर्यात प्रतिबंध या निर्यात शुल्क सरकारी न्यस्तीकरण या निर्देशन का गठन नहीं करते केवल इसलिए कि वे बाजार स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। वियतनाम सरकार आगे ध्यान देती है कि, यद्यपि यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से बायोडीजल पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में पैनल रिपोर्ट वर्तमान में "शून्य में अपील" के अधीन है, रिपोर्ट एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) की सबसे हालिया और आधिकारिक व्याख्या बनी हुई है। चूंकि अपीलीय निकाय निष्क्रिय है, ऐसी अपीलें पैनल जांच परिणामों को अमान्य या पलटती नहीं हैं, और विश्व व्यापार संगठन सदस्य "शून्य में अपील" के अधीन रिपोर्टों पर प्रेरक कानूनी प्राधिकार के रूप में भरोसा करते रहे हैं।

xxxii. चूना पत्थर के आपूर्तिकर्ता मूल्य निर्धारण, ग्राहकों और बिक्री के संबंध में पूर्ण वाणिज्यिक विवेक रखते हैं। इसलिए कोई भी घरेलू मूल्य प्रभाव साक्ष्य-आधारित आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से सरकारी प्रत्यायोजन या आदेश के बजाय सामान्य बाजार गतिशीलता को दर्शाता है। महानिदेशालय ने संचरण विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण, लागत संवर्धन विश्लेषण, या लेन-देन-स्तरीय तुलना आयोजित नहीं की जो यह प्रदर्शित करे कि चूना पत्थर पर निर्यात शुल्क प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के लिए निम्न कीमतों में परिवर्तित हुए।

xxxiii. वियतनाम सरकार आगे सादर प्रस्तुत करती है कि चूना पत्थर और प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर भिन्न वर्गीकरणों, उत्पादन प्रक्रियाओं, विशेषताओं, लागत संरचनाओं और अंतिम उपयोगों वाले पृथक उत्पाद हैं। चूना पत्थर मुख्यतः सीमेंट और इस्पात उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला कच्चा प्राकृतिक खनिज है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर एक प्रसंस्कृत औद्योगिक उत्पाद है जिसके लिए प्लास्टिक, पेंट, कागज और मास्टरबैच उत्पादन में उपयोग के लिए पिसाई, पेषण, वर्गीकरण, शुष्कीकरण, पैकेजिंग, सतह उपचार और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है। निर्यात शुल्क केवल कच्चे चूना पत्थर पर लागू होते हैं न कि प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादों पर। इसलिए वियतनाम सरकार सादर प्रस्तुत करती है कि महानिदेशालय ने अनुचित रूप से कच्चे चूना पत्थर को प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादों के साथ मिला दिया और बिना पर्याप्त साक्ष्य आधार के यह मान लिया कि कोई कथित अपस्ट्रीम विकृति स्वतः अनुप्रवाह उत्पादों को संचरित हो जाती है। वियतनाम सरकार आगे ध्यान देती है कि महानिदेशालय ने प्रभावी रूप से एक बहु-स्तरीय संचरण सिद्धांत अपनाया बिना किसी स्तर पर कोई संचरण विश्लेषण किए, जो एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(ख) और 14(घ) तथा स्थापित विश्व व्यापार संगठन विधिशास्त्र के विपरीत है।

xxxiv. *महानिदेशालय द्वारा चयनित मलेशियाई मानक एचएस कोड 283650 के तहत वर्गीकृत रासायनिक रूप से प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादों से संबंधित है, जबकि वियतनामी उत्पादक एचएस कोड 251741 के तहत वर्गीकृत प्राकृतिक पिसे हुए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये उत्पाद उत्पादन विधियों, विशेषताओं, लागत संरचनाओं, शुद्धता स्तरों और बाजार उपयोगों में भौतिक रूप से भिन्न हैं। इसलिए वियतनाम सरकार सादर प्रस्तुत करती है कि चयनित मानक वियतनाम में प्रचलित बाजार स्थितियों को उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप विकृत तुलना और कथित लाभ की बढ़ी हुई गणना होती है। वियतनाम सरकार आगे ध्यान देती है कि महानिदेशालय ने मलेशिया और वियतनाम के बीच गुणवत्ता, उत्पादन स्थितियों, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, संभार-तंत्र, व्यापार प्रतिरूपों या प्रतिस्पर्धी स्थितियों के संदर्भ में तुलनीयता को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया।*

xxxv. वियतनाम सरकार यह भी सादर ध्यान देती है कि, भारत द्वारा वियतनाम को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में औपचारिक मान्यता दिए जाने को देखते हुए, महानिदेशालय घरेलू कीमतों को अस्वीकार करने और उनके स्थान पर देश से बाहर के स्थानापन्न मानकों का उपयोग करने का हकदार नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण वियतनाम को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता के साथ असंगत है और प्रभावी रूप से स्थानापन्न-मूल्य पद्धति के अनुप्रयोग के समकक्ष है, जो इस संदर्भ में अनुज्ञेय नहीं है।

xxxvi. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर पर कथित निर्यात कर को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के तहत "वित्तीय अंशदान" का गठन नहीं करता। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वियतनाम सरकार ने निजी

आपूर्तिकर्ताओं को जांचाधीन वस्तुओं के उत्पादकों को किसी विशेष मूल्य पर चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रदान करने के लिए न्यस्त या निर्देशित किया। केवल निर्यात प्रतिबंध या नियामक उपाय का बाजार प्रभाव सरकारी निर्देशन के समकक्ष नहीं हो सकता, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र में मान्यता प्राप्त है।

xxxvii. उत्तरदाताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी ने कोई "लाभ" स्थापित नहीं किया है, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई लेन-देन-स्तरीय विश्लेषण, लागत विश्लेषण या कंपनी-विशिष्ट जांच नहीं की गई कि इनपुट प्रचलित बाजार कीमतों से नीचे खरीदे गए थे। वीएमआई, वीटाप्लास और एडीसी जैसी कंपनियों ने कहा कि उनके कैल्शियम कार्बोनेट इनपुट स्वतंत्र निजी आपूर्तिकर्ताओं से बाजार आधारित, व्यावसायिक रूप से तय शर्तों पर खरीदे गए थे, जिनमें कोई सरकारी संलिप्तता या अधिमान्य उपचार नहीं था।

xxxviii. एक प्रमुख आपत्ति चूना पत्थर की डलियों और कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर को समान उत्पाद मानने के गलत व्यवहार से संबंधित है। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर की डलियाँ कच्ची खनिज चट्टानें हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर एक प्रसंस्कृत, मूल्य-वर्धित औद्योगिक इनपुट है, जिसके भिन्न एचएस वर्गीकरण, विशेषताएं, अशुद्धता स्तर, उपयोग और कीमतें हैं। चूंकि कथित निर्यात कर चूना पत्थर पर लागू होता है न कि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर पर, जहाँ उत्पादक ने चूना पत्थर की डलियों का उपयोग किया है वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को प्रासंगिक मानक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

xxxix. प्रकटीकरण विवरण सब्सिडी नियमों के नियम 18 का अनुपालन नहीं करता जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित है। प्रकटीकरण विवरण उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए अनेक प्रमुख मुद्दों पर अत्यंत मौन है। कुछ प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:

क) निर्यात कर को वित्तीय अंशदान मानने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 और एससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) में प्रदत्त "न्यस्तीकरण"/"निर्देशन" का परीक्षण नहीं किया गया है।

ख) प्रकटीकरण विवरण ने इस मुद्दे की जांच नहीं की है कि आर्थिक प्रभावों को सरकार द्वारा किसी निजी निकाय को वस्तुएँ प्रदान करने के लिए "जिम्मेदारी देना (न्यस्तीकरण)" या "अधिकार का प्रयोग करना (निर्देशन)" के रूप में सम्मिश्रित नहीं किया जा सकता। सरकारी उपाय (जैसे निर्यात कर) के प्रति निजी संस्थाओं की प्रतिक्रिया सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान के निर्धारण का आधार नहीं हो सकती।

ग) प्रकटीकरण विवरण में यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया या प्रस्ताव नहीं रखा गया कि वियतनाम सरकार ने चूना पत्थर की डलियों के आपूर्तिकर्ताओं को जांचाधीन वस्तुओं के निर्माताओं को या किसी विशेष मूल्य पर चूना पत्थर की डलियाँ प्रदान करने का निर्देश दिया।

घ) चूना पत्थर की डलियों के आपूर्तिकर्ताओं को अपने उत्पाद घरेलू बाजार में जांचाधीन वस्तुओं/गैर-जांचाधीन वस्तुओं/अनुप्रवाह उद्योगों के निर्माताओं को बेचने, स्वउपभोग या निर्यात करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

ङ) निम्नलिखित विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय और पैनल रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि सौपने/निर्देशन के लिए निजी व्यवहार को प्रभावित करने वाले केवल नियामक हस्तक्षेप से अधिक की आवश्यकता है, सरकारी कार्रवाई का साक्ष्य होना चाहिए जिसका उद्देश्य निजी निकायों पर "कार्य का एक प्रकार" अधिरोपित करना है, जो उन्हें

व्यावसायिक रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता से वंचित करता है। सामान्य आर्थिक प्रभाव, जैसे घरेलू आपूर्ति या मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले निर्यात प्रतिबंध, पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि "सरकार को उन स्थितियों में निजी पक्ष को न्यस्त या निर्देशित करने वाला नहीं माना जाएगा जहाँ निजी पक्ष का व्यवहार केवल उस नियामक ढांचे से प्रभावित होता है जिसमें वह कार्य करता है।

क) यूएस – ड्रैम्स पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में अपीलीय निकाय रिपोर्ट

ख) विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट (डब्ल्यूटी/डीएस618/आर दिनांक 22 अगस्त 2025) - यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से बायोडीजल के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क

ग) विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट (डब्ल्यूटी/डीएस616/आर दिनांक 02 अक्टूबर 2025) - यूरोपीय संघ – इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर प्रतिसंतुलनकारी और पाटन रोधी शुल्क"

च) वियतनाम से 600 मिलीमीटर के बराबर या अधिक चौड़ाई वाले एल्यूमीनियम जिंक लेपित इस्पात के मामले में ऑस्ट्रेलियाई आयोग के जांच परिणाम की प्रकटीकरण विवरण में जांच नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि यह इस मामले में शामिल तथ्यों और मुद्दों पर सीधे लागू होता है।

छ) निर्यात कर को विशिष्ट मानने के लिए "स्पष्ट" परीक्षण नहीं किया गया है।

xl. पूर्वोक्त पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए अधिकांश प्रमुख मुद्दों की प्रकटीकरण विवरण में उचित जांच या संबोधन नहीं किया गया है, जो प्राधिकारी को नियमों के तहत करना अपेक्षित है।

xli. उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया मानक मूलभूत रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि उत्तरदाता ने जांचाधीन उत्पाद के निर्माण के लिए चूना पत्थर की डलियों का उपयोग किया न कि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर का। जब प्राधिकारी ने स्वयं यह मान्यता दी कि अनुच्छेद 14(घ) के तहत "प्रासंगिक वस्तु" के संदर्भ में मानक निर्धारण किया जाना चाहिए, तब वर्तमान मामले में प्रासंगिक वस्तु चूना पत्थर की डलियाँ होनी चाहिए थी, विशेष रूप से जब कथित निर्यात प्रतिबंध/कर चूना पत्थर पर है न कि कैल्शियम कार्बोनेट पर।

xlii. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रकटीकरण विवरण स्वयं यह अभिलिखित करता है कि जहाँ कोई उत्पादक कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदता है, कैल्शियम कार्बोनेट मानक उपयुक्त हो सकता है, और जहाँ कोई उत्पादक चूना पत्थर की डलियों का उपयोग करता है, चूना पत्थर-आधारित मानक आवश्यक है। इस स्वीकृत स्थिति के बावजूद, प्राधिकारी ने उत्तरदाता पर मलेशियाई कैल्शियम कार्बोनेट निर्यात कीमतों को लागू करने का प्रस्ताव किया, स्पष्टतः इस गलत धारणा पर कि सभी भाग लेने वाले निर्यातकों ने सीधे कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदा। चूंकि उत्तरदाता ने स्वीकृत रूप से चूना पत्थर की डलियों का उपयोग किया, कैल्शियम कार्बोनेट को मानक के रूप में अपनाना तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से अस्थिर है।

xliii. उत्तरदाता ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर की डलियाँ और कैल्शियम कार्बोनेट पृथक उत्पाद हैं। चूना पत्थर अशुद्धियों वाली प्राकृतिक चट्टान है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रसंस्कृत, मूल्य-वर्धित रासायनिक उत्पाद है। वे भिन्न एचएस वर्गीकरणों के अंतर्गत आते हैं, भिन्न विशेषताएं, प्रसंस्करण स्तर और कीमतें रखते हैं, और घरेलू उद्योग ने स्वयं चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पृथक मलेशियाई एफओबी मानक प्रदान किए। इसलिए, केवल इसलिए कि दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को प्रासंगिक मानक नहीं माना जा सकता।

xliv. तदनुसार, चूंकि आरोप अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर की डलियों के प्रावधान से संबंधित है न कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रावधान से, सब्सिडी अंतर, यदि कोई है, केवल चूना पत्थर की डलियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक, प्रसंस्करण लागतों के लिए उपयुक्त समायोजन के बाद, प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट में अंतर्निहित केवल चूना पत्थर के घटक पर विचार किया जा सकता है। ऐसे समायोजन के बिना कैल्शियम कार्बोनेट मानक का उपयोग इसलिए सिद्धांत, तथ्य और कानून में त्रुटिपूर्ण है।

<u>यूएई को मानक के रूप में गलत तरीके से अस्वीकार किया गया</u>

xlv. इसके अलावा, पैरा 121 में ही, प्राधिकारी यह मानते हैं "कि संयुक्त अरब अमीरात से चूना पत्थर का आयात मुख्यतः इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है न कि जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों द्वारा"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त कथन किसी ठोस सूचना या विश्लेषण पर आधारित नहीं है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने बिना कोई प्रमाणीकरण या समर्थक साक्ष्य मांगे घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार करना चुना है। उत्तरदाता इस संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:

क) संयुक्त अरब अमीरात से चूना पत्थर की डलियों का आयात जांचाधीन वस्तुओं के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। आवेदक उद्योग ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि संयुक्त अरब अमीरात से आयातित चूना पत्थर की डलियाँ जांचाधीन वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग नहीं की जातीं।

ख) एफओबी मूल्य निर्धारित करने के लिए सीआईएफ मूल्य में दावा किए गए समायोजन या तो आवेदन के आधार पर लिए गए हैं या प्राधिकारी द्वारा अनुसरित सतत प्रथा के अनुसार हैं।

ग) प्राधिकारी, अधिक से अधिक, अनुपलब्ध सूचना पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना लागू कर सकते हैं और उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत आठ-अंक स्तर के लेन-देन-वार पृथक्कृत आयात आंकड़ों को पूर्णतः अस्वीकार नहीं कर सकते जो वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आठ-अंक स्तर के आयात आंकड़ों से भी मान्य होते हैं।

xlvi. बिना किसी पूर्वाग्रह के, प्राधिकारी उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात सभी स्रोतों से चूना पत्थर की डलियों के भारत में औसत आयात मूल्यों पर विचार कर सकते हैं। प्राधिकारी मानक निर्धारण के प्रयोजन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से विधिवत पुष्ट चूना पत्थर की डली के आठ-अंक स्तर के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं।

xlvii. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि संयुक्त अरब अमीरात से भारत की कीमतें चूना पत्थर की डलियों के मानक निर्धारण प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं पाई जातीं,

तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्राधिकारी "प्रासंगिक वस्तु" अर्थात चूना पत्थर की डलियों, जिस पर कथित रूप से वियतनाम सरकार द्वारा प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान की गई है, के संबंध में उत्तरदाता द्वारा दायर आंकड़ों की अवहेलना करे।

xlviii. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रकटीकरण विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी को प्रासंगिक वस्तु अर्थात चूना पत्थर की डलियों के लिए आठ-अंक स्तर पर निर्यातक द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट आयात आंकड़ों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, सिवाय इस आशंका के कि ऐसे आंकड़े "उपयुक्त प्रसंस्करण समायोजनों और प्रत्येक लागत कटौती का समर्थन करने वाले सत्यापन योग्य साक्ष्य" के अभाव में जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक इनपुट के "वास्तविक आर्थिक मूल्य" को कम करके आंक सकते हैं। आदर सहित, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित कारणों से किसी भी तथ्यात्मक सार से रहित है:

क) मलेशिया एफओबी निर्यात कीमतें 4-अंकीय एचएस कोड 2521 स्तर पर वर्गीकृत उत्पादों के लिए, जो चूना पत्थर, चूना पत्थर प्रवाह और चूना या सीमेंट के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ उपयोग किए जाने वाले अन्य चूनेदार पत्थरों को समुच्चित करता है।

ख) उद्धृत एफओबी कीमतें, जो लगभग 28 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लेकर 51,43,672 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक हैं, एक व्यापक, विषम उत्पाद समूह से संबंधित हैं जो न तो समरूप है और न ही जांचाधीन वस्तुओं से प्रासंगिक सामग्री से पर्याप्त रूप से तुलनीय है।

ग) मानक निर्धारण के लिए वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आठ-अंकीय स्तर के आयात आंकड़ों से विधिवत मान्य चूना पत्थर की डलियों के आठ-अंक स्तर के पृथक्कृत लेन-देन-वार भारतीय आयात आंकड़ों पर विचार करने के उत्तरदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण सतही हैं।

घ) उत्तरदाता द्वारा द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों, वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आयात आंकड़ों और हमारे 10 मार्च, 2026 के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आवेदक उद्योग द्वारा दायर व्यापार मानचित्र आंकड़ों का तुलनात्मक सारांश दर्शाता है कि चूना पत्थर की डली सहित वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट किए गए कच्चे/अपृथक्कृत आयात आंकड़े उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत कच्चे/अपृथक्कृत आयात आंकड़ों के तुलनीय हैं। प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं (देशों) का औसत मूल्य भी उसी सीमा में है।

ङ) प्रस्तावित आंकड़े आठ-अंक स्तर पर हैं जबकि प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने का प्रस्तावित आंकड़ा चार-अंक स्तर पर है और इसमें चूना पत्थर, चूना पत्थर प्रवाह और चूना या सीमेंट के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ उपयोग किए जाने वाले अन्य चूनेदार पत्थर शामिल हैं।

च) निर्यातक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से पूर्णतः पुष्ट हो चुके हैं।

छ) प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि "प्रसंस्करण समायोजनों के संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं है", पूर्णतः अबोधगम्य है क्योंकि आंकड़े स्वयं प्रासंगिक उत्पाद अर्थात चूना पत्थर की डलियों से संबंधित हैं और इसलिए, किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण समायोजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

चार-अंक स्तर का मलेशिया से भारत को चूना पत्थर के टुकड़ों का एफओबी निर्यात कीमत, जो आवेदक उद्योग द्वारा दावा किया गया है, मलेशिया से भारत को चूना पत्थर की डलियों के सीआईएफ आयात मूल्य से अधिक है

xlix. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्राधिकारी का 4-अंकीय स्तर पर आंकड़े (व्यापार मानचित्र से कच्चे/अचयनित आयात आंकड़े) लेने के प्रस्ताव ने एक बेतुकी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें मलेशिया से भारत को एफओबी मूल्य का प्रस्तावित मानक 43 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है जबकि "प्रासंगिक वस्तु" अर्थात चूना पत्थर की डलियों के लिए 8-अंक स्तर पर पृथक्कृत लेन-देन-वार आंकड़े स्वयं मलेशिया से आयात का सीआईएफ मूल्य लगभग 41 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन दर्शाते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरदाता द्वारा दावा किया गया मलेशिया से भारत को चूना पत्थर की डलियों का सीआईएफ आयात मूल्य आठ-अंक स्तर के लेन-देन-वार पृथक्कृत आयात आंकड़ों पर आधारित है जो वाणिज्य मंत्रालय के आयात आंकड़ों से विधिवत पुष्ट हैं।

l. यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक उद्योग द्वारा व्यापार मानचित्र से लिया गया चार-अंक स्तर का कच्चा/अपृथक्कृत एफओबी आंकड़ा गलत है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विषम उत्पाद शामिल हैं।

प्रकटीकरण विवरण में मलेशिया से निर्यात कीमत को उपयुक्त मानक मानने का प्रस्ताव गलत और अनुपयुक्त है

li. प्रकटीकरण विवरण में इस आधार पर मलेशियाई निर्यात कीमत को उपयुक्त मानक मानने का प्रस्ताव कि बाह्य मानक उपयुक्त समायोजनों के बाद, प्रासंगिक वस्तु के लिए अविकृत प्रचलित बाजार स्थितियों को सबसे अधिक तर्कसंगत रूप से प्रतिबिंबित करता है, पूर्णतः अनुपयुक्त और त्रुटिपूर्ण है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनेक जांचों में, माननीय प्राधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया है न कि पड़ोसी देश में प्रचलित कीमतों पर। प्राधिकारी के सुगम संदर्भ के लिए उदाहरणात्मक मामलों की सूची नीचे प्रदान की गई है।

क्र.सं.	**जांच का नाम**	**फाइल सं. एवं दिनांक**	**विचारित मानक**	**टिप्पणी**
1	फाइबरबोर्ड इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका से	फा.सं. 06/17/2019-डीजीटीआर दिनांक 03 मई 2021	अंतिम जांच परिणाम का पैरा 71 - न्यूजीलैंड से लट्ठे की निर्यात कीमत को सबसे बड़े निर्यातक होने के नाते उपयुक्त मानक माना गया।	अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया न कि संबद्ध देश के पड़ोसी देश में प्रचलित कीमत पर
2	चीन से एट्राजीन टेक्निकल	फा.सं. 6/19/2018-डीजीएडी 22 अगस्त, 2019	पैरा 56 – सायन्यूरिक क्लोराइड और कास्टिक सोडा की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को उपयुक्त मानक मूल्य माना गया।	

3	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से संतृप्त वसीय अल्कोहल	फा.सं. 6/18/2021-डीजीटीआर दिनांक 07 फरवरी 2023	पैरा 56 - सीपीकेओ सीआईएफ रॉटरडैम कीमतों को उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय मानक मूल्य माना गया।	

liii. आवेदक उद्योग द्वारा दायर भ्रामक सूचना के आधार पर प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित चूना पत्थर सब्सिडी अंतर गलत है क्योंकि चूना पत्थर मानक के बजाय कैल्शियम कार्बोनेट मानक पर विचार किया गया है।

liii. आन टिएन ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने चूना पत्थर की डलियों के साथ-साथ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के लिए एक मानक मूल्य प्रस्तावित किया है जो खरीद मूल्य से तीन गुना से अधिक है, जबकि निर्यात कर के रूप में कथित सब्सिडीकरण की सीमा मात्र 30% है। यह मानते हुए भी, परंतु स्वीकार न करते हुए, कि 30% के निर्यात कर की संपूर्ण सीमा को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी माना जा सकता है (जो वास्तव में इस मुद्दे पर स्थापित विधिशास्त्र के घोर विरोधाभास में होगा), 300% से अधिक का मानक मूल्य प्रत्यक्षतः बेतुका होगा। दुर्भाग्यवश, प्रकटीकरण विवरण में इस बुनियादी तथ्य की अवहेलना की गई प्रतीत होती है और स्वयं को घरेलू उद्योग द्वारा पूर्णतः गुमराह होने दिया गया है। यह हमारे इस कथन को सुदृढ़ करता है कि यदि निर्यात कर को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी माना भी जाए, तो मानक निर्धारण केवल और केवल "प्रासंगिक वस्तु" के लिए किया जाना चाहिए, जो इस मामले में चूना पत्थर की डलियाँ हैं न कि कैल्शियम कार्बोनेट। दुर्भाग्यवश, यह स्थिति स्वयं प्राधिकारी द्वारा पैरा 116 में प्रतिपादित की गई है किंतु मानक मूल्य प्रस्तावित करते समय इसका पालन नहीं किया गया।

62. <u>घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:</u>

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक कच्चा माल है, जो जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कुल कच्चे माल इनपुट का लगभग 70-85% होता है।

ii. उसने प्रस्तुत किया कि, वियतनाम की विश्व व्यापार संगठन व्यापार नीति समीक्षा के अनुसार, वियतनाम सरकार खनिजों सहित कुछ उत्पादों पर निर्यात कर लगाती है। इस संबंध में, वियतनाम ने डिक्री संख्या 26/2023/एनडी-सीपी के तहत चूना पत्थर पर निर्यात कर लगाया है।

ii. चूना पत्थर एचएसएन कोड 2521 00 00 के तहत वर्गीकृत हैं, जो चूना पत्थर-आधारित गलाने वाले कारकों और चूने या सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य चूनेदार पत्थरों को शामिल करता है। वियतनाम द्वारा चूना पत्थर पर लगाई गई लागू निर्यात कर दरें समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ी हैं और निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

अवधि	**निर्यात कर की दर**
01-01-2020 से 30-06-2022	17%
01-07-2022 से 30-06-2023	20%
01-07-2023 से 30-06-2024	25%
01-07-2024 से आगे	30%

iv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि बढ़ते निर्यात कर लगाने से वियतनाम से चूना पत्थर के निर्यात को हतोत्साहित किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी उपलब्धता प्रतिबंधित होती है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू आपूर्ति में वृद्धि होती है और वियतनाम में चूना पत्थर और चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट की घरेलू कीमतों पर गिरावट का दबाव पड़ता है।

v. यह प्रस्तुत किया गया है कि वियतनाम सरकार ने स्वीकार किया है कि निर्यात कर नीति का उद्देश्य निर्यातों को विनियमित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और घरेलू रूप से चूना पत्थर का उपयोग करने वाले अनुप्रवाह उद्योगों की दक्षता में सुधार करना है। नीति ढाँचे का लक्ष्य कच्चे और अप्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात को सीमित करना और वियतनाम के भीतर अनुप्रवाह मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।

vi. निर्यात कर व्यवस्था और संबद्ध नियामक ढांचे के माध्यम से, चूना पत्थर जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों सहित घरेलू अनुप्रवाह उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय स्तरों से नीचे की कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है। यह एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(घ) और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12(2)(घ) के अर्थ में अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं का प्रावधान है।

vii. घरेलू उद्योग ने ध्यान दिया कि उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता स्थापित नहीं की गई है और विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए प्रतिवाद किया है कि निर्यात कर या प्रतिबंध केवल बाजार प्रभावों के आधार पर वित्तीय अंशदान के समकक्ष नहीं हो सकते। उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित मानक को भी चुनौती दी है और भारतीय आयात कीमतों या संयुक्त अरब अमीरात की कीमतों पर आधारित वैकल्पिक मानक प्रस्तावित किए हैं, समायोजनों सहित।

viii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1 के तहत, सब्सिडी तब विद्यमान होती है जब कोई सरकार वित्तीय अंशदान करती है और लाभ प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के अनुसार, वित्तीय अंशदान वहाँ उत्पन्न हो सकता है जहाँ कोई सरकार किसी निजी निकाय को वस्तुओं का प्रावधान जैसे कार्य करने के लिए न्यस्त या निर्देशित करती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी, जहाँ प्रथा सामान्य सरकारी प्रथाओं से सार्थक रूप से भिन्न नहीं होती।

ix. उसने प्रस्तुत किया कि निर्यात कर निर्यात की लागत बढ़ाकर उन्हें हतोत्साहित करता है, आपूर्ति को घरेलू बाजार की ओर मोड़ता है, और घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार स्तरों से नीचे दबाता है। ऐसी परिस्थितियों में, सरकार प्रभावी रूप से निजी आपूर्तिकर्ताओं को दबी हुई कीमतों पर घरेलू रूप

से उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए न्यस्त या निर्देशित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं को अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं का प्रावधान होता है।

x. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि निर्यात कर प्रायः कच्चे माल को घरेलू रूप से बनाए रखने, घरेलू कीमतों को स्थिर करने और अनुप्रवाह मूल्य-वर्धित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति ढांचे के साधन होते हैं। वियतनाम में, चूना पत्थर लाइसेंसिंग, अंतिम जांच परिणाम ण नियंत्रण और निर्यात विनियमन के अधीन है, जो सामूहिक रूप से घरेलू आपूर्ति और मूल्य निर्धारण स्थितियों को प्रभावित करते हैं।

xi. जहाँ सरकारी नीति, स्पष्ट या विवक्षित रूप से, कम या स्थिर कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करके घरेलू अनुप्रवाह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित है, प्राधिकारी को यह जांच करना आवश्यक है कि क्या ऐसा हस्तक्षेप ऐसी घरेलू कीमतों में परिणत होता है जो अब प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं, जैसा कि अनुच्छेद 14(घ) के तहत अपेक्षित है।

xii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र पर रखा गया भरोसा कि निर्यात कर कभी भी वित्तीय अंशदान नहीं हो सकते, अनुपयुक्त है। विश्व व्यापार संगठन पैनलों ने निरंतर यह निर्णय दिया है कि सब्सिडी निर्धारण तथ्य-विशिष्ट होते हैं और संबंधित उपायों की अभिकल्पना, संचालन और प्रभावों पर निर्भर करते हैं।

xiii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की अपनी स्थापित प्रथा पर भरोसा किया। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में, प्राधिकारी ने एक अपस्ट्रीम कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंधों की जांच की और निर्णय दिया कि निर्यात शुल्कों और राजकोषीय उपायों ने निर्यातों को हतोत्साहित किया, घरेलू आपूर्ति बढ़ाई, घरेलू कीमतों को दबाया, और अनुप्रवाह उद्योगों को अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं का प्रावधान किया।

xiv. उस जांच में, प्राधिकारी ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि केवल इसलिए कोई सब्सिडी विद्यमान नहीं हो सकती क्योंकि इनपुट निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए थे। प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि निर्यात शुल्कों और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप घरेलू मूल्य निर्धारण को विकृत कर सकता है और आपूर्तिकर्ता की पहचान पर ध्यान दिए बिना लाभ प्रदान कर सकता है।

xv. इसी प्रकार के अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा संतृप्त वसीय अल्कोहल और सतत ढलवाँ तांबे के तार की छड़ों से संबंधित जांचों में दर्ज किए गए, जहाँ अपस्ट्रीम कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंधों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी माना गया।

xvi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि समान कानूनी सिद्धांत वर्तमान जांच में लागू होते हैं। वियतनाम की चूना पत्थर पर निर्यात कर व्यवस्था खनिज संसाधनों को घरेलू रूप से बनाए रखने और अनुप्रवाह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित है, जिससे चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट का घरेलू मूल्य निर्धारण विकृत होता है।

xvii. कुछ पक्षकारों द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि कार्यक्रम उन पर लागू नहीं है क्योंकि वे चूना पत्थर की डलियाँ नहीं खरीदते बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदते हैं, गलत धारणा पर आधारित है।

xviii. आरोप चूना पत्थर की डलियों की प्रत्यक्ष खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि अपस्ट्रीम चूना पत्थर बाजार को प्रभावित करने वाले सरकारी उपायों से उत्पन्न अनुप्रवाह इनपुट बाजार की विकृति से संबंधित है।

xix. कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर से प्राप्त होता है और जांचाधीन उत्पाद के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। पिसा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर चूना पत्थर को पीसकर उत्पादित किया जाता है, विशेष रूप से 98% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री वाले उच्च-शुद्धता वाले चूना पत्थर के भंडारों से, जो वियतनाम में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।

xx. वियतनामी आपूर्तिकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना इस बात की पुष्टि करती है कि पिसा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट व्यावसायिक रूप से "चूना पत्थर पाउडर" के रूप में संदर्भित किया जाता है और चूना पत्थर के भंडारों से उत्पन्न होता है। चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर इसलिए समान खनिज मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और मास्टरबैच क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए कार्यात्मक रूप से समकक्ष इनपुट हैं।

xxi. परिणामस्वरूप, चूना पत्थर की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकारी उपाय तर्कसंगत रूप से चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट की घरेलू आपूर्ति और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं, भले ही उत्पादक कच्चे खनिज के बजाय प्रसंस्कृत प्राप्त खरीदते हों।

xxii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि केवल एचएस वर्गीकरण पर भरोसा सब्सिडी विश्लेषण के लिए निर्धारक नहीं है। एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत प्रासंगिक जांच यह है कि क्या सरकारी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अपर्याप्त पारिश्रमिक पर किसी वस्तु का प्रावधान होता है और लाभ प्रदान करता है, चाहे इनपुट एक शुल्क शीर्ष या दूसरे के तहत खरीदा गया हो।

xxiii. यह प्रस्तुतीकरण कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या सफेद पत्थर से प्राप्त होता है न कि चूना पत्थर से, तकनीकी रूप से गलत है। औद्योगिक और भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, चूना पत्थर मास्टरबैच उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पिसे हुए कैल्शियम कार्बोनेट का प्राथमिक स्रोत है। संगमरमर एक उच्च-मूल्य वाला कायांतरित पत्थर है और बहुलक मास्टरबैच अनुप्रयोगों में भराव के रूप में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से अनुपयुक्त और अलाभकर है।

xxiv. चूना पत्थर-प्राप्त पिसा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच उद्योग में नियंत्रित कण आकार, परिक्षेपण, श्वेतता और बहुलक आधात्री के साथ अनुकूलता के लिए इसकी उपयुक्तता के कारण पसंद किया जाता है। वियतनामी आपूर्तिकर्ता स्वयं पिसे हुए कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादों का विपणन चूना पत्थर-प्राप्त सामग्री के रूप में करते हैं।

xxv. यह तथ्य कि कुछ पक्षकारों के पास चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर में बदलने की सुविधाएं नहीं हैं, अप्रासंगिक है। कथित लाभ वियतनाम में खरीदे गए कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के मूल्य के माध्यम से प्राप्त होता है, और प्रासंगिक जांच यह है कि क्या वह मूल्य प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है या अपस्ट्रीम चूना पत्थर बाजार में सरकारी हस्तक्षेप से विकृत है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि विशिष्टता विद्यमान है क्योंकि कथित लाभ मुख्यतः जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों सहित चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को इनपुट के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों को प्राप्त होता है। विशिष्टता के लिए जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों द्वारा अनन्य उपयोग आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रमुख लाभार्थियों और बाजार संरचना के आधार पर तथ्यतः स्थापित की जा सकती है।

xxvii. घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं द्वारा यूरोपीय संघ – बायोडीजल (डीएस618) में विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट पर रखा गया भरोसा अनुपयुक्त है, क्योंकि रिपोर्ट अपील के अधीन है और विश्व व्यापार संगठन कानून की अंतिम या स्थापित व्याख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी भी स्थिति में, जांच प्राधिकारियों को अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर एससीएम समझौते और

घरेलू कानून को लागू करना आवश्यक है और पैनल तर्क को यांत्रिक रूप से अपनाने के लिए बाध्य नहीं हैं।

xxviii. इसके विपरीत, पूर्ण हो चुकी जांचों में प्राधिकारी के अपने जांच परिणाम, जिनमें डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स और संतृप्त वसीय अल्कोहल शामिल हैं, स्थापित घरेलू प्रथा का गठन करते हैं और वर्तमान मामले से सीधे प्रासंगिक हैं।

xxix. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम में घरेलू कीमतों को पारिश्रमिक की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मानक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी कीमतें सरकारी हस्तक्षेप से विकृत हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ देश के भीतर की कीमतें विकृत हैं, विश्व व्यापार संगठन कानून बाह्य मानक के उपयोग की अनुमति देता है।

xxx. इस प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि मलेशिया से चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट के एफओबी निर्यात मूल्य एक उपयुक्त मानक हैं। मलेशिया उसी क्षेत्र में तुलनीय सामग्री का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, समान भूवैज्ञानिक चूना पत्थर भंडार रखता है, और तुलनीय निर्यात प्रतिबंधों के बिना बाजार-उन्मुख स्थितियों में कार्य करता है।

xxxi. इस कार्यक्रम के तहत लाभ की गणना इसलिए मानक मूल्य और जांच अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद के वियतनामी उत्पादकों द्वारा चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट की खरीद या स्वउपभोग की कीमत के बीच अंतर के रूप में की जानी चाहिए।

xxxii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि अन्य पक्षकारों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की कीमतों पर आधारित प्रस्तावित मानक दोषपूर्ण है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादन मुख्यतः अवसादी चूना पत्थर के बजाय संगमरमर के अपशिष्ट पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप मूलतः भिन्न लागत संरचना और बाजार गतिशीलता है।

xxxiii. इसके विपरीत, मलेशिया में वियतनाम के तुलनीय अवसादी चूना पत्थर के भंडार हैं, चूना पत्थर से उच्च-शुद्धता वाला कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादित करता है, बाजार-उन्मुख स्थितियों में कार्य करता है, और भारत सहित वैश्विक बाजारों को कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रमुख निर्यातक है, विशेष रूप से मास्टरबैच उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। मलेशिया से निर्यात कीमतें इसलिए अविकृत बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं और मानक निर्धारण के लिए उपयुक्त हैं।

xxxiv. मलेशिया का चयन कच्चे माल की समानता, उत्पाद विशेषताओं, प्रसंस्करण चरण, आंकड़ों की उपलब्धता और तुलनीय निर्यात प्रतिबंधों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संदर्भ देश है।

xxxv. यह दावा कि कथित कार्यक्रम कुछ उत्पादकों पर "लागू नहीं" है, अपरिपक्व है और प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं की जांच, इनपुट सोर्सिंग, मूल्य निर्धारण के सत्यापन और इस आकलन के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि घरेलू कीमतें विकृत बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं या नहीं।

<u>प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:</u>

वित्तीय अंशदान

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम सरकार ने डिक्री संख्या 26/2023/एनडी-सीपी के तहत चूना पत्थर पर निर्यात कर लगाया है, जिसकी दरें उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं और जांच अवधि के दौरान 30% तक पहुँच गई हैं।

चूना पत्थर एक प्राकृतिक खनिज संसाधन है, जिसका वियतनाम में अंतिम जांच परिणाम ण और निर्यात लाइसेंसिंग, नियामक पर्यवेक्षण और सरकार द्वारा राजकोषीय नियंत्रण के अधीन है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए प्रमुख अपस्ट्रीम कच्चा माल है, जो बदले में जांचाधीन उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल की खपत का पर्याप्त अनुपात रखता है। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि निर्यात कर स्पष्ट रूप से कच्चे चूना पत्थर के निर्यात को हतोत्साहित करने और खनिज को वियतनाम के भीतर बनाए रखने के लिए अभिकल्पित है।

65. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे निर्यात कर उपाय, पृथक रूप में या खनिज संसाधनों को शासित करने वाले व्यापक नियामक ढांचे के साथ संयोजन में देखे जाने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12 और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क) के अर्थ में वित्तीय अंशदान का गठन कर सकते हैं।

66. जहाँ प्राधिकारी वियतनाम सरकार और कुछ निर्यातकों की इस प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं कि निर्यात कर एक नियामक उपाय है और इसमें निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण या वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रावधान शामिल नहीं है, प्राधिकारी का मानना है कि एससीएम समझौते का अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) यह मान्यता देता है कि वित्तीय अंशदान वहाँ भी विद्यमान हो सकता है जहाँ सरकार, उपायों के एक समूह के माध्यम से, प्रभावी रूप से निजी निकायों से ऐसे कार्य करवाती है जो सामान्यतः सरकार में निहित होते, जिसमें वस्तुओं का प्रावधान शामिल है, जहाँ ऐसा आचरण सामान्य सरकारी प्रथा से सार्थक रूप से भिन्न नहीं होता।

67. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूना पत्थर एक राज्य-नियंत्रित प्राकृतिक संसाधन है और निर्यात कर व्यवस्था ऐसे तरीके से कार्य करती है जो निर्यातों को प्रतिबंधित करती है, आपूर्ति स्थितियों को परिवर्तित करती है, और चूना पत्थर और चूना पत्थर-प्राप्त इनपुटों की घरेलू उपलब्धता और मूल्य निर्धारण को भौतिक रूप से प्रभावित करती है। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि वियतनाम सरकार ने अपनी प्रतिक्रियाओं में स्वीकार किया है कि निर्यात कर का नीतिगत उद्देश्य चूना पत्थर के निर्यातों को विनियमित करना और अनुप्रवाह उद्योगों की दक्षता में सुधार करना है।

68. प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे नियामक और राजकोषीय उपाय, जब संचयी रूप से जांचे जाते हैं, सकारात्मक सरकारी कार्रवाई का गठन करते हैं जो उन स्थितियों को परिवर्तित करती है जिनके तहत घरेलू बाजार में चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है। परिणामी घरेलू आपूर्ति स्थितियाँ केवल मुक्त बाजार शक्तियों का परिणाम नहीं हैं बल्कि निर्यात कराधान और खनिज नीति के रूप में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा आकार दी गई हैं।

69. निर्यात करों जैसे निर्यात प्रतिबंध सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के अर्थ में वित्तीय अंशदान का गठन करते हैं क्योंकि वे निधियों का अप्रत्यक्ष अंतरण हैं। यह स्थिति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न उत्पादों से संबंधित जांचों में पुष्ट की गई है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से "संतृप्त वसीय अल्कोहल" और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "सतत ढलवाँ तांबे की तार की छड़ें", चीन और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स"।

70. इस तर्क के संबंध में कि खरीद निजी आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है, न कि सरकार से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम सरकार अपने नियामक तंत्र के माध्यम से, विशेष रूप से वियतनाम सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों, जैसे 30% निर्यात शुल्क, के माध्यम से निजी निकायों पर अपना प्राधिकार प्रयोग करती है, ताकि उन्हें अनुप्रवाह उद्योगों को सस्ती कीमत पर चूना पत्थर प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सके। चूना पत्थर के लिए घरेलू कीमतों को कृत्रिम रूप से दबाकर, ये उपाय वियतनाम में चूना पत्थर के बाजार को महत्वपूर्ण रूप से विकृत करते हैं और जांचाधीन उत्पाद के अनुप्रवाह निर्माताओं को अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, निजी आपूर्तिकर्ता भी इन राज्य-समर्थित उपायों से लाभान्वित होते हैं।

71. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वियतनाम में चूना पत्थर को शासित करने वाला निर्यात कर और नियामक ढांचा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के साथ पठित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12 और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के अर्थ में वियतनाम सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान का गठन करता है, क्योंकि सरकार, अपने उपायों के माध्यम से, घरेलू बाजार में अनुप्रवाह उद्योगों को एक प्रमुख कच्चे माल के प्रावधान को प्रभावी रूप से प्रभावित करती है।

लाभ

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(ख) और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 12 के अनुसार, सब्सिडी केवल तभी विद्यमान होती है जब कोई वित्तीय अंशदान प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है। एससीएम समझौते का अनुच्छेद 14(घ) प्रावधान करता है कि, जहाँ सरकार द्वारा या उसके हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं, पारिश्रमिक की पर्याप्तता प्रावधान वाले देश में प्रचलित बाजार स्थितियों के संबंध में निर्धारित की जाएगी।

73. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऊपर चिह्नित वित्तीय अंशदान के परिणामस्वरूप चूना पत्थर या चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों को अविकृत बाजार स्थितियों के तहत प्रचलित पारिश्रमिक से नीचे उपलब्ध कराया गया है।

74. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क पर ध्यान देते हैं कि निर्यात कर चूना पत्थर के निर्यातों को हतोत्साहित करता है, घरेलू उपलब्धता बढ़ाता है, और चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट की घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय स्तरों से नीचे दबाता है। प्राधिकारी निर्यातकों की इस प्रस्तुति पर भी ध्यान देते हैं कि कुछ उत्पादक निजी आपूर्तिकर्ताओं से कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदते हैं, एचएस कोड भिन्न हैं, और कोई प्रत्यक्ष सरकारी मूल्य नियंत्रण विद्यमान नहीं है।

75. प्राधिकारी का मानना है कि अनुच्छेद 14(घ) के तहत प्रासंगिक जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की आपूर्ति करती है या नहीं, बल्कि यह है कि प्रासंगिक इनपुट के लिए भुगतान की गई कीमत प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती है या नहीं। प्राधिकारी आगे मानते हैं कि निजी आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट खरीदना लाभ के अंतिम जांच परिणाम को बाधित नहीं करता जहाँ घरेलू कीमतें स्वयं अपस्ट्रीम सरकारी हस्तक्षेप के कारण विकृत हैं।

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट व्यावसायिक रूप से "चूना पत्थर पाउडर" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो औद्योगिक रूप से चूना पत्थर से प्राप्त है और चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट बाजार आर्थिक रूप से एकीकृत हैं। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि केवल एचएस वर्गीकरण पर आधारित भेद एससीएम समझौते के तहत लाभ विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए अपस्ट्रीम-अनुप्रवाह संबंध को नकारते नहीं हैं।

77. प्राधिकारी पाते हैं कि निर्यात कर व्यवस्था, चूना पत्थर के निर्यातों को प्रतिबंधित करके, सामान्य आपूर्ति-मांग संतुलन को परिवर्तित करती है और ऐसी घरेलू कीमतों में परिणत होती है जो अविकृत बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं। परिणामस्वरूप, चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करने वाले अनुप्रवाह उत्पादक इस इनपुट तक सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर पहुँच प्राप्त करते हैं।

78. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वियतनाम सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों पर लाभ प्रदान करता है, क्योंकि चूना पत्थर-प्राप्त इनपुट एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(घ) और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12(2)(घ) के अर्थ में अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

विशिष्टता

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, सब्सिडी केवल तभी प्रतिसंतुलनकारी होती है जब वह किसी उद्यम, उद्योग या उद्यमों या उद्योगों के समूह के लिए विधितः या तथ्यतः विशिष्ट हो।

80. प्राधिकारी ने निर्यातकों की इस प्रस्तुति की जांच की है कि चूना पत्थर अनेक उद्योगों में उपयोग किया जाता है और इसलिए उपाय में विशिष्टता का अभाव है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशिष्टता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं का उपयोग संबद्ध उद्योग द्वारा अनन्य रूप से किया जाए, बल्कि इसकी जांच आवश्यक है कि क्या लाभ मुख्यतः कुछ उद्योगों को प्राप्त होता है या व्यवहार में सीमित है।

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूना पत्थर और चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच उत्पादकों सहित अनुप्रवाह उद्योगों के एक परिभाषित समूह के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि वियतनाम की निर्यात कर व्यवस्था का नीतिगत उद्देश्य खनिज संसाधनों को घरेलू रूप से बनाए रखना और अनुप्रवाह मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है, जो अंतर्निहित रूप से चूना पत्थर/कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमुख इनपुट के रूप में उपभोग करने वाले उद्योगों का पक्ष लेता है।

82. प्राधिकारी का मानना है कि चूना पत्थर/कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर न रहने वाले उद्योग निर्यात कर व्यवस्था से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते, जबकि चूना पत्थर/चूना पत्थर-प्राप्त इनपुटों का उपयोग करने वाले उद्योग बढ़ी हुई घरेलू उपलब्धता और ह्रासमान कीमतों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। इसलिए लाभ व्यवहार में उन उद्योगों के समूह तक सीमित है जो चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं।

83. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर के प्रावधान से उत्पन्न सब्सिडी एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अर्थ में, जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों सहित चूना पत्थर-प्राप्त इनपुटों का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए विशिष्ट है।

मानक

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(घ) और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12(2)(घ) के तहत लाभ के निर्धारण के लिए, पारिश्रमिक की पर्याप्तता का आकलन प्रावधान वाले देश में प्रश्नगत वस्तुओं के लिए प्रचलित बाजार स्थितियों के संबंध में किया जाना चाहिए। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि जहाँ सरकारी हस्तक्षेप के कारण देश के भीतर की कीमतें विकृत हैं, तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समायोजनों के अधीन, एक बाह्य मानक का उपयोग किया जा सकता है।

85. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वियतनाम में चूना पत्थर और चूना पत्थर-प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट की घरेलू कीमतें उपयुक्त मानक नहीं हैं, क्योंकि चूना पत्थर पर निर्यात कर व्यवस्था निर्यातों को हतोत्साहित करती है और घरेलू मांग-आपूर्ति संतुलन को परिवर्तित करती है। घरेलू उद्योग ने इसलिए मलेशिया से कैल्शियम कार्बोनेट के एफओबी निर्यात मूल्यों पर आधारित एक बाह्य मानक प्रस्तावित किया है, यह दावा करते हुए कि मलेशिया उसी क्षेत्र के भीतर एक निकटस्थ, तुलनीय आपूर्तिकर्ता है और इसकी कीमतें अविकृत बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं।

86. प्राधिकारी उत्पादकों/निर्यातकों और कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों की घरेलू उद्योग के प्रस्तावित मानक का विरोध करने वाली अनुरोधों पर नोट करते हैं, इस आधार पर कि निर्यात कर केवल चूना पत्थर पर लागू होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर पर नहीं; 4-अंकीय एचएस स्तर पर मलेशिया का आंकड़ा विभिन्न पत्थर उत्पादों को मिलाता है, जिससे तुलनीयता कम होती है; मलेशियाई मूल्य आंकड़ों में चरम बाह्य बिंदु शामिल हैं; और घरेलू उद्योग ने वास्तव में वियतनाम की घरेलू कीमतों में विकृति नहीं दिखाई है। वे चूना पत्थर की डलियों (मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात से) के भारतीय आयात मूल्यों पर आधारित एक वैकल्पिक मानक भी प्रस्तावित करते हैं, जिसे एफओबी मूल्य प्राप्त करने के लिए समायोजित किया गया है।

87. प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा की गई अनुरोधों की जांच की है और पाते हैं कि मानक निर्धारण अभ्यास निम्नलिखित की पहचान करके किया जाना चाहिए:

i. प्रासंगिक "वस्तु" जिसके पारिश्रमिक का आकलन अनुच्छेद 14(घ) के तहत किया जाना है;

ii. क्या वियतनाम में उस वस्तु की घरेलू कीमतें प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं; और

iii. यदि नहीं, तो कौन सा बाह्य मानक उपयुक्त समायोजनों के बाद, प्रासंगिक वस्तु के लिए अविकृत प्रचलित बाजार स्थितियों को सबसे अधिक तर्कसंगत रूप से प्रतिबिंबित करता है।

88. यद्यपि कार्यक्रम "अपर्याप्त पारिश्रमिक पर चूना पत्थर की आपूर्ति" के रूप में वर्णित है, प्राधिकारी यह मान्यता देते हैं कि संबद्ध उत्पाद का अनुप्रवाह निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर का उपयोग करता है, जो स्वयं चूना पत्थर या समान चूनेदार फीडस्टॉक से उत्पादित होता है।

89. प्राधिकारी यह भी ध्यान देते हैं कि वियतनाम का चूना पत्थर पर निर्यात कर पर्याप्त और बढ़ता हुआ है, और इसका उद्देश्य निर्यातों को विनियमित करना और अनुप्रवाह प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इसके आधार पर, प्राधिकारी चूना पत्थर-प्राप्त इनपुटों के लिए वियतनामी घरेलू कीमतों को सावधानी से लेना और बाह्य मानकों पर विचार करना तर्कसंगत पाते हैं।

90. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के प्रस्तावित मलेशियाई मानक का मूल्यांकन करते हैं, तुलनीय उच्च-शुद्धता वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ता के रूप में मलेशिया की भूमिका पर ध्यान देते हुए, जिसका जांच अवधि के दौरान भारत को सर्वाधिक निर्यात रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग भी जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए मलेशिया से कैल्शियम कार्बोनेट खरीद रहा है।

91. प्राधिकारी यह पाते हैं कि भाग लेने वाले निर्यातक चूना पत्थर की डलियों के बजाय सीधे कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदते हैं, इसलिए, मानक को यह आकलन करना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के लिए पारिश्रमिक पर्याप्त है या नहीं।

92. प्राधिकारी यह पाते हैं कि चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट का एचएस अध्याय अंतर नामपद्धति या प्रसंस्करण स्तरों को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन रासायनिक पहचान (कैल्शियम कार्बोनेट) या सब्सिडी विश्लेषण को परिवर्तित नहीं करता। प्राधिकारी संयुक्त अरब अमीरात से चूना पत्थर की डलियों के भारतीय आयात मूल्यों पर आधारित निर्यातकों के प्रस्तावित मानक की भी जांच करते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि जांचाधीन उत्पाद उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 98% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री वाले, महीन कण आकार के उच्च-शुद्धता वाले चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात से चूना पत्थर का आयात मुख्यतः इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है न कि जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों द्वारा। इसके अलावा, निर्यातकों का मानक केवल चूना पत्थर की डलियों पर केंद्रित है लेकिन डलियों को कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर में बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रसंस्करण का हिसाब नहीं रखता। उपयुक्त प्रसंस्करण समायोजनों और प्रत्येक लागत कटौती का समर्थन करने वाले सत्यापन योग्य साक्ष्य के बिना, निर्यातकों का मानक जांचाधीन उत्पाद उत्पादकों द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक इनपुट के वास्तविक आर्थिक मूल्य को कम करके आंक सकता है।

93. इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि एक ऐसा मानक दृष्टिकोण जो विशेष रूप से जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट/चूना पत्थर-प्राप्त औद्योगिक इनपुटों के सक्रिय निर्यात वाले तुलनात्मक बाजार पर निर्भर करता है, और जो तुलनीय मूल्य आधार पर रूपांतरण को सक्षम बनाता है, अनुच्छेद 14(घ) के प्रयोजनों के लिए अधिक उपयुक्त है।

94. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मानक आंकड़ों (व्यापार मानचित्र) की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई निम्नलिखित अनुरोधों पर विचार किया है:

क) आवेदकों द्वारा मानक के रूप में प्रस्तावित मलेशिया एफओबी निर्यात मूल्य 4-अंकीय एचएस कोड स्तर पर वर्गीकृत हैं, जिसमें अन्य विषम उत्पाद शामिल हैं।

ख) आवेदकों द्वारा प्रस्तावित एफओबी मूल्य लगभग 28 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लेकर 51,43,672 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है

कि आंकड़ों में एक व्यापक, विषम उत्पाद समूह शामिल है जो न तो समरूप है और न ही संबद्ध वस्तुओं से प्रासंगिक सामग्री से पर्याप्त रूप से तुलनीय है।

ग) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा द्वितीयक स्रोत से आठ-अंक स्तर पर प्राप्त आयात आंकड़ों, वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आयात आंकड़ों और आवेदक उद्योग द्वारा दायर व्यापार मानचित्र आंकड़ों का तुलनात्मक सारांश दर्शाता है कि चूना पत्थर की डली और कैल्शियम कार्बोनेट सहित वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट किए गए कच्चे/अचयनित आयात आंकड़े उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत कच्चे/ अचयनित आयात आंकड़ों के तुलनीय हैं। प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं (देशों) का औसत मूल्य भी उसी सीमा में है।

घ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित आंकड़े 8-अंक स्तर पर हैं जबकि आवेदकों द्वारा प्रारंभ में प्रस्तावित आंकड़ा 4-अंक स्तर पर था और इसमें चूना पत्थर, चूना पत्थर प्रवाह और चूना या सीमेंट के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ उपयोग किए जाने वाले अन्य चूनेदार पत्थर शामिल थे।

ङ) तत्पश्चात, आवेदक ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से निकाले गए मलेशिया से भारत को कैल्शियम कार्बोनेट के आयात से संबंधित एचएसएन कोड 28365000 के 8 अंक स्तर के आंकड़े सीआईएफ आधार पर प्रस्तुत किए। एफओबी आधार पर मानक दर पर पहुंचने के लिए इसमें आवश्यक उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

च) घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित प्रदान किए गए आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से पूर्णतः पुष्ट हो चुके हैं।

95. तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रारंभ में अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत उपयुक्त मानक के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आठ अंकीय स्तर के डेटा के आधार पर मुक्त पोत बंदरगाह आधार पर भारत को $CaCO_3$ के मलेशियाई निर्यात मूल्य को अपनाने का प्रस्ताव किया और परिणामी लाभ की मात्रा सत्यापित जानकारी के आधार पर प्रतिक्रियाकर्ता निर्यातकों के लिए निर्धारित की गई है।

96. हालाँकि, प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों के दृष्टिगत, जिनमें अन्य इच्छुक पक्षों ने मिस्र से भारत में आयात की अधिक मात्रा के कारण भारत में मिस्र से आयात मूल्यों को उपयुक्त बाह्य मानक के रूप में अपनाने का अनुरोध किया, और दूसरी ओर घरेलू उद्योग का प्रशुल्क मद 28365000 के अंतर्गत केवल भारत में मलेशियाई आयात मूल्यों को उपयुक्त मानक के रूप में विचार करने पर बल दिया, प्राधिकरण ने बाह्य मानक के विचार के संबंध में इन परस्पर विरोधी दावों की विशेष रूप से जांच की। भागीदारी करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने मिस्र के पर्याप्त उत्पादन और निर्यात, भारतीय आयात में उसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, घरेलू उद्योग की स्वयं की मिस्र से खरीद और मिस्री कीमतों की वाणिज्यिक प्रासंगिकता पर निर्भरता जताई। घरेलू उद्योग ने प्रशुल्क मद 28365000 के अंतर्गत उत्पाद-विशिष्ट और मिलान योग्य मलेशियाई डेटा पर निर्भरता जताई। पुनर्विचार पर, प्राधिकरण ने पाया कि दोनों देशों ने जांच अवधि के दौरान भारत को प्रासंगिक कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति की और किसी भी स्रोत को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरे के पास अधिक मात्रा या अधिक विस्तृत लेनदेन डेटा था।

97. प्राधिकरण ने नियम 12(2)(घ), अनुलग्नक चार और सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 14(घ) के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मानक की पुनः जांच की है, जिसमें पारिश्रमिक की पर्याप्तता का मूल्यांकन प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर करने की आवश्यकता है, जिसमें मूल्य, गुणवत्ता, उपलब्धता,

विपणन योग्यता, परिवहन और बिक्री की अन्य शर्तें शामिल हैं। इसलिए मानक चयन न्यूनतम मूल्य, निकटतम स्रोत, सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता या किसी भी पक्ष के लिए सबसे अनुकूल परिणाम द्वारा शासित नहीं होता। नियंत्रक परीक्षण यह है कि मानक विश्वसनीय, प्रतिनिधिक, तुलनीय और समान आधार पर लाभ को मापने में सक्षम हो।

98. मिस्र ने भारत में कैल्शियम कार्बोनेट के भौतिक रूप से अधिक आयात मात्रा का प्रतिनिधित्व किया और घरेलू उद्योग द्वारा इसके उपयोग ने औद्योगिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक उपलब्धता की पुष्टि की। हालाँकि, मलेशिया ने अधिक विस्तृत उत्पाद-विशिष्ट लेनदेन डेटा और विवरण, मूल्य विक्षेपण और शिपमेंट स्थितियों पर उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसलिए, प्राधिकरण ने कार्यक्रम संख्या 1 के प्रयोजन के लिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से निकाले गए मिस्र और मलेशिया दोनों स्रोतों से भारत के आयात मूल्यों को, जिन्हें यथोचित रूप से मुक्त पोत बंदरगाह स्तर पर समायोजित किया गया है, अर्थात् मिस्र के साथ-साथ मलेशिया से भारत के आयात मूल्यों के भारित औसत बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्य को एक उपयुक्त बाह्य मानक के रूप में माना है। प्राधिकरण ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से निकाले गए जांच अवधि में मिस्र और मलेशिया से भारत में बीमा एवं भाड़ा सहित लागत स्तर पर 8 अंकीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली संख्या कोड के वास्तविक आयातों पर निर्भरता जताई है, जिसे यथोचित रूप से मुक्त पोत बंदरगाह स्तर पर समायोजित किया गया है।

99. मानक की गणना प्रत्येक देश के समायोजित मूल्य को उसकी संगत पात्र आयात मात्रा से भारित करके की गई । यह पद्धति परस्पर विरोधी दावों के बीच एक समानतापूर्ण समझौता नहीं है; यह अभिलेख पर उपलब्ध प्रचलित बाजार पारिश्रमिक का सबसे प्रतिनिधिक और कानूनी रूप से समर्थनीय माप है। यह मिस्र की अधिक वाणिज्यिक उपस्थिति को मान्यता देता है, मलेशियाई उत्पाद-विशिष्ट डेटा की विश्वसनीयता को संरक्षित करता है, स्रोत-विशिष्ट विकृति को न्यूनतम करता है और अंतिम प्राप्तकर्ता-विशिष्ट लाभ तथा सब्सिडी अंतर गणनाओं के लिए एक संतुलित, वस्तुनिष्ठ और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। श्रेणी, कण आकार, शुद्धता, लेपन, श्वेतता, प्रसंस्करण मार्ग, अंतिम उपयोग और प्रशुल्क वर्गीकरण से संबंधित आपत्तियों की दोनों देशों के लिए यथोचित रूप से जांच की गई।

100. यह नोट किया जाता है कि मलेशियाई बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्यों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए समसामयिक, मार्ग-विशिष्ट और उत्पाद-प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्यापित भाड़े और बीमा मूल्यों को घटाकर मुक्त पोत बंदरगाह-समतुल्य आधार पर परिवर्तित किया गया है, जबकि मिस्री बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्यों को प्रतिवादियों या उत्पादक-निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए समसामयिक, मार्ग-विशिष्ट और उत्पाद-प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्यापित भाड़े और बीमा मूल्यों को घटाकर मुक्त पोत बंदरगाह-समतुल्य आधार पर परिवर्तित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि मानक आगत के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित करे और उत्पाद विशेषताओं, शिपमेंट शर्तों या व्यापार के स्तर में अंतर से विकृत न हो।

101. समग्र मानक को किसी एक देश के अनन्य उपयोग की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रतिनिधिक माना जाता है। केवल मिस्र पर अनन्य निर्भरता विस्तृत मलेशियाई लेनदेन साक्ष्य की अनदेखी करेगी, जबकि केवल मलेशिया पर अनन्य निर्भरता मिस्र से तुलनीय आयात की अधिक मात्रा के महत्व को कम आँकेगी। उत्पाद दायरे और वाणिज्यिक शर्तों के सामंजस्य के पश्चात संयुक्त श्रृंखला, प्रचलित बाजार स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करती है।

102. इस पद्धति का कानूनी आधार नियम 12 और अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत प्रतिनिधित्वता, तुलनीयता और प्रचलित बाजार स्थितियाँ हैं। यद्यपि यह आनुषंगिक रूप से निर्यातकों और घरेलू उद्योग की परस्पर विरोधी चिंताओं को संतुलित करता है, तथापि इसे इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यह एक व्यापक और अधिक विश्वसनीय बाह्य बाजार संदर्भ आधारित मानक प्रदान करता है।

103. भारित मानक केवल उन उत्पादकों पर लागू किया जाता है जिन्होंने जांच अवधि के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट की खरीद या खपत की। इसकी तुलना प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के सत्यापित खरीद मूल्य से समान आधार पर की जाती है, जिसमें भाड़े, बीमा, बंदरगाह प्रबंधन, व्यापार स्तर और खरीद की अन्य शर्तों के लिए समायोजन किया जाता है। कंपनी-विशिष्ट लाभ गणनाएँ गोपनीय गणना पत्रकों में निहित हैं।

104. विशिष्टता की पुष्टि की गई क्योंकि पहचाना गया खनिज-आगत ढाँचा प्रभावित चूना पत्थर और चूना पत्थर से व्युत्पन्न आगत पर निर्भर अनुप्रवाह उद्यमों के एक सीमित समूह को लाभान्वित करता है। यह तथ्य कि इन खनिजों के अन्य उपयोग हो सकते हैं, विशिष्टता को नकारता नहीं है जहाँ कार्यक्रम का डिजाइन और संचालन तथा जांचे गए उत्पादकों को लाभ स्थापित हो।

105. तदनुसार, कार्यक्रम 1 प्रतिकारी योग्य बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट की खरीद के लिए, अंतिम उत्पादक-विशिष्ट सब्सिडी गणनाएँ मिस्र और मलेशिया से समायोजित तुलनीय जांच अवधि आयात मूल्यों के मात्रा-भारित औसत का उपयोग करेंगी। सब्सिडी अंतरों में परिणामी संशोधन किए जाएंगे।

सब्सिडी मार्जिन

106. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्राधिकारी ने लाभ को ऊपर निर्धारित मानक मूल्य और जांच अवधि के दौरान उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट की खरीद की कीमत के बीच अंतर के रूप में परिमाणित किया है।

107. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं, वियतनाम व्यापार उपचार प्राधिकारी के माध्यम से वियतनाम सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना, और घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर रखे गए मानक आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्तरदाता निर्यातक के लिए इस कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी सब्सिडी राशि की गणना की है, जिसे शुद्ध प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी अंतर में शामिल किया गया है।

योजना 12 - अपर्याप्त पारिश्रमिक पर विद्युत खपत के लिए प्राकृतिक गैस/बिजली/कोयले की आपूर्ति

108. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:</u>

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयला वियतनामी प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्रदान किए जाते हैं, इस आधार पर कि सरकार-निर्धारित कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों से कम

हैं, जिससे प्राप्तकर्ता उद्यमों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई लाभ प्राप्त करने से इनकार किया।

ii. यह प्रस्तुत किया गया कि वियतनाम में उत्पादक विद्युत उत्पादन या अपने विनिर्माण कार्यों के लिए प्राकृतिक गैस या कोयले का उपयोग नहीं करते। तदनुसार, अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृतिक गैस या कोयले के प्रावधान से संबंधित आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत और उन पर लागू नहीं होने वाला बताया गया है।

iii. बिजली के संबंध में, पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि बिजली निजी वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के माध्यम से खरीदी जाती है और वियतनाम सरकार द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि बिजली विधिवत निष्पादित समझौतों के अनुसार निजी संस्थाओं से खरीदी जाती है, और ऐसी खरीद को प्रमाणित करने वाले मासिक बिजली बिल प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं।

iv. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि जल जैसी उपयोगिताएँ वाणिज्यिक शर्तों पर निजी संस्थाओं से खरीदी जाती हैं। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि बिजली और उपयोगिताएँ किसी कथित सरकारी कार्यक्रम के बजाय निजी अनुबंधों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

v. पक्षकारों ने तर्क दिया कि वियतनाम में बिजली की कीमतें विकृत नहीं हैं और प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने, जहाँ तक लागू हो, चूना पत्थर के अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्रदान किए जाने के आरोप के संबंध में की गई अपनी अनुरोधों को दोहराया, और प्रस्तुत किया कि कीमतों का विनियमन, अपने आप में, किसी उपाय को एससीएम समझौते या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत कार्रवाई योग्य नहीं बनाता।

vi. पक्षकारों ने वियतनाम से एल्यूमीनियम जिंक लेपित इस्पात के आयात से संबंधित सब्सिडी रोधी जांच में ऑस्ट्रेलियाई पाटन रोधी आयोग के जांच परिणामों पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयोग ने, विश्व बैंक के आंकड़ों के संदर्भ में वियतनाम में बिजली मूल्य निर्धारण की जांच करने के बाद, अंतिम जांच परिणाम निकाला कि वियतनामी बिजली बाजार में कोई महत्वपूर्ण लागत विकृतियाँ नहीं थीं और वियतनाम में बिजली की कीमतें कई अन्य देशों की कीमतों के तुलनीय या उनसे अधिक थीं।

vii. पक्षकारों ने इस बात पर जोर दिया कि, यद्यपि वियतनाम सरकार बिजली मूल्य निर्धारण को विनियमित करती है और विभिन्न शुल्क श्रेणियाँ जैसे विनिर्माण, प्रशासनिक/सरकारी, व्यापारिक और घरेलू निर्धारित करती है, प्रत्येक श्रेणी के भीतर सभी संस्थाओं से एकसमान और सार्वजनिक रूप से अधिसूचित दरें वसूल की जाती हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा वर्गीकरण भारत सहित विभिन्न अधिकारिताओं में सामान्य है, और लक्षित लाभ, अधिमान्य उपचार या विशिष्टता को नहीं दर्शाता।

viii. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह दिखाने के लिए कोई उद्यम-विशिष्ट या उद्योग-विशिष्ट साक्ष्य अभिलेख पर रखने में विफल रहा है कि उत्तरदाताओं ने वियतनाम में अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों से भिन्न कीमतों पर बिजली, प्राकृतिक गैस या कोयला प्राप्त किया, या कोई अधिमान्य शुल्क, छूट, बट्टा या वित्तीय लाभ उन्हें दिया गया।

ix. पक्षकारों ने तर्क दिया कि उपयोगिताओं का सरकारी विनियमन स्वतः अपर्याप्त पारिश्रमिक या सब्सिडीकरण नहीं दर्शाता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिजली और गैस क्षेत्र अपने

सार्वजनिक उपयोगिता स्वरूप के कारण दुनिया भर में विनियमित हैं, और ग्रिड स्थिरता, सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए विनियमन यह स्थापित नहीं करता कि कीमतें बाजार मानकों से कम हैं या सब्सिडी विद्यमान है।

x. पक्षकारों ने फाइबरबोर्ड जांच सहित पूर्ववर्ती महानिदेशालय जांच परिणामों पर आवेदक के भरोसे पर विवाद किया और प्रस्तुत किया कि ऐसा भरोसा अनुपयुक्त है। उन्होंने तर्क दिया कि वे अंतिम जांच परिणाम उन जांचों में विशिष्ट तथ्यात्मक अभिलेख पर आधारित थे, जबकि वर्तमान मामले में पूर्ण शुल्क अनुसूचियाँ, प्रपत्र, बिल और सरकारी अधिसूचनाएँ प्रदान की गई हैं, जिससे विकृति का अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं बचता।

xi. पक्षकारों ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानकों को भी चुनौती दी, जिसमें ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज या मलेशिया में प्रचलित कीमतों पर भरोसा शामिल है, इस आधार पर कि ऐसे स्रोत खुदरा या उपभोक्ता-स्तरीय कीमतों को प्रतिबिंबित करते हैं, औद्योगिक शुल्कों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और ईंधन मिश्रण, पारेषण और वितरण लागत, सब्सिडी ढाँचों और जलवायु स्थितियों जैसे देश-विशिष्ट कारकों का हिसाब नहीं रखते।

xii. प्राकृतिक गैस के संबंध में, पक्षकारों ने दोहराया कि वे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं करते। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक गैस के उपयोग के संबंध में आरोप काल्पनिक है और अभिलेख पर किसी दस्तावेजी या तकनीकी साक्ष्य से असमर्थित है।

xiii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि डिक्री 87/2018 के तहत उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण सुरक्षा, लाइसेंसिंग और तकनीकी मानकों से संबंधित है, न कि मूल्य निर्धारण से। उन्होंने तर्क दिया कि वियतनाम में प्राकृतिक गैस की कीमतें वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं और प्लैट्स, सीपी या एफओबी कीमतों जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर उतार-चढ़ाव करती हैं।

xiv. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि जहाँ प्राकृतिक गैस खरीदी जाती है, वह मूल्य भिन्नता खंडों वाले बाजार-आधारित वाणिज्यिक अनुबंधों के तहत निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती है, और प्रपत्र तथा भुगतान अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि कोई रियायत, सब्सिडी या अपर्याप्त पारिश्रमिक विद्यमान नहीं है।

xv. यह भी प्रस्तुत किया गया कि बिना स्वीकार किए, केवल तर्क के लिए यह मानते हुए भी कि बिजली या गैस भिन्न मूल्य पर आपूर्ति की गई, विशिष्टता के अभाव में आरोप फिर भी विफल होगा। उत्तरदाताओं के अनुसार, शुल्क वियतनाम में सभी औद्योगिक उपयोगकर्ताओं पर एकसमान रूप से लागू होते हैं, बिना किसी उद्यम-विशिष्ट, क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्रीय या सशर्त वरीयता के, जिससे एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत विशिष्टता की आवश्यकताएँ विफल हो जाती हैं।

xvi. वियतनाम सरकार प्रस्तुत करती है कि किसी बाजार में सरकारी संलिप्तता स्वतः मूल्य विकृति स्थापित नहीं करती और महानिदेशालय ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि देश के भीतर की कीमतें उपयुक्त मानक के रूप में कार्य क्यों नहीं कर सकतीं। वियतनाम सरकार आगे प्रस्तुत करती है कि महानिदेशालय ने पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया है कि चयनित बाह्य मानक गुणवत्ता, परिवहन, उपलब्धता और बिक्री की अन्य शर्तों से संबंधित समायोजनों के माध्यम से वियतनाम में प्रचलित बाजार स्थितियों को उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

xvii. यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, न्घे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। मलेशियाई बिजली कीमतों पर भरोसा कानूनी रूप से अस्थिर है, क्योंकि सिद्ध विकृति के अभाव में वियतनाम में घरेलू कीमतों का उपयोग किया जाना चाहिए।

xviii. वीएमआई ने प्रस्तुत किया कि बिजली बाजार-निर्धारित वाणिज्यिक दरों पर निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई थी, न कि सरकारी स्वामित्व वाली उपयोगिताओं से। वीएमआई ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने वीएमआई के सत्यापित बिजली अनुबंधों और प्रपत्रों का कंपनी-विशिष्ट विश्लेषण किए बिना अनुचित रूप से वियतनाम के बिजली बाजार में विकृति का अनुमान लगाया। वीएमआई ने मानक के रूप में ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज से मलेशियाई बिजली कीमतों के उपयोग को भी चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि मलेशिया की ऊर्जा बाजार संरचना, सब्सिडी व्यवस्था और उपभोक्ता शुल्क आंकड़े वियतनाम की औद्योगिक बिजली बाजार स्थितियों से तुलनीय नहीं थे।

xix. वीटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी प्रस्तुत करती है कि वह विधिवत निष्पादित बिजली आपूर्ति समझौतों के अनुसार निजी वाणिज्यिक संस्थाओं से बिजली खरीदती है, वीटाप्लास द्वारा भुगतान किए जाने वाले बिजली शुल्क वियतनाम में सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू सार्वजनिक रूप से अधिसूचित शुल्क अनुसूचियों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वीटाप्लास ने अधिमान्य दरों, रियायती शर्तों, या बाजार से कम कीमतों पर बिजली प्राप्त की है।

xx. बिजली एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है जो पारेषण और वितरण नेटवर्कों में प्राकृतिक एकाधिकार विशेषताओं द्वारा चित्रित है। भारत सहित वस्तुतः सभी देश, ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने, एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग को रोकने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने, उपयोगिताओं के लिए लागत वसूली सुनिश्चित करने और कुशल संसाधन आवंटन को बढ़ावा देने के लिए बिजली शुल्कों को विनियमित करते हैं। ऐसा विनियमन सरकार का एक सामान्य और आवश्यक कार्य है और यह, अपने आप में, एससीएम समझौते के अर्थ में वित्तीय अंशदान का गठन या लाभ प्रदान नहीं करता।

xxi. एडीसी बिजली और अन्य उपयोगिताएँ वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के तहत स्वतंत्र आपूर्तिकर्ताओं से खरीदती है। ऐसी खरीद बाजार-आधारित आधार पर और प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है, बिना ऐसी उपयोगिताओं के प्रावधान में वियतनाम सरकार की किसी संलिप्तता के। प्राधिकारी ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं पहचाना है जहाँ वियतनाम सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता को बिजली, प्राकृतिक गैस, कोयला, या कोई अन्य उपयोगिता प्रदान की हो। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क) के तहत वित्तीय अंशदान की आवश्यक अनिवार्यता संतुष्ट नहीं होती।

xxii. उत्तरदाता आगे प्रस्तुत करता है कि ऊर्जा क्षेत्र में नियामक पर्यवेक्षण या राज्य की भागीदारी का मात्र अस्तित्व यह अर्थ नहीं रखता कि अर्थव्यवस्था के भीतर आपूर्ति की जाने वाली सभी उपयोगिताएँ सरकार द्वारा या पाटित दरों पर प्रदान की जाती हैं। प्राधिकारी को सरकार और उत्तरदाता को वस्तुओं के प्रावधान के बीच सीधा संबंध स्थापित करना आवश्यक है, जो नहीं किया गया है।

xxiii. उत्तरदाता ने बिजली कीमतों पर कोई अपर्याप्त पारिश्रमिक लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्रकटीकरण विवरण में किया गया प्रस्ताव कि "प्राधिकारी, अभिलेख पर रखे गए नियामक/शुल्क-निर्धारण ढांचे और उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के माध्यम से वियतनाम सरकार की भूमिका के आधार पर, यह पाते हैं कि एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अर्थ में बिजली के प्रावधान के संबंध में वित्तीय अंशदान विद्यमान है।" पूर्णतः गलत, भ्रामक है और इसलिए, अस्वीकृत किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि वियतनाम सरकार ने निर्माताओं को निम्नलिखित में से किसी भी रूप में कोई लाभ प्रदान किया है:

(i) जांचाधीन वस्तुओं के निर्माताओं को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण;

(ii) राजस्व का त्याग या गैर-संग्रहण अर्थात बिजली प्रभारों की पूर्ण या आंशिक छूट;

xxiv. प्राधिकारी ने निरंतर विश्लेषण किया है कि क्या संबंधित सरकार द्वारा जांचाधीन वस्तुओं के निर्माताओं को सामान्य दरों की तुलना में बिजली शुल्क पर कोई छूट/बट्टा/उन्मोचन प्रदान किया जाता है। यदि हाँ, तो इसे जांचाधीन वस्तुओं के निर्माताओं को प्रदान की गई छूट/बट्टे/उन्मोचन की सीमा तक सब्सिडी माना गया है।

xxv. प्राधिकारी ने हाल की जांचों में बिजली पर अपर्याप्त पारिश्रमिक नहीं पाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी हाल के जांच परिणामों से इस दावे की क्रॉस-चेक कर सकते हैं। प्राधिकारी के सुगम संदर्भ के लिए जांचों की उदाहरणात्मक सूची नीचे प्रदान की गई है:

क) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 7/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 15 जून, 2024]

ख) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 6/22/2018-डीजीएडी दिनांक 31 जुलाई, 2019]

ग) वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास [फा.सं. 6/32/2023-डीजीटीआर दिनांक 11 फरवरी, 2025]

xxvi. आश्चर्यजनक रूप से, इस जांच में सब्सिडीकरण के एक गैर-मौजूद मामले को सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग की भ्रामक अनुरोधों के आधार पर एक तुलनाहीन मानक पर विचार किया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सरकार की नीति समान बनी हुई है। ऐसे मामले में, उत्तरदाता इस जांच में एक अभूतपूर्व पद्धति अपनाने का कारण समझने में सक्षम नहीं है।

xxvii. आवेदक के आरोप ऑस्ट्रेलियाई पाटन रोधी आयोग के निर्धारण से भी अप्रमाणित और अमान्य हो जाते हैं जिसमें आयोग ने, वियतनाम से 600 मिलीमीटर के बराबर या अधिक चौड़ाई वाले एल्यूमीनियम जिंक लेपित इस्पात के आयात के विरुद्ध सब्सिडी रोधी जांच में, वियतनामी बिजली बाजार में लागत विकृतियों की अनुपस्थिति पाई। ऑस्ट्रेलियाई आयोग ने निम्नानुसार नोट किया है:

क) वियतनाम में विभिन्न क्षेत्रों पर भिन्न दरें लागू होती हैं और वोल्टेज पर निर्भर होती हैं;

ख) विश्व बैंक की बिजली कीमत वियतनाम में बिजली कीमतों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करती है और वियतनाम सरकार द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से संरेखित होती है।

ग) कोरिया, मलेशिया और ताइवान में बिजली की कीमतें सभी वियतनाम से सस्ती हैं।

xxviii. विशिष्टता के संबंध में, प्रकटीकरण विवरण में यह नोट किया गया है कि यह योजना विशिष्ट है क्योंकि विनिर्माण, प्रशासनिक/गैर-व्यावसायिक, व्यावसायिक और घरेलू सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए खुदरा शुल्क निर्धारित है। ऐसा विभेदीकरण इंगित करता है कि शुल्क प्रणाली सभी उपयोगकर्ताओं पर एकसमान रूप से लागू नहीं है, बल्कि परिभाषित उपयोगकर्ता श्रेणियों के माध्यम से प्रशासित है, जिसमें औद्योगिक/विनिर्माण उपयोगकर्ता शामिल हैं जो उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में बिजली का उपभोग करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशिष्टता के संबंध में किया गया प्रस्ताव पूर्णतः गलत है क्योंकि उपर्युक्त कारकों के आधार पर शुल्क हमेशा भिन्न होता है। यह प्रथा भारत सहित पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। शुल्क सभी उद्यमों पर लागू होता है और किसी विशेष उद्यम के लिए विशिष्ट नहीं है।

109. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम में बिजली, प्राकृतिक गैस और कोयले सहित ऊर्जा की कीमतें सरकारी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित या विनियमित की जाती हैं और बाजार-निर्धारित स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा प्रशासित मूल्य निर्धारण वियतनाम में ऊर्जा कीमतों की विकृति में परिणत होता है।

ii. घरेलू उद्योग के अनुसार, प्रशासित कीमतों पर बिजली, प्राकृतिक गैस और कोयले का प्रावधान एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुच्छेद 14(घ) के अर्थ में अपर्याप्त पारिश्रमिक पर वस्तुओं का प्रावधान है। सरकार-निर्धारित कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों के बीच का अंतर प्राप्तकर्ता उद्यमों को प्रदान किए गए वित्तीय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

iii. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वियतनामी प्राधिकारियों द्वारा विद्युत खपत के लिए अपर्याप्त पारिश्रमिक पर बिजली, प्राकृतिक गैस और कोयले का प्रावधान प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी का गठन करता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम सरकार उद्योग और व्यापार मंत्रालय के माध्यम से इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, जो प्रदर्शित करता है कि कार्यक्रम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य है।

iv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि पारिश्रमिक की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए मानक घरेलू वियतनामी कीमतें नहीं हो सकतीं, क्योंकि ये सरकारी हस्तक्षेप के कारण विकृत हैं। उसने प्रस्तावित किया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, मलेशिया जैसे तुलनीय बाह्य बाजार से ऊर्जा कीमतों का उपयुक्त मानक के रूप में उपयोग किया जाए। घरेलू उद्योग के अनुसार, लाभ की गणना ऐसे मानक मूल्यों और वियतनाम में जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई कीमतों के बीच अंतर के रूप में की जानी चाहिए।

v. बिजली के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय चार श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं, अर्थात् (i) विनिर्माण क्षेत्र, (ii) प्रशासनिक और गैर-व्यावसायिक क्षेत्र, (iii) व्यावसायिक क्षेत्र, और (iv) घरेलू, के लिए निर्धारित मूल्य सीमाओं के भीतर बिजली के खुदरा शुल्क निर्धारित करता है।

vi. घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका से फाइबरबोर्ड के आयात से संबंधित सब्सिडी रोधी जांच में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया, जिसमें प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि वियतनाम में बिजली दरें विकृत थीं और सरकारी नियंत्रण के कारण बाजार शक्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं।

vii. फाइबरबोर्ड जांच में, प्राधिकारी ने 'ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज' पर एक मानक स्रोत के रूप में इस आधार पर भरोसा किया था कि यह देशों में खुदरा ऊर्जा कीमतों पर विश्वसनीय और अद्यतन सूचना की एक विस्तृत श्रृंखला प्रकाशित करता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित प्रथा इस अंतिम जांच परिणाम का समर्थन करती है कि वियतनामी बिजली कीमतें विकृत हैं।

viii. इस आधार पर, घरेलू उद्योग ने उपयुक्त बाह्य मानक के रूप में एक अन्य आसियान देश, अर्थात् मलेशिया, से बिजली कीमतों को अपनाने का प्रस्ताव किया। 'ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज' से निकाली गई मलेशियाई बिजली कीमतें अभिलेख पर रखी गईं, और प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि उत्तरदाता वियतनामी उत्पादकों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक बिजली शुल्कों की तुलना इस मानक से करके सब्सिडी अंतर निर्धारित करें।

ix. पक्षकारों द्वारा अपर्याप्त पारिश्रमिक के इनकार के जवाब में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि ऐसे इनकार गलत, चयनात्मक और भ्रामक हैं। उसने दोहराया कि वियतनाम में बिजली मूल्य निर्धारण वियतनाम सरकार द्वारा प्रशासित, विनियमित और नियंत्रित है और इसलिए एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(घ) के तहत अपेक्षित प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करता।

x. घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि ऑस्ट्रेलियाई पाटन रोधी आयोग के जांच परिणामों पर पक्षकारों का भरोसा अनुपयुक्त है, क्योंकि विदेशी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण इस प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं और विभिन्न अवधियों, तथ्यों और साक्ष्य अभिलेखों पर आधारित हैं।

xi. घरेलू उद्योग ने इंगित किया कि स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए उद्धरण भी स्वीकार करते हैं कि वियतनाम में बिजली की कीमतें सरकार द्वारा क्षेत्र-वार निर्धारित की जाती हैं और एकसमान रूप से लागू होती हैं, बजाय प्रतिस्पर्धी बाजार शक्तियों के माध्यम से निर्धारित होने के। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा प्रशासित मूल्य निर्धारण स्वयं अनुच्छेद 14(घ) के तहत जांच को उचित ठहराता है।

xii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसकी मानक प्रस्तुतियाँ शुल्क सीमाओं और राज्य-स्वामित्व या राज्य-नियंत्रित संस्थाओं द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से वियतनाम में बिजली शुल्कों के व्यवस्थित दमन को प्रदर्शित करती हैं। तदनुसार, उसने पक्षकारों के इस दावे को अस्वीकार किया कि बिजली के संबंध में कोई अपर्याप्त पारिश्रमिक विद्यमान नहीं है और प्राधिकारी से अनुरोध किया कि पहले से प्रस्तावित वस्तुनिष्ठ बाह्य मानकों के आधार पर बिजली मूल्य निर्धारण का आकलन करें।

xiii. प्राकृतिक गैस के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि डिक्री संख्या 87/2018/एनडी-सीपी के तहत, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय को पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी नामित किया गया है और यह एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी से संबंधित सभी व्यावसायिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। संबंधित डिक्री अभिलेख पर रखी गई थी।

xiv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि ऐसा नियामक पर्यवेक्षण वियतनाम में प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण प्रदर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस की कीमतें विकृत होती हैं। यह तर्क दिया गया कि ये कीमतें इसलिए बाजार-निर्धारित स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

xv. मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से कॉपर ट्यूब और पाइप के आयात से संबंधित सब्सिडी रोधी जांच में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया, जिसमें प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि वियतनाम में प्राकृतिक गैस की कीमतें सरकारी नियंत्रण के कारण विकृत थीं और बाजार शक्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं।

xvi. उस जांच में, प्राधिकारी ने प्राकृतिक गैस कीमतों के लिए 'ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज' पर एक मानक स्रोत के रूप में भरोसा किया था। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यह उन परिस्थितियों में प्राधिकारी की सुस्थापित प्रथा का गठन करता है जहाँ घरेलू कीमतें विकृत हैं।

xvii. तदनुसार, घरेलू उद्योग ने 'ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज' से निकाली गई मलेशिया से प्राकृतिक गैस कीमतों को उपयुक्त मानक के रूप में अपनाने का प्रस्ताव किया। संबंधित मलेशियाई प्राकृतिक गैस मूल्य आंकड़े अभिलेख पर रखे गए, और प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि सब्सिडी अंतर निर्धारित करने के लिए इन मानक मूल्यों की तुलना वियतनामी उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई कीमतों से करें।

110. प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:

वित्तीय अंशदान और लाभ

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके तहत आरोप प्रशासित या विनियमित कीमतों पर वियतनाम में विद्युत खपत के लिए ऊर्जा इनपुटों, अर्थात् बिजली, प्राकृतिक गैस और कोयले के प्रावधान से संबंधित है। तथापि, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अभिलेख पर रखी गई प्रश्नावली प्रतिक्रिया/अतिरिक्त प्रश्नावली प्रतिक्रिया के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों सहित उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं ने अपर्याप्त पारिश्रमिक पर बिजली का उपभोग किया है।

112. प्राधिकारी ने वियतनाम में बिजली क्षेत्रों की संरचना और शुल्क निर्धारण तथा पर्यवेक्षण में उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के माध्यम से वियतनाम सरकार की भूमिका के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच की है।

113. प्राधिकारी, अभिलेख पर रखे गए नियामक/शुल्क-निर्धारण ढांचे और उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के माध्यम से वियतनाम सरकार की भूमिका के आधार पर, यह पाते हैं कि एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अर्थ में बिजली के प्रावधान के संबंध में वित्तीय अंशदान विद्यमान है।

विशिष्टता

114. प्राधिकारी ने अभिलेख पर रखी गई बिजली शुल्क व्यवस्था की संरचना की जांच की है, जिसमें विनिर्माण, प्रशासनिक/गैर-व्यावसायिक, व्यावसायिक और घरेलू सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए खुदरा शुल्क निर्धारित है। तथापि, यह प्रत्येक उपयोगकर्ता श्रेणी के अंतर्गत सभी उपयोगकर्ताओं पर एकसमान रूप से लागू होता है। आवेदक यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं कि बिजली केवल जांचाधीन उत्पाद के निर्माताओं को सामान्य दरों से कम दर पर प्रदान की जाती है।

115. इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, यह इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि प्राधिकारी ने निम्नलिखित जांचों प्राधिकरण द्वारा संचालित में भी वियतनाम में बिजली पर अपर्याप्त पारिश्रमिक नहीं पाया है।

क) वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास [फा.सं. 6/32/2023-डीजीटीआर दिनांक 11 फरवरी, 2025]

ख) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 7/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 15 जून, 2024]

ग) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 6/22/2018-डीजीएडी दिनांक 31 जुलाई, 2019]

116. तदनुसार, प्राधिकरण ने इस विशेष कार्यक्रम की प्रतिकारी योग्यता की जांच नहीं की है।

<u>कार्यक्रम 13 - अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि का प्रावधान और भूमि एवं जल किराए से छूट या कटौतियाँ</u>

117. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:</u>

i. उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि यह आरोप कि वियतनाम सरकार अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि, जल किराया छूट या कटौतियाँ प्रदान करती है, निराधार, तथ्यात्मक रूप से गलत है, और उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू नहीं होता।

ii. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कार्यक्रम तीन से ग्यारह वर्ष की अवधि के लिए भूमि और जल किराए में छूट या कटौतियों, और कुछ उद्यमों के लिए पचास प्रतिशत तक की कटौतियों को संदर्भित करता है। पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान ऐसा कोई कथित कार्यक्रम प्राप्त नहीं किया है।

iii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा उपयोग की गई भूमि वियतनाम सरकार द्वारा स्वामित्व में नहीं दी गई है या सीधे आवंटित नहीं की गई है। इसके बजाय, भूमि निजी औद्योगिक पार्क अवसंरचना विकास कंपनियों के साथ वाणिज्यिक उप-पट्टा व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त की गई है।

iv. इस संबंध में, एक पक्ष ने प्रस्तुत किया कि उसने 2065 तक वैध पट्टे के साथ एक भूमि उप-पट्टा समझौता किया।

v. उसने प्रस्तुत किया कि उक्त समझौते के तहत अवसंरचना सहित भूमि के उप-पट्टे के लिए इकाई मूल्य (वैट को छोड़कर) लगभग 75 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर के समकक्ष है, जो संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए लागू है।

vi. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा भुगतान किया गया भूमि मूल्य हंग येन प्रांत की जन समिति द्वारा डिक्री संख्या 40/2019/क्यूडी-यूबीएनडी दिनांक 20 दिसंबर 2019 के तहत निर्धारित आधार भूमि कीमतों से काफी अधिक है, जो 2020-2024 की अवधि के लिए भूमि मूल्य सूची प्रख्यापित करता है।

vii. डिक्री संख्या 40/2019/क्यूडी-यूबीएनडी की तालिका 09 के अनुसार, येन माय जिले में स्थित औद्योगिक पार्कों में वाणिज्यिक, सेवा और गैर-कृषि उत्पादन भूमि के लिए आधार मूल्य 12,00,000 वियतनामी डोंग प्रति वर्ग मीटर है।

viii. उसने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों द्वारा भुगतान किया गया भूमि मूल्य उक्त डिक्री के तहत निर्धारित आधार मूल्य से अधिक है। यह प्रीमियम प्रदर्शित करता है कि भूमि पट्टा मूल्य प्रोत्साहित, रियायती या अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्रदान नहीं किया गया है।

ix. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि प्रांतीय आधार मूल्य पर प्रीमियम का भुगतान निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है और यह लेन-देन बाजार-आधारित वाणिज्यिक शर्तों को प्रतिबिंबित करता है।

x. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि के प्रावधान का आरोप लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भूमि खरीदी नहीं है बल्कि केवल पट्टे पर ली है। पक्षकारों के अनुसार, याचिका गलत रूप से पट्टा व्यवस्थाओं को भूमि के सरकारी प्रावधान के समकक्ष मानती है।

xi. पक्षकार वियतनाम से 600 मिलीमीटर के बराबर या अधिक चौड़ाई वाले एल्यूमीनियम जिंक लेपित इस्पात के आयात से संबंधित सब्सिडी रोधी जांच में ऑस्ट्रेलियाई पाटन रोधी आयोग के जांच परिणामों पर भरोसा करते हैं, जिसमें भूमि उपयोग शुल्क छूट या कटौतियों के संबंध में कोई सब्सिडी नहीं पाई गई।

xii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारी ने कोई साक्ष्य नहीं पाया कि जांचाधीन वस्तुओं के निर्यातकों ने भूमि-संबंधित कार्यक्रमों के तहत कोई वित्तीय लाभ प्राप्त किया था और परिणामस्वरूप उस कार्यक्रम के संबंध में जांच समाप्त कर दी।

xiii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम में भूमि किराया छूट और कटौती नीतियाँ सामान्य निवेश प्रोत्साहन उपाय हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने वाले सभी उद्यमों के लिए एकसमान रूप से उपलब्ध हैं, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से कठिन क्षेत्रों में स्थित उद्यमों के लिए।

xiv. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये उपाय क्षेत्रों, उत्पादों, उद्यमों के आकारों, निर्यात अभिविन्यास, या स्थानीयकरण आवश्यकताओं के बीच भेद नहीं करते, और इसलिए इनमें विधितः और तथ्यतः दोनों रूप में विशिष्टता का अभाव है।

xv. किसी भूमि या जल किराया छूट या कटौती के लिए पात्रता पूर्णतः वस्तुनिष्ठ भौगोलिक मानदंडों पर आधारित है, अर्थात् नामित औद्योगिक क्षेत्रों या आर्थिक रूप से कठिन क्षेत्रों में परियोजना का स्थान, न कि निर्मित उत्पाद की प्रकृति पर।

xvi. एक उत्तरदाता प्रस्तुत करता है कि उसकी परियोजना, जो येन बाई प्रांत में स्थित है, डिक्री संख्या 46/2014/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 19 के खंड 3 के बिंदु (ख) के तहत भूमि किराया छूट के लिए योग्य है, क्योंकि परियोजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक रूप से कठिन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित है।

xvii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि ऐसे प्रोत्साहन सामान्य क्षेत्रीय विकास उपाय हैं और अनुज्ञेय निवेश प्रोत्साहन नीतियों की श्रेणी में आते हैं, जो विशिष्टता के अभाव में प्रतिसंतुलनकारी नहीं हैं।

xviii. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि समान क्षेत्रीय विकास प्रोत्साहन भारत और अन्य विश्व व्यापार संगठन सदस्यों में विद्यमान हैं, और इसलिए वियतनाम की भूमि नीतियों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

xix. पक्षकारों ने इस आरोप का खंडन किया कि वियतनाम सरकार जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों को अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि प्रदान करती है और प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान भूमि कीमतों में किसी विकृति या प्रदान किए गए किसी लाभ को स्थापित करने में विफल रहा है।

xx. पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के देश से बाहर के मानकों, जिसमें मुद्रास्फीति सूचकांकों द्वारा समायोजित थाईलैंड निवेश बोर्ड का भूमि किराया आंकड़ा शामिल है, पर भरोसा करने के प्रस्ताव को भी चुनौती दी।

xxi. उन्होंने प्रस्तुत किया कि थाईलैंड और वियतनाम में मूलतः भिन्न भूमि कार्यकाल प्रणालियाँ, औद्योगिक क्षेत्रीकरण ढाँचे, भू-संपदा बाजार, भूमि रूपांतरण लागतें और अवसंरचना प्रावधान मॉडल हैं, जो ऐसी तुलनाओं को अमान्य बनाते हैं।

xxii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि असंबद्ध भू-संपदा बाजारों में मुद्रास्फीति-आधारित समायोजनों का आर्थिक औचित्य नहीं है और ये एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(घ) के तहत तुलनीयता की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करते।

xxiii. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि थाईलैंड निवेश बोर्ड की दरें वियतनामी औद्योगिक क्षेत्र पट्टे की संरचना को प्रतिबिंबित नहीं करतीं, जिसमें सामान्यतः बंडल की गई अवसंरचना, सेवाएँ और दीर्घकालिक रियायत व्यवस्थाएँ शामिल होती हैं।

xxiv. पक्षकारों ने तर्क दिया कि देश से बाहर के मानकों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग की पूर्ववर्ती प्रथाओं पर भरोसा अनुपयुक्त है और प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।

xxv. अमेरिकी प्रथा के तहत भी, बाह्य मानकों के उपयोग के लिए घरेलू बाजार विकृति का पूर्व अंतिम जांच परिणाम और एक कठोर तुलनीयता विश्लेषण आवश्यक है, जिनमें से कोई भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है।

xxvi. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि पारिश्रमिक की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी को भूमि की प्रकृति, पट्टा अवधि, वृद्धि खंड, शामिल अवसंरचना, स्थानीय बाजार स्थितियों, क्षेत्रीकरण प्रतिबंधों और बंडल प्रभारों पर विचार करना चाहिए।

xxvii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अभिलेख पर पूर्ण भूमि पट्टा समझौते, किराया भुगतान अनुसूचियाँ और यह प्रदर्शित करने वाले सहायक दस्तावेज रखे हैं कि भूमि बाजार-आधारित शर्तों पर प्राप्त की गई थी।

xxviii. उन्होंने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग वित्तीय अंशदान, लाभ या विशिष्टता के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा है, और इसलिए अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि के प्रावधान और भूमि एवं जल किराए की छूट या कटौती से संबंधित आरोप पूर्णतः खारिज किए जाने योग्य हैं।

xxix. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि कथित भूमि-संबंधित कार्यक्रम के तहत कोई प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, न्धे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने तर्क दिया कि थाईलैंड के भूमि किराया मानकों पर भरोसा कानूनी रूप से अस्थिर है, क्योंकि जब तक वियतनाम में विकृति पहले स्थापित नहीं की जाती, घरेलू वियतनामी कीमतों का उपयोग किया जाना चाहिए।

xxx. वीएमआई ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी का अंतिम जांच परिणाम असमर्थित है, क्योंकि उसने भूमि उपयोग अधिकार प्राप्त करने, कारखाना अवसंरचना के निर्माण और अपने स्वयं के खर्च पर औद्योगिक सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक लागतें वहन कीं। ऐसी लागतें उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत की गईं और किसी कथित काल्पनिक भूमि किराया लाभ से अधिक मूल्यह्रास व्यय में परिणत हुईं। वीएमआई ने आगे आपत्ति की कि प्रकटीकरण विवरण मानक दर, भूमि क्षेत्र, गणना अवधि और लागू समायोजनों जैसे आवश्यक गणना तत्वों का खुलासा नहीं करता। उसने थाईलैंड निवेश बोर्ड की किराया दरों के उपयोग को भी चुनौती दी, क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम भूमि स्वामित्व प्रणालियों, आर्थिक स्थितियों, अवसंरचना, भूगोल और औद्योगिक विकास में भौतिक रूप से भिन्न हैं।

xxxi. एडीसी ने प्रस्तुत किया कि उसने लागू मानक मूल्यों से लगभग 45% अधिक कीमतों पर भूमि अधिग्रहीत की, जिससे किसी भी लाभ की अनुपस्थिति स्थापित होती है। उसने आगे प्रस्तुत किया कि भूमि या जल किराए के संबंध में छूट, कटौती, उन्मोचन या अधिमान्य उपचार का कोई साक्ष्य नहीं है, और सभी भुगतान वाणिज्यिक रूप से निर्धारित दरों पर लागू कानूनों के अनुसार किए गए थे। वियतनाम सरकार द्वारा किसी वित्तीय अंशदान के अभाव में, सब्सिडी स्थापित करने की सीमा आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं होती।

xxxii. उत्तरदाताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि वियतनाम सरकार द्वारा निधियों के किसी प्रत्यक्ष अंतरण या राजस्व के त्याग, जैसे भूमि प्रभारों की पूर्ण या आंशिक छूट, को दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। प्रकटीकरण विवरण इस बात की भी अवहेलना करता है कि वियतनाम सरकार केवल एक न्यूनतम या आधार दर निर्धारित करती है, जबकि वास्तविक खरीद मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, केवल इस शर्त के अधीन कि वह ऐसी न्यूनतम दर से नीचे नहीं गिर सकता। यह भारत सहित अनेक देशों में अपनाई जाने वाली एक सामान्य नियामक प्रथा है, और सब्सिडीकरण स्थापित नहीं करती।

xxxiii. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानक से संबंधित एक प्रमुख आपत्ति है। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि थाईलैंड का नखोन नायोक प्रांत, वियतनाम के येन बाई प्रांत की वान टिएन कम्यून, जहाँ कारखाना स्थित है, से तुलनीय नहीं है। वान टिएन हनोई से लगभग 200 किमी दूर एक विकासशील ग्रामीण क्षेत्र है, जबकि नखोन नायोक मध्य थाईलैंड का एक विकसित प्रांत है, जो बैंकॉक से लगभग 100 किमी दूर है, जहाँ परिपक्व पर्यटन और अवसंरचना सुविधाएँ हैं। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि जनसंख्या घनत्व तुलना का उचित आधार नहीं है; प्रासंगिक मानदंड विकास का स्तर है। प्रस्तावित थाई मानक उत्तरदाता द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक किराए से 1,000 गुना से अधिक है, जो स्वयं दर्शाता है कि मानक विकृत, अतुलनीय और भ्रामक है।

	विवरण	**वान टिएन कम्यून, येन बाई प्रांत, वियतनाम**	**नखोन नायोक प्रांत, थाईलैंड**
i	स्थान	ग्रामीण क्षेत्र	मध्य थाईलैंड
ii	राजधानी शहर से दूरी	हनोई से 200 किमी	बैंकॉक से 100 किमी
iii	पैमाना	छोटी प्रशासनिक इकाई	संपूर्ण प्रशासनिक प्रांत
iv	विकास का स्तर	विकासशील ग्रामीण क्षेत्र	परिपक्व; अंतरराष्ट्रीय-मानक रिसॉर्ट, वाटर पार्क, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (खाओ याई) का भाग।
v	दावा किया गया मानक ($ प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष)	-	50.53
vi	वास्तविक किराए के गुणक के रूप में मानक	*** गुना	किसी तुलनीय क्षेत्र में किराए में *** गुना अंतर नहीं हो सकता

xxxiv. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि इस योजना के तहत सब्सिडी अंतर का आकलन हमेशा 0.5% से कम किया गया है। इसे नीचे उल्लिखित महानिदेशालय द्वारा जारी हाल के जांच परिणामों से क्रॉस-चेक किया जा सकता है। इस मामले में, इस मद पर कथित सब्सिडी अंतर 5% परिकलित किया गया है, जो प्राधिकारी द्वारा पहले निर्धारित किए गए अंतर से 10 गुना से अधिक है। प्राधिकारी के सुगम संदर्भ के लिए जांचों की उदाहरणात्मक सूची नीचे प्रदान की गई है:

क) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 7/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 15 जून, 2024]

ख) चीन और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब [फा.सं. 6/22/2018-डीजीएडी दिनांक 31 जुलाई, 2019]

ग) वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास [फा.सं. 6/32/2023-डीजीटीआर दिनांक 11 फरवरी, 2025]

xxxv. विशिष्टता पर, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि अंतिम जांच परिणाम असमर्थित है क्योंकि प्रकटीकरण विवरण में केवल यह कहा गया है कि कार्यक्रम क्षेत्र-विशिष्ट है और प्रोत्साहित क्षेत्रों तक सीमित है। तथापि, उत्तरदाताओं की परियोजना किसी प्रोत्साहित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, और घरेलू उद्योग द्वारा अन्यथा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।

xxxvi. अंत में, उत्तरदाताओं ने वियतनाम से एल्यूमीनियम जिंक लेपित इस्पात से संबंधित सब्सिडी रोधी जांच की ऑस्ट्रेलियाई पाटन रोधी आयोग द्वारा समाप्ति पर भरोसा किया, जिसमें समान/समरूप भूमि-संबंधित कार्यक्रम के संबंध में कोई सब्सिडी नहीं पाई गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह उनकी इस स्थिति का समर्थन करता है कि कथित कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान नहीं करता।

118. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम सरकार कम भूमि किराए, भूमि किराए से पूर्ण या आंशिक छूट, और भूमि एवं जल सतह किराए में कटौतियों या छूटों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमों को अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि-उपयोग अधिकार प्रदान करती है।

ii. ये उपाय चिह्नित क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, या वियतनामी कानून के तहत प्रोत्साहित उद्योगों के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमों पर लागू सरकारी ढाँचों के तहत प्रदान किए जाते हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि ऐसे उपाय एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iii) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अर्थ में वित्तीय अंशदान का गठन करते हैं, क्योंकि इनमें वस्तुओं, अर्थात् भूमि का प्रावधान शामिल है, और भूमि एवं जल किराए में छूट या कटौतियों के रूप में सरकारी राजस्व का त्याग भी शामिल है।

iv. कम किराए पर या किराया छूट के साथ भूमि का प्रावधान प्राप्तकर्ता उद्यमों को लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ऐसे भूमि-उपयोग अधिकारों के नियम और शर्तें बाजार-निर्धारित स्थितियों के तहत प्रचलित नियमों और शर्तों से अधिक अनुकूल हैं।

v. सब्सिडी एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के अर्थ में विशिष्ट है, क्योंकि ऐसी छूटों या कटौतियों तक पहुँच विशेष क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित, या वियतनामी निवेश नीति के तहत प्रोत्साहित के रूप में वर्गीकृत परियोजनाएँ चलाने वाले उद्यमों तक सीमित है।

vi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों का यह तर्क कि भूमि कार्यक्रम लागू नहीं है क्योंकि भूमि खरीदने के बजाय पट्टे पर ली गई थी, कानूनी रूप से अस्थिर है। एससीएम समझौते का अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iii) प्रावधान के तरीके पर ध्यान दिए बिना, चाहे बिक्री, पट्टे या रियायत द्वारा, वस्तुओं के प्रावधान को शामिल करता है।

vii. प्रासंगिक कानूनी जांच यह नहीं है कि भूमि खरीदी गई या पट्टे पर ली गई, बल्कि यह है कि क्या भूमि पट्टे के नियम और शर्तें प्रचलित बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित पर्याप्त पारिश्रमिक को प्रतिबिंबित करती हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने अधिमान्य भूमि मूल्य निर्धारण, छूटों, कटौतियों और प्रशासित भूमि-उपयोग शुल्कों से जुड़ी योजनाओं के अस्तित्व का आरोप लगाया है, जिन सभी की प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि पारिश्रमिक पर्याप्त है या नहीं।

ix. जहाँ पक्ष दावा करते हैं कि कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, प्राधिकारी प्रयोज्यता और लाभ, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं, भूमि पट्टा समझौतों और सत्यापन अभिलेखों पर भरोसा कर सकते हैं।

x. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम सरकार भूमि प्रशासन और निवेश प्रोत्साहन को शासित करने वाली विभिन्न डिक्रियों के तहत, संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए या सीमित वर्षों के लिए भूमि किराया छूट, साथ ही कुछ उद्यमों के लिए किराया कटौतियाँ प्रदान करती है।

xi. ये छूट और कटौतियाँ सरकारी राजस्व के त्याग में परिणत होती हैं और प्राप्तकर्ता उद्यमों पर प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं, जिससे सब्सिडी की परिभाषा संतुष्ट होती है।

xii. घरेलू उद्योग ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से कॉपर ट्यूब और पाइप के आयात से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया, जिसमें प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि वियतनाम सरकार द्वारा अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि का प्रावधान और भूमि एवं जल किराए की छूट या कटौतियाँ वित्तीय अंशदान थीं और लाभ प्रदान करती थीं।

xiii. उस जांच में, प्राधिकारी ने आगे निर्णय दिया कि ऐसे भूमि-संबंधित उपाय विशिष्ट थे, क्योंकि वे विशेष क्षेत्रों में स्थित उद्यमों और प्रोत्साहित क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं तक सीमित थे।

xiv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वही तर्क और कानूनी सिद्धांत वर्तमान जांच में लागू होते हैं, क्योंकि वियतनामी भूमि प्रोत्साहन ढांचे की संरचना, अभिकल्पना और संचालन तुलनीय बने हुए हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य अधिकारिताओं में जांच प्राधिकारियों ने भी समान वियतनामी भूमि कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी माना है।

xvi. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने वियतनाम से प्रशीतित गर्म जल झींगा से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य विभाग के जांच परिणामों पर भरोसा किया, जिसमें यूएसडीओसी ने निर्धारित किया कि वियतनामी घरेलू भूमि किराया आंकड़े राज्य के हस्तक्षेप से विकृत थे।

xvii. उस जांच में, यूएसडीओसी ने उपयुक्त बाजार-आधारित भूमि किराए निर्धारित करने के लिए "थाईलैंड में व्यवसाय करने की लागत 2023" रिपोर्ट में थाईलैंड निवेश बोर्ड द्वारा प्रकाशित देश से बाहर के मानकों पर भरोसा किया।

xviii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि थाईलैंड निवेश बोर्ड के आंकड़ों को यूएसडीओसी द्वारा सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना माना गया, क्योंकि यह तुलनीय क्षेत्रीय संदर्भ में बाजार-आधारित औद्योगिक भूमि किराया दरें प्रदान करता था।

xix. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने उपयुक्त बाह्य मानक के रूप में "थाईलैंड में व्यवसाय करने की लागत 2023" रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई औद्योगिक और संभार-तंत्र संपत्तियों के लिए किराया दरों को अपनाने का प्रस्ताव किया।

xx. निवेश बोर्ड की रिपोर्ट में आंकड़े क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उपयुक्त तुलनीय क्षेत्र की पहचान करने के लिए, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि थाईलैंड के क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व की तुलना उन स्थानों के जनसंख्या घनत्व से की जानी चाहिए जहाँ वियतनामी उत्पादकों के कारखाने स्थित हैं।

xxi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यही पद्धति यूएसडीओसी द्वारा प्रशीतित गर्म जल झींगा जांच में अपनाई गई थी और तुलनीय क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक तर्कसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।

xxii. चूंकि थाईलैंड निवेश बोर्ड ने 2024 के लिए "व्यवसाय करने की लागत" रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि 2024 के लिए मानक भूमि किराए वियतनाम के मुद्रास्फीति

सूचकांक का उपयोग करके 2023 की निवेश बोर्ड की किराया दरों को समायोजित करके प्राप्त किए जाने चाहिए।

xxiii. लाभ को इन मानक दरों पर देय भूमि किराए और किसी छूट या कटौती के हिसाब के बाद वियतनाम में जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए किराए के बीच अंतर के रूप में परिमाणित किया जाना चाहिए।

xxiv. ऐसे मामलों में जहाँ पूर्ण भूमि किराया छूट प्रदान की गई है, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि संपूर्ण मानक किराया राशि को संबंधित अवधि के दौरान प्रदान किया गया लाभ माना जाना चाहिए।

<u>प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:</u>

वित्तीय अंशदान और लाभ

119. प्राधिकारी का मानना है कि प्रावधान का रूप (बिक्री, पट्टा, रियायत, उप-पट्टा) वित्तीय अंशदान की जांच के प्रयोजन के लिए निर्धारक नहीं है। जहाँ भूमि-उपयोग अधिकार सरकार-प्रशासित ढांचे के भीतर उपलब्ध कराए जाते हैं और/या जहाँ भूमि एवं जल किराए में छूट/कटौतियाँ कानूनी उपकरणों के अनुसरण में प्रदान की जाती हैं, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे उपायों में सरकार द्वारा या उसके निर्देश पर भूमि-उपयोग अधिकारों का प्रावधान शामिल है और/या अन्यथा देय राजस्व का त्याग शामिल है।

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भूमि वियतनाम सरकार के स्वामित्व में है और भूमि का मूल्य उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई भूमि किराया छूट/कटौती के उपाय सरकारी राजस्व का त्याग हैं। प्राधिकारी ने "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब" और "सतत ढलवाँ तांबे की तार की छड़ें" से संबंधित अपनी पिछली सब्सिडी रोधी जांच में पहले ही निर्धारित किया है कि इन कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

121. व्यक्तिगत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों पर कार्यक्रम-वार प्रयोज्यता के मुद्दे की जांच उनकी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और सहायक दस्तावेजों के आधार पर की गई है।

विशिष्टता

122. प्राधिकारी का मानना है कि उपाय चिह्नित क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, या नामित निवेश-प्रोत्साहन क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों तक सीमित हैं। पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह क्षेत्र-विशिष्ट है और कुछ प्रोत्साहित क्षेत्रों तक सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

मानक

123. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की है, जिसमें पट्टा समझौते, भुगतान अनुसूचियाँ, और किसी छूट/कटौती का विवरण शामिल है। प्राधिकारी ने ध्यान दिया कि वियतनाम सरकार ने जांचाधीन उत्पाद के निर्माताओं को भूमि दरों में छूट प्रदान की।

124. तदनुसार, वर्तमान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी वियतनाम में प्रचलित सामान्य दरों अर्थात बिना छूट वाली दरों को उपयुक्त मानते हैं।

सब्सिडी अंतर

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों की गणना जांच अवधि के दौरान विद्यमान पाए जाने वाले प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ के संदर्भ में की जाती है।

126. तदनुसार, जांच अवधि के दौरान भूमि-संबंधित लाभ प्राप्त करते पाए गए उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने (i) तुलनीय औद्योगिक भूमि-उपयोग अधिकारों के लिए बाजार-संगत स्थितियों के तहत देय सामान्य भूमि दरों पर आधारित मानक किराए की तुलना (ii) किसी छूट या कटौती के हिसाब के बाद वास्तव में भुगतान किए गए किराए से करके लाभ की गणना की है।

कर छूट और कटौतियों के रूप में चिह्नित योजनाओं की सूची

कार्यक्रम 3 - उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट

127. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग द्वारा कथित कॉर्पोरेट आयकर छूट या कटौतियाँ वियतनामी कानून के तहत सामान्य नीतिगत उपाय हैं और वस्तुनिष्ठ वैधानिक मानदंडों को पूरा करने वाले सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे उपाय एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत विशिष्टता की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करते।

ii. एडीसी प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्रस्तुत किया कि जांच अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त एकमात्र प्रोत्साहन छह महीने की सीमित अवधि के लिए लागू एक सामान्य निवेश-संबद्ध कॉर्पोरेट आयकर छूट थी। यह छूट कॉर्पोरेट आयकर पर कानून संख्या 32/2013/क्यूएच13 और निवेश पर कानून संख्या 61/2020/क्यूएच14 के तहत स्वतः उत्पन्न होती है, जो निर्यात निष्पादन, उद्योग, क्षेत्र, विदेशी स्वामित्व, या उद्यम आकार पर ध्यान दिए बिना वस्तुनिष्ठ निवेश सीमाओं के आधार पर पात्रता प्रदान करती है।

iii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट आयकर प्रोत्साहन पूर्णतः गैर-विशिष्ट है, जैसा कि निवेश पंजीकरण प्रमाणपत्र और कर अभिलेखों से पुष्ट होता है।

iv. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग विधितः या तथ्यतः विशिष्टता स्थापित करने में विफल रहा है। कॉर्पोरेट आयकर प्रोत्साहनों को शासित करने वाले वैधानिक उपकरण वियतनामी अर्थव्यवस्था में क्षैतिज रूप से लागू होते हैं और न तो प्लास्टिक उद्योग के लिए निर्देशित हैं और न ही निर्यात, स्थानीयकरण, या विदेशी निवेश पर आकस्मिक हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक

प्राधिकारी द्वारा कुछ उद्यमों के पक्ष में कोई विवेकाधिकार प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पात्रता पूर्णतः वस्तुनिष्ठ कानूनी मानदंडों के आधार पर निर्धारित होती है।

v. यूनाइटेड स्टेट्स – सॉफ्टवुड लम्बर IV में अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, जिसमें निर्णय दिया गया कि सामान्य सरकारी नीतियाँ जो आकस्मिक रूप से बाजार स्थितियों को प्रभावित करती हैं, उन्हें वित्तीय अंशदान या न्यस्तीकरण या निर्देशन नहीं माना जा सकता। पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि केवल आर्थिक प्रभाव, विशेष उद्यमों को आर्थिक संसाधनों के लक्षित अंतरण या अधिमान्य उपचार के साक्ष्य के अभाव में, एससीएम समझौते के तहत सब्सिडी का अस्तित्व स्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

vi. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, केवल तर्क के लिए यह मानते हुए भी कि प्राधिकारी कॉर्पोरेट आयकर प्रोत्साहन को विशिष्ट मानते हैं, जांच अवधि के दौरान प्रदान किए गए लाभ की मात्रा न्यूनतम है।

vii. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी को केवल जांच अवधि के दौरान उपार्जित वास्तविक लाभ पर विचार करना चाहिए और जांच अवधि से परे लाभों का वार्षिकीकरण या बहिर्वेशन नहीं कर सकता।

viii. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट आयकर प्रोत्साहन निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक नहीं हैं और इसलिए एससीएम समझौते के अनुच्छेद 3.1(क) के तहत निर्यात सब्सिडी नहीं माने जा सकते। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लाभ उद्यम स्तर पर लागू होता है और विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या निर्यात से संबद्ध नहीं है।

ix. उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत सहित अनेक अधिकारिताओं में समान सामान्य कर प्रोत्साहन ढाँचे विद्यमान हैं। वियतनाम और भारत दोनों एक मानक कॉर्पोरेट कर दर लागू करते हैं जो कर छुट्टियों, कम दरों और अनुसंधान एवं विकास कटौतियों जैसे सामान्यतः उपलब्ध निवेश-संबद्ध प्रोत्साहनों द्वारा पूरित होती है। यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वियतनामी उद्यम भारतीय उद्यमों की तुलना में व्यवस्थित रूप से अधिक अनुकूल कर व्यवस्था प्राप्त करते हैं।

x. पक्षकारों ने प्राधिकारी के पिछले निर्धारणों पर भरोसा किया, जिसमें चीन से पॉलिएस्टर यार्न और कोरिया से कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, जहाँ यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रीय कानून के तहत उपलब्ध सामान्य कर लाभ उद्यम-विशिष्ट या उद्योग-विशिष्ट लक्ष्यीकरण के अभाव में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं बनते।

xi. लाभ का कोई भी आकलन प्राप्तकर्ता-विशिष्ट होना चाहिए और वास्तविक कर देयता पर आधारित होना चाहिए, कर योग्य आय, मूल्यह्रास, हानि अग्रगमन और लागू कर प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए। घरेलू उद्योग का वास्तविक कर आधार और प्रभावी कर दर की जांच किए बिना वैधानिक कर दर को मानक मानने का दृष्टिकोण कानूनी रूप से अस्थिर है।

xii. कुछ पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान कोई कॉर्पोरेट आयकर छूट या कटौती प्राप्त नहीं की और उन्होंने 20% की मानक दर पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान किया और कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया। अन्य पक्षकारों ने इसी प्रकार प्रस्तुत किया कि उन्होंने कथित कॉर्पोरेट आयकर छूट योजनाओं के तहत न तो आवेदन किया और न ही कोई लाभ प्राप्त किया।

xiii. वियतनाम सरकार प्रस्तुत करती है कि प्रासंगिक नीतियाँ सामान्यतः लागू कानूनी ढांचे का हिस्सा हैं और कुछ उद्यमों या उद्योगों के लिए विशिष्ट नहीं हैं।

xiv. वीएमआई ने कहा कि उसने संपूर्ण जांच अवधि के दौरान 20% की मानक वैधानिक दर पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान किया और कोई कर छूट या अधिमान्य कटौती प्राप्त नहीं की। वीएमआई ने प्रस्तुत

किया कि उसकी कर फाइलिंग और भुगतान अभिलेखों ने किसी प्रतिसंतुलनकारी कर लाभ की अनुपस्थिति की पुष्टि की।

xv. यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, न्घे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट आयकर-संबंधित प्रोत्साहन प्रतिसंतुलनकारी नहीं हैं, क्योंकि वे निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभुक्त इनपुटों से संबद्ध नहीं हैं।

xvi. एडीसी ने प्रस्तुत किया है कि जबकि उसने जांच अवधि के एक भाग के लिए सीमित कॉर्पोरेट आयकर छूट की प्राप्ति का खुलासा किया है, प्राधिकारी द्वारा इस उपाय को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी मानना कानूनी रूप से अस्थिर है और एससीएम समझौते के ढांचे के विपरीत है। वियतनाम में कॉर्पोरेट आयकर व्यवस्था क्षेत्रों और उद्योगों में लागू एक सामान्य राजकोषीय उपाय है। प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई छूट एक व्यापक, अर्थव्यवस्था-व्यापी कर ढांचे का हिस्सा है और किसी विशिष्ट उद्यम या उद्योग तक सीमित नहीं है। तदनुसार, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत विशिष्टता की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती। उत्तरदाता दोहराता है कि कथित लाभ न्यूनतम है और, जब उचित रूप से आवंटित किया जाता है, नगण्य प्रकृति का है। प्राधिकारी ने इस प्रस्तुति पर विचार नहीं किया है, न ही यह प्रदर्शित किया है कि लाभ की मात्रा प्रतिसंतुलनकारी उपायों को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह जांचने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है कि क्या एडीसी द्वारा प्राप्त कर उपचार वियतनाम में लागू सामान्य कराधान व्यवस्था से विचलित होता है। ऐसे मानक विश्लेषण के अभाव में, यह अंतिम जांच परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि कोई लाभ प्रदान किया गया है। विशिष्टता स्थापित किए बिना और सार्थक लाभ का परिमाणीकरण किए बिना एक सामान्य कर उपाय को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी मानना एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

xvii. आन टिएन ने प्रस्तुत किया है कि कॉर्पोरेट आयकर के संबंध में उसकी अनुरोधों की उचित जांच नहीं की गई है। उत्तरदाता ने निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित कोई आयकर लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, उत्तरदाता पर कॉर्पोरेट आयकर सब्सिडी लगाने का प्रस्ताव पूर्णतः गलत और भ्रामक है।

क) जांच अवधि के दौरान वियतनाम में 20% सामान्य/नियमित कॉर्पोरेट आयकर दर थी जैसा कि वियतनाम सरकार ने भी अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में पुष्टि की है।

ख) कंपनी ने जांच अवधि के दौरान 20% की सामान्य दर पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान किया है जैसा कि सत्यापन दस्तावेजों के भाग के रूप में प्राधिकारी को दायर आयकर रिटर्न से प्रमाणित है।

ग) प्रस्तावित कॉर्पोरेट आयकर सब्सिडी भ्रामक और गलत है क्योंकि कंपनी ने प्राधिकारी को दायर आयकर रिटर्न से प्रमाणित वित्त वर्ष 2023/वित्त वर्ष 2024 दोनों में आयकर का अधिक भुगतान किया।

xviii. उपरोक्त पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारी ने वियतनाम सरकार के उस कार्यक्रम का उल्लेख तक नहीं किया है जिसके तहत कॉर्पोरेट आयकर पर प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर के भुगतान में विलंब पर प्रतिसंतुलनकारी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वियतनाम सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई।

128. <u>घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:</u>

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम उद्यम आयकर पर कानून के तहत कुछ उद्यमों को अधिमान्य कॉर्पोरेट आयकर दरें और कर छुट्टियाँ प्रदान करता है। वियतनाम में वैधानिक कॉर्पोरेट आयकर दर 20% है। प्रोत्साहन योजनाओं के तहत योग्य उद्यम या तो प्रारंभिक अवधि के लिए कॉर्पोरेट आयकर के भुगतान से मुक्त होते हैं या कम दरों पर कर लगाया जाता है।

ii. उसने प्रस्तुत किया कि ऐसा अधिमान्य उपचार त्यागे गए सरकारी राजस्व में परिणत होता है जो अन्यथा 20% की वैधानिक दर पर संग्रहीत किया जाता और इसके द्वारा प्राप्तकर्ता उद्यमों को लाभ प्रदान करता है। यह एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अनुसार वित्तीय अंशदान का गठन करता है।

iii. उक्त सब्सिडी विशिष्ट है, क्योंकि ऐसी छूटों या कम दरों तक पहुँच विशेष क्षेत्रों, क्षेत्रों, परियोजना विशेषताओं, या सरकार-प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों से संबंधित परिभाषित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उद्यमों तक सीमित है। ये शर्तें व्यवहार में सीमित संख्या में उद्यमों को ही लाभ उपलब्ध होने में परिणत होती हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने पक्षकारों के इस तर्क का खंडन किया कि कॉर्पोरेट आयकर छूट सामान्य और गैर-विशिष्ट हैं। उसने प्रस्तुत किया कि तटस्थ वैधानिक भाषा में निर्मित निवेश-संबद्ध कर छूट भी एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2.1(ग) के तहत तथ्यतः विशिष्ट हो सकती हैं यदि, व्यवहार में, वे कुछ उद्यमों, क्षेत्रों या क्षेत्रों तक सीमित हों।

v. पक्षकारों का जांच अवधि के दौरान कॉर्पोरेट आयकर छूट या कटौती प्राप्त करने का अपना अभिस्वीकरण वित्तीय अंशदान और लाभ दोनों का अस्तित्व स्थापित करता है। सब्सिडी का अस्तित्व लाभ के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, और यह तर्क कि लाभ छोटा या समय-सीमित है, यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक हैं कि कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी है या नहीं।

vi. प्राधिकारी को सत्यापित कर अभिलेखों के आधार पर जांच अवधि के दौरान उपार्जित वास्तविक लाभ की जांच करना आवश्यक है। जहाँ पक्ष दावा करते हैं कि लाभ नगण्य है, ऐसे दावों का प्राधिकारी द्वारा गोपनीय वित्तीय और कर आंकड़ों के आधार पर आकलन और पुष्टि की जानी चाहिए।

vii. कानून संख्या 14/2008/क्यूएच12 के तहत, वियतनाम में मानक कॉर्पोरेट आयकर दर प्रारंभ में 25% थी, जो बाद में कानून संख्या 32/2013/क्यूएच13 के अनुसरण में 1 जनवरी 2016 से प्रभावी रूप से घटाकर 20% कर दी गई। 20% की यह वैधानिक दर उन सभी उद्यमों पर लागू होती है जो अधिमान्य उपचार के लिए योग्य नहीं हैं।

viii. वियतनाम सरकार ने ऐसी योजनाएँ शुरू की हैं जिनके तहत कुछ उद्यमों को दो से चार वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए कॉर्पोरेट आयकर से पूर्ण छूट प्रदान की जाती है, जिसके बाद 10% से 20% के बीच कम कॉर्पोरेट आयकर दरें विस्तारित अवधियों के लिए लागू होती हैं जो 30 वर्ष तक चल सकती हैं। इन योजनाओं के लिए पात्रता क्षेत्रीय फोकस, क्षेत्रीय स्थान, परियोजना आकार और उच्च प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, अनुसंधान और कृषि सहित सरकारी प्राथमिकताओं के साथ संरेखण जैसे मानदंडों पर आधारित है।

ix. जहाँ उद्यम 20% की वैधानिक दर से कम दर पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान करते हैं, सरकार अन्यथा देय राजस्व का त्याग करती है, और ऐसे उद्यमों पर लाभ प्रदान किया जाता है। यह व्याख्या एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1 और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध IV के अनुरूप है।

x. प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वैधानिक दर पर देय कर की तुलना वास्तव में भुगतान किए गए कर से करके प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की राशि की गणना करें।

xi. इसी प्रकार का दृष्टिकोण अन्य अधिकारिताओं में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया है। प्रशीतित गर्म जल झींगा पर जांच का संदर्भ दिया गया, जिसमें वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर को मानक माना गया और लाभ निर्धारित करने के लिए अधिमान्य दरों की तुलना इसके विरुद्ध की गई।

129. **<u>प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:</u>**

वित्तीय अंशदान

130. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के सत्यापित कर अभिलेखों और प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के आधार पर, प्राधिकारी पाते हैं कि, जहाँ तक किसी भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान कॉर्पोरेट आयकर छूट या कटौती प्राप्त की है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य वैधानिक उपचार से कम कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान हुआ है, इस कार्यक्रम में अन्यथा देय सरकारी राजस्व के त्याग के रूप में वित्तीय अंशदान शामिल है।

लाभ

131. प्राधिकारी पाते हैं कि, जहाँ तक भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने 20% की सामान्य वैधानिक कॉर्पोरेट आयकर दर से कम दर पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान किया है, या किसी प्रोत्साहन के कारण जांच अवधि के प्रासंगिक भाग के दौरान कोई कॉर्पोरेट आयकर नहीं चुकाया है, इसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है, जो सामान्य वैधानिक उपचार के तहत देय कॉर्पोरेट आयकर और जांच अवधि के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए कॉर्पोरेट आयकर के बीच अंतर के रूप में मापने योग्य है।

विशिष्टता

132. अभिलेख पर प्रमाणित प्रोत्साहन योजनाओं के संचालन के आधार पर, प्राधिकारी पाते हैं कि कॉर्पोरेट आयकर छूट/कटौती कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि लाभ तक पहुँच चिह्नित क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों और/या योग्यता प्राप्त परियोजना श्रेणियों से संबद्ध परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उद्यमों तक सीमित है, और लाभ समान शर्तों के तहत सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध नहीं है।

मानदंड

133. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत लाभ मापने के लिए उपयुक्त मानक 20% की सामान्य वैधानिक कॉर्पोरेट आयकर दर है, जो जांच अवधि के लिए सत्यापित कर योग्य आय/कर आधार पर

लागू की जाती है, जिसमें सत्यापित कर अभिलेखों में प्रतिबिंबित प्राप्तकर्ता-विशिष्ट कर गणनाओं पर उचित ध्यान दिया गया है।

सब्सिडी मार्जिन

134. इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी राशि की गणना प्रत्येक भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक के लिए जांच अवधि के सत्यापित कर फाइलिंग, कर गणना विवरण और सहायक लेखा अभिलेखों के आधार पर, (i) सामान्य वैधानिक उपचार पर मानक कर देयता, (ii) जांच अवधि के दौरान वास्तविक कर देयता और भुगतान किया गया कर, और (iii) दोनों के बीच अंतर को लाभ के रूप में निर्धारित करके की गई है।

<u>कार्यक्रम 4 - कच्चे माल, मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क से छूट</u>

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. कच्चे माल पर आयात शुल्क छूट से संबंधित आरोप उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू नहीं होता। किसी भी उत्तरदाता ने जांच अवधि या क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल या पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरी के लिए किसी आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं किया या उसे प्राप्त नहीं किया। कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के सभी आयात, उत्पत्ति के वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत पहले से ही शून्य सीमा शुल्क के अधीन थे। मुक्त व्यापार समझौते के तहत त्यागा गया शुल्क प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं बनता।

ii. पक्षकारों को उनके परिचालनों से संबद्ध कोई पृथक या अतिरिक्त आयात शुल्क छूट प्राप्त नहीं हुई। यह प्रदर्शित करने के लिए मद-वार आयात शुल्क स्क्रीनशॉट, बिल ऑफ एंट्री और शुल्क-मुक्त आयात अभिलेख प्रस्तुत किए गए कि आयात पूर्णतः मुक्त व्यापार समझौतों के प्रचालन द्वारा शून्य शुल्क पर क्लियर किए गए थे न कि किसी सब्सिडी योजना के तहत।

iii. वियतनाम सरकार ने प्रस्तुत किया कि निर्यातित उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुटों पर आयात शुल्क छूट, अपने आप में, प्रतिसंतुलनकारी निर्यात सब्सिडी नहीं बनती। एससीएम समझौते के अनुबंध I(i) पर भरोसा किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि निर्यातित उत्पादों के उत्पादन में उपभुक्त इनपुटों पर आयात प्रभारों की छूट या वापसी प्रतिसंतुलनकारी नहीं है, बशर्ते ऐसी छूट आयातित इनपुटों पर वास्तव में लगाए गए शुल्कों से अधिक न हो।

iv. वियतनाम सरकार ने आगे प्रस्तुत किया कि वियतनाम में प्रभावी अनुवर्तन प्रणाली के अभाव का आरोप लगाने वाले पूर्व निर्धारण अब मान्य नहीं हैं। वियतनाम ने निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क-मुक्त कच्चे माल के आयात, उपभोग और उपयोग का अनुवर्तन करने के लिए एक व्यापक सीमा शुल्क नियंत्रण और सत्यापन तंत्र स्थापित किया है। डिक्री 08/2015/एनडी-सीपी, परिपत्र 38/2015/टीटी-बीटीसी और 39/2018/टीटी-बीटीसी, और डिक्री 59/2018/एनडी-सीपी का संदर्भ दिया गया, जो उत्पादकों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर दायित्व निर्धारित करते हैं।

v. वियतनाम सरकार ने प्रस्तुत किया कि निर्यात उत्पादन के लिए कच्चा माल आयात करने वाले उत्पादकों को (i) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उत्पादन सुविधाओं और भंडारण स्थानों की सूचना देना, (ii) प्रत्येक उत्पाद के लिए सामग्री उपभोग के मानकों को बनाए रखना, (iii) आयातित

सामग्रियों के स्टॉक-इन, स्टॉक-आउट और अवशेषों का विस्तृत अभिलेख रखना, और (iv) ऐसे अभिलेखों का लेखा दस्तावेजीकरण के साथ मिलान करना आवश्यक है। आयातकों पर ऐसे अभिलेखों और घोषणाओं की सटीकता के लिए कानूनी उत्तरदायित्व होने का उल्लेख किया गया है।

vi. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क प्राधिकारी इन अभिलेखों को प्राप्त करने और जांचने, सुविधा निरीक्षण करने, मालसूचियों का सत्यापन करने और जोखिम प्रबंधन मानदंडों के आधार पर क्लियरेंस पश्चात लेखापरीक्षा करने के लिए सशक्त हैं। जहाँ अनियमितताओं या व्यापार धोखाधड़ी का संदेह हो, सीमा शुल्क प्राधिकारी कानून के अनुसार शुल्क और शास्ति लगा सकते हैं। इसने तर्क दिया कि यह प्रणाली सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाती है कि क्या शुल्क-मुक्त आयातित इनपुट वास्तव में निर्यातित उत्पादों में उपयोग किए गए हैं।

vii. वियतनाम सरकार ने प्रस्तुत किया कि यह सीमा शुल्क सत्यापन ढांचा अन्य अधिकारिताओं में अपनाई गई प्रणालियों से तुलनीय है। इसने तर्क दिया कि, यदि घरेलू उद्योग वियतनाम की प्रणाली की प्रभावशीलता पर विवाद करता है, तो उसे प्रदर्शित करना होगा कि वियतनाम की प्रणाली भारत की सीमा शुल्क प्रणाली से किस प्रकार भौतिक रूप से भिन्न या कम प्रभावी है। ऐसे प्रमाण के अभाव में, कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी नहीं माना जाना चाहिए।

viii. व्यक्तिगत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान कच्चे माल पर किसी आयात शुल्क छूट या छूट का लाभ नहीं उठाया है। चूंकि उनके द्वारा कोई छूट या छूट नहीं ली गई, सब्सिडी, वित्तीय अंशदान और लाभ के आवश्यक तत्व उनके मामले में अनुपस्थित हैं।

ix. पक्षकारों ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का यह आरोप कि आयात शुल्क छूट त्यागे गए राजस्व का गठन करती है, गलत है। आवेदक का वैधानिक शुल्क दरों को मानक मानने और इनपुटों के लिए आवर्ती आधार पर या पूंजीगत वस्तुओं के लिए कल्पित औसत उपयोगी आयु पर लाभ आवंटित करने का प्रस्ताव, वास्तव में प्राप्त किसी छूट के अभाव में काल्पनिक और साक्ष्य से असमर्थित है।

x. पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि औसत उपयोगी आयु पर आवंटन केवल तभी प्रासंगिक हो सकता है जब छूट वास्तव में प्राप्त की गई हो। अन्यथा भी, आवेदक का सभी मशीनरी के लिए आठ वर्ष की एकसमान औसत उपयोगी आयु की धारणा मनमानी है और डी जी टी आर की प्रथा के असंगत है। औसत उपयोगी आयु परिसंपत्ति-विशिष्ट होनी चाहिए और लेखापरीक्षित अभिलेखों या लागू मूल्यह्रास अनुसूचियों जैसे साक्ष्य द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

136. घरेलू **उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:**

i. डिक्री संख्या 134/2016/एनडी-सीपी के तहत, वियतनाम सरकार उत्पादन और निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करती है। ऐसी छूटों में सीमा शुल्क के रूप में अन्यथा संग्रहीत किए जाने वाले सरकारी राजस्व का त्याग शामिल है और इसलिए एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अर्थ में वित्तीय अंशदान का गठन करती हैं।

ii. कच्चे माल पर आयात शुल्क छूट आवर्ती सब्सिडी हैं, क्योंकि कच्चा माल उत्पादन के लिए निरंतर और पुनरावृत्त आधार पर आयात किया जाता है। कच्चे माल के शुल्क-मुक्त आयात का प्रत्येक उदाहरण सरकार द्वारा त्यागे गए राजस्व में परिणत होता है और प्राप्तकर्ता उद्यमों पर लाभ प्रदान करता है।

iii. विश्व व्यापार संगठन कानून और महानिदेशालय की प्रथा के तहत, निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में उपभुक्त इनपुटों पर आयात शुल्क छूट को केवल वहीं गैर-प्रतिसंतुलनकारी माना जा सकता है जहाँ एक उचित रूप से क्रियान्वित और सत्यापित प्रणाली विद्यमान हो जो यह सुनिश्चित करे कि शुल्क-मुक्त इनपुट पूर्णतः निर्यातित वस्तुओं में उपभुक्त मात्राओं तक सीमित हैं। ऐसी सत्यापित प्रणाली के अभाव में, या जहाँ इसका क्रियान्वयन अपर्याप्त है, संपूर्ण शुल्क छूट को प्रतिसंतुलनकारी माना जाना चाहिए।

iv. वियतनाम में जांचाधीन उत्पाद के भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों पर यह दायित्व है कि वे अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और सहायक साक्ष्य के माध्यम से, आयातित विशिष्ट कच्चे माल, उत्पादन में उपभुक्त मात्राओं और जिस प्रकार कोई शुल्क छूट लागू की गई, को प्रदर्शित करें। जहाँ ऐसा साक्ष्य अनुपस्थित, अपूर्ण या असत्यापनीय है, प्राधिकारी को संपूर्ण त्यागे गए शुल्क को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी मानना चाहिए।

v. महानिदेशालय की पिछली प्रथा पर भरोसा किया गया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका से "फाइबरबोर्ड" के आयात से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शामिल है, जिसमें निर्यातित वस्तुओं में शुल्क-मुक्त इनपुटों के उपभोग के प्रभावी सत्यापन के अभाव में कच्चे माल पर आयात शुल्क छूट को प्रतिसंतुलनकारी माना गया था।

vi. कच्चे माल के लिए उपयुक्त मानक जांच अवधि के दौरान प्रासंगिक कच्चे माल पर लागू वैधानिक आयात शुल्क दर है। लाभ की गणना देय वैधानिक शुल्क और वास्तव में भुगतान किए गए शुल्क के बीच अंतर के रूप में की जानी चाहिए। जहाँ कोई शुल्क भुगतान नहीं किया गया है, संपूर्ण त्यागे गए वैधानिक शुल्क को लाभ माना जाना चाहिए।

vii. मशीनरी और उपकरणों के संबंध में, आयात शुल्क छूट अनावर्ती सब्सिडी हैं, क्योंकि मशीनरी और उपकरण सामान्यतः एक बार आयात किए जाते हैं और फिर अपने उपयोगी जीवनकाल में उपयोग किए जाते हैं। यद्यपि छूट एक ही समय बिंदु पर होती है, लाभ उस अवधि में उपार्जित होता रहता है जिसके दौरान परिसंपत्ति उत्पादन में उपयोग की जाती है।

viii. विश्व व्यापार संगठन कानून और महानिदेशालय की प्रथा यह मान्यता देती है कि पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क छूट प्रतिसंतुलनकारी है, भले ही ऐसी वस्तुओं का उपयोग निर्यातित उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता हो। प्रदान किया गया लाभ आयात के समय त्यागा गया शुल्क है, जिसे मशीनरी या उपकरण की औसत उपयोगी आयु पर आवंटित किया जाना चाहिए।

ix. मशीनरी और उपकरणों के लिए मानक आयात के समय लागू वैधानिक सीमा शुल्क होना चाहिए। लाभ, वैधानिक दर पर देय शुल्क और वास्तव में भुगतान किए गए शुल्क के बीच का अंतर है।

x. व्यापार उपचार जांच के लिए महानिदेशालय की संचालन प्रथाओं की नियमावली स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अनावर्ती सब्सिडियों, जैसे पूंजीगत परिसंपत्तियों पर शुल्क छूट, से लाभों पर उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक मूर्त या अमूर्त परिसंपत्तियों की औसत उपयोगी आयु पर विचार किया जाना चाहिए।

xi. घरेलू उद्योग ने फाइबरबोर्ड जांच सहित स्थापित महानिदेशालय प्रथा के अनुरूप, आठ वर्ष की औसत उपयोगी आयु प्रस्तावित की है। तदनुसार, मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क छूट से उत्पन्न किसी भी लाभ को जांच अवधि के लिए उत्तरदायी लाभ का भाग निर्धारित करने के लिए आठ वर्ष की अवधि पर आवंटित किया जाना चाहिए।

xii. प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या मशीनरी और उपकरणों पर ऐसी कोई अनावर्ती सब्सिडी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान वियतनाम में जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा प्राप्त की गई थी, क्योंकि पूर्व वर्षों में प्राप्त किंतु जांच अवधि के दौरान लाभ देना जारी रखने वाली अनावर्ती सब्सिडियाँ प्रतिसंतुलनकारी बनी रहती हैं।

xiii. प्राधिकारी यह सत्यापित करने के लिए गोपनीय आयात आंकड़ों, बिल ऑफ एंट्री, शुल्क भुगतान अभिलेखों और प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं पर भरोसा कर सकते हैं कि क्या कोई त्यागा गया आयात शुल्क वित्तीय अंशदान और लाभ का गठन करता है।

प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्तरदाता ने जांच अवधि या क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल या पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरी के लिए किसी आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं किया या उसे प्राप्त नहीं किया। कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के सभी आयात पहले से ही शून्य सीमा शुल्क के अधीन थे।

138. तदनुसार, प्राधिकरण ने इस विशेष कार्यक्रम की प्रतिकारी योग्यता की जांच नहीं की है।

ब्याज दर सब्सिडियों के रूप में चिह्नित योजनाओं की सूची

कार्यक्रम 5 - निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण

कार्यक्रम 7 - निर्यातकों को अधिमान्य ऋण

कार्यक्रम 8 - निवेश ऋण ऋणों की ब्याज दर

कार्यक्रम 9 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश सहायता

कार्यक्रम 10 - वियतनाम विकास बैंक से निर्यात ऋण

कार्यक्रम 11 - वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उपरोक्त कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण संबंधी आरोप उन पर लागू नहीं है, क्योंकि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने वियतनाम विकास बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।

ii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम या वियतनाम विकास बैंक से कोई रियायती या निर्यात-संबद्ध ऋण प्राप्त नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की ब्याज दर सीमाएँ और संबंधित उपाय अर्थव्यवस्था-व्यापी अनुप्रयोग के सामान्य मौद्रिक नीति उपकरण हैं और सब्सिडी का गठन या विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करते।

iii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ढांचे के तहत पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनका पूंजी निवेश लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकरण की सीमाओं से अधिक है। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम उन पर लागू नहीं होता।

iv. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जांच अवधि या किसी अन्य प्रासंगिक अवधि के दौरान वियतनाम विकास बैंक से कोई निर्यात ऋण या निर्यात-संबद्ध वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान वियतिन बैंक या किसी अन्य राज्य-स्वामित्व वाले बैंक से कोई वित्तीय गारंटी प्राप्त नहीं की है। वियतिन बैंक के साथ कोई ऋण या गारंटी संबंध नहीं है।

v. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि जांच अवधि के दौरान प्राप्त ऋण बाजार-आधारित शर्तों पर बाजार-निर्धारित ब्याज दरों पर निजी वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त किए गए थे। ऐसे वाणिज्यिक उधारों के दस्तावेजी साक्ष्य किसी रियायती या सरकार-निर्देशित ऋण की अनुपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर रखे गए हैं।

vi. अधिमान्य ऋण के लिए नीतिगत ढांचे का अस्तित्व, अपने आप में, प्रतिकार्यता स्थापित नहीं करता। लाभ केवल वहीं उत्पन्न हो सकता है जहाँ ऋण बाजार पर उपलब्ध शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान मामले में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

vii. वियतनाम सरकार प्रस्तुत करती है कि जांच किए गए निर्यातकों को कोई वास्तविक मापने योग्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ और सब्सिडी अंतिम जांच परिणाम धारणाओं या सैद्धांतिक गणनाओं के बजाय संबंधित उद्यमों को वास्तविक और मापने योग्य लाभ के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले सत्यापित साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।

viii. वीएमआई ने जोर देकर कहा कि उसने जांच अवधि के दौरान राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों, वियतनाम विकास बैंक, या किसी अधिमान्य सरकारी वित्तपोषण कार्यक्रम से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया था। वीएमआई ने कहा कि प्रासंगिक अवधि के दौरान सभी वित्तपोषण व्यवस्थाएँ बाजार ब्याज दरों पर निजी वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त की गई थीं और इन तथ्यों का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे। इसलिए वीएमआई ने तर्क दिया कि इन कार्यक्रमों के तहत कोई वित्तीय अंशदान या लाभ विद्यमान नहीं था और प्राधिकारी से तदनुसार शून्य सब्सिडी अंतर निर्धारित करने का अनुरोध किया।

ix. आन टिएन ने कहा कि उसे कोई अधिमान्य ऋण या ब्याज दर लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वह तर्क देता है कि प्रकटीकरण विवरण ने यह दिखाने वाले साक्ष्य की उचित जांच नहीं की है कि वियतनामी राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा निधियों का कोई प्रत्यक्ष अंतरण नहीं किया गया था, और राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों से सामान्य ऋणों को वित्तीय अंशदान मानना गलत रूप से यह अर्थ लगाएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, से ऋण भी सब्सिडी हैं। आन टिएन आगे प्रस्तुत करता है कि उसकी परियोजनाएँ/उत्पाद डिक्री संख्या 32/2017/एनडी-सीपी के तहत शामिल नहीं हैं, और उसके स्थानीय मुद्रा ऋण राज्य-स्वामित्व और निजी विदेशी बैंकों दोनों से बाजार-चालित ब्याज दरों पर प्राप्त किए गए थे। बैंकों की दोनों श्रेणियों द्वारा ली जाने वाली तुलनीय दरें प्रदर्शित करती हैं कि कोई अधिमान्य दर या प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

x. विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर) ऋणों की ब्याज दर अंतरराष्ट्रीय मानक (लिबोर) द्वारा निर्धारित होती है न कि वियतनाम सरकार के विनियमों/डिक्री द्वारा। यही कारण है कि फाइबरबोर्ड जैसी पिछली जांचों में प्राधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों पर कोई ब्याज सब्सिडी निर्धारित नहीं की गई है।

xi. मानक के संबंध में, प्रकटीकरण विवरण में यह प्रस्तावित है कि "प्राधिकारी वियतनाम में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा, जो वियतनाम में राज्य-स्वामित्व वाला बैंक नहीं है, द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर को अपनाने का प्रस्ताव करते हैं।" इसका अर्थ है कि विदेशी निजी बैंक की ब्याज दर को मानक मानने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया की वियतनाम शाखा की ब्याज दर मानक के रूप में मनमानी है और यह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि ऋण सुरक्षित है या नहीं, ऋण

की अवधि, ऋणपात्रता निर्धारण, उद्योग जोखिम आदि जैसे मापदंड। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर के लिए प्रदान किए गए सहायक दस्तावेज स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि "उपरोक्त दरें संदर्भ के लिए हैं और मामला-दर-मामला आधार पर बातचीत योग्य हैं"। इसलिए, इसे मानक नहीं माना जा सकता।

xii. उत्तरदाता के इस प्रस्तुतीकरण पर बिना किसी पूर्वाग्रह के कि उसने कोई ब्याज सब्सिडी प्राप्त नहीं की है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता ने *** (निजी विदेशी बैंक) और *** (निजी विदेशी बैंक) से भी ऋण लिया है। इसलिए, उत्तरदाता के सब्सिडी अंतर के निर्धारण के लिए उसी की वास्तविक ब्याज दर पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उपर्युक्त कारकों के कारण ब्याज दर भिन्न होती है।

140. <u>घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:</u>

i. सरकार-स्वामित्व या सरकार-निर्देशित वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण देना निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का गठन करता है। जहाँ ऐसे ऋण रियायती ब्याज दरों पर दिए जाते हैं, वे प्राप्तकर्ता उद्यमों पर मापने योग्य लाभ प्रदान करते हैं।

ii. वियतनाम सरकार डिक्री संख्या 75/2011/एनडी-सीपी के तहत वियतनाम विकास बैंक के माध्यम से निवेशकों को अधिमान्य ऋण प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के तहत, पात्र उद्यम वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध ब्याज दरों से कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वियतनाम में राज्य-स्वामित्व वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के नीतिगत निर्देशन और नियामक नियंत्रण के तहत निर्यातकों को रियायती ब्याज दरों पर निर्यात-संबद्ध ऋण प्रदान करते हैं।

iii. प्लास्टिक निर्माण को एक सहायक उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, प्लास्टिक निर्माण में संलग्न उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत निवेश ऋण ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, और यह कार्यक्रम जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों पर लागू है।

iv. वियतनाम सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता पर कानून के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमों को निवेश सहायता प्रदान करती है। ये कानूनी उपकरण पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का ढांचा निर्धारित करते हैं, चाहे ऐसे उद्यम घरेलू या विदेशी निवेशकों द्वारा स्वामित्व में हों।

v. वियतनाम सरकार एक निर्यात ऋण कार्यक्रम संचालित करती है। इस कार्यक्रम के तहत, पात्र निर्यातकों को निर्यात अनुबंधों के मूल्य के 85% तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे सीधे ऋण की उपलब्धता निर्यात गतिविधि से संबद्ध हो जाती है।

vi. वियतनाम बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय गारंटी कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी का गठन किया जाता है। ऋणों पर गारंटी प्रदान करके, वियतिन बैंक ऋण जोखिम वहन करता है जो अन्यथा वाणिज्यिक ऋणदाताओं द्वारा वहन किया जाता। ऐसी गारंटियाँ जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले प्राप्तकर्ता उद्यमों की ऋणपात्रता में सुधार करती हैं और उन्हें कम ब्याज दरों पर, या ऐसी शर्तों पर वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं जो ऐसी गारंटियों के अभाव में उपलब्ध नहीं होतीं।

vii. ली जाने वाली रियायती ब्याज दर और बाजार-निर्धारित वाणिज्यिक ब्याज दर के बीच का अंतर प्रदान किए गए लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, और त्यागी गई ब्याज आय सरकार द्वारा त्यागे गए राजस्व का गठन करती है।

viii. लाभ के निर्धारण के लिए, उपयुक्त मानक तुलनीय ऋणों के लिए वियतनाम में निजी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है। केवल ऐसी वाणिज्यिक दरों के साथ रियायती ऋण दर की तुलना करके ही प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में प्राप्तकर्ता ने क्या भुगतान किया होता।

ix. प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वियतनाम में वाणिज्यिक ऋण दरों के साक्ष्य की जांच करें, जिसमें वियतनाम में कार्यरत निजी बैंकों द्वारा ली जाने वाली दरें और विश्व बैंक ब्याज दर आंकड़े जैसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संकेतक शामिल हैं, ताकि लाभ गणना के लिए एक विश्वसनीय मानक स्थापित किया जा सके।

<u>प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:</u>

वित्तीय अंशदान

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम विकास बैंक और वियतनाम के अन्य राज्य-स्वामित्व वाले बैंक एक सार्वजनिक निकाय हैं क्योंकि यह वियतनाम सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है और सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करता है। वियतनाम विकास बैंक या किसी अन्य राज्य-स्वामित्व वाले बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान की प्रकृति में हैं।

142. जब कोई वित्तीय संस्थान जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, ऋण प्रदान करता है, यह निधियों के प्रत्यक्ष प्रावधान के माध्यम से वित्तीय अंशदान के समकक्ष है। यदि ये ऋण बाजार से कम ब्याज दरों पर दिए जाते हैं, तो ये प्राप्तकर्ता कंपनियों को परिमाणात्मक लाभ देते हैं।

143. प्राधिकारी ने "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब", "सतत ढलवाँ तांबे की तार की छड़ें", "कॉपर ट्यूब और पाइप" और "फाइबरबोर्ड" से संबंधित वियतनाम के विरुद्ध पिछली सब्सिडी रोधी जांच में इन कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलनकारी माना है। क्या किसी दिए गए उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान ऐसा वित्तीय अंशदान प्राप्त किया है, इस प्रश्न की जांच सत्यापित कंपनी-विशिष्ट अभिलेखों के आधार पर की गई है।

लाभ

144. प्राधिकारी का मानना है कि, जहाँ ऋण प्राप्त किए जाते हैं और वियतनामी बाजार में प्राप्तकर्ता को उपलब्ध तुलनीय वाणिज्यिक ऋण से अधिक अनुकूल दरों पर हैं, ऐसा ऋण प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध IV और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 14(ख) के अर्थ में लाभ प्रदान करता है। प्रत्येक उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक के लिए लाभ का अस्तित्व और परिमाण सत्यापित ऋण दस्तावेजीकरण और उपयुक्त वाणिज्यिक मानक के साथ तुलना के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विशेषता

145. प्राधिकारी का मानना है कि ये कार्यक्रम नियम 9 और अनुच्छेद 2 के अर्थ में विशिष्ट हैं, क्योंकि कार्यक्रम तक पहुँच संबंधित परियोजना सूचियों और संबंधित मानदंडों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उद्यमों/परियोजनाओं तक सीमित है, और इसलिए बिना किसी प्रतिबंध के अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमों के लिए सामान्यतः उपलब्ध नहीं है।

मानक

146. प्राधिकारी का मानना है कि लाभ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मानक जांच अवधि के दौरान वियतनाम में प्राप्तकर्ता को उपलब्ध तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज दर है। आवेदकों ने वियतनाम में बैंक ऑफ इंडिया

की शाखा, जो वियतनाम में राज्य-स्वामित्व वाला बैंक नहीं है, द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर को अपनाने का प्रस्ताव किया। तथापि, आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए सहायक साक्ष्य से यह ध्यान दिया जाता है कि प्रस्तावित दरें केवल संदर्भ प्रयोजनों के लिए हैं और मामला-दर-मामला आधार पर बातचीत योग्य हैं। प्रस्तावित दर इस बात पर ध्यान नहीं देती कि ऋण सुरक्षित है या नहीं, ऋण की अवधि, ऋणपात्रता निर्धारण, उद्योग जोखिम आदि जैसे मापदंड। इसलिए, इसे मानक के रूप में नहीं किया है।

147. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया से यह ध्यान दिया जाता है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों और निजी विदेशी (गैर-वियतनाम) बैंकों दोनों से ऋण लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी वियतनाम में कार्यरत निजी विदेशी बैंकों की वास्तविक ब्याज दर (जांच अवधि से संबंधित) को उपयुक्त मानक के रूप में अपनाते हैं।

सब्सिडी मार्जिन

148. प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि वियतनाम विकास बैंक और वियतनाम के स्थानीय वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी प्रत्येक उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक के सत्यापित ऋण आंकड़ों और ऊपर निर्धारित मानक के आधार पर अधिमान्य ऋण के तहत कंपनी-विशिष्ट सब्सिडी अंतरों की गणना करते हैं, और परिणामी अंतरों को सब्सिडी गणना तालिकाओं में शामिल करते हैं।

अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में चिह्नित योजनाओं की सूची

कार्यक्रम 2 - वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए कथित मास्टर प्लान के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। मास्टर प्लान को कच्चे माल के उत्पादन से लेकर तैयार माल तक एक समन्वित प्लास्टिक उद्योग विकसित करने के लिए वियतनाम सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले एक योजना दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया है। मास्टर प्लान कुछ प्राथमिकता या लाभार्थी परियोजनाओं की पहचान करता है, जिनमें से कोई भी उत्तरदाताओं या जांचाधीन उत्पाद को शामिल नहीं करता। यह उनके निवेश पंजीकरण प्रमाणपत्रों से भी स्पष्ट है, जो मास्टर प्लान से कोई लाभ या संबद्धता दर्ज नहीं करते।

ii. मास्टर प्लान एक उच्च-स्तरीय औद्योगिक नीति या रणनीति दस्तावेज है और, अपने आप में, सब्सिडी कार्यक्रम का गठन नहीं करता। इसमें वित्तीय अंशदान प्रदान करने के लिए कोई प्रचालन तंत्र शामिल नहीं है, जैसे बजटीय आवंटन, अनुदान, अधिमान्य ऋण, कर प्रोत्साहन, गारंटी या प्रतिपूर्तियाँ। एक नीतिगत ढांचे को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी नहीं माना जा सकता जब तक कि यह वित्तीय अंशदान से जुड़ी एक ठोस योजना स्थापित न करे और पहचान योग्य उद्यमों पर मापने योग्य लाभ प्रदान न करे। ऐसे प्रचालन प्रावधानों के अभाव

में, मास्टर प्लान को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों या एससीएम समझौते के अर्थ में सब्सिडी नहीं माना जा सकता।

iii. मास्टर प्लान निधियों के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतरण, त्यागे गए राजस्व, वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान, या मूल्य/आय समर्थन को अधिदेशित या प्रदान नहीं करता। पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मास्टर प्लान के अनुसरण में कोई अधिमान्य ऋण, कर लाभ, व्यापार प्रोत्साहन सहायता, प्रशिक्षण सहायता, अवसंरचना सहायता, या वित्तीय सहायता का कोई अन्य रूप प्राप्त नहीं किया है। आवेदकों द्वारा किसी संवितरण, लेन-देन या मापने योग्य लाभ का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया बताया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय अंशदान और लाभ दोनों तत्वों की अनुपस्थिति का दावा किया गया है।

iv. मास्टर प्लान वियतनाम में संपूर्ण प्लास्टिक उद्योग मूल्य श्रृंखला पर व्यापक रूप से लागू होता है, जिसमें कच्चा माल, मध्यवर्ती इनपुट, तैयार उत्पाद, योजक और सहायक उद्योग शामिल हैं। ऐसी क्षेत्र-व्यापी नीति विशिष्टता की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, क्योंकि यह कुछ उद्यमों, उद्यमों के समूहों, क्षेत्रों या उत्पादों तक सीमित नहीं है, न ही इसमें लाभार्थियों का विवेकाधीन चयन शामिल है। इस आधार पर, मास्टर प्लान के गैर-विशिष्ट और इसलिए प्रतिसंतुलनकारी न होने का दावा किया गया है।

v. अन्य देशों की बाजार विकास या औद्योगिक योजनाओं से संबंधित पूर्ववर्ती महानिदेशालय जांच परिणामों पर घरेलू उद्योग का भरोसा अनुपयुक्त है। वे मामले वियतनामी मास्टर प्लान के विपरीत, वास्तविक बजटीय आवंटनों और प्रतिपूर्ति योग्य अनुदानों वाली स्पष्ट रूप से परिभाषित योजनाओं से जुड़े थे, जो बिना किसी स्वचालित या प्रचालन वित्तीय सहायता तंत्र के केवल नीतिगत उद्देश्यों को निर्धारित करता है।

vi. भले ही कोई अनुप्रवाह पहल काल्पनिक रूप से मास्टर प्लान से संबद्ध थीं, पक्षकारों ने जांच अवधि के दौरान ऐसी कोई पहल प्राप्त नहीं की है। महानिदेशालय की प्रथा के अनुरूप, जहाँ कोई कार्यक्रम किसी पक्ष द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, उत्तरदायी लाभ शून्य माना जाना चाहिए।

150. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वियतनाम सरकार ने वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए एक मास्टर प्लान शुरू किया है जिसका घोषित उद्देश्य कच्चे माल के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद प्रसंस्करण तक क्रमशः प्रगति करते हुए एक समकालिक प्लास्टिक उद्योग का निर्माण और विकास करना है। मास्टर प्लान का लक्ष्य प्लास्टिक उद्योग को सतत विकास के साथ एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र में रूपांतरित करना है। इसके उद्देश्यों में कच्चे माल, अर्ध-तैयार उत्पादों, रसायनों और योजकों के उत्पादन के लिए घरेलू और विदेशी निवेश जुटाना; उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक सामग्री और उत्पादों का उत्पादन करना; और प्लास्टिक सामग्री निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है।

ii. मास्टर प्लान प्लास्टिक उद्योग प्रतिभागियों को सहायता के अनेक रूपों की परिकल्पना और प्रावधान करता है। इनमें सरकार से अधिमान्य ऋण, प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए विकास और प्रौद्योगिकी सहायता कोषों की स्थापना, उन्नत व्यापार प्रोत्साहन और बाजार अनुसंधान सहायता, तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए आंशिक राज्य सहायता, और निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। मास्टर प्लान प्रमुख यांत्रिक इंजीनियरी उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के समान निवेश प्रोत्साहनों के लिए प्लास्टिक उद्योग परियोजनाओं की पात्रता की भी परिकल्पना करता है, जिसमें कुल निवेश लागतों के एक महत्वपूर्ण भाग तक को कवर करने वाले निवेश ऋण तक पहुँच शामिल है। इसके अलावा, यह सरकार-समर्थित गारंटियों, औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता, और उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल और तैयार प्लास्टिक उत्पादों पर आयात शुल्कों के समायोजन का प्रावधान करता है।

iii. मास्टर प्लान में रेखांकित उपायों में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण, सेवाओं का प्रावधान, और कर एवं शुल्क प्रोत्साहनों के रूप में सरकारी राजस्व का त्याग शामिल है। ये उपाय, एक साथ लिए जाने पर, वियतनाम सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान का गठन करते हैं। प्राप्तकर्ता उद्यमों को लाभ रियायती वित्त, अनुदान, गारंटियों, कर राहत, प्रशिक्षण सब्सिडियों, व्यापार प्रोत्साहन सहायता और अवसंरचना सहायता तक पहुँच से उत्पन्न होता है, जो बाजार स्थितियों की तुलना में उत्पादन और निवेश लागतों को कम करते हैं।

iv. जांचाधीन उत्पाद प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसलिए मास्टर प्लान के तहत प्रोत्साहित उत्पादों के दायरे में पूर्णतः आता है। ऐसे कच्चे माल का उत्पादन विशेष रूप से निवेश, वित्त, अवसंरचना और आयात शुल्क समायोजनों से संबंधित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। परिणामस्वरूप, जांचाधीन उत्पाद के उत्पादक मास्टर प्लान के तहत परिकल्पित सहायता उपायों को प्राप्त करने और उनसे लाभान्वित होने के पात्र हैं।

v. मास्टर प्लान के तहत सहायता उपाय प्लास्टिक उद्योग मूल्य श्रृंखला के भीतर चिह्नित क्षेत्रों और गतिविधियों तक सीमित हैं। प्लास्टिक उद्योग और इसके अपस्ट्रीम कच्चे माल, जिसमें जांचाधीन उत्पाद शामिल है, को लक्षित करके, यह कार्यक्रम क्षेत्र-विशिष्ट है और इसलिए, प्रतिकार्यता के लिए विशिष्टता की आवश्यकता को पूरा करता है।

vi. प्राधिकारी ने, पूर्व प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में, समान बाजार विकास या उद्योग-विशिष्ट योजनाओं को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी माना है, भले ही उत्तरदाताओं ने गैर-प्राप्ति का दावा किया हो। ऐसे मामलों में, प्राधिकारी ने कार्यक्रम की अभिकल्पना और कार्यक्षेत्र की जांच की है और उपायों को प्रतिसंतुलनकारी माना है जहाँ उनमें परिभाषित क्षेत्र के लिए वित्तीय अंशदान और लाभ शामिल थे। इस आधार पर, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम का गठन करता है।

vii. इस कार्यक्रम के तहत लाभ को जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि या, जहाँ लागू हो, मास्टर प्लान के अनुसरण में प्रदान किए गए कर और शुल्क प्रोत्साहनों, गारंटियों, या रियायती वित्तपोषण के माध्यम से त्यागे गए सरकारी राजस्व की राशि के रूप में मापा जाना चाहिए।

प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम की प्रतिकारी योग्यता की जांच नहीं की है।

कार्यक्रम 6 - निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम

152. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि वियतनाम सरकार निर्यात-संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने वाला एक निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित करती है, पक्षकारों ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत किसी सहायता में भाग नहीं लिया, आवेदन नहीं किया या प्राप्त नहीं की। यह कहा गया है कि आवेदक ने किसी पक्ष द्वारा लाभों की वास्तविक प्राप्ति प्रदर्शित करने वाला प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभिलेख पर रखे बिना इस कार्यक्रम की जांच की मांग की है।

ii. यह स्वीकार किया गया है कि निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए आंशिक लागत सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिसमें निर्यात विकास के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति, व्यापार मेलों में भागीदारी, परामर्श और संबंधित प्रोत्साहन पहलों के लिए खर्चों की 50% तक की प्रतिपूर्ति शामिल है। आवेदक ने जांचाधीन उत्पाद के निर्यात पर 6% के निर्यात-संबंधित कर प्रोत्साहन के अस्तित्व का भी आरोप लगाया है, यद्यपि उत्तरदाता तर्क देते हैं कि आवेदक स्वयं सीमित जानकारी होना स्वीकार करता है और उसने व्यवहार में ऐसे प्रोत्साहन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य या वैधानिक प्रावधानों से इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

iii. उनके मामले में कोई वित्तीय अंशदान विद्यमान नहीं है, क्योंकि वियतनाम सरकार से कोई अनुदान, प्रतिपूर्ति, सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, वापसी या अन्य वित्तीय अंतर्वाह प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि जांच अवधि के लिए उत्तरदाताओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखा अभिलेखों, बैंक खाताबहियों और वैधानिक फाइलिंग में किसी निर्यात प्रोत्साहन या राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्तियों या लाभों को प्रतिबिंबित करने वाली कोई प्रविष्टियाँ नहीं हैं। उन्होंने ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हुए जैसे निर्यात परामर्श, व्यापार मेला भागीदारी, या सलाहकार सेवाएँ जो कथित कार्यक्रम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए योग्य होतीं।

iv. वियतनाम में राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम देश की समग्र व्यापार प्रोफाइल और अंतरराष्ट्रीय दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य सरकारी कार्य हैं। ऐसे उपायों में बाजार अध्ययन, व्यापार मेले, ब्रांडिंग पहल, सूचना का प्रसार और निर्यात-संबंधी सलाहकार सहायता शामिल हैं, जो क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों तक सीमित नहीं हैं। ऐसी सामान्य प्रोत्साहन गतिविधियाँ, भले ही सरकार द्वारा की जाएँ, विशिष्ट सब्सिडी नहीं बनतीं और किसी विशेष उद्यम, उद्योग या उद्यमों के समूह पर लक्षित नहीं होतीं।

v. निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम एससीएम समझौते या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अर्थ में विशिष्ट नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम तक पहुँच व्यापक, अर्थव्यवस्था-व्यापी मानदंडों पर आधारित है और किसी विशेष उद्योग, उत्पाद या निर्यातकों के समूह तक सीमित नहीं है। केवल यह तथ्य कि कुछ उद्यम भाग लेना चुन सकते हैं, कार्यक्रम को विशिष्ट नहीं बनाता, और आवेदक ने जांचाधीन उत्पाद के निर्यातकों के संबंध में न तो विधितः और न ही तथ्यतः विशिष्टता प्रदर्शित की है।

vi. कथित कार्यक्रम विश्व व्यापार संगठन कानून के तहत अपेक्षित अर्थ में निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक नहीं है। व्यापार प्रोत्साहन गतिविधियों में भागीदारी निर्यात मात्रा, निर्यात मूल्यों या निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर नहीं करती, और स्वतः निर्यात निष्पादन से संबद्ध वित्तीय पुरस्कार प्रदान नहीं करती। जांचाधीन उत्पाद के निर्यात और वित्तीय सहायता की प्राप्ति के बीच किसी संबद्धता का कोई साक्ष्य नहीं है।

vii. सभी लागू करों का भुगतान वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया, और कर देयता में कोई कमी या निर्यात-संबद्ध राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसी कर रियायत के अभाव में, उत्तरदाताओं के संबंध में वियतनाम सरकार द्वारा त्यागा गया कोई राजस्व नहीं है।

viii. मानक निर्धारण पर चर्चाएँ अपरिपक्व और शैक्षिक हैं, क्योंकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क ढांचे के तहत मानक निर्धारण वित्तीय अंशदान और लाभ का अस्तित्व स्थापित होने के बाद ही उत्पन्न होता है। चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, किसी मानक तुलना को करने का कोई आधार नहीं है।

ix. वास्तविक संवितरण, लाभ की प्राप्ति और विशिष्टता प्रदर्शित करने का भार आवेदक पर है। आवेदक ने यह दिखाने वाला लेन-देन-स्तरीय साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना सरकारी कार्यक्रमों के सामान्यीकृत संदर्भों पर भरोसा किया है कि किसी उत्तरदाता ने निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त की।

153. <u>घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:</u>

i. वियतनाम सरकार निर्णय 279 द्वारा स्थापित और निर्णय 80 द्वारा शासित राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत निर्यात प्रोत्साहन उपाय संचालित करती है। ये उपाय जांचाधीन उत्पाद के निर्यातकों सहित निर्यातकों को सहायता देने के लिए अभिकल्पित हैं और इसलिए, प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियाँ बनते हैं।

ii. निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम में निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में वियतनाम सरकार द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है। इसमें निर्यात विकास और संबंधित सेवाओं पर सलाह देने के लिए उद्यमों द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए किए गए खर्चों की 50% तक की प्रतिपूर्ति शामिल है। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध IV और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1 के अर्थ में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण हैं।

iii. कार्यक्रम में त्यागा गया सरकारी राजस्व भी शामिल है, क्योंकि निर्यातकों को निर्यात गतिविधि से संबद्ध कर-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। अपने निर्यात के मूल्य के आधार पर निर्यातकों की कर देयता कम करके, वियतनाम सरकार उस राजस्व का त्याग करती है जो अन्यथा वैधानिक कर ढांचे के तहत देय होता। कर देयता में यह कमी परिचालन लागतों को कम करके और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करती है।

iv. निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत लाभ दो रूपों में उत्पन्न होता है:

(क) निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के मामलों में, लाभ उद्यम द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि के बराबर है; और

(ख) त्यागे गए राजस्व के मामलों में, लाभ वैधानिक कर देयता और निर्यात-संबद्ध प्रोत्साहन के लागू होने के बाद कम हुई देयता के बीच का अंतर है।

v. निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम, अपनी प्रकृति से ही, निर्यात गतिविधि पर आकस्मिक हैं और इसलिए विशिष्ट हैं। लाभों की उपलब्धता निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात-संबंधित गतिविधियों में संलग्नता से संबद्ध है, जो एससीएम समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत विशिष्टता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ऐसे कार्यक्रम निर्यात-आकस्मिक हैं और इस प्रकार प्रतिसंतुलनकारी हैं।

vi. जबकि कुछ पक्षकारों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में भाग नहीं लिया या लाभ प्राप्त नहीं किए, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि गैर-भागीदारी सत्यापन का मामला है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि गोपनीय अभिलेखों, सरकारी संवितरण आंकड़ों और सत्यापन जांच परिणामों पर भरोसा करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि जांच अवधि के दौरान वास्तव में कोई वित्तीय सहायता या कर लाभ प्राप्त हुआ था या नहीं।

vii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का अनुबंध IV मानक निर्धारण पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए, मानक उद्यम द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि है। त्यागे गए राजस्व से जुड़े उपायों के लिए, मानक वैधानिक कर देयता है जो प्रोत्साहन के अभाव में देय होती। लाभ वैधानिक देयता और निर्यात प्रोत्साहन उपायों के लागू होने के बाद कम हुई देयता के बीच का अंतर है।

<u>प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की है:</u>

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम की प्रतिकारी योग्यता की परीक्षा नहीं की है।

<u>वियतनाम में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क योजनाएँ</u>

155. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि वियतनामी उत्पादक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों से लाभान्वित होते हैं। की गई जांचों, अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और पूर्व में की गई जांचों के आधार पर, और जांचाधीन उत्पाद के कुछ वियतनामी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की ओर से पूर्ण सहयोग के अभाव पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और उनमें सब्सिडी के अंतरों को नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार परिमाणित किया है। प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अंतरों का परिमाण न्यूनतम स्तर से ऊपर है।

156. फिलर मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि अर्थात अप्रैल 2023 से जून 2024 के बजाय कैलेंडर वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के लिए

प्रश्नावली प्रारूप/अतिरिक्त प्रश्नावली प्रारूप में विवरण/सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फिलर मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने दिए गए प्रारूप में सूचना प्रदान नहीं की और प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रही है। इसलिए, प्राधिकरण ने एफएमजेएससी को व्यक्तिगत सब्सिडी अंतर प्रदान नहीं किया है।

157. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से जांचाधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक, अर्थात् जीसीसी मिनरल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियत ट्रुंग प्लास्टिक केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और मेगाप्लास्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा जारी मूल एवं अतिरिक्त प्रश्नावली प्रतिक्रिया में प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं और प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहे हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों को व्यक्तिगत अंतर प्रदान नहीं किए हैं।

सब्सिडी अंतर तालिका

क्र. सं	उत्पादक	कार्यक्रम सं. 1 – एलटीआर पर लाइमस्टोन की आपूर्ति			कार्यक्रम सं. 3 - उद्यम के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट			कार्यक्रम सं. 5, 7, 8, 10,11 - प्राथमिकता-आधारित ऋण			कार्यक्रम सं.. 13 एलटीएआर में सरकार द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराना और ज़मीन व पानी के किराए में छूट/कमी।			कुल		
		सब्सिडी माज़िन			सब्सिडी माज़िन			सब्सिडी माज़िन			सब्सिडी माज़िन			सब्सिडी माज़िन		
		अम. डा./ मीट.	%	रेंज	अम. डा./ मीट.	%	रेंज	अम.डा. /मीट.	%	रेंज	अम.डा ./मीट.	%	रेंज	अम.डा. /मीट.	%	रेंज
1	यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
2	येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
3	न्घे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
4	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (जिन्हें सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट ग्रुप" कहा जाता है)	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
	यूरो प्लास्ट ग्रुप के लिए डब्ल्यू औसत	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
5	एडीसी	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-	***	***	0-10

	प्लास्टिक, जेएससी												10			
6	एन टिएन इंडस्ट्रीज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
7	विटाप्लास जॉइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास)	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
8	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स जॉइंट स्टॉक कंपनी	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
9	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
10	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी – हंग येन ब्रांच	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
	(जिन्हें सामूहिक रूप से "यूएस मास्टरबैच ग्रुप" कहा जाता है)	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
11	अन्य	***	***	10-20	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	20-30

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि याचिका घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति या कथित सब्सिडीकरण और घरेलू उत्पादकों की स्थिति के बीच कारणात्मक संबंध का अस्तित्व स्थापित नहीं करती। यह प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकारी को प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की सिफारिश करने से पहले कारण-निर्धारण और गैर-आरोपण विश्लेषण करना चाहिए।

ii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का नियम 13 एससीएम समझौते के अनुच्छेद 15.5 का प्रतिबिंब है, जो सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच के आधार पर "सब्सिडियों के प्रभावों के माध्यम से" पाटित आयातों द्वारा क्षति पहुँचाए जाने के प्रदर्शन की आवश्यकता रखता है और आगे प्राधिकारी से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि ऐसे कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों पर आरोपित न की जाए।

iii. याचिका इन अनिवार्य आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करती और इसलिए खारिज की जानी चाहिए।

iv. यद्यपि याचिका मूल्य न्यूनीकरण, कीमत ह्रास और मात्रा-आधारित क्षति का आरोप लगाती है, यह विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं करती कि वियतनाम से आयात ने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण मूल्य दबाव डाला।

v. घरेलू उद्योग स्वयं स्वीकार करता है कि जांचाधीन उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री, बहुलक आधार और योजक संरचना सहित संरचना में काफी भिन्न होता है। मूल्य तुलना के लिए श्रेणी, कार्यक्षमता और विशिष्टताओं के लिए "सम-रूप" समायोजनों की आवश्यकता होती है, जो याचिका नहीं करती।

vi. याचिका में कीमत कटौती पद्धति सरल है और साक्ष्य सीमा को पूरा नहीं करती क्योंकि यह उत्पाद भिन्नताओं का हिसाब नहीं रखती। कीमत कटौतीने निरंतर सकारात्मक प्रवृति दिखाए हैं, और इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने हानियों से बचने के लिए अपना व्यवहार नहीं बदला है। यह इंगित करता है कि हानियाँ वियतनाम से आयात के बजाय घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा से संचालित हैं।

vii. याचिका महत्वपूर्ण मूल्य अवसाद प्रदर्शित नहीं करती। कोई आंकड़ा यह नहीं दिखाता कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू कीमतें गिरीं, और कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उत्पादकों ने कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन आयातों द्वारा ऐसा करने से रोके गए।

viii. याचिका स्वयं कहती है कि जांचाधीन उत्पाद अनुप्रवाह प्लास्टिक उत्पादों के लिए लागत का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है और बहुलक/रेजिन लागत मूल्य निर्धारण के प्रमुख निर्धारक हैं। इनपुट लागत प्रवृतियों के साथ संरेखित घरेलू कीमतों में स्थिरता या मामूली वृद्धि मूल्य अवसाद का गठन नहीं कर सकती।

ix. कीमत ह्रास बिना यह दिखाए स्थापित नहीं किया जा सकता कि "यदि आयात नहीं होते" तो घरेलू कीमतें बढ़ जातीं। याचिका ऐसा कोई प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण प्रदान नहीं करती।

x. याचिका आयात कीमतों और घरेलू मूल्य निर्धारण व्यवहार के बीच प्रत्यक्ष या सुसंगत सह-संबंध दिखाने में विफल रहती है। याचिका स्वयं क्षति अवधि के दौरान लागतों पर रेजिन और कैल्शियम कार्बोनेट इनपुट सहित कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के पर्याप्त प्रभाव को स्वीकार करती है, और ये कारक आयातों से स्वतंत्र हैं और क्षति आरोपण से बाहर रखे जाने चाहिए।

xi. याचिका वियतनाम से आयातों द्वारा घरेलू बिक्री का विस्थापन स्थापित नहीं करती। जांचाधीन उत्पाद का बाजार विस्तार कर रहा है, जो घरेलू उत्पादकों और आयातों दोनों के लिए स्थान प्रदान कर रहा है।

xii. याचिका में अनुबंध IV-क वर्षों में उत्पादन में ऐसी तीव्र गिरावट नहीं दिखाता जो सामान्यतः आयात उछाल से होने वाली क्षति को इंगित करे। कई घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन स्तर बनाए रखा या बढ़ाया।

xiii. जहाँ आयात बढ़े, यह घरेलू बाजार हिस्सेदारी की हानि के बजाय राष्ट्रव्यापी मांग में वृद्धि के साथ संपाती था। याचिका स्वयं घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना की गई परिचालन बाधाओं का उल्लेख करती है, जिसमें उद्योग की खंडित संरचना और कोविड-19 अवधि के दौरान बंदी शामिल है।

xiv. आयात एक आपूर्ति अंतराल भर रहे हैं जिसे घरेलू उत्पादक पूरा नहीं कर सके, चाहे क्षमता बाधाओं या वाणिज्यिक निर्णयों के कारण, यह क्षति नहीं बन सकता।

xv. याचिका एचएस कोड 3824 99 00 के तहत अन्य देशों से आयातों को स्वीकार करती है, लेकिन कथित क्षति को पूर्णतः वियतनामी आयातों पर आरोपित करती है। गैर-संबद्ध आयातों के मूल्य और

मात्रा प्रभावों का विश्लेषण किए बिना, प्राधिकारी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के नियम 13 और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 15.5 के तहत गैर-आरोपण आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता।

xvi. याचिका कुछ गैर-आयात कारकों की पहचान करती है लेकिन क्षति विवरण से उनके प्रभावों का विश्लेषण और बहिष्करण नहीं करती। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचाने गए कारकों में अनेक घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा, घरेलू फर्मों द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ, मांग प्रतिरूपों में परिवर्तन, उत्पादन दक्षता में भिन्नताएँ, अनुप्रवाह बाजार में उतार-चढ़ाव, मांग में संकुचन या उपभोग प्रतिरूपों में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल थे।

xvii. भारतीय बाजार महत्वपूर्ण अंतर-घरेलू प्रतिस्पर्धा के साथ खंडित है, और घरेलू उत्पादकों के बीच आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा आयातों से स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारण व्यवहार, लाभप्रदता और क्षमता उपयोग को प्रभावित कर सकती है।

xviii. घरेलू उत्पादक अतिरिक्त क्षमता और कम क्षमता उपयोग के साथ कार्य करते हैं, जो आयातों से स्वतंत्र रूप से अति-आपूर्ति और कीमतों पर गिरावट का दबाव उत्पन्न करता है।

xix. उत्पाद विभाजन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मास्टरबैच (जांचाधीन उत्पाद) और रंग मास्टरबैच के बीच मूल्य अंतर, और रंग मास्टरबैच में उच्चतर अंतर शामिल हैं, यदि उचित रूप से पृथक न किए जाएँ तो लाभप्रदता और क्षति आकलन को विकृत कर सकते हैं।

xx. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित छोटे उत्पादक, आक्रामक घरेलू प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील होते हैं, और कोई भी वित्तीय दबाव आयातों के बजाय इन संरचनात्मक स्थितियों से उत्पन्न हो सकता है।

xxi. याचिका दर्शाती है कि संबद्ध आयातों द्वारा कीमत कटौतीजांच अवधि सहित सभी वर्षों में निरंतर सकारात्मक रहा, और स्थिर न्यूनीकरण स्तरों के बावजूद घरेलू उद्योग ने कथित रूप से जांच अवधि के दौरान बढ़ी हुई हानियाँ रिपोर्ट कीं। यह तर्क दिया गया कि यह वियोग इंगित करता है कि क्षति वियतनामी आयातों के लिए आरोप्य नहीं है।

xxii. विश्व व्यापार संगठन और घरेलू विधिशास्त्र पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकारी को अन्य ज्ञात कारकों के चोटिल प्रभावों को "पृथक और भिन्न" करना चाहिए और संबद्ध आयातों के सापेक्ष उनकी प्रकृति और सीमा की मात्रा निर्धारित या व्याख्या करनी चाहिए।

xxiii. स्वयं घरेलू उद्योग के आंकड़ों में भी, अधिकांश क्षति मापदंड आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों से सुधार दिखाते हैं, और इसलिए आवेदकों ने क्षति स्थापित नहीं की है।

xxiv. क्षति सूचना के आधार पर, घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष में 4,15,302 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 4,75,748 मीट्रिक टन हो गई।

xxv. उत्पादन आधार वर्ष में 2,52,179 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 3,03,862 मीट्रिक टन हो गया, और उत्पादकता भी बढ़ी।

xxvi. क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 61% से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 64% हो गया।

xxvii. घरेलू बिक्री आधार वर्ष में 1,90,683 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 2,23,632 मीट्रिक टन हो गई।

xxviii. प्रति इकाई घरेलू बिक्री मूल्य आधार वर्ष में 100 के सूचकांक से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 112 के सूचकांक पर पहुँच गया।

xxix. जहाँ कुछ कारकों में गिरावट आई हो, ऐसी गिरावटें वियतनाम से आयातों पर आरोपित नहीं की जा सकतीं और इसके बजाय घरेलू उत्पादकों की अक्षमताओं और बढ़ी हुई मूल्यह्रास एवं ब्याज लागतों जैसे आंतरिक कारकों के कारण हैं।

xxx. याचिका संबद्ध देश में सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं करती, और इसलिए कोई क्षति अंतिम जांच परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

xxxi. आवेदक का क्षति विश्लेषण कानूनी रूप से अपर्याप्त है क्योंकि यह मुख्यतः आयात मात्रा प्रवृतियों पर निर्भर करता है, बिना कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच अनिवार्य कारणात्मक संबंध स्थापित किए, जो सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों की जांच करने की आवश्यकता के विपरीत है।

xxxii. आयात मात्राएँ सब्सिडियों से असंबंधित विभिन्न वाणिज्यिक कारणों से बदल सकती हैं, जिनमें क्रेता खरीद रणनीतियाँ, मालसूची समायोजन, मौसमी या चक्रीय मांग, अस्थायी घरेलू आपूर्ति की कमी, पहुँच मूल्य समता को प्रभावित करने वाली विनिमय दर गतियाँ, गुणवत्ता या लागत-कुशल आयातों की मांग में बदलाव, और अनुप्रवाह मांग में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

xxxiii. आवेदक ने लेन-देन-स्तरीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जो यह दर्शाए कि कथित सब्सिडियाँ निम्न निर्यात कीमतों में परिवर्तित हुईं या सब्सिडी से निर्यात मूल्य निर्धारण में कोई संचरण हुआ।

xxxiv. एक हितबद्ध पक्षकार ने प्रस्तुत किया कि उसके निर्यात क्षति पहुँचाने के लिए बहुत छोटे हैं और दावा किया कि, आवेदक के स्वयं के अनुमानों पर भी, उसके निर्यात भारत की मांग का 0.98% और वियतनाम के भारत को निर्यात का 5.15% प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए याचिका में कथित पैमाने के घरेलू उद्योग को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकते।

xxxv. एक हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया कि उसका भारत को निर्यात मूल्य उसके घरेलू मूल्य से अधिक है और अन्य गंतव्यों को उसके निर्यात मूल्यों से अधिक है, जो घरेलू उद्योग पर कोई मूल्य दबाव न होने का संकेत देता है।

xxxvi. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई असंगत, असमान और कथित रूप से अनुपालनहीन आंकड़ों और अत्यधिक गोपनीयता के कारण, वे इस स्तर पर क्षति और कारणात्मक संबंध पर सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि सार्थक टिप्पणियाँ तभी प्रस्तुत की जा सकती हैं जब व्यापार सूचनाओं के अनुरूप उचित अवधि के लिए उचित सूचना प्रदान की जाए।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

159. क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध I के साथ पठित नियम 13 द्वारा शासित होता है, जो सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित जांच और (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के

लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव, और (ख) घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की आवश्यकता रखता है।

ii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से आयातों, भारतीय मांग, भारतीय उत्पादन और आयात हिस्सेदारी पर आंकड़े प्रदान किए।

iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि आंकड़े निरपेक्ष रूप में संबद्ध देश से आयातों में निरंतर वृद्धि और मांग के सापेक्ष और भारतीय उत्पादन के सापेक्ष भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि दर्शाते हैं।

iv. आयात 2020-21 में 48,155 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 63,043 मीट्रिक टन और आगे 2022-23 में 1,00,122 मीट्रिक टन तथा फिर जांच अवधि के दौरान 2,20,912 मीट्रिक टन तक बढ़ गए। भारतीय मांग 2020-21 में 6,30,693 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 10,87,076 मीट्रिक टन हो गई, लेकिन भारतीय उत्पादन 2020-21 में 6,06,939 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 8,94,395 मीट्रिक टन हो गया।

v. घरेलू उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि से कम थी, जो संबद्ध देश से आयातों द्वारा विस्थापन का संकेत देती है।

vi. संबद्ध आयातों की मांग में हिस्सेदारी क्षति अवधि में 8% से बढ़कर 20% हो गई और उत्पादन के सापेक्ष उनकी हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 25% हो गई, जो बढ़ती पैठ और घरेलू उत्पादन के प्रतिस्थापन को दर्शाती है।

vii. मात्रा प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि वृद्धिशील मांग तेजी से संबद्ध देश से आयातों द्वारा हथिया ली गई, जिससे विस्तारित होती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की भारतीय उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की क्षमता सीमित हुई।

viii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण और सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए, जो इंगित करते हैं कि संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू बिक्री मूल्यों को न्यून किया।

ix. घरेलू उद्योग सभी वर्षों में बिक्री लागत से नीचे बेचने के लिए बाध्य हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण क्षति अवधि में हानियाँ हुईं। पहुँच कीमतों और घरेलू बिक्री मूल्यों के बीच निरंतर अंतर, लागत से नीचे बिक्री के साथ, कीमत ह्रास और मूल्य अवसाद प्रदर्शित करता है।

x. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के पैरा 7 के अनुसार, जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 11/2021 द्वारा संशोधित, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को नमूना चयनित घरेलू उत्पादकों के रूप में चुना:

(i) सॉल्टेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड;

(ii) आलोक मास्टरबैचेज प्रा. लिमिटेड;

(iii) आलोक इंडस्ट्रीज; और

(iv) कांडुई इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड।

xi. नमूना चयनित घरेलू उत्पादकों ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना दायर की। यह प्रस्तुत किया गया कि उत्पाद नियंत्रण संख्या क, उत्पाद नियंत्रण संख्या ख और उत्पाद नियंत्रण

संख्या ग के लिए भारित औसत संयुक्त क्षति रहित कीमत 400-550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की सीमा में दावा की गई है।

xii. घरेलू उद्योग ने प्लास्टिक उद्योग से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का विस्तार किया। जांच अवधि के दौरान, संबद्ध देश से बढ़े हुए कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण वास्तविक उत्पादन और बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में गिर गई।

xiii. जांच अवधि में क्षमता उपयोग गिर गया और बढ़ती मांग के बावजूद, क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग अप्रयुक्त रहा। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग लगभग 60%-70% क्षमता पर संचालित हुआ।

xiv. आवेदक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 30% से गिरकर जांच अवधि में 26% हो गई, जबकि इसी अवधि में संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 20% हो गई।

xv. अन्य देशों से आयात नगण्य थे, और आयात हिस्सेदारी में वृद्धि मुख्यतः संबद्ध देश से थी। यह वृद्धि संबद्ध देश से बड़ी मात्रा में पाटित आयातों से संबद्ध है, जो पिछले कुछ वर्षों में और जांच अवधि के दौरान अधिक आक्रामक हो गए।

xvi. बाजार हिस्सेदारी खो दी और भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद उचित मूल्यों पर नहीं बेच सके।

xvii. लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रत्याय संपूर्ण क्षति अवधि में ऋणात्मक रहे और जांच अवधि में उच्चतम हानियों के साथ हानियाँ बढ़ीं। संबद्ध आयातों के आक्रामक सब्सिडीकरण के कारण हानियाँ तेजी से बढ़ीं।

xviii. औसत मालसूची क्षति अवधि में निरंतर बढ़ी और जांच अवधि में तेजी से बढ़ी।

xix. सभी मात्रा मापदंड जांच अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं, और सभी मूल्य मापदंड क्षति अवधि और जांच अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। बढ़ती मालसूची और गिरती बाजार हिस्सेदारी पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है।

xx. यद्यपि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं का विस्तार किया, यह बढ़े हुए सब्सिडीकरण के कारण मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है और हानियाँ उठा रहा है। इसलिए उद्योग जांचाधीन वस्तुओं में नए निवेश करने के लिए अनिच्छुक है जब तक मौजूदा क्षमताएँ पूरी तरह उपयोग नहीं हो जातीं।

xxi. भौतिक क्षति का खतरा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए न कि आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावना पर, और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 15.7 और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध I के खंड (3) पर भरोसा किया गया।

xxii. वियतनाम सरकार द्वारा वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान की गई सब्सिडियों के कारण भौतिक क्षति के खतरे का संकेत देने वाले विशिष्ट तथ्य हैं, जिनमें निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ और नीतियाँ शामिल हैं जो कच्चे माल (चूना पत्थर/कैल्शियम कार्बोनेट सहित) को पाटित कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं, और इसमें अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपयोगिताएँ, कर प्रोत्साहन, सस्ती भूमि और बिजली और समान सहायता भी शामिल हैं।

xxiii. ये सब्सिडियाँ भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात सक्षम बनाती हैं, जो भारत में घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा पहुँचाती हैं।

xxiv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चूना पत्थर पर जुलाई 2024 से 30% तक पहुँचने वाली बढ़ती निर्यात कर दरें इंगित करती हैं कि खतरा तीव्र होने की संभावना है।

xxv. वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान निर्यात बाजारों में व्यापार प्रोत्साहन और प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयात कर दरों के समायोजन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारत को बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को इंगित करता है, जो भौतिक क्षति का पूर्वानुमान योग्य और आसन्न खतरा उत्पन्न करता है।

xxvi. आंकड़े क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की महत्वपूर्ण दर दर्शाते हैं, जो भविष्य में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना का संकेत देते हैं।

xxvii. वियतनामी निर्माताओं के पास वियतनाम की घरेलू मांग से अधिक उत्पादन क्षमताएँ हैं और इसलिए अतिरिक्त उत्पादन निर्यात के लिए अभिप्रेत है। ये अतिरिक्त क्षमताएँ भारत की कुल मांग से कहीं अधिक हैं और भारत को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यातों की संभावना उत्पन्न करती हैं।

xxviii. भारत एक महत्वपूर्ण बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रमुख वियतनामी उत्पादकों की स्थापित क्षमताएँ निम्नलिखित हैं:

क) यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – 8,00,000 मीट्रिक टन

ख) यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – 2,30,000 मीट्रिक टन

ग) मेगा प्लास्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – 1,40,000 मीट्रिक टन

घ) आन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – 96,000 मीट्रिक टन

ङ) फा ले प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग – 4,50,000 मीट्रिक टन

च) वीटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – 48,000 मीट्रिक टन

xxix. ये उत्पादक अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को लक्षित करने की संभावना रखते हैं, और ह्रास/न्यूनीकरण कीमतों पर पाटित आयातों का अंतर्वाह घरेलू उद्योग के अस्तित्व को खतरे में डालता है।

xxx. घरेलू उत्पादक लागत से नीचे बेचने के लिए बाध्य हुए और न्यूनीकरण कीमतों पर प्रवेश करने वाले आयातों के कारण जांच अवधि में घरेलू कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में गिर गईं। घरेलू कीमतों और लागत की तुलना में पहुँच कीमतों का प्रवृति दर्शाता है कि आयात महत्वपूर्ण अवसादक/दमनकारी प्रभाव वाली कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए आयातों के और बढ़ने की संभावना है।

xxxi. विदेशी उत्पादकों के मालसूची स्तर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और अनुरोध किया गया कि प्राधिकारी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्यातकों के मालसूची स्तरों का सत्यापन करें।

xxxii. घरेलू उद्योग ने अन्य कारकों का संरचित विश्लेषण किया, जिनमें शामिल हैं: (क) गैर-पाटित आयातों की मात्रा और कीमतें; (ख) मांग में संकुचन या उपभोग प्रतिरूपों में परिवर्तन; (ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा; (घ) प्रौद्योगिकी में विकास; (ङ) निर्यात निष्पादन; और (च) उत्पादकता।

क) अन्य देशों से आयातों ने क्षति नहीं पहुँचाई क्योंकि संबद्ध देश से आयात भारत में कुल आयातों का लगभग 99% है और अन्य देशों से आयात लगभग 1% हैं।

ख) क्षति अवधि में मांग बढ़ी और इसलिए क्षति को मांग संकुचन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ग) ग्राहक वार्ताएँ आयातित कीमतों पर मानकीकृत होती हैं और घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की कीमतों से मेल खाने के लिए बाध्य होते हैं; यदि निर्यातक बेहतर कीमतें प्रस्तुत करते हैं, ग्राहक आयातों की ओर स्थानांतरित होते हैं।

घ) प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण कोई क्षति नहीं है।

ङ) घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात नगण्य हैं और क्षति निर्धारण में निर्यात निष्पादन पर विचार नहीं किया गया, और इसलिए क्षति को निर्यातों पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

च) क्षति विश्लेषण केवल जांचाधीन उत्पाद से संबंधित है और अन्य उत्पादों की लाभप्रदता को बाहर रखता है, और इसलिए क्षति को अन्य उत्पादों के निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

xxxiii. क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण नहीं है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

xxxiv. यह तर्क कि क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच अंतर-प्रतिस्पर्धा के कारण है, अनुपयुक्त है, और खंडन इस तथ्य को नकारता नहीं कि पाटित आयातों द्वारा पहुँचाई गई क्षति वहाँ विद्यमान है जहाँ आंकड़े प्रतिकूल मूल्य प्रभावों के साथ आयात मात्राओं में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हैं।

xxxv. बढ़ी हुई आयात मात्रा बाजार हिस्सेदारी, लाभप्रदता, नकद प्रवाह और मालसूचियों सहित प्रमुख मापदंडों में गिरावट के साथ संपाती है, जो मात्रा प्रभाव के माध्यम से क्षति स्थापित करती है।

xxxvi. यह तर्क कि कीमत कटौती"स्थिर" है, भ्रामक है, क्योंकि निरंतर और महत्वपूर्ण न्यूनीकरण स्वयं मूल्य दबाव को इंगित करता है, और क्षति तब और बढ़ जाती है जब ऐसा न्यूनीकरण पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई मात्राओं पर संचालित होता है।

xxxvii. जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती25-30% तक पहुँच गया, जो घरेलू कीमतों का ह्रास करता है और लागतों की वसूली को रोकता है।

xxxviii. अप्रयुक्त क्षमता और कम क्षमता उपयोग पर तर्क विस्थापन की अवहेलना करते हैं, और प्रासंगिक मुद्दा यह है कि क्या पाटित आयातों की उपस्थिति में क्षमता का उपयोग किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया कि वृद्धिशील मांग कम कीमत वाले आयातों द्वारा हथिया ली गई, जिससे उत्पादन और उपयोग में आनुपातिक वृद्धि रुक गई।

xxxix. गोपनीयता के कारण टिप्पणी करने में असमर्थता पर आपत्तियाँ निराधार हैं, क्योंकि सूचीबद्ध प्रवृतियों और क्षति मापदंडों सहित पर्याप्त अगोपनीय सूचना उचित समझ को सक्षम करने के लिए प्रकट की गई है, गोपनीयता का दावा व्यापार सूचनाओं और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुसार किया गया है, और प्राधिकारी के पास गोपनीय सूचना को सत्यापित करने की शक्ति है। गोपनीयता क्षति विश्लेषण को दूषित नहीं करती और जांच समयसीमाओं को पुनः आरंभ करने को उचित नहीं ठहराती।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

160. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध I के साथ पठित नियम 13 प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं,

"(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में, प्राधिकारी यह अतिरिक्त अंतिम जांच परिणाम देंगे कि भारत में ऐसे वस्तु का आयात भारत में स्थापित किसी उद्योग को भौतिक क्षति पहुँचाता है या पहुँचाने का खतरा उत्पन्न करता है, या भारत में किसी उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से विलंबित करता है।

(2) उप-नियम (3) के तहत क्षति का अंतिम जांच परिणाम दिए जाने के सिवाय, प्राधिकारी क्षति, क्षति का खतरा, उद्योग की स्थापना में भौतिक विलंबन और पाटित आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण, अन्य बातों के साथ, नियम के अनुबंध I में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करेंगे।

(3) प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, क्षति के अस्तित्व के बारे में अंतिम जांच परिणाम दे सकते हैं, भले ही घरेलू उद्योग का कोई पर्याप्त भाग चोटिल न हो, यदि - (i) किसी पृथक बाजार में पाटित आयातों का संकेंद्रण है, और (ii) पाटित आयात ऐसे बाजार के भीतर लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुँचा रहे हैं।"

161. इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कटौती करना या कीमत वृद्धियों को, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है जो अन्यथा घटित होतीं,। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध I के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, निवेश पर प्रत्याय, सब्सिडीकरण का परिमाण और अंतर आदि पर विचार किया गया है।

162. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

163. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए कथनों और आंकड़ों पर आधारित अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।

छ.3.1. <u>पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव</u>

क) <u>मांग/प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन</u>

164. क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने महानिदेशालय प्रणाली से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। भारत में उत्पाद की मांग/प्रत्यक्ष उपभोग के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने आवेदकों, अन्य उत्पादकों और संबद्ध देश से आयात तथा अन्य देशों से आयात की घरेलू बिक्री के योग पर विचार किया है। इस प्रकार परिकलित मांग/प्रत्यक्ष उपभोग निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
1	वियतनाम से आयात	मी.टन	48,182	62,228	94,458	1,81,824
2	अन्य देश से आयात	मी.टन	207	27	969	5,702
3	घरेलू बिक्री (आवेदक)	मी.टन	1,90,683	2,40,084	2,32,183	2,23,632
4	घरेलू बिक्री (समर्थकों सहित अन्य उत्पादक)	मी.टन	3,91,758	4,19,307	4,37,761	4,64,831
5	भारतीय मांग	मी.टन	6,30,830	7,21,645	7,65,372	8,75,988

165. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ख) <u>भारत में उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात मात्रा</u>

166. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से जांचाधीन वस्तुओं की आयात मात्राएँ और संबद्ध आयातों का हिस्सा निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
1	वियतनाम से आयात	मी.टन	48,182	62,228	94,458	1,81,824
2	अन्य देशों से आयात	मी.टन	207	27	969	5,702
3	भारतीय मांग	मी.टन	6,30,830	7,21,645	7,65,372	8,75,988
4	भारतीय उत्पादन	मी.टन	6,06,939	6,78,391	6,96,823	7,15,516
5	संबद्ध देशों के आयात का संबंध -					
क	भारतीय मांग	%	8%	9%	12%	21%
ख	भारतीय उत्पादन	%	8%	9%	14%	25%

167. यह देखा गया है कि वियतनाम से जांचाधीन वस्तुओं के आयात में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों से आयात नगण्य हैं। वियतनाम से आयात भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में भी क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़े हैं।

छ.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

168. नियमावली के अनुबंध I (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास करना या कीमत वृद्धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क) कीमत कटौती

169. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका इसे दर्शाती है-

विवरण	यूओएम	पीओआई (ए)
निवल विक्रय प्राप्ति	रू. / मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रू. / मी.ट.	25,760
कीमत कटौती	रू. / मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज %	25-35%

170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

171. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास करना या कीमत वृद्धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, रोकना है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत एवं निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत से की है।

172. नीचे दी गई तालिका जांचाधीन उत्पाद की बिक्री लागत, बिक्री मूल्य और आयातों की पहुँच कीमत दर्शाती है-

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
बिक्री लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	119	113
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	115	109
पहुँच कीमत	रु./मी.टन	23,926	29,808	29,695	25,760

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	125	124	108

173. उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग जांचाधीन उत्पाद को घरेलू बाजार में अपनी बिक्री लागत से नीचे बेच रहा है, जिससे हानियाँ हो रही हैं। पहुँच कीमतें घरेलू बिक्री मूल्यों से नीचे रही हैं, और बिक्री मूल्य बिक्री लागत से नीचे है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने कीमत ह्रास झेला है।

छ.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

174. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का अनुबंध I अपेक्षित करता है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रत्याय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, सब्सिडीकरण अंतर का परिमाण; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

क) <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राएँ</u>

175. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
उत्पादन जांचाधीन उत्पाद	मी.टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
घरेलू बिक्री	मी.टन	1,90,683	2,40,084	2,32,183	2,23,632

176. यह ध्यान दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। भारत में जांचाधीन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अपने क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि की। घरेलू उद्योग जांच अवधि में ***% पर कार्य कर रहा है।

177. इसके अलावा, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन स्तर में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सुधार दिखा है।

ख) बाजार हिस्सेदारी

178. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई (A)**
घरेलू उद्योग के आवेदक का हिस्सा	%	30%	33%	30%	26%
सहयोगियों सहित अन्य भारतीय उतपादकों का हिस्सा	%	62%	58%	57%	53%
संबद्ध देश का हिस्सा	%	8%	9%	12%	21%
अन्य देशों का हिस्सा	%	0.03 %	0.00 %	0.13 %	0.65%

179. उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में गिर गई है, भारतीय मांग में कहीं अधिक हिस्सेदारी पूरी करने की क्षमता होने के बावजूद। इसके अलावा, समर्थक सहित अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा भी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान गिरा है।

180. इसके विपरीत, संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ती रही है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नगण्य है।

ग) मालसूची

181. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
औसत	मी.टन	***	***	***	***

182. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी।

घ) <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

183. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच अवधि (A)**
लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-260	-319	-306

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-557	-718	-661
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-363	-402	-349

184. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में निरंतर गिरावट आ रही है और घरेलू उद्योग वित्तीय हानियाँ उठा रहा है।

ङ) <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

185. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (A)
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***

186. घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किया गया वेतन और मजदूरी क्षति अवधि में बढ़ा है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी जांच अवधि में गिरी है।

च) वृद्धि

187. घरेलू उद्योग के सभी मूल्य मापदंड क्षति अवधि और जांच अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। क्षति अवधि में औसत मालसूची भी बढ़ी है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी ऋणात्मक वृद्धि दर्शाती है। घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान हानियों में है।

छ) <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव</u>

188. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारत में जांचाधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताएँ बढ़ाने हेतु नए निवेश किए हैं, यह पाटित आयातों के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और हानियों का सामना कर रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता महत्वपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई है।

ज) <u>कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण थी और ऐसे आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी नीचे की कीमतों पर थे। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति संबद्ध आयातों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस प्रकार, संबद्ध देश से जांचाधीन वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है।

झ) <u>सब्सिडी का अंतर</u>

190. सब्सिडी का अंतर इस बात का सूचक है कि पाटित आयात किस हद तक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम के लिए सब्सिडी अंतर सकारात्मक है।

ख.3.4. भौतिक क्षति का खतरा

191. प्राधिकारी ने भौतिक क्षति के खतरे से संबंधित जांच के कार्यक्षेत्र के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई अनुरोधों की जांच की है।

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों का नियम 13 में प्रावधान है कि प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुँचाई है या पहुँचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

193. प्राधिकारी का मानना है कि जांच शुरू करने की सूचना में कहा गया था कि जांच इस बात की जांच करेगी कि क्या पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुँचाई है या पहुँचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जांच शुरू करने की सूचना में परिभाषित जांच का कार्यक्षेत्र भौतिक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा दोनों को शामिल करता है, और प्राधिकारी जांच के दौरान उभरने वाले साक्ष्य के आधार पर दोनों पहलुओं की जांच करने के लिए सशक्त हैं।

194. प्राधिकारी का मानना है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुबंध I का पैरा (3) अपेक्षित करता है कि भौतिक क्षति के खतरे का कोई निर्धारण केवल आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावना के आधार पर नहीं किया जाएगा और परिस्थितियों में वह परिवर्तन जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें सब्सिडीकरण क्षति पहुँचाएगा, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान योग्य और आसन्न होना चाहिए।

195. प्राधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद आयात आंकड़ों की जांच की है और ध्यान देते हैं कि क्षति अवधि के दौरान वियतनाम से जांचाधीन वस्तुओं के आयातों में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयात मात्राएँ आधार वर्ष से जांच अवधि तक तीन गुना से अधिक हो गई हैं, जो वृद्धि की पर्याप्त दर प्रदर्शित करती हैं।

196. अभिलेख पर मौजूद आंकड़े दर्शाते हैं कि वियतनामी उत्पादकों के पास वियतनाम में घरेलू मांग से अधिक पर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अस्तित्व, भारत को बढ़ते निर्यातों से प्रमाणित वियतनामी उत्पादकों के निर्यात अभिविन्यास के साथ संयुक्त, भारतीय बाजार में और पर्याप्त वृद्धि वाले निर्यातों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।

198. प्राधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद मूल्य विश्लेषण की भी जांच की है और ध्यान देते हैं कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू कीमतों को न्यून करती हैं, जिससे घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हो रहा है।

199. प्राधिकारी का मानना है कि आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, वियतनाम में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, कीमत कटौती और ह्रास, तथा घरेलू उद्योग के बिगड़ते निष्पादन सहित कारकों का संयोजन ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करता है जहाँ भौतिक क्षति का खतरा स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान योग्य और आसन्न है।

ग. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

200. क्षति के अस्तित्व, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रा और मूल्य प्रभावों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक पर आरोपित की जा सकती है।

क. <u>तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत</u>

201. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयात लगभग नगण्य हैं। इसलिए, क्षति तीसरे देशों से आयातों के लिए आरोप्य नहीं है।

ख. <u>मांग का संकुचन</u>

202. विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि देखी गई है। इसलिए, मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण कोई क्षति नहीं पहुँची है।

ग. <u>खपत की पद्धति□ँ में परिवर्तन</u>

203. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति□ँ में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. <u>प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ</u>

204. जांचाधीन वस्तुओं की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकारी के ध्यान में कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं लाई गई हैं।

ङ. <u>प्रौद्योगिकी में विकास</u>

205. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. <u>निर्यात निष्पादन</u>

206. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के क्षति आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

207. प्राधिकारी ने केवल जांचाधीन वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. क्षति मार्जिन का परिमाण

208. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित जांचाधीन वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यात की पहुँच कीमत से की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक	क्षति रहित कीमत	पहुँच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range %
1.	यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")	***	***	***	***	20-30
2.	येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई")	***	***	***	***	20-30
3.	न्घे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे")	***	***	***	***	20-30
4.	पॉलीफिल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल")	***	***	***	***	20-30
5.	एडीसी प्लास्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	25-35
6.	आन टिएन इंडस्ट्रीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	20-30
7.	वीटाप्लास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वीटाप्लास)	***	***	***	***	25-35
8.	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	55-65
9	यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	10-20
10	यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी – हंग येन शाखा	***	***	***	***	10-20

11	अन्य	***	***	***	***	60-70

झ. उपयोगकर्ता प्रभाव विश्लेषण (भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे)

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

209. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक हित/भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वर्तमान जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना एससीएम समझौते के अनुच्छेद 19.2 के अर्थ में सार्वजनिक हित के विपरीत होगा।

ii. अनुच्छेद 19.2 मान्यता देता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का निर्णय, और जिस स्तर पर यह अनुरोधित है, विवेकाधीन है और इसमें घरेलू हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें उपभोक्ता और औद्योगिक उपयोगकर्ता शामिल हैं, जिनके हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, द्वारा किए गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

iii. प्राधिकारी ने पहले ही वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है जिसमें अनुशंसित शुल्क 0 से 75 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक है।

iv. पाटन रोधी शुल्क के अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से एक संचयी और अत्यधिक व्यापार-प्रतिबंधात्मक बोझ उत्पन्न होगा, जो घरेलू उद्योग को किसी कथित क्षति को संबोधित करने के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक होगा।

v. व्यापार उपचारात्मक उपाय क्षति का समाधान करने के लिए हैं न कि घरेलू उद्योग को अति-संरक्षण या दोहरा संरक्षण प्रदान करने के लिए। पाटन रोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का संचयी अधिरोपण आयातों की पहुँच लागत को पर्याप्त रूप से बढ़ाएगा और कृत्रिम रूप से घरेलू कीमतों को बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धी कीमत वाले कच्चे माल की उपलब्धता घटाएगा, और अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं के नुकसान के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत करेगा। ऐसा परिणाम व्यापार उपचार विधि के अंतर्निहित आनुपातिकता और सार्वजनिक हित के सिद्धांतों के साथ असंगत होगा।

vi. कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट है जो अनुप्रवाह उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग (कठोर और लचीली), बुने हुए बोरे और पैकेजिंग सामग्री, उपभोक्ता वस्तुएँ और घरेलू उत्पाद, कृषि फिल्म और पाइप, मोटर वाहन और विद्युत प्लास्टिक घटक, और निर्माण एवं अवसंरचना-संबंधित प्लास्टिक अनुप्रयोग शामिल हैं।

vii. इस उत्पाद का उपयोग कच्चे माल की लागत कम करने, प्रसंस्करण दक्षता सुधारने और प्लास्टिक उत्पादों के भौतिक गुणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस इनपुट की लागत में कोई भी वृद्धि अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और तत्काल सोपानी प्रभाव डालेगी।

viii. भारत में अनुप्रवाह उद्योग इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से पहले ही अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं पर लागत दबाव बढ़ गया है, और एक अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उत्पादन लागतों को और बढ़ाएगा, घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कम करेगा, अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों की

ओर ले जाएगा, और संभावित रूप से उत्पादन में कमी, छँटनी या व्यवसायों की बंदी का कारण बनेगा।

ix. जांचाधीन वस्तुओं के व्यापक उपयोग को देखते हुए, प्रतिकूल प्रभाव घरेलू मास्टरबैच उत्पादकों से परे विस्तारित होंगे और व्यापक विनिर्माण पारितंत्र को प्रभावित करेंगे।

x. जांचाधीन उत्पाद का भारतीय बाजार अत्यधिक खंडित है, जिसमें बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक आयातों के साथ-साथ कार्य कर रहे हैं। आयात आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने, मूल्य अनुशासन प्रदान करने और अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट गुणवत्ता और संगतता आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक व्यापार उपचारात्मक उपाय आपूर्ति विकल्पों को प्रतिबंधित करेंगे और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कमजोर करेंगे, जो सार्वजनिक हित के विपरीत होगा।

xi. व्यापार उपचार विधि के तहत सार्वजनिक हित विश्लेषण के लिए एक ओर घरेलू उत्पादकों और दूसरी ओर अनुप्रवाह उद्योगों, उपभोक्ताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था के बीच हितों का संतुलन आवश्यक है। वर्तमान मामले में, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को प्राप्त होने वाला कोई भी सीमांत लाभ अनुप्रवाह उद्योगों और उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, और ऐसी अतिरिक्त लागतें अंततः उच्च कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाली जाएँगी।

xii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना असंगत और अत्यधिक होगा, पाटन रोधी शुल्क के साथ संयुक्त होने पर अनुचित संचयी बोझ उत्पन्न करेगा, और अनुप्रवाह उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

xiii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उपयोगकर्ता प्रभाव और सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों पर किए गए दावे बिना सहायक साक्ष्य के दावों, अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं। आवेदक द्वारा अपनी अनुरोधों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है, और ऐसे अप्रमाणित दावों पर मामले की योग्यता का निर्णय करने के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

210. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक हित/भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य अनुचित सब्सिडीकरण प्रथाओं से होने वाली क्षति को दूर करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ बहाल करना है, जो देश के समग्र हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का आशय आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि सब्सिडीकरण से उत्पन्न अनुचित लाभ को निष्प्रभाव करना है।

iii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का मूल्य स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम नहीं करता। इसके विपरीत, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्धा सब्सिडीकरण के बजाय बाजार शक्तियों पर आधारित हो, घरेलू उद्योग के और अधिक पतन को रोकता है, और उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक उपलब्धता और विकल्प बनाए रखने में मदद करता है।

iii. सार्वजनिक हित के आकलन के लिए प्राधिकारी को वस्तुओं की उपलब्धता, अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग और आम जनता पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के प्रभाव की जांच करना आवश्यक है। ऐसा आकलन जांच के दौरान अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।

iv. स्थापित प्रथा के अनुसार, प्राधिकारी अनुप्रवाह प्रभाव का आकलन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपयोगकर्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली के माध्यम से दायर सूचना पर भरोसा करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, जहाँ उपयोगकर्ता प्रतिक्रियाएँ संघ हित विश्लेषण का आधार बनती हैं।

v. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की और उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से भागीदारी आमंत्रित की। तथापि, किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली या आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है।

vi. किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने उत्पादन लागत, मूल्य निर्धारण, रोजगार या प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली कोई परिमाणित या सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं की है। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, कथित अनुप्रवाह प्रभाव पर निर्यातकों और विदेशी उत्पादकों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ काल्पनिक और असमर्थित हैं।

vii. विश्व व्यापार संगठन की विधिशास्त्र जांच प्राधिकारियों के कठोर समयसीमाएँ लगाने और विलंबित अनुरोधों की अवहेलना करने के अधिकार को मान्यता देती है। वर्तमान मामले में, किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने अपनी चिंताओं को अभिलेख पर रखने के लिए जांच के दौरान प्रदान किए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया है, और बाद के चरण में की गई किसी भी प्रस्तुति को इसलिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

viii. जांचाधीन वस्तुओं के अनुप्रवाह उपयोगकर्ता अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के सदस्य समझे जाते हैं। तथापि, अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ या इसके किसी सदस्य द्वारा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया है। भागीदारी की कमी इंगित करती है कि निर्यातकों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ भारतीय अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

ix. आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तरों की पूर्ण अनुपस्थिति प्रदर्शित करती है कि अनुप्रवाह उपयोगकर्ता प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने को अपने प्रचालनों पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं मानते। यह दिखाने के लिए कोई परिमाणित सूचना अभिलेख पर नहीं रखी गई है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अनुप्रवाह उद्योगों को अक्षम या अप्रतिस्पर्धी बना देगा।

x. अभिलेख पर एकमात्र परिमाणित और सत्यापन योग्य प्रभाव आकलन स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया है, जो दर्शाता है कि अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकारी से इस साक्ष्य पर भरोसा करने का अनुरोध किया गया।

xi. भारत के पास कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता है। भारतीय उद्योग की कुल स्थापित क्षमता लगभग 12-15 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान घरेलू उत्पादन 7,15,516 मीट्रिक टन था, जो क्षमता के महत्वपूर्ण अल्प-उपयोग को इंगित करता है।

xii. अतिरिक्त घरेलू क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए, आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध देश से आयात आवश्यक नहीं हैं। यह तर्क कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से उपलब्धता प्रतिबंधित होगी या आपूर्ति बाधित होगी, इसलिए तथ्यात्मक रूप से गलत है।

xiii. यह प्रस्तुत किया गया कि सार्वजनिक हित विश्लेषण को सभी घरेलू हितधारकों के हितों को संतुलित करना चाहिए। घरेलू उद्योग अत्यधिक खंडित है और मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से बना

है, जो भारत में रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और मूल्य-श्रृंखला सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

xiv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि निरंतर पाटित आयात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। ऐसे आयातों को घरेलू विनिर्माण क्षमता को क्षरित करने की अनुमति देना भारत के औद्योगिक और आर्थिक नीति उद्देश्यों के विपरीत होगा और सार्वजनिक हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

xv. वियतनाम से पाटित आयातों ने पहले ही भारतीय बाजार में प्रतिकूल संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं, जिसमें कई घरेलू उत्पादकों ने या तो परिचालन बंद कर दिया है या वियतनामी उत्पादकों के लिए श्वेत-लेबल निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हो गए हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता कमजोर हुई है।

xvi. ऐसे घटनाक्रम आयातों पर दीर्घकालिक निर्भरता उत्पन्न करते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य को पराजित करते हैं और सार्वजनिक हित के विपरीत हैं।

xvii. जांचाधीन वस्तुएँ अनुप्रवाह प्लास्टिक उत्पादों की कुल लागत का केवल एक छोटा अनुपात बनाती हैं। यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि लागत में कोई वृद्धि मुद्रास्फीति दबाव या उपभोक्ता हानि की ओर ले जाएगी।

xviii. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करके और घरेलू उत्पादकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करके, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना भारतीय बाजार में दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता और उत्पाद की विश्वसनीय उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

xix. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं होगा और घरेलू विनिर्माण (मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों से मिलकर), रोजगार और दीर्घकालिक बाजार स्थिरता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

211. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उत्पादकों/निर्यातकों की अनुरोधों ने एससीएम समझौते के अनुच्छेद 19.2 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है, विशेष रूप से वियतनाम से उसी उत्पाद से संबंधित पाटन रोधी जांच में पहले से अनुशंसित पाटन रोधी शुल्क को देखते हुए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा।

212. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि पाटन रोधी शुल्क के अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से अत्यधिक और असंगत व्यापार-प्रतिबंधात्मक बोझ उत्पन्न होगा। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में लागू व्यापार उपचारात्मक ढांचे में न्यूनतर शुल्क नियम का सिद्धांत शामिल है, जो अत्यधिक संरक्षण के विरुद्ध एक अंतर्निहित रक्षोपाय के रूप में कार्य करता है।

213. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, लागू नियमों और सुसंगत प्रथा के अनुसार, अनुशंसित शुल्क की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक स्तर तक सीमित रखी जाती है। तदनुसार, पाटन रोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का संचयी प्रभाव घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन द्वारा सीमित होता है और पाटन और सब्सिडीकरण के क्षति□ँ प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक नहीं हो सकता।

214. प्राधिकारी आगे पाते हैं कि पाटन रोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क क्रमशः पाटन और सब्सिडीकरण, अर्थात भिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं को संबोधित करते हैं। तथापि, न्यूनतर शुल्क नियम का अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त उपचारात्मक प्रभाव सत्यापित आंकड़ों के आधार पर स्थापित क्षति मार्जिन से परे न जाए। यह तंत्र घरेलू उद्योग को अति-प्रतिकार से रोकता है और व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाने में आनुपातिकता सुनिश्चित करता है।

215. प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित/उपयोगकर्ता प्रभाव विश्लेषण उन घरेलू हितधारकों द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके हित प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें उपयोगकर्ता/उपभोक्ता/आयातक शामिल हैं, न कि व्यापक दावों के आधार पर।

216. इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, वर्तमान जांच में, उपयोगकर्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थीं, और जांच शुरू करने की सूचना ने अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके प्रचालनों पर शुल्कों के किसी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में प्रासंगिक आंकड़े अभिलेख पर रखने का अवसर प्रदान किया था।

217. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली या आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी आगे ध्यान देते हैं कि किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता संघ ने अपनी लागत संरचना में जांचाधीन वस्तुओं की हिस्सेदारी, उत्पादन लागत, मूल्य निर्धारण, रोजगार या प्रतिस्पर्धात्मकता पर शुल्कों के अपेक्षित प्रभाव, या इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य सत्यापन योग्य साक्ष्य के बारे में परिमाणित सूचना प्रदान नहीं की है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

218. उपयोगकर्ताओं से ऐसी परिमाणित और सत्यापन योग्य सूचना के अभाव में, प्राधिकारी का मानना है कि अनुप्रवाह उद्योगों को क्षति के दावे वर्तमान जांच के अभिलेख पर अप्रमाणित रहते हैं।

219. घरेलू उद्योग ने एक परिमाणित प्रभाव विश्लेषण प्रदान किया जो प्रदर्शित करता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का उत्पाद के अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

i. एचडीपीई बुना बोरा एक उदाहरण है जहाँ जांचाधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है।

ii. आईएस 11652:2017 के अनुसार, एचडीपीई बुने बोरे (अनुप्रवाह उत्पाद) में राख सामग्री 5% है, जो इंगित करती है कि तैयार उत्पाद में 5% कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री है।

iii. जांचाधीन उत्पाद में लगभग 75-85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है।

iv. इसलिए, 1 किग्रा के एचडीपीई बुने बोरे में 0.0625 किग्रा (6.25%) जांचाधीन उत्पाद होगा।

v. किसी भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाने का अंतिम उत्पाद पर **0.001%** का नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

220. प्राधिकारी इस तर्क पर ध्यान देते हैं कि शुल्क उपलब्धता और आपूर्ति स्थिरता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस पहलू पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने कहा है कि भारतीय उद्योग की कुल स्थापित क्षमता लगभग 12-15 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान कुल भारतीय उत्पादन 7,15,516 मीट्रिक टन बताया गया है, जो क्षमता के अल्प-उपयोग को इंगित करता है।

221. उपयोगकर्ताओं से यह प्रदर्शित करने वाले परिमाणित साक्ष्य के अभाव में कि संबद्ध देश से आयात आपूर्ति स्थिरता के लिए अपरिहार्य हैं, प्राधिकारी का मानना है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के कारण आपूर्ति व्यवधान का तर्क अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

222. प्राधिकारी इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि जांचाधीन वस्तुएँ अनेक अनुप्रवाह अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं और इनपुट लागत में कोई वृद्धि उपभोक्ताओं पर डाली जा सकती है। तथापि, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी ध्यान देते हैं कि जांचाधीन वस्तुएँ अनुप्रवाह प्लास्टिक उत्पादों की कुल लागत का एक छोटा अनुपात बनाती हैं, और किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के कारण संभावित लागत पारेषण, मुद्रास्फीति प्रभाव या प्रतिस्पर्धात्मकता की हानि प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य नहीं रखा है। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी का मानना है कि दावा किया गया अनुप्रवाह लागत प्रभाव अपरिमाणित बना हुआ है।

223. प्राधिकारी भारतीय उद्योग की संरचना और निरंतर पाटित आयातों के संभावित व्यापक प्रभावों के बारे में घरेलू उद्योग की अनुरोधों पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें क्षमता का अल्प-उपयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों पर दबाव, और बंदी या श्वेत-लेबलिंग में रूपांतरण जैसे कथित संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित विश्लेषण के लिए घरेलू उत्पादकों और घरेलू उपयोगकर्ताओं के हितों का संतुलन आवश्यक है, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित खंडित घरेलू विनिर्माण आधार के हित भी प्रासंगिक विचारणीय हैं जहाँ पाटित आयातों के कारण क्षति पाई जाती है।

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेख भारत में घरेलू उत्पादन और क्षमता की उपलब्धता को इंगित करता है और किसी भी अनुप्रवाह उपयोगकर्ता ने आंकड़ों के साथ यह प्रदर्शित नहीं किया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अनुप्रवाह उद्योगों या आम जनता पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तदनुसार, प्राधिकारी केवल उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा की गई सार्वजनिक हित अनुरोधों के आधार पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की सिफारिश करने से परहेज करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं।

225. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादक मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की खंडित संरचना, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादक हैं, वर्तमान जांच की शुरुआत में और खंडित उद्योगों पर लागू प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुप्रयोग में पहले ही स्वीकार की जा चुकी है।

226. प्राधिकारी पाते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादक सामान्यतः सीमित वित्तीय सुदृढ़ता, पूंजी तक बाधित पहुँच और पाटित आयातों से उत्पन्न निरंतर कीमत दबाव को अवशोषित करने की कम क्षमता के साथ कार्य करते हैं। बड़े एकीकृत उत्पादकों के विपरीत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विशेष रूप से लंबे समय तक कीमत कटौती और कीमत ह्रास के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ सीधे उनकी व्यवहार्यता, नकद प्रवाह और प्रचालन जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

227. प्राधिकारी का मानना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों का संरक्षण सार्वजनिक हित विश्लेषण में एक प्रासंगिक विचारणीय तत्व है, विशेष रूप से जहाँ घरेलू उद्योग रोजगार प्रदान करता है, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का समर्थन करता है और देश के भीतर मूल्य संवर्धन में योगदान देता है। पाटित आयातों के कारण ऐसे उद्योग का क्षरण तत्काल उत्पाद बाजार से परे विस्तृत व्यापक आर्थिक प्रभाव डालेगा।

228. प्राधिकारी पाते हैं कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध मुख्यतः कथित अनुप्रवाह प्रभाव पर केंद्रित रही हैं, बिना घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों को निरंतर क्षति के परिणामों को संबोधित किए। सार्वजनिक हित विश्लेषण के लिए सभी घरेलू हितधारकों के हितों का संतुलित आकलन आवश्यक है, जिसमें घरेलू विनिर्माण और रोजगार की स्थिरता शामिल है।

229. अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं से भौतिक प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित करने वाले परिमाणित साक्ष्य के अभाव में, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-प्रधान घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की सिफारिश घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादकों को पाटित आयातों के क्षति□ँ के प्रभावों से बचाने और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ बहाल करने के लिए एक आवश्यक और आनुपातिक उपाय है।

230. तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि, सार्वजनिक हित के विपरीत होने से दूर, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण क्षमता की रक्षा करके, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और पाटित आयातों पर दीर्घकालिक निर्भरता को रोककर सार्वजनिक हित की सेवा को पूरा करता है।

231. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित के संबंध में सभी अनुरोधों पर विचार किया है और नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों का मूल उद्देश्य भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को पहुँचाई गई क्षति को समाप्त करना है।

232. **<u>शुल्क प्रभाव विश्लेषण का परिमाणीकरण:</u>**

Impact of Duty on Calcium Carbonate Filler Masterbatch Users & Consumers in India

Illustrative downstream impact analysis

Illustrative Duty Rate = USD 10/MT = approx. ₹0.97 per kg of filler masterbatch

Assumptions: Exchange rate ₹96.84/USD | Filler masterbatch loading in end products assumed at 10%–20%

#	Product	Indicative Product Value	Article Weight	Filler Masterbatch Content	Impact at Illustrative Duty (₹ increase per unit & % impact)	Impact status
1	HDPE woven sack	Packed goods value ₹800	80 g	10%	₹0.008 per sack (0.001%)	Low Impact
2	Small T-shirt carry bag	Goods value ₹300	8 g	15%	₹0.001 per bag (0.0003%)	Low Impact
3	Garbage bag	₹15 per bag	20 g	20%	₹0.004 per bag (0.03%)	Low Impact
4	Nursery / plant bag	Plant value ₹20	12 g	20%	₹0.002 per bag (0.01%)	Low Impact
5	Courier / packing bag	Shipment value ₹500	25 g	15%	₹0.004 per bag (0.001%)	Low Impact
6	25 kg woven sack / liner	Packed goods value ₹1,000	70 g	10%	₹0.007 per sack (0.001%)	Low Impact
7	Industrial liner / heavy duty bag	Packed goods value ₹1,125	100 g	10%	₹0.010 per bag (0.001%)	Low Impact
8	PE film / packaging pouch	Packed goods value ₹80	10 g	15%	₹0.001 per pouch (0.002%)	Low Impact
9	Shopping / carry bag	Goods value ₹500	15 g	15%	₹0.002 per bag (0.0004%)	Low Impact

Absolute impact per unit at illustrative duty

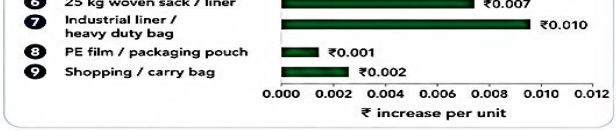

Consumer Applications mostly **0.0003%** to **0.03%** of product value

Industrial Applications around **0.001%** of packed product value

Analysis

At an illustrative duty of USD 10/MT, the impact works out to only about ₹0.97 per kg of filler masterbatch. Since filler masterbatch is used only in limited proportions, typically 10%–20% of the end product, the duty impact per downstream article remains extremely small. Across the examples shown, the increase ranges from about ₹0.001 to ₹0.010 per unit and generally remains well below 0.03% of product value. This demonstrates that the duty burden is highly diluted in downstream products and is unlikely to materially affect users or consumers.

For most consumer and industrial applications, the impact of duty on calcium carbonate filler masterbatch is generally below 0.03% of product value.

ञ. प्रकटीकरण के बाद का विवरण

ञ.1 वियतनाम सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

233. वियतनाम सरकार, भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रकटीकरणोत्तर अनुरोध किए हैं:

i. दिनांक 20 मार्च 2026 के पहले प्रकटीकरण के बाद संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य जारी किए जाने को प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित बताया गया। यह अनुरोध किया गया कि प्राधिकारी पूर्ण संशोधित गणनाएं प्रकट किए बिना और टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना प्रकटीकृत पद्धति अथवा मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता।

ii. संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समय को अपर्याप्त बताया गया। कुछ पक्षकारों ने यह भी आपत्ति की कि प्रकटीकरण के बाद घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किसी नई सूचना पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक उसे सार्वजनिक फाइल में न रखा जाए और उसका प्रभावी खंडन करने का अवसर न दिया जाए।

iii. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के उत्पादन, पात्रता, नमूनाकरण, क्षति संबंधी आंकड़ों, क्षतिरहित कीमत, मानदंड संबंधी आंकड़ों और सहायिकी गणनाओं के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का आरोप लगाया। यह तर्क दिया गया कि सूचकांकित अथवा समेकित प्रकटीकरण से प्रभावी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना संभव नहीं था।

iv. आवेदक संगठनों और आवेदक घरेलू उत्पादकों की पात्रता पर विवाद किया गया। यह अनुरोध किया गया कि प्राधिकारी ने नियम 6(3) के अनुपालन को स्थापित करने के लिए आवश्यक उत्पादन हिस्सेदारी प्रकट नहीं की तथा चार घरेलू उत्पादकों का नमूना प्रतिनिधिक सिद्ध नहीं किया गया।

v. पंद्रह माह की जांच अवधि को असाधारण और पर्याप्त कारणों से असमर्थित बताया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि क्षति विश्लेषण विकृत हो सकता है, क्योंकि नमूने में शामिल कुछ उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का भी निर्माण करते हैं।

vi. हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के दायरे अथवा पीसीएन पद्धति में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की; तथापि, उन्होंने कहा कि सभी तुलनाएं और मार्जिन निर्धारण पीसीएन-विशिष्ट तथा सत्यापित उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित रहने चाहिए।

vii. पहले और संशोधित प्रकटीकरण के बीच सहायिकी मार्जिन में हुई पर्याप्त कमी के आधार पर यह तर्क दिया गया कि पहला प्रकटीकरण अविश्वसनीय मानदंडों और धारणाओं पर आधारित था। तथापि, कुछ निर्यातकों ने

कहा कि संशोधित गणनाओं में भी पूर्ण कार्यपत्रक, भाजक, आवंटन का आधार, विनिमय दरें और समायोजन प्रकट नहीं किए गए।

viii. कार्यक्रम 1 के संबंध में यह अनुरोध किया गया कि चूना पत्थर पर निर्यात कर एक सामान्य राजकोषीय और संसाधन-संरक्षण उपाय है तथा एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के अंतर्गत निजी आपूर्तिकर्ताओं को सौंपना अथवा निर्देश देना नहीं माना जा सकता।

ix. वियतनाम सरकार और निर्यातकों ने अनुरोध किया कि घरेलू उपलब्धता अथवा कीमत पर निर्यात कर के मात्र प्रभाव से वित्तीय अंशदान स्थापित नहीं होता। यह तर्क दिया गया कि प्राधिकारी को ऐसी सकारात्मक सरकारी कार्रवाई की पहचान करनी होगी, जो निजी निकायों को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को चूना पत्थर अथवा कैल्शियम कार्बोनेट उपलब्ध कराने के लिए बाध्य या अधिकृत करती हो।

x. प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि वे स्वतंत्र निजी आपूर्तिकर्ताओं से सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदते हैं और सरकार से चूना पत्थर नहीं खरीदते। चूना पत्थर और प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट को अलग-अलग वस्तुएं बताया गया, जो विभिन्न प्रशुल्क शीर्षकों के अंतर्गत आती हैं और जिनकी भौतिक विशेषताएं तथा प्रसंस्करण लागत अलग हैं।

xi. यह तर्क दिया गया कि लाभ अंतरण अथवा कंपनी-विशिष्ट लाभ का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। निर्यातकों के अनुसार, चूना पत्थर पर किसी अपस्ट्रीम प्रभाव को प्रसंस्कृत कैल्शियम कार्बोनेट के डाउनस्ट्रीम क्रेता से तब तक नहीं जोड़ा जा सकता, जब तक प्राधिकारी सत्यापित लेन-देन-विशिष्ट साक्ष्य से यह स्थापित न करे कि कथित लाभ उस क्रेता तक पहुंचा।

xii. कार्यक्रम 1 की विशिष्टता पर इस आधार पर विवाद किया गया कि चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। प्रत्यर्थियों ने अनुरोध किया कि केवल इस कारण से कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक इस निविष्टि का उपयोग करते हैं, व्यापक रूप से उपलब्ध निविष्टि अथवा सामान्य रूप से लागू निर्यात-कर उपाय को विशिष्ट नहीं माना जा सकता।

xiii. कैल्शियम कार्बोनेट के मलेशियाई निर्यात मूल्यों को बाह्य मानदंड के रूप में उपयोग किए जाने को चुनौती दी गई। प्रत्यर्थियों ने इस संबंध में तुलना-योग्यता पर प्रश्न उठाए कि व्यापारित सामग्री ग्राउंड अथवा प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट थी, उसका प्रशुल्क वर्गीकरण, कण आकार, शुद्धता, कोटिंग, सफेदी, अंतिम उपयोग, मात्रा, व्यापार स्तर और अन्य वाणिज्यिक शर्तें क्या थीं।

xiv. यह अनुरोध किया गया कि प्रशुल्क मद 28365000 में रासायनिक रूप से परिभाषित, प्रेसिपिटेटेड, कोटेड अथवा परिष्कृत कैल्शियम कार्बोनेट शामिल हो सकता है, जबकि कई वियतनामी उत्पादक ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट अथवा स्टोन पाउडर का उपयोग करते हैं। अतः मानदंड को उत्पाद की दृष्टि से असंगत और बढ़ा हुआ बताया गया।

xv. एन तिएन, यूएस मास्टरबैच और विटाप्लास ने मिस्र को मानदंड स्रोत के रूप में अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मिस्र कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, वह सामान्य वाणिज्यिक शर्तों वाला तथा अविकृत बाजार है और भारतीय उद्योग द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट आपूर्ति करता है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 23.06.2026 के अपने मेल के माध्यम से मलेशिया से भारत तक विषय वस्तु के समुद्री भाड़ा प्रभारों से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किए हैं।

xvi. प्रत्यर्थियों ने जांच अवधि के दौरान भारत में कैल्शियम कार्बोनेट के आयातों में वियतनाम, मिस्र और मलेशिया की कथित हिस्सेदारी पर भरोसा किया, जो क्रमशः लगभग 45%, 37% और 13% बताई गई। इस

आधार पर मिस्र को मलेशिया की तुलना में कहीं अधिक प्रतिनिधिक बताया गया और मलेशिया को अपेक्षाकृत छोटा स्रोत कहा गया।

xvii. यह भी तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग ने संबंधित पाटनरोधी जांच में स्वीकार किया था कि वह मिस्र, वियतनाम और भारत से कैल्शियम कार्बोनेट खरीदता है। प्रस्तावित मानदंड निर्धारण से मिस्र को बाहर रखने को चयनात्मक तथा अधिक सहायिकी मार्जिन उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया बताया गया।

xviii. कुछ प्रत्यर्थियों ने कहा कि वियतनामी उत्पादकों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट की औसत खरीद कीमत 35 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, जबकि आवेदक उद्योग ने लगभग 130 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का एफओबी मानदंड मूल्य प्रस्तावित किया है। चूना पत्थर के ढेलों और कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों के लिए प्रस्तावित मानदंड मूल्य खरीद कीमत के तीन गुने से अधिक है, जबकि निर्यात कर के रूप में कथित सहायिकी केवल 30% है। यदि यह मान भी लिया जाए, किंतु स्वीकार नहीं किया जाता, कि संपूर्ण 30% निर्यात कर को प्रतिकार योग्य सहायिकी माना जा सकता है, जो इस विषय पर स्थापित न्यायशास्त्र के विपरीत होगा, तब भी 300% से अधिक का मानदंड मूल्य प्रथम दृष्टया अनुचित है।

xix. प्रत्यर्थियों ने अनुरोध किया कि उचित समायोजन के बाद मिस्र की कीमतें किसी लाभ की अनुपस्थिति दर्शाती हैं। उन्होंने मिस्र की सीआईएफ कीमतों से समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार, बीमा और व्यापारी मार्जिन घटाने का प्रस्ताव किया, जिसमें पत्तन प्रभार के लिए 3%, बीमा के लिए 0.05% और व्यापारी मार्जिन के लिए 3% के सांकेतिक समायोजन शामिल थे। अपने तर्क के समर्थन में, दिनांक 23.06.2026 के अपने ईमेल के माध्यम से, उन्होंने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से भारत के न्हावा शेवा बंदरगाह तक समुद्री भाड़ा प्रभारों से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा प्रदान किया गया समुद्री भाड़ा 45-55 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की सीमा में है।

xx. यह तर्क दिया गया कि मानदंड देश का भौगोलिक रूप से निकट होना आवश्यक नहीं है; उसे समान व्यापार स्तर पर विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत दर्शानी चाहिए। फाइबरबोर्ड, एट्राजीन टेक्निकल और सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल से संबंधित प्राधिकारी के पूर्व निर्धारणों पर भरोसा किया गया, जिनमें अंतरराष्ट्रीय अथवा तीसरे देश की कीमतों का संदर्भ लिया गया था।

xxi. प्रत्यर्थियों ने मलेशियाई सीआईएफ मूल्यों को एफओबी में परिवर्तित किए जाने को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मलेशियाई सीआईएफ कीमत और कथित स्थानीय कीमत के बीच अंतर मुख्यतः भाड़ा, पत्तन, बीमा और व्यापारिक लागत को दर्शाता है; कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा और कम मूल्य वाला उत्पाद है; तथा केवल वास्तविक, समकालीन और उत्पाद-विशिष्ट भाड़े का उपयोग किया जाना चाहिए।

xxii. पूर्वाग्रह के बिना, वियतनाम सरकार और कुछ निर्यातकों ने सत्यापित घरेलू वियतनामी कीमतों पर भरोसा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वियतनाम को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता तथा निजी लेन-देन की मौजूदगी के कारण प्राधिकारी को घरेलू कीमतों का उपयोग करना चाहिए, जब तक सकारात्मक साक्ष्य से महत्वपूर्ण विकृति स्थापित न हो।

xxiii. कार्यक्रम 12 के संबंध में प्रत्यर्थियों ने बिजली, प्राकृतिक गैस अथवा कोयले को प्रतिकार योग्य न मानने के प्राधिकारी के प्रस्ताव का समर्थन किया। यह अनुरोध किया गया कि भाग लेने वाले उत्पादकों ने प्राकृतिक गैस अथवा कोयले का उपयोग नहीं किया और उपभोक्ताओं की व्यापक श्रेणियों पर लागू प्रकाशित प्रशुल्क दरों पर सामान्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिजली खरीदी।

xxiv. प्रत्यर्थियों ने कहा कि वोल्टेज, उपयोग के समय अथवा उपभोक्ता श्रेणी पर आधारित बिजली प्रशुल्क में अंतर सामान्य उपयोगिता-मूल्य निर्धारण की विशेषताएं हैं और इनसे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को विशिष्टता अथवा अधिमान्य लाभ स्थापित नहीं होता।

xxv. कार्यक्रम 13 के संबंध में निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने औद्योगिक पार्क विकासकर्ताओं से वाणिज्यिक शर्तों पर भूमि-उपयोग अधिकार प्राप्त किए अथवा उप-पट्टे पर लिए और कुछ मामलों में प्रांतीय आधार दरों से अधिक राशि का भुगतान किया। यह तर्क दिया गया कि किसी निजी इकाई से उप-पट्टा लेना सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराना नहीं है।

xxvi. प्रत्यर्थियों ने भूमि प्रोत्साहनों की विशिष्टता पर विवाद करते हुए कहा कि छूट और कटौतियां वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीय-विकास मानदंडों पर आधारित हैं तथा नामित क्षेत्रों में स्थित सभी पात्र उद्यमों को उपलब्ध हैं। एडीसी प्लास्टिक ने आगे दावा किया कि उसकी भूमि कीमत संबंधित मानदंड से लगभग 45% अधिक थी और उसे भूमि अथवा जल-किराए में कोई रियायत नहीं मिली।

xxvii. थाईलैंड निवेश बोर्ड के आंकड़ों अथवा निर्मित कारखाने/गोदाम की किराया दरों के उपयोग का इस आधार पर विरोध किया गया कि वे तुलना योग्य नहीं हैं। एक प्रत्यर्थी ने, पूर्वाग्रह के बिना, कहा कि यदि थाईलैंड के मानदंड का उपयोग किया जाए तो कारखाना किराया दर के स्थान पर औद्योगिक एस्टेट की भूमि दर अपनाई जानी चाहिए।

xxviii. कार्यक्रम 3 के संबंध में प्रत्यर्थियों ने अनुरोध किया कि कॉरपोरेट आयकर प्रोत्साहन वस्तुनिष्ठ वैधानिक मानदंडों पर आधारित सामान्य राजकोषीय व्यवस्था का भाग हैं। यह तर्क दिया गया कि ये प्रोत्साहन न तो निर्यात पर निर्भर हैं और न ही प्लास्टिक उद्योग तक सीमित हैं; इसलिए वे विशिष्ट नहीं हैं।

xxix. एडीसी प्लास्टिक ने जांच अवधि के एक भाग के दौरान सीमित कर छूट स्वीकार की, किंतु तर्क दिया कि कोई भी लाभ अत्यंत कम और न्यूनतम सीमा से नीचे था। प्रत्यर्थियों ने यह भी अनुरोध किया कि लाभ को छूट की वास्तविक अवधि तक सीमित रखा जाए और कंपनी-विशिष्ट करयोग्य आय तथा सामान्य वैधानिक देयता के आधार पर गणना की जाए।

xxx. कार्यक्रम 4 तथा कार्यक्रम 2 और 6 के संबंध में भाग लेने वाले निर्यातकों ने कहा कि उन्होंने किसी आयात-शुल्क छूट, मास्टर प्लान सहायता अथवा निर्यात-संवर्धन लाभ का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अनुरोध किया कि किसी कार्यक्रम का कानून में अस्तित्व अथवा उसकी संभावित उपलब्धता, सत्यापित लाभ प्राप्ति के अभाव में, किसी मार्जिन का आधार नहीं बन सकती।

xxxi. कार्यक्रम 5, 7, 8, 9, 10 और 11 के संबंध में प्रत्यर्थियों ने कहा कि उनके ऋण निजी वाणिज्यिक बैंकों से अथवा बाजार शर्तों पर प्राप्त किए गए। उन्होंने प्रत्येक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक को सार्वजनिक निकाय मानने पर विवाद किया और अनुरोध किया कि किसी लाभ की जांच समान मुद्रा में तुलना योग्य ऋणों के आधार पर की जाए तथा परिपक्वता, प्रतिभूति, ऋण-पात्रता और उधारकर्ता-विशिष्ट शर्तों का उचित ध्यान रखा जाए।

xxxii. एन तिएन और अन्य पक्षकारों ने अनुरोध किया कि बैंक ऑफ इंडिया, वियतनाम शाखा की सांकेतिक दरों के स्थान पर वियतनाम में निजी विदेशी बैंकों द्वारा वास्तव में ली गई दरों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋणों का अलग उपचार किया जाना चाहिए।

xxxiii. यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और उसकी हंग येन शाखा ने अनुरोध किया कि उन्होंने अपने मूल उत्तरों में संबंधित कार्यक्रम की सूचना दाखिल की थी और संशोधित प्रकटीकरण में उन्हें व्यक्तिगत मार्जिन सही

रूप से दिया गया। अन्य पक्षकारों ने सहयोग की सीमा और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर कंपनी-विशिष्ट उपचार की मांग की।

xxxiv. वीएमआई ने तर्क दिया कि समान सहायिकी मार्जिन सीमा के बावजूद उसका क्षति मार्जिन अन्य भाग लेने वाले निर्यातकों की तुलना में काफी अधिक था। उसने पीसीएन-वार पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत की तुलना तथा भारित औसत पद्धति की पुनः जांच का अनुरोध किया।

xxxv. प्रत्यर्थियों ने वास्तविक क्षति, क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्षों पर विवाद किया। उन्होंने घरेलू उद्योग के निष्पादन के संभावित कारणों के रूप में मांग वृद्धि, क्षमता विस्तार, आंतरिक प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की लागत, उत्पाद मिश्रण, उद्योग की विखंडित संरचना और अन्य कारकों पर भरोसा किया।

xxxvi. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि किसी भी प्रतिकारी शुल्क को सहायिकी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि तक सीमित रखा जाना चाहिए। वियतनाम से उसी उत्पाद पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए उन्होंने दोहरे उपचार से संरक्षण की मांग की और कुछ अनुरोधों में कहा कि पाटनरोधी तथा प्रतिकारी शुल्क का संयुक्त भार क्षति मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

xxxvii. प्रयोक्ताओं और निर्यातकों ने अनुरोध किया कि संबद्ध वस्तुएं प्लास्टिक उत्पादों की महत्वपूर्ण निविष्टि हैं और अतिरिक्त शुल्क से डाउनस्ट्रीम लागत बढ़ेगी। उन्होंने जांच समाप्त करने अथवा वैकल्पिक रूप से ऐसा सीमित और संतुलित शुल्क लगाने का अनुरोध किया, जिससे आपूर्ति अथवा डाउनस्ट्रीम प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित न हो।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

234. घरेलू उद्योग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रकटीकरणोत्तर अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने कहा कि संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित था, क्योंकि उसमें पहले प्रकट किए गए सहायिकी मार्जिन में महत्वपूर्ण कमी की गई। घरेलू उद्योग ने पहले के मार्जिन बहाल करने अथवा संशोधित मानदंड मूल्यों, समायोजनों, गणनाओं और परिवर्तन के कारणों का पूर्ण प्रकटीकरण करने का अनुरोध किया।

ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसे उत्तर देने के लिए प्रभावी रूप से केवल तीन कार्य दिवस दिए गए और संशोधित गणना पत्रकों तथा मानदंड समायोजनों के प्रकटीकरण संबंधी उसके अनुरोध पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए गए। फिर भी उसने अनुमत समय के भीतर अतिरिक्त सहायक सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की।

iii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए उत्पाद दायरे और पीसीएन पद्धति का समर्थन किया, जो वियतनाम से उसी उत्पाद से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम रूप दी गई पद्धति के समान हैं।

iv. यह अनुरोध किया गया कि आवेदन और घरेलू उद्योग की पात्रता सीवीडी नियमावली तथा व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुरूप हैं। बारह आवेदक उत्पादकों ने निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई और इक्कीस अतिरिक्त उत्पादकों ने आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया।

v. चार घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण को विखंडित और मुख्यतः एमएसएमई उद्योग के लिए वैध तथा प्रतिनिधिक बताया गया। यह कहा गया कि नमूने में शामिल उत्पादक बड़े उत्पादकों में से हैं और भौगोलिक तथा परिचालन विविधता को दर्शाते हैं।

vi. पंद्रह माह की जांच अवधि को विखंडित उद्योग की परिस्थितियों में विधिसम्मत और उपयुक्त बताया गया। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए सभी क्षति और लागत संबंधी आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट हैं।

vii. गोपनीयता के दावों को इस आधार पर उचित बताया गया कि उत्पादक-वार बिक्री मूल्य, लाभप्रदता, लागत, वित्त लागत, मूल्यह्रास, संयंत्र संबंधी आंकड़े, क्षमता उपयोग और उपभोग मानकों के प्रकटीकरण से वाणिज्यिक हानि होगी। यह कहा गया कि सूचकांकित और समेकित प्रवृत्तियां पर्याप्त समझ प्रदान करती हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि वियतनामी उत्पादकों/निर्यातकों को न्यूनतम सीमा से अधिक प्रतिकार योग्य सहायिकी प्राप्त हुई, किंतु लगभग सभी भाग लेने वाले उत्पादकों तथा अवशिष्ट श्रेणी के मार्जिन में पर्याप्त कमी पर कड़ी आपत्ति की।

ix. कार्यक्रम 1 के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रतिकार योग्यता के निष्कर्ष का समर्थन किया। उसने अनुरोध किया कि चूना पत्थर ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमुख अपस्ट्रीम कच्चा माल है और कैल्शियम कार्बोनेट संबद्ध वस्तुओं की मुख्य निविष्टि है; अतः चूना पत्थर को देश में बनाए रखने और उसकी कीमत दबाने वाले उपायों का प्रभाव चूना पत्थर से निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट तक पहुंचता है।

x. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि कार्यक्रम केवल उन उत्पादकों तक सीमित नहीं है जो सीधे चूना पत्थर के ढेले खरीदते हैं। जहां उत्पादक कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर खरीदता है, वहां तुलना उपयुक्त कैल्शियम कार्बोनेट मानदंड से होनी चाहिए; और जहां वह चूना पत्थर के ढेलों का उपयोग करता है, वहां मानदंड चूना पत्थर के अनुरूप होना चाहिए। तत्काल खरीद का स्वरूप पहचान की गई खनिज मूल्य शृंखला को समाप्त नहीं करता।

xi. संयुक्त अरब अमीरात के चूना पत्थर मानदंड को अनुपयुक्त बताया गया, क्योंकि उसके अंतर्गत लेन-देन मुख्यतः इस्पात, सीमेंट और धातुकर्म फ्लक्स के उपयोगों से संबंधित थे, जिनमें फ्लक्स-ग्रेड सामग्री भी शामिल थी, और वे फिलर मास्टरबैच में प्रयुक्त निविष्टि से तुलना योग्य नहीं थे।

xii. मलेशिया को उपयुक्त बाह्य स्रोत बताया गया, क्योंकि मलेशिया से भारत को निर्यात किया गया कैल्शियम कार्बोनेट कण आकार, शुद्धता, सफेदी और औद्योगिक विशेषताओं की दृष्टि से वाणिज्यिक रूप से तुलना योग्य था तथा उत्पाद-विशिष्ट प्रशुल्क स्तर पर जांच अवधि की निरंतर मूल्य शृंखला उपलब्ध थी।

xiii. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उसका मानदंड साक्ष्य केवल चार अंकों वाले विषम उत्पाद समूह तक सीमित नहीं था। उसने एचएस 283650 के आंकड़ों, संबंधित भारतीय प्रशुल्क मद 28365000 के आंकड़ों, ट्रेड मैप सूचना, ट्रेडस्टैट आंकड़ों, खरीद अभिलेखों और संबंधित पाटनरोधी जांच की सामग्री पर भरोसा किया।

xiv. घरेलू उद्योग ने मलेशियाई सीआईएफ आयात आंकड़ों को एफओबी में बदलना केवल इस शर्त पर स्वीकार किया कि भाड़ा और बीमा वास्तविक कैल्शियम कार्बोनेट भाड़े के आधार पर घटाए जाएं। उसने जांच अवधि के बीजक, प्रवेश पत्र, खरीद रजिस्टर, लेखा उद्धरण और तृतीय-पक्ष आपूर्तिकर्ता के भाड़ा साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा अनुरोध किया कि ये रिकॉर्ड पर पहले रखी गई एफओबी शृंखला की पुष्टि करते हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि किसी असमान उत्पाद अथवा अवधि का भाड़ा आंकड़ा समकालीन कैल्शियम कार्बोनेट भाड़ा साक्ष्य को अप्रभावी नहीं कर सकता। उसने सीआईएफ आधार मूल्य और

समायोजनों के प्रकटीकरण तथा सत्यापित उत्पाद-विशिष्ट भाड़े और बीमा का उपयोग करने के बाद कार्यक्रम 1 का मार्जिन बहाल करने का अनुरोध किया।

xvi. घरेलू उद्योग ने कार्यक्रम 12 को प्रतिकार योग्य मानने का अनुरोध किया। उसने कहा कि वियतनाम में बिजली की कीमतें उद्योग और व्यापार मंत्रालय तथा ईवीएन के माध्यम से केंद्रीय रूप से विनियमित हैं, प्रशुल्क विभेदन विनिर्माण प्रयोक्ताओं के पक्ष में है और लाभ क्षेत्र-विशिष्ट है।

xvii. कार्यक्रम 13 के संबंध में घरेलू उद्योग ने वित्तीय अंशदान और विशिष्टता संबंधी निष्कर्षों का समर्थन किया, किंतु सरकार द्वारा प्रशासित भूमि व्यवस्था से विकृत बताई गई वियतनामी दरों के स्थान पर तुलना योग्य थाई औद्योगिक भूमि आंकड़ों सहित बाह्य बाजार मानदंड के उपयोग का अनुरोध किया।

xviii. घरेलू उद्योग ने कार्यक्रम 3 को प्रतिकार योग्य मानने का समर्थन किया। उसने अनुरोध किया कि 20% की सामान्य वैधानिक कॉरपोरेट आयकर दर उपयुक्त मानदंड है और लाभ सत्यापित सामान्य कर देयता तथा जांच अवधि के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए कर के बीच का अंतर है।

xix. घरेलू उद्योग ने उन सभी मामलों में आयात-शुल्क छूट को प्रतिकार योग्य मानने का अनुरोध किया, जहां किसी भाग लेने वाले निर्यातक को विशिष्ट छूट अथवा अधिक वापसी प्राप्त हुई। उसने स्वीकार किया कि मात्रा निर्धारण जांच अवधि के दौरान सत्यापित रूप से छोड़े गए राजस्व की राशि पर आधारित होना चाहिए।

xx. घरेलू उद्योग ने वीडीबी तथा सरकारी स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा निर्देशित बैंकों के अधिमान्य ऋण को प्रतिकार योग्य मानने का समर्थन किया। उसने अनुरोध किया कि लाभ को वियतनाम में तुलना योग्य निजी वाणिज्यिक ऋण दरों के आधार पर मापा जाना चाहिए।

xxi. कार्यक्रम 2 और 6 को उनकी संरचना के अनुसार क्षेत्र-विशिष्ट अथवा निर्यात-आधारित बताया गया। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि लाभ न लेने के दावों की जांच सत्यापित अभिलेखों और सरकारी संवितरण सूचना के आधार पर की जानी चाहिए।

xxii. घरेलू उद्योग ने यूएस मास्टरबैच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और उसकी हंग येन शाखा को व्यक्तिगत मार्जिन दिए जाने पर आपत्ति की तथा उत्तरों में महत्वपूर्ण कमियों और कार्यक्रम संबंधी पूर्ण सूचना के अभाव का आरोप लगाते हुए असहयोगी अवशिष्ट दर लागू करने का अनुरोध किया।

xxiii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के क्षति संबंधी निष्कर्षों का समर्थन किया। उसने अनुरोध किया कि सहायिकी प्राप्त आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई, उन्होंने बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की, घरेलू कीमतों में कटौती और दबाव उत्पन्न किया तथा लाभ, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट का कारण बने।

xxiv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि क्षति विश्लेषण नमूने में शामिल उत्पादकों के सत्यापित विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट अभिलेखों पर आधारित है और किसी प्रमाणित वैकल्पिक कारण ने सहायिकी प्राप्त आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं किया।

xxv. घरेलू उद्योग ने न्यूनतर शुल्क नियम लागू करने का समर्थन किया और अनुरोध किया कि प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए शुल्क सहायिकी मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कम होना चाहिए। उसने अधिनियम और नियमावली के अनुसार पाटनरोधी उपाय के साथ होने वाले अतिव्यापन का उचित उपचार करने का भी अनुरोध किया।

xxvi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रतिकारी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित करने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करेगा। डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव सीमित बताया गया, जबकि शुल्क न लगाए जाने से बड़े और विखंडित घरेलू उद्योग को हो रही क्षति जारी रहेगी।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

I. प्रक्रियात्मक और प्रारंभिक मुद्दे

235. प्राधिकारी ने वियतनाम सरकार, भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटीकरणोत्तर अनुरोधों की जांच की। संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य में पहले ही निपटाए गए दोहराव वाले अनुरोध पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए; केवल नए मुद्दों, कथित गणना त्रुटियों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले विषयों की जांच की गई।

236. सीवीडी नियमावली के नियम 18 के अनुसार अंतिम जांच परिणाम से पहले विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण और हितों की रक्षा के लिए सार्थक अवसर देना आवश्यक है। प्रकटीकरण वक्तव्य अंतिम निर्धारण नहीं है और किसी अस्थायी मानदंड, गणना अथवा मार्जिन में निहित अधिकार उत्पन्न नहीं करता। प्राधिकारी प्रासंगिक गणनाओं के कार्यसाधन में उपयोग की जाने वाली पद्धति पर टिप्पणियों पर पुनर्विचार कर सकता है, त्रुटियों को सुधार सकता है और पद्धति को परिष्कृत कर सकता है।

237. दिनांक 16 जून 2026 के संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य ने प्रतिकार योग्यता, मानदंड चयन, विशिष्टता, कंपनी-विशिष्ट लाभ और सहयोग पर पुनर्विचार के बाद दिनांक 20 मार्च 2026 के पहले प्रकटीकरण का स्थान लिया। समय के भीतर दाखिल की गई टिप्पणियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया, जबकि नई जानकारी का उपयोग केवल वहीं किया गया जहाँ वह सत्यापन योग्य थी।

238. कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पर आधारित उत्पाद दायरा और पीसीएन पद्धति बनाए रखी गई। घरेलू उद्योग की पात्रता की भी पुष्टि की गई: आवेदन दो संगठनों द्वारा बारह उत्पादकों की ओर से दायर किया गया था और इक्कीस अतिरिक्त उत्पादकों ने उसका समर्थन किया था। उद्योग की विखंडित संरचना को देखते हुए चार प्रतिनिधिक उत्पादकों का नमूनाकरण उचित माना गया। प्राधिकारी ने सत्यापित विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट लागत, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया।

239. पंद्रह माह की जांच अवधि को नियमावली के अनुरूप और प्रतिनिधिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाया गया। गोपनीयता के दावों की नियम 8 के अंतर्गत जांच की गई। कच्चे माल की खरीद कीमतों, कर अभिलेखों, ऋण शर्तों, भूमि समझौतों, उत्पादन लागत और उत्पादक-वार लाभप्रदता जैसे वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील आंकड़ों को सुरक्षित रखा गया, जबकि जहां संभव था वहां अगोपनीय सारांश, सूचकांकित प्रवृत्तियां और सीमाएं प्रकट की गईं।

II. सहायिकी पद्धति

240. पहले और संशोधित प्रकटीकरण के बीच सहायिकी मार्जिन में परिवर्तन कार्यक्रम-वार पुनः जांच, अधिक उत्पाद-विशिष्ट मानदंडों के उपयोग, कुछ कार्यक्रमों के उपचार में सुधार और कंपनी-विशिष्ट सूचना की जांच के

कारण हुआ। मार्जिन में परिवर्तन मनमानेपन का प्रमाण नहीं है; यह प्रकटीकरण प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

241. नियम 12 के अंतर्गत प्रतिकार योग्य राशि वह लाभ है, जो जांच अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता को दिया गया। अतः केवल सत्यापित प्राप्तकर्ता-विशिष्ट लाभों की मात्रा निर्धारित की गई। लाभों का आवंटन उपयुक्त सत्यापित कारोबार अथवा बिक्री भाजकों का उपयोग करते हुए संबद्ध वस्तुओं को किया गया। केवल इस कारण से कि कोई कार्यक्रम कानून में विद्यमान था, कोई लाभ नहीं जोड़ा गया।

III. कार्यक्रम 1 - पर्याप्त प्रतिफल से कम पर चूना पत्थर/कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति

242. प्राधिकारी ने वित्तीय अंशदान, लाभ, विशिष्टता और प्रतिकारी योग्यता की अलग-अलग अपेक्षाओं के संदर्भ में कार्यक्रम 1 की पुनः जांच की। निर्धारण केवल वियतनाम द्वारा चूना पत्थर पर लगाए गए निर्यात कर अथवा घरेलू और बाह्य कीमतों के अंतर पर आधारित नहीं है। यह वियतनाम के उस खनिज-नीति ढांचे की समग्र संरचना और संचालन पर आधारित है, जो खनन, निर्यात को सीमित कर खनिजों को देश में बनाए रखने तथा चूना पत्थर और उससे निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट की घरेलू उपलब्धता को नियंत्रित करता है।

243. एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) के अंतर्गत वित्तीय अंशदान तब उत्पन्न हो सकता है, जब सरकार निजी निकायों को वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य सौंपती अथवा निर्देश देती है। ऐसा सौंपना अथवा निर्देश केवल कीमत प्रभावों से अनुमानित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने विधिक ढांचे, निर्यात-कर उपचार, घरेलू डाउनस्ट्रीम उपयोग के लिए खनिजों को बनाए रखने के नीतिगत उद्देश्य और आपूर्तिकर्ताओं के आचरण पर विचार किया तथा पाया कि ये सभी कारक मिलकर सामान्य बाजार प्रतिक्रिया से आगे जाते हैं।

244. सत्यापित खरीद/चूना पत्थर/कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर की खपत की तुलना कैल्शियम कार्बोनेट मानक से की गई। चूँकि जांचे गए उत्पादक इस आगत के प्रत्यक्ष क्रेता या उपभोक्ता थे, इसलिए कोई पृथक पारगमन परीक्षण आवश्यक नहीं था। लाभ का निर्धारण वास्तव में भुगतान की गई कीमत की तुलना एक उपयुक्त मानक से करके किया गया, जो गुणवत्ता, उपलब्धता, परिवहन और खरीद या बिक्री की अन्य शर्तों सहित प्रचलित बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है।

245. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से भारत में कैल्शियम कार्बोनेट के आयात से संबंधित आयात डेटा निकाला गया, और यह नोट किया गया कि जांच अवधि के दौरान भारत में कैल्शियम कार्बोनेट के आयात में वियतनाम (44%) का स्थान सर्वोच्च था, इसके पश्चात मिस्र (37%) और मलेशिया (12%) का स्थान था। चूँकि यह जांच वियतनाम के कथित सब्सिडी कार्यक्रमों और उससे संबंधित कथित मूल्य विकृति के मुद्दों के विरुद्ध की जा रही है, इसलिए वियतनाम से भारत के आयात मूल्यों को उपयुक्त मानक के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया कि भारत को कैल्शियम कार्बोनेट के अगले सबसे बड़े निर्यातकों अर्थात् मिस्र और मलेशिया के आयात मूल्य, जब संयुक्त रूप से विचार किए गए, तो भारत में कुल आयात के 49 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे और इस कार्यक्रम के लिए मानक के रूप में अपनाने हेतु एक प्रतिनिधिक नमूने के रूप में विचार किए जाने योग्य पाए गए। इसलिए, मिस्र और मलेशिया दोनों के भारत में आयात

मूल्यों को भारित औसत के रूप में संयुक्त रूप से विचार करने की संभावना की जांच की गई और इसे इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त मानक के रूप में विचार करने के लिए उपयुक्त पाया गया।

246. प्राधिकारी ने मानक के लिए मिस्र और मलेशिया के विचार के संबंध में परस्पर विरोधी दावों की विशेष रूप से जांच की। भागीदारी करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने मिस्र के पर्याप्त उत्पादन और निर्यात, भारतीय आयात में उसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, घरेलू उद्योग की स्वयं की मिस्र से खरीद और मिस्री कीमतों की वाणिज्यिक प्रासंगिकता पर निर्भरता जताई।घरेलू उद्योग ने प्रशुल्क मद 28365000 के अंतर्गत उत्पाद-विशिष्ट और मिलान योग्य मलेशियाई शृंखला पर भरोसा किया। पुनर्विचार के बाद प्राधिकारी ने पाया कि जांच अवधि के दौरान दोनों देशों ने भारत को संबंधित कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति की और केवल इस कारण से किसी स्रोत को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि दूसरे स्रोत की मात्रा अधिक थी अथवा उसके लेन-देन संबंधी आंकड़े अधिक विस्तृत थे।

247. प्राधिकरण ने नियम 12(2)(घ), अनुलग्नक चार और सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 14(घ) के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मानक की पुनः जांच की है, जिसमें पारिश्रमिक की पर्याप्तता का मूल्यांकन प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर करने की आवश्यकता है, जिसमें मूल्य, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणन योग्यता, परिवहन और बिक्री की अन्य शर्तें शामिल हैं। इसलिए मानक चयन न्यूनतम मूल्य, निकटतम स्रोत, सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता या किसी भी पक्ष के लिए सबसे अनुकूल परिणाम द्वारा शासित नहीं होता। नियंत्रक परीक्षण यह है कि मानक विश्वसनीय, प्रतिनिधिक, तुलनीय और समान आधार पर लाभ को मापने में सक्षम हो।

248. मिस्र ने भारत में कैल्शियम कार्बोनेट के भौतिक रूप से अधिक आयात मात्रा का प्रतिनिधित्व किया और घरेलू उद्योग द्वारा इसके उपयोग ने औद्योगिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक उपलब्धता की पुष्टि की। हालाँकि, मलेशिया ने अधिक विस्तृत उत्पाद-विशिष्ट लेनदेन डेटा और विवरण, मूल्य विक्षेपण और शिपमेंट स्थितियों पर उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसलिए, प्राधिकरण ने कार्यक्रम संख्या 1 के प्रयोजन के लिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से निकाले गए मिस्र और मलेशिया दोनों स्रोतों से भारत के आयात मूल्यों को, जिन्हें यथोचित रूप से मुक्त पोत बंदरगाह स्तर पर समायोजित किया गया है, अर्थात् मिस्र के साथ-साथ मलेशिया से भारत के आयात मूल्यों के भारित औसत बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्य को एक उपयुक्त बाह्य मानक के रूप में माना है। प्राधिकरण ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से निकाले गए जांच अवधि में मिस्र और मलेशिया से भारत में बीमा एवं भाड़ा सहित लागत स्तर पर 8 अंकीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली संख्या कोड के वास्तविक आयातों पर निर्भरता जताई है, जिसे यथोचित रूप से मुक्त पोत बंदरगाह स्तर पर समायोजित किया गया है।

249. मानक की गणना प्रत्येक देश के समायोजित मूल्य को उसकी संगत पात्र आयात मात्रा से भारित करके की जाएगी। यह पद्धति परस्पर विरोधी दावों के बीच एक समानतापूर्ण समझौता नहीं है; यह अभिलेख पर उपलब्ध प्रचलित बाजार पारिश्रमिक का सबसे प्रतिनिधिक और कानूनी रूप से समर्थनीय माप है। यह मिस्र की अधिक वाणिज्यिक उपस्थिति को मान्यता देता है, मलेशियाई उत्पाद-विशिष्ट डेटा की विश्वसनीयता को संरक्षित करता है, स्रोत-विशिष्ट विकृति को न्यूनतम करता है और अंतिम प्राप्तकर्ता-विशिष्ट लाभ तथा सब्सिडी अंतर गणनाओं के लिए एक संतुलित, वस्तुनिष्ठ और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। श्रेणी, कण आकार, शुद्धता,

लेपन, श्वेतता, प्रसंस्करण मार्ग, अंतिम उपयोग और प्रशुल्क वर्गीकरण से संबंधित आपत्तियों की दोनों देशों के लिए यथोचित रूप से जांच की गई।

250. यह नोट किया जाता है कि मलेशियाई बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्यों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए सत्यापित भाड़े और बीमा मूल्यों को घटाकर मुक्त पोत बंदरगाह-समतुल्य आधार पर परिवर्तित किया गया है, जबकि मिस्री बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्यों को प्रतिवादियों या उत्पादक-निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए सत्यापित भाड़े और बीमा मूल्यों को घटाकर मुक्त पोत बंदरगाह-समतुल्य आधार पर परिवर्तित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि मानक आगत के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित करे और उत्पाद विशेषताओं, शिपमेंट शर्तों या व्यापार के स्तर में अंतर से विकृत न हो।

251. समग्र मानक को किसी एक देश के अनन्य उपयोग की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रतिनिधिक माना जाता है। केवल मिस्र पर अनन्य निर्भरता विस्तृत मलेशियाई लेनदेन साक्ष्य की अनदेखी करेगी, जबकि केवल मलेशिया पर अनन्य निर्भरता मिस्र से तुलनीय आयात की अधिक मात्रा के महत्व को कम आँकेगी। उत्पाद दायरे और वाणिज्यिक शर्तों के सामंजस्य के पश्चात संयुक्त श्रृंखला, प्रचलित बाजार स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करती है।

252. इस पद्धति का विधिक आधार नियम 12 और अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत प्रतिनिधिकता, तुलना-योग्यता और विद्यमान बाजार परिस्थितियां हैं। यद्यपि इससे संयोगवश निर्यातकों और घरेलू उद्योग के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन होता है, इसे इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यह अधिक व्यापक और विश्वसनीय बाह्य बाजार संदर्भ-आधारित मानदंड प्रदान करती है।

253. भारित मानदंड केवल उन उत्पादकों पर लागू किया गया है, जिन्होंने जांच अवधि के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट खरीदा अथवा उसका उपभोग किया। इसकी तुलना प्रत्येक सहयोगी उत्पादक की सत्यापित खरीद कीमत से समान आधार पर की गई है तथा भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रबंधन, व्यापार स्तर और खरीद की अन्य शर्तों के लिए समायोजन किए गए हैं। कंपनी-विशिष्ट लाभ गणनाएं गोपनीय गणना पत्रकों में दी गई हैं।

254. विशिष्टता की पुष्टि की गई, क्योंकि चिह्नित खनिज-निविष्टि ढांचा प्रभावित चूना पत्थर और उससे निर्मित निविष्टि पर निर्भर सीमित डाउनस्ट्रीम उद्यमों के समूह को लाभ पहुंचाता है। इन खनिजों के अन्य उपयोग होने मात्र से विशिष्टता समाप्त नहीं होती, जब कार्यक्रम की संरचना और संचालन तथा जांचाधीन उत्पादकों को प्राप्त लाभ स्थापित हो।

255. अतः कार्यक्रम 1 प्रतिकार योग्य बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट की खरीद के लिए अंतिम उत्पादक-विशिष्ट सहायिकी गणनाओं में मिस्र और मलेशिया से समायोजित तथा तुलना योग्य जांच अवधि के आयात मूल्यों का मात्रा-भारित औसत उपयोग किया जाएगा। सहायिकी मार्जिन में तदनुसार संशोधन किए जाएंगे।

IV. अन्य सहायिकी कार्यक्रम

256. प्राधिकारी ने पर्याप्त प्रतिफल से कम पर प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयला उपलब्ध कराने के कथित कार्यक्रम 12 की जांच की। भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक गैस अथवा कोयले का उपयोग स्थापित नहीं हुआ। बिजली के संबंध में यह पाया गया कि प्रशुल्क में अंतर वोल्टेज स्तर, उपभोग श्रेणी, उपयोग के समय और आपूर्ति शर्तों जैसे सामान्य वाणिज्यिक कारकों से उत्पन्न हुआ। कोई साक्ष्य नहीं मिला कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को समान स्थिति वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं की तुलना में अधिमान्य शर्तों पर बिजली मिली। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिकार योग्य लाभ निर्धारित नहीं किया गया।

257. कार्यक्रम 13 के अंतर्गत प्राधिकारी ने भूमि-उपयोग अधिकार, पट्टा और उप-पट्टा समझौतों, भुगतान अभिलेखों, निवेश प्रमाणपत्रों तथा संबंधित प्रांतीय साधनों की जांच की। केवल इस कारण से लाभ नहीं माना गया कि कोई उत्पादक औद्योगिक पार्क अथवा निवेश क्षेत्र में स्थित था। लाभ की मात्रा केवल वहां निर्धारित की गई, जहां सत्यापित अभिलेखों से यह स्थापित हुआ कि उत्पादक को भूमि-उपयोग अधिकार अथवा भूमि या जल-किराए में छूट अथवा कमी वियतनाम में सामान्य रूप से लागू शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर मिली।

258. कार्यक्रम 13 के अंतर्गत लाभ निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा वास्तव में भुगतान की गई किराया की तुलना रियायत के अभाव में वियतनाम में लागू सामान्य दर से की। थाईलैंड में कारखानों अथवा औद्योगिक संपत्तियों के किराया मूल्यों के प्रस्तावित उपयोग को अस्वीकार किया गया, क्योंकि स्थान, अधिकार-अवधि, विधिक ढांचे और संपत्ति की प्रकृति की दृष्टि से वे पर्याप्त रूप से तुलना योग्य नहीं थे। अतः प्रतिकार योग्य लाभ केवल उन उत्पादकों के लिए निर्धारित किया गया, जिन्हें जांच अवधि के दौरान सत्यापित भूमि-संबंधी रियायत मिली।

259. कार्यक्रम 3 के अंतर्गत कॉरपोरेट आयकर में छूट अथवा कटौती को सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व के रूप में माना गया। 20% की सामान्य वैधानिक कॉरपोरेट आयकर दर मानदंड के रूप में उपयोग की गई। लाभ उस कर के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया गया, जो सामान्य रूप से देय होता, और रियायत लेने के बाद वास्तव में देय कर के बीच था। गणना को सत्यापित अवधि और कर राहत की राशि तक सीमित रखा गया।

260. कॉरपोरेट आयकर कार्यक्रम को उन मामलों में विशिष्ट माना गया, जहां पात्रता निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा औद्योगिक जोनों में स्थित उद्यमों या पहचानी गई निवेश श्रेणियां अपनाने वाले उद्यमों तक सीमित थी। अतः प्रतिकार योग्य लाभ केवल संबंधित उत्पादक को जांच अवधि के दौरान प्राप्त सत्यापित कर राहत की सीमा तक निर्धारित किया गया।

261. कार्यक्रम 4 के अंतर्गत प्राधिकारी ने जांच की कि क्या भाग लेने वाले उत्पादकों ने कच्चे माल, मशीनरी अथवा उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क छूट का वास्तव में उपयोग किया था। वियतनामी कानून में ऐसी छूट का मात्र अस्तित्व पर्याप्त नहीं माना गया। जांच अवधि के दौरान कंपनी-विशिष्ट सत्यापित उपयोग और उससे संबंधित छोड़े गए शुल्क की राशि के अभाव में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई अलग सहायिकी मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया।

262. कार्यक्रम 5, 7, 8, 9, 10 और 11 के अंतर्गत अधिमान्य ऋण, निर्यात ऋण और ऋण गारंटी के संबंध में प्राधिकारी ने यह पूर्वधारणा नहीं बनाई कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण सहायिकी है। प्रत्येक ऋण की ऋणदाता, मुद्रा, अवधि, प्रतिभूति, ब्याज दर और अन्य उधार शर्तों के संदर्भ में जांच की गई। लाभ केवल वहां निर्धारित किया गया, जहां सत्यापित शर्तें तुलना योग्य वाणिज्यिक ऋण की उपलब्ध शर्तों से अधिक अनुकूल थीं। जहां किसी भाग लेने वाले उत्पादक ने समान मुद्रा में और समान शर्तों पर निजी वाणिज्यिक बैंक से तुलना योग्य स्वतंत्र वाणिज्यिक ऋण प्राप्त किया था, उस ऋण को मानदंड के रूप में उपयोग किया गया।

263. प्लास्टिक उद्योग के विकास की मास्टर योजना और निर्यात संवर्धन कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम 2 और 6 के अंतर्गत जांच अवधि में भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा कोई सत्यापित वित्तीय अंशदान अथवा लाभ प्राप्त किया जाना नहीं पाया गया। वास्तविक रूप से मापने योग्य लाभ प्राप्त न होने पर सरकारी नीति अथवा कार्यक्रम का मात्र अस्तित्व पर्याप्त नहीं माना गया। अतः इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई सहायिकी मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया।

V. सहयोग, क्षति, न्यूनतर शुल्क नियम और निष्कर्ष

264. यूएस मास्टरबैच और उसकी हंग येन शाखा को व्यक्तिगत उपचार दिया गया, क्योंकि उनके उत्तरों में अंततः प्रतिकार योग्य पाए गए कार्यक्रमों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध थी और उसका सत्यापन किया जा सकता था। जिन इकाइयों ने जांच अवधि की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उन पर अवशिष्ट अथवा उपलब्ध तथ्यों वाला दृष्टिकोण लागू रहा।

265. प्राधिकारी ने आयात मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, पीसीएन-वार कीमत कटौती, कीमत दबाव और कीमत ह्रास तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की जांच के बाद वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध की पुनः पुष्टि की। मांग में परिवर्तन, क्षमता वृद्धि, कच्चे माल की कीमतें, उत्पाद मिश्रण और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य कारकों की भी जांच की गई और उन्हें कारणात्मक संबंध समाप्त करने वाला नहीं पाया गया।

266. क्षतिरहित कीमत नमूने में शामिल घरेलू उत्पादकों की सत्यापित लागतों पर विहित समायोजन और युक्तिसंगत प्रतिफल जोड़ने के बाद निर्धारित की गई। निर्यातक-विशिष्ट क्षति मार्जिन पीसीएन-वार क्षतिरहित कीमत की पहुंच मूल्य से तुलना पर आधारित थे और उत्पाद मिश्रण, लेन-देन कीमतों, भाड़े तथा निर्यात मात्रा के कारण अलग हो सकते थे।

267. न्यूनतर शुल्क नियम लागू किया गया। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए अनुशंसित प्रतिकारी शुल्क सकारात्मक सहायिकी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि से अधिक नहीं हो सकता। पाटनरोधी शुल्क का अस्तित्व प्रतिकारी उपाय को नहीं रोकता, किंतु अनुशंसा में उसी निर्यात सहायिकी लाभ के दोहरे प्रतिकार से बचना आवश्यक है।

268. प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रयोक्ताओं और आयातकों के हितों पर पर्याप्त विचार किया गया। समुचित रूप से निर्धारित शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि क्षतिकारक सहायिकी के प्रभाव को निष्प्रभावी करना है। अतः अंतिम अनुशंसा संशोधित प्रकटीकरण वक्तव्य के मूल दृष्टिकोण की पुष्टि करती है, जिसमें प्रमुख परिवर्तन यह है कि कार्यक्रम 1 के अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट मानदंड मिस्र और मलेशिया से भारत में जांच अवधि के समायोजित तथा तुलना योग्य आयात मूल्यों का मात्रा-भारित औसत होगा। प्रकटीकरणोत्तर टिप्पणियां जांच समाप्त करने को उचित नहीं ठहरातीं।

ट. निष्कर्ष

269. सभी इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की जांच के पश्चात, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचता है:

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट भराव मास्टरबैच है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख घटक है अर्थात् मात्रा/सामग्री में 50 प्रतिशत से अधिक है।

ख) विषय देश से निर्यात की गई विषय वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु, प्रतिकारी शुल्क नियम, 1995 के अर्थ में एक-दूसरे की 'समान वस्तु' हैं।

ग) आवेदक घरेलू उत्पादक, प्रतिकारी शुल्क नियम, 1995 के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

घ) घरेलू उद्योग को सब्सिडीयुक्त आयात के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है। क्षति अंतर महत्वपूर्ण है।

ङ) वियतनाम सरकार विषय वस्तु के उत्पादकों को कर लाभ, ब्याज रियायत, भूमि छूट और पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में सब्सिडी प्रदान कर रही है।

270. प्रतिकारी शुल्क का आरोपण सार्वजनिक हित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

i. उपयोगकर्ता उद्योग की लागत पर शुल्कों के प्रभाव के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

ii. व्यापार उपचारात्मक उपाय देश में आयात को प्रतिबंधित नहीं करते, बल्कि आयात और घरेलू विनिर्माण के बीच समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं। एक व्यवहार्य घरेलू उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता उद्योग पूरी तरह से आयात पर निर्भर न हो।

iii. प्रतिकारी शुल्क का आरोपण केवल घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा तक ही होगा। इसलिए, शुल्कों का आरोपण कोई अतिरिक्त संरक्षण प्रदान नहीं करता, बल्कि केवल अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई करता है।

ठ. सिफारिश

271. प्राधिकरण यह नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई और सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक देश की सरकारों, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों को सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध के पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

272. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सब्सिडी, क्षति और उनके बीच कार्य-कारण संबंध के सकारात्मक साक्ष्य विद्यमान हैं, प्राधिकरण का मत है कि विषय देश से विषय वस्तु पर प्रतिकारी शुल्क आरोपित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण नीचे वर्णित स्वरूप और रीति में विषय देश से विषय वस्तु के आयात पर निश्चित प्रतिकारी शुल्क आरोपण की सिफारिश करना आवश्यक समझता है। प्राधिकरण ने विषय वस्तु से संबंधित जांच में दिनांक 27.09.2025 के अपने अंतिम निष्कर्ष फाइल संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर के माध्यम से डंपिंग-रोधी शुल्क आरोपण की सिफारिश की है।

273. न्यूनतम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए सब्सिडी अंतर और क्षति अंतर में से जो कम हो उसके बराबर या उससे कम निश्चित प्रतिकारी शुल्क आरोपण की सिफारिश करता है। प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विषय वस्तु पर पहले से ही डंपिंग-रोधी शुल्क लागू है।

274. तदनुसार, शुल्क तालिका के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित निश्चित प्रतिकारी शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए विषय देश से विषय वस्तु के सभी आयातों पर आरोपित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/उप-शीर्षक/प्रशुल्क मद	वस्तु का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	मात्रा	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3824 99 00	कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")	15.16	मीट्रिक टन	यूएस डी
2.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई")	15.16	मीट्रिक टन	यूएस डी
3.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	न्घे आन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("न्घे")	15.16	मीट्रिक टन	यूएस डी
4.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल")	15.16	मीट्रिक टन	यूएस डी
5.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई	एडीसी प्लास्टिक., जेएससी	14.20	मीट्रिक टन	यूएस डी

				भी देश				
6.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	आन तिएन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी	13.42	मीट्रिक टन	यूएस डी
7.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	विटाप्लास जॉइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास)	9.11	मीट्रिक टन	यूएस डी
8.	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल जॉइंट स्टॉक कंपनी	16.03	मीट्रिक टन	यूएस डी
9	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी	22.52	मीट्रिक टन	यूएस डी
10	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी – हुंग येन शाखा	22.52	मीट्रिक टन	यूएस डी
11	-वही-	-वही-	वियत नाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	अन्य	69.19	मीट्रिक टन	यूएस डी
12	-वही-	-वही-	कोई अन्य देश	वियतनाम	उत्पादक	69.19	मीट्रिक टन	यूएस डी

(1) सीरियल नंबर 1 से 8, और 11, 12 के लिए, क्योंकि ऊपर बताई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी और संबंधित सामान के लिए 24 दिसंबर, 2025 के कस्टम्स नोटिफिकेशन नंबर 37/2025-कस्टम्स (ADD) के तहत लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी का कुल योग उत्पादकों के संबंधित इंजरी मार्जिन से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऊपर दी गई ड्यूटी टेबल के कॉलम नंबर 7 में बताई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी वसूली जाएगी।

(2) सीरियल नंबर 9 और 10 के लिए, क्योंकि ऊपर बताई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी और संबंधित सामान के लिए 24 दिसंबर, 2025 के कस्टम्स नोटिफिकेशन नंबर 37/2025-कस्टम्स (ADD) के तहत 'रेसिडुअल कैटेगरी' (बची हुई कैटेगरी) में लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी का कुल योग उत्पादकों के संबंधित इंजरी मार्जिन से ज़्यादा है, इसलिए ऊपर दी गई ड्यूटी टेबल के कॉलम नंबर 7 में बताई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी।

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेची गई (विषय वस्तु) की (मात्रा) का निर्माण (देश का नाम) में

(उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क प्रभावी होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।"

ड. आगे की प्रक्रिया

275. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध अपील अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th June, 2026

Case No. – CVD(OI) – 03/2024

Subject: Countervailing duty investigation concerning imports of "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" originating in or exported from Vietnam.

F. No. 6/39/2024 - DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "CVD Rules" or "the Rules");

1. Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as "CMMAI") and Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter referred to as "MMA") (hereinafter collectively referred to as the "petitioners" or "applicants") on behalf of the domestic producers in India filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Act and the CVD Rules for initiation of a countervailing duty investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or "PUC") originating in or exported from Vietnam (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. The domestic industry in the present case is fragmented and consists of a large number of domestic producers located across India, hence the application for countervailing duty investigation was filed by two associations, namely CMMAI and MMA on behalf of their member entities**.** All the relevant information in the prescribed format as required under Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 as amended vide Trade Notice No. 11/2021 dated 18th November 2021 (collectively, "Trade Notice 9/2021") was provided.

3. The following twelve (12) applicant domestic producers (hereinafter referred to as the

"applicants") of subject goods filed the required information as per Annexure-I to Trade Notice 9/2021 for fragmented industries:

i. Kandui Industries Private Limited
ii. Sonali Polyplast Private Limited
iii. Blend Colors Private Limited
iv. Bajaj Masterbatches Private Limited
v. Bajaj Superpack India Limited
vi. Bajaj Plast Private Limited
vii. Bajaj Polyblends Private Limited
viii. Siddh Chemiplast Private Limited
ix. Shri Ambica Polyfill
x. Soltex Petro Products Limited
xi. Alok Industries
xii. Alok Masterbatches Private Limited

4. Further, the following twenty-one (21) domestic producers supported the application and provided the required data in the prescribed format:

i. Sonali Polymers Pvt. Ltd.
ii. Masterplast India Pvt. Ltd.
iii. Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.
iv. S.P. Polymer
v. 365 Plastium Pvt. Ltd.
vi. N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.
vii. Satya Polyalloys LLP
viii. Adex Ployblend Pvt. Ltd.
ix. Rama Vyapaar Pvt. Ltd.
x. Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.
xi. Swastik Plastoalloys
xii. Manan Polymers Pvt. Ltd.
xiii. Aditya Polyspin Pvt. Ltd.
xiv. J K Paras Ploycoats Ltd.
xv. Speciality Masterbatches LLP
xvi. Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.
xvii. Everplus Plastics Pvt. Ltd.
xviii. Manhar Polymers Pvt. Ltd.
xix. Dolphin Polyfill
xx. JJ Plastalloy
xxi. Prabhu Polycolor

5. In view of the duly substantiated application filed by the petitioners, the Authority issued a public notice *vide* Notification F. No. 6/39/2024-DGTR, dated 27th December 2024, published in the Gazette of India, initiating countervailing duty investigation into imports of the product under consideration from the subject country in accordance with Rule 6 of the CVD Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidization of the subject goods and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the present

investigation:

i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present countervailing duty application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 6 of the CVD Rules.

ii. The Authority invited the Government of Vietnam for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The consultations were held on 03.12.2024 with the Government of Vietnam, through video conferencing. The consultations were attended by the representatives of the Government of Vietnam.

iii. The Authority issued a public notice dated 27th December 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating countervailing duty investigation concerning imports of subject goods from the subject country.

iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users as well as other interested parties, as per the addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

v. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassy in India, in accordance with Rule 7(3) of the CVD Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested. Further, the non-confidential version of the application was also uploaded on the website of the Authority.

vi. The embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

vii. The Authority sent the exporters' questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject country in accordance with Rule 7(4) of the CVD Rules.

S. NO.	**PRODUCER/EXPORTER**
1.	PMJ JOINT STOCK COMPANY
2.	CPI VIET NAM PLASTIC LIMITED
3.	UB MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY
4.	MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
5.	ADC PLASTIC JSC
6.	HP CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
7.	POLYFILL JOINT STOCK COMPANY
8.	PHU LAM TRADE COMPANY LIMITED
9.	EUROPEAN PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
10.	SUN PLASTIKS COMPANY LIMITED
11.	HUU NGHI PLASTIC COMPOUNDSJSC
12.	THANH XUAN STONE MINERALS JSC
13.	FIVE CONTINENTS PLASTICS JSC
14.	VSV GROUP CORPORATION
15.	VINARES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
16.	FILLPLAS COMPANY LIMITED
17.	BAO LAI MARBLE ONE MERMER CO LTD

18.	PLASTEX JOINT STOCK COMPANY
19.	MASKA GLOBAL COMPANY LIMITED
20.	VINA PLASTIC COMPANY LIMITED
21.	SUNSHINE PLASTIC COMPANY LIMITED
22.	CAPOT VIETNAM COMPANY LIMITED
23.	PHA LE PLASTIC MANUFACTURING AND TECHNOLOGY
24.	VIET TRUNG PLASTIC CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY
25.	PLASTIC HA NOI TRADING JOINT STOCK
26.	FILTER MASTER BATCH JOINT STOCK COMPANY
27.	BEENPLAST COMPANY LIMITED
28.	VIETNAM COLOR TRADING AND MANUFACTURING BEEN A AND T COMPANY LIMITED
29.	GLOBAL MINERALS JSC
30.	ANBIO JOINT STOCK COMPANY
31.	TLD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
32.	AN THANH BICSOL JOINT STOCK COMPANY
33.	MINH KHANG CHEMICAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
34.	US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY
35.	HOANG GIA MINERAL GROUP JSC
36.	DAI A INDUSTRAY JOINT STOCK COMPANY
37.	VIETNAM HANOTECH JOINT STOCK C
38.	AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
39.	VITAPLUS JOINT STOCK COMPANY
40.	RAINFOREST EXPORT GOODS WHOLESALERS L L C
41.	ASIA PLASTICS INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
42.	VIETNAM INDUSTRIAL MINERAL INTERNATIONAL
43.	US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY-HUNG YEN US MASTERBATCH JSC
44.	CONG TY TNHH MINH HIEN LS DAPLAST JOINT STOCK COMPANY
45.	GCC MINERALS JOINT STOCK COMPANY
46.	NO MMA PLASTIC COMPANY LIMITED
47.	DUC PHONG MATERIALS CO LTD
48.	FILLER MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY
49.	POLY PLOY JSC SONG MINH IMPORT EXPORT COMPANY

viii. In response to the initiation notification, the following producers/exporters from the subject country registered themselves as interested parties in the investigation:

S. NO.	**PRODUCER/EXPORTER**
1.	NGHE AN EUROPEAN PLASTIC ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
2.	YEN BAI EUROPEAN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
3.	EUROPEAN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
4.	POLYFILL JOINT STOCK COMPANY
5.	AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
6.	A DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
7.	VITAPLAS JOINT STOCK COMPANY
8.	VIETNAM INDUSTRIAL MINERALS INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
9.	GCC MINERALS JSC
10.	VIET TRUNG PLASTIC CHEMICAL JSC

11.	US MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY
12.	FILLER MASTERBATCH JOINT STOCK COMPANY
13.	MEGAPLAST JOINT STOCK COMPANY

ix. Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject country, the Government of Vietnam also filed the relevant information through the Trade Remedies Authority of Vietnam.

x. The Authority sent Importer's / User's Questionnaire to the following known importers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the CVD Rules.

S. NO.	NAME OF IMPORTER	S. NO.	NAME OF IMPORTER
1	ASIAN TRADELINKS PRIVATE LIMITED	136	SHRI DAKSHINESHWARI MAA POLYFABS LIMITED
2	DVM PROTECH	137	SRIJA POLYMERS
3	PARIKH PACKAGING PRIVATE LIMITED	138	MVS ACMEI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	PREMIER POLYMERS	139	SDR POLYMERS PRIVATE LIMITED
5	SPINPACK INDUSTRIES CO	140	RATHI ENTERPRISES
6	NEELAMEGAM GANAPATHI RAM	141	SHIVAM AGRI PIPES
7	PADMA POLYMERS	142	BINA PLASTICS
8	EUPHORIA PACKAGING LLP	143	BOHRA SALES SERVICES LIMITED
9	RAWPLAST IMPEX	144	SUPER PACKWELL PRIVATE LIMITED
10	JUMBO BAG LIMITED	145	JUPAX VANIJYA PRIVATE LIMITED
11	GSV POLYMERS PVT LTD	146	RUCHAK CHEMICALS
12	DOLLAR SENSE	147	MEGAPLAST INDIA PRIVATE LIMITED
13	SOUTHERN BIO-TECH POLY INDUSTRY	148	SRI SHYAM ADDITIVES PRIVATE LIMITED
14	MITHILA PLYWOOD PRIVATE LIMITED	149	MOHAN KUMAR AGARWAL
15	INDO CHEMICALS PVT LTD	150	POLYSPIN EXPORTS LIMITED
16	PARASHNATH POLYPACK PVT LTD	151	GOVIND AGARWAL HUF
17	PRAGATI POLYPLAST INDIA PRIVATE LIMITED	152	RUSHABH PLASTIC
18	NIRMAL PLASTIC INDUSTRIES	153	NATIONAL PLASTO CONTAINERS PRIVATE LIMITED
19	GOTHI IMPEX	154	RAJESH COLOUR COMPANY
20	PRIME AGENCIES	155	BHAGYASHREE COLOURS PVT LTD
21	VIRGO POLYMERS I LTD	156	SUN ENTERPRISE
22	A M TRADERS	157	ORACLE POLYPLAST
23	ATULYA FABRICS LLP	158	KAVERI GLOBAL
24	PUJA SALES	159	N K IMPORTS
25	TOPSACK PACKAGING PRIVATE LIMITED	160	PARK SHELDRAKE
26	RAJSHREE POLYPACK LIMITED	161	PYARE LAL FOAMS PVT LTD
27	VISHWAA PACKWEL PRIVATE	162	SRIVARI INDUSTRIES

S. NO.	NAME OF IMPORTER	S. NO.	NAME OF IMPORTER
	LIMITED		
28	SRI LAKOSHA POLYMER PRIVATE LIMITED	163	INDAUTO FILTERS
29	RGK POLYCHEM INDIA PRIVATE LIMITED	164	AJAY LOGISTICS PVT LTD
30	SHREE ADITYA POLYMERS	165	KAVERI IMPEX
31	SHIV INTERNATIONAL LTD	166	NAGINDAS HIRALAL BHAYANI
32	AERO PLAST LTD	167	JAKHOTIA POLYCHEM PVT LTD
33	J VASANTH EXPORTS	168	VGR FOODTECH AGRO PRIVATE LIMITED
34	SERVO PACKAGING LTD	169	MARUTI ENTERPRISE
35	GAGAN POLYMERS	170	EVEREST POLYFILLERS PRIVATE LIMITED
36	TEXBOND NONWOVENS	171	ALPINE FIBC PRIVATE LIMITED
37	PIYUSH POLYTEX INDUSTRIES PVT LTD	172	VAIBHAV MINERALS CHEMICALS
38	DELTA IRRIGATION INDIA LLP	173	MAHASHAKTI POLYCOAT
39	BULK LIQUID SOLUTIONS PVT LTD	174	SHREE KRISHNA SALES AGENCY
40	NIRMAL FIBRES PRIVATE LIMITED	175	NAV - DIV INDUSTRIES
41	TIRUMALAI AGENCY	176	PLASTENE INDIA LIMITED
42	ALLWIN PIPES	177	RANASARIA POLY PACK PVT LTD
43	BROCADE INDIA POLYTEX LIMITED	178	KONKAN SPECIALITY POLYPRODUCTS PRIVATE LIMITED
44	H AND H POLYMERS	179	THANIGAI INTERNATIONAL
45	AARCH NONWOVEN	180	ALPS POLYTEX
46	GIRIVARYA NON WOVEN FABRICS PVT LTD	181	SINGLA PLASTIC UDYOG
47	VIRAT IMPEX	182	ZEEL PACKAGING
48	SAI KANDAN AGENCY	183	OMYA INDIA PRIVATE LIMITED
49	PRATAP SYNTHETICS LIMITED	184	PRAGATI PAPER ENTERPRISES
50	KRISHNA LAMICOAT PRIVATE LIMITED	185	SHREEJI POLYMIX INDUSTRIES
51	ULTRA NONWOVEN	186	VIBGYOR POLYADDITIVES PVT LTD
52	A-ONE TEX TECH PRIVATE LIMITED	187	KIK PLASTICS PRIVATE LIMITED
53	RAJSHREE FABRICS	188	ORIANA GLOBAL TRADE LLP
54	MATRIX IMPEX	189	NEOTEX POLYMER PACKAGING PRIVATE LIMITED
55	PRIMO INDUSTRIES	190	K K POLYCOLOR ASIA LIMITED
56	SHRI MAA POLYFABS LIMITED	191	MADHU PLASTICS PRIVATE LIMITED
57	PRAKRIT IMPEX PRIVATE LIMITED	192	BALAJI POLY UDYOG
58	BIG BAGS INTERNATIONAL PVT LTD	193	CRESCENT ORGANICS PVT LTD
59	PEEKAY AGENCIES PVT LTD	194	SARAF FABTRADE PRIVATE

S. NO.	NAME OF IMPORTER	S. NO.	NAME OF IMPORTER
			LIMITED
60	PROTON POLYMER	195	FORMOSA SYNTHETICS PVT LTD
61	A P POLYPLAST PVT LTD	196	BANGLORE POLYCOTTERS PRIVATE LIMITED
62	SIGNODE INDIA LIMITED	197	MEHUL COLOURS MASTERBATCHES PVT LTD
63	AGARWAL TECHNOPLAST PVT LTD	198	KASHYAP UNITEX CORPORATION
64	NAAD NONWOVEN PRIVATE LIMITED	199	SURAJ LOGISTIX PRIVATE LIMITED
65	BHOOMI PLASTIC	200	SURAJ JAISWAL
66	ELECTRO POLYCHEM LIMITED	201	H J INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED
67	MILI EXPORTS	202	K C SONS
68	SURYA LAXMI INDUSTRIES	203	MASTER EXTRUSIONS
69	VARNA BAGS	204	PINNACLE POLYMERS
70	CAPSTONE POLYWEAVE PRIVATE LIMITED	205	JHUNSONS CHEMICALS
71	JEMINI IMPEX SOLUTIONS	206	SEYYON HI-TECH POLY FABS PRIVATE LIMITED
72	SUVARNA EXPORTERS	207	ABIS EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
73	HARIOM POLYPACKS LIMITED	208	SAI INDUSTRIES PVT LTD
74	DNS POLYFAB PVT LTD	209	AYUSHMAN MERCHANT PRIVATE LIMITED
75	LINGAM POLYMERS	210	TRIMURTI POLYCHEM PRIVATE LIMITED
76	GIRDHAR ROLL WRAP PVT LTD	211	ADISHA MOULDS
77	RAJGURU INDUSTRIES	212	OSWAL INDUSTRIES
78	SKP ENTERPRISES	213	SIDWIN FABRIC PRIVATE LIMITED
79	COVAI POLYMER TRADERS	214	DARSHAN PLASTIC
80	PREET FLEX	215	GLOBECHEM IMPORTS
81	AMCO ENTERPRISES	216	SUVJAY INDUSTRIES INDIA LLP
82	BLOW PACKAGING I PVT LTD	217	STANDARD PACKAGING
83	AVI ADDITIVES PRIVATE LIMITED	218	ESQUIRE MULTIPLAST PRIVATE LIMITED
84	D B POLYMERS	219	BHIM POLYFAB INDUSTRIES
85	POLSTAR	220	BHUYAN ASSOCIATES PVT LTD
86	SKILL DYE CHEM P LTD	221	ANJANI INTERWEAVE
87	VIDVAR COMPANY	222	FASTRAX POLYPLAST PRIVATE LIMITED
88	MANSAROVAR AGRO SACKS PVT LTD	223	SHYAM CHEMICAL AND MINERALS
89	VARDHAMAN POLYPACKS	224	MERIT POLYMERS
90	SAMRUDDHI INDUSTRIES LTD	225	ISHOM PACKAGING PRIVATE LIMITED
91	SUNIL FIBRES PVT LTD	226	MANIKA MOULDS PVT LTD
92	R L COMMERCIAL PRIVATE	227	CHURIWAL TECHNOPACK PVT LTD

S. NO.	NAME OF IMPORTER	S. NO.	NAME OF IMPORTER
	LIMETED		
93	FLEXIBLE BAGS	228	SUPRABHA PROTECTIVE PRODUCTS PVT LTD
94	TOTAL PACKAGING SERVICES	229	KNK OVERSEAS
95	MARIS ASSOCIATES PVT LTD	230	POLYSQUARE LLP
96	SERVO PLASTICS PVT LTD	231	MICO PLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
97	MITTAL TECHNOPACK PVT LTD	232	VIJAY POLYMERS
98	NEXXA COMPOUNDS PRIVATE LIMITED	233	TIRUPATHI HYDROCARBON PRIVATE LIMITED
99	BUILDMET FIBRES PRIVATE LIMITED	234	MALLINATH TEXTILE MILLS
100	POLIVEX OVERSEAS	235	DAMAN POLYFABS
101	SAI SURFACTANTS PVT LTD	236	TIBRIWAL PLASTICS PVT LTD
102	BHAGIRATHI PACKAGING PVT LTD	237	BARODA PACKAGING
103	SIMANDHAR IMPEX	238	PRIYADARSHINI POLYSACKS LTD
104	RACHANA POLYMERS PRIVATE LIMITED	239	VISHAL SYNTHETICS
105	BULKPACK EXPORTS LIMITED	240	PATCO POLYPACK PRIVATE LIMITED
106	DURA PLASTSOLUTIONS LLP	241	RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD
107	FINE TECH INDUSTRIES	242	MICO POLY PACK
108	SYNTHETIC PACKERS PVT LTD	243	SUN MASTERBATCH PVT LTD
109	COLORPLAS POLYADDITIVES LLP	244	BHAVANI PLASTICS
110	GAUTAM SINGHAL	245	K B UDYOG
111	PLASMIX PVT LTD	246	SUN TEX MILLS
112	M D P TRADEING	247	AASTHA PLASTICON
113	HOOGHLY EXTRUSIONS LIMITED	248	ANANYA IMPEX
114	DEEPEE CHEM INDUSTRIES	249	AL-SA AD ENTERPRISES
115	PEKON ELECTRONICS LIMITED	250	VIJAYNEHA POLYMERS PVT LIMITED
116	GIRIRAJ POLYPACK	251	NAVKAR PACKAGING
117	SARAF FINCOM PRIVATE LIMITED	252	KANDOI FABRICS PRIVATE LIMITED
118	KT PYROCHEM	253	SHANKAR PACKAGINGS LIMITED
119	RDB RASAYANS LIMITED	254	SNG MICRONS PRIVATE LIMITED
120	DHWANI POLYPRINTS PVT LTD	255	SHREE SALASAR TRADING COMPANY
121	MANHAR POLYMERS PRIVATE LIMITED	256	VIBRANT POLYMERS LLP
122	CHANDRA POLYMER PRIVATE LIMITED	257	SEALION WORLD TRADE PVT LTD
123	SAVITRIDEVI POLYFABRICS INDIA PVT LTD	258	SRI RAM POLYMERS
124	POLYZEN TRADING CO	259	AMIT OIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED

S. NO.	NAME OF IMPORTER	S. NO.	NAME OF IMPORTER
125	NS FABRICS	260	S G POLYMERS
126	KULODAY PLASTOMERS PVT LTD	261	V M POLYTEX LIMITED
127	PEARL POLYFILM MANUFACTURERS	262	CONSOLIDATED SHIPPING LINE INDIA PVT LTD
128	PARIVARTAN MERCANTILES PRIVATE LIMITED	263	CREATIVE POLY PACKS P LTD
129	AMORA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	264	VEN PACK
130	PARADISE ENTERPRISES	265	VR FIBC JAMBO BAG INDUSTRIES
131	BARODA RAPIDS	266	SAKTHI POLY CHEM
132	SHREE ANGIRA ENTERPRISES	267	DEEP POLYMERS LIMITED
133	PIONEER ENTERPRISES I PVT LTD	268	MEHRASONS COATINGS PVT LTD
134	VIVA PETROCHEMICAL LLP	269	LINCON POLYMERS PVT LTD
135	RAJENDRA CHEMICALS	270	BAJAJ POLYBLENDS PRIVATE LIMITED
		271	PADMAJA POLY PACKS PRIVATE LIMITED

xi. In response to the initiation notification**,** the following importers/users registered themselves as interested parties:

S. NO.	IMPORTER/USER
1	RISHABH COLOURS PVT. LTD.

xii. A copy of the initiation notification and a non-confidential version of the application were sent to the known associations.

xiii. In response to the initiation notification, none of the known associations have registered themselves as interested parties.

xiv. Exporters, foreign producers and other interested parties who have failed to respond to, or supply, relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating.

xv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicant. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry.

xvi. The period of investigation ("period of investigation" or "POI") for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury period covers the period of investigation and the three preceding financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23.

xvii. The Directorate General of Systems (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period. The said data were received by the Authority and considered for the subject investigation. For the purpose of the present final findings, the Authority has relied upon the DG Systems import data.

xviii. The Authority decided the PCN Methodology in the recently concluded anti-dumping investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam bearing file number F. No. 06/38/2024 – DGTR in Case No. AD(OI)-36/2024 through notification dated 4th December 2024. Since the scope of the product under consideration

in the anti-dumping investigation and present CVD investigation is the same, the Authority considered it appropriate to adopt the same PCN methodology in the present CVD investigation as that decided in the anti-dumping investigation Case No. AD (OI)-36/2024.

xix. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all interested parties to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

xx. In accordance with Paragraph 7 of the Trade Notice No. 09/2021, the Authority limited the detailed examination of applicant domestic producers for determining injury margin. Using statistically valid techniques, the Authority selected the following entities as part of the sample:

a. Soltex Petro Products Ltd.
b. Alok Masterbatches Pvt. Ltd.
c. Alok Industries
d. Kandui Industries Pvt. Ltd.

xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.

xxii. The Authority sought further information to the extent deemed necessary. The on-site verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.

xxiii. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

xxiv. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the actual data/information furnished by the domestic industry. The NIP, based on the optimum cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India, has been worked out on the basis of the information furnished by the domestic industry and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the CVD Rules, so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xxv. In accordance with Rule 7(6) of the CVD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th December 2025. The parties that presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the submissions submitted by them with the other interested parties.

xxvi. The disclosure statement was issued on 20.03.2026. Subsequently, in the post disclosure comments, the interested parties raised issues on several aspects of the investigation including countervailability of the schemes, benchmarks considered for different schemes, specificity, injury, causal link, rejection of the questionnaire response etc. The Authority has examined these submissions and considered it appropriate to incorporate them in the disclosure of all relevant facts pertaining to this investigation. Therefore, in supersession of the disclosure statement issued earlier on 20.03.2026, the Authority issued a revised/additional disclosure statement dated 16.06.2026, in the larger public interest in accordance with Rule 18 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended, disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to this investigation. Thereafter, the post disclosure comments, to the disclosure statement dated 16.06.2026, submitted by the domestic industry and other interested parties have been incorporated in these final findings.

xxvii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been treated as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

xxviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxix. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent that they are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

xxx. "***" in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs 83.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

"3. The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound" wherein calcium carbonate (CaCO3) is the major constituent, i.e., more than 50% by volume."

4. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a mix of calcium carbonate (a mineral), base plastic materials like polypropylene or polyethylene, and other additives. The said mixture is extruded at a certain temperature to produce the Calcium Carbonate Filler Masterbatch in compound granules form. The PUC majorly constitutes calcium carbonate, with the rest being plastics and other additives.

5. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a special material used in the plastic industry for enhancement of properties of plastic items. Its primary function is to act as a cost-effective and eco-friendly filler imparting specific physical and chemical properties.

6. Many industries use Calcium Carbonate Filler Masterbatch, such as packaging, construction, automotive and consumer goods. When added to plastics, Calcium Carbonate Filler Masterbatch can make them stronger, less likely to break, better at keeping their shape, and less likely to shrink.

7. Calcium Carbonate Filler Masterbatch can also change how plastic feels on the surface, how it handles heat, and how easy it is to work with. It is often used to make plastic films, sheets, pipes, shaped items, and other plastic goods.

8. The product under consideration is classifiable under tariff item 3824 99 00 of the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Major imports are cleared under tariff item 3824 99 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

9. The applicants have proposed that the Product Control Numbers (PCNs) for the present investigation may be considered as already adopted in the ongoing anti-dumping investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam bearing file number F. No. 06/38/2024 – DGTR in Case No. AD(OI)-36/2024. The Authority has decided on the PCN Methodology in the above-mentioned anti-dumping investigation vide notification dated 4th December 2024. Since the scope

of the product under consideration in the anti-dumping investigation and present investigation is same, the Authority considers it appropriate to adopt the same PCN methodology in the present investigation, i.e., on the basis of calcium carbonate content with the following three categories:

Criteria	***PCN Code***
Less than 75% CaCO3	*A*
75-85% CaCO3	*B*
More than 85% CaCO3	*C*

C.1. <u>Submissions by other interested parties</u>

8. The other interested parties have not made any submissions or comments concerning the scope of the product under consideration or the PCN methodology in the present countervailing duty investigation.

C.2. <u>Submissions made by the domestic industry</u>

9. The domestic industry has made the following submissions regarding the product under consideration and the PCN Methodology:

i. The domestic industry submitted that the scope of the product under consideration (PUC) and the PCN methodology in the present investigation should remain identical to that finalized by the Authority in the recently concluded anti-dumping investigation concerning imports of the same product from Vietnam. The anti-dumping investigation involved the same product description and the same subject country. The determinations made therein are directly relevant to the present investigation.

ii. The domestic industry submitted that the issue of scope of the PUC and the PCN methodology has already attained finality in the anti-dumping investigation after detailed examination by the Authority.

iii. In the anti-dumping investigation, the Authority examined extensive submissions from all interested parties, including exporters, importers, users and the domestic industry. Multiple rounds of written submissions were filed and a dedicated meeting on PUC and PCN was held before the Authority reached its determination.

iv. The domestic industry submitted that the present countervailing duty investigation should not be used to re-open or re-litigate issues relating to the scope of the PUC and the PCN methodology which have already been examined and settled after full participation of all interested parties in a prior investigation.

v. With respect to the PCN methodology, the domestic industry submitted that the Authority, in the anti-dumping investigation, had examined and rejected proposals for PCN classification based on base polymer type, end-use application and production technology.

vi. The Authority accepted PCN classification based solely on calcium carbonate content, as this parameter reflects cost and price differences in the market. This conclusion was reached after examination of cost data and submissions placed on record by all interested parties.

vii. In view of the above, the domestic industry requested that the scope of the PUC and the PCN methodology, as finalized by the Authority in the anti-dumping investigation, be adopted without modification in the present countervailing duty investigation.

C.3 Examination by the Authority

10. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the PUC and PCN methodology have been examined as under:

11. The Authority notes that the scope of the PUC and the PCN methodology were examined in detail and finalized in the anti-dumping investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam bearing file number F. No. 06/38/2024 – DGTR in Case No. AD(OI)-36/2024 through notification dated 4th December 2024.

12. The Authority further notes that the said anti-dumping investigation (Case No. AD(OI)-36/2024) involved the same product description from the same subject country. The determination on scope of PUC and PCN in that investigation is therefore directly relevant and applicable to the present investigation. The Authority also notes that no comments have been made by other interested parties seeking any modification to the scope of PUC or the PCN methodology.

13. In view of the above, the Authority retains the same scope of the PUC and the same PCN methodology as adopted in the anti-dumping investigation for the purpose of the present countervailing duty investigation. The scope of the PUC is determined as follows:

"The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound" wherein calcium carbonate (CaCO3) is the major constituent, i.e., more than 50% by volume."

14. The product under consideration is classifiable under tariff item 3824 99 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Major imports are cleared under tariff item 382499 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

15. Further, the Authority holds that it is appropriate to retain the same PCNs in the present investigation as that decided *vide* Notification dated 04th December 2024 in the anti-dumping investigation (Case No. AD(OI)-36/2024), which was based on calcium carbonate content with the following three categories:

Criteria	**PCN**
Less than 75% $CaCO_3$	A
75-85% $CaCO_3$	B
More than 85% $CaCO_3$	C

D. DOMESTIC INDUSTRY STANDING & SAMPLING PROCESS

D.1 Submissions made by other interested parties:

16. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The initiation of the countervailing duty investigation is based on insufficient grounds, as the petition does not disclose producer-wise production volumes of the

domestic producers. In the absence of such information, interested parties are unable to verify whether the applicant producers satisfy the statutory standing requirements under the Customs Tariff Act, 1975.

ii. Where multiple domestic manufacturers exist, the domestic industry is required to establish its standing with reliable and verifiable evidence. The petition does not provide individual production data of each producer, thereby preventing verification of whether the applicant producers constitute a major share of total domestic production of the subject goods in India.

iii. The definition of "domestic industry" under the Customs Tariff Act, 1975 requires that producers collectively account for a major proportion of total domestic production of the like article. The petition provides no evidence to demonstrate that this requirement is satisfied.

iv. While the petition includes support letters from certain producers, it does not establish whether the applicant producers and supporting producers together constitute a major proportion of total domestic production. Claims of excessive confidentiality were stated to have been used to withhold essential information.

v. The information provided by the twenty-one supporting producers is seriously deficient. The supporting producers have filed only brief, single-page statements without meaningful data on production, capacity, sales, or financial performance.

vi. The non-confidential versions of the supporting producers' submissions are almost entirely redacted, with no indexed, summarized, or trend-based data. As a result, interested parties cannot assess production volumes, sales trends, cost structures, or profitability of the supporting producers.

vii. This is inconsistent with Trade Notice No. 05/2021, which requires supporting producers to provide installed capacity with evidence, production quantity, and sales volume and value of the subject goods, separately for domestic sales, exports, and captive consumption.

viii. The complete absence of indexed or summarized non-confidential data also violates Trade Notice No. 14/2018, which mandates that confidentiality claims must be accompanied by meaningful non-confidential summaries sufficient to permit reasonable understanding of the information submitted.

ix. In the absence of compliant and verifiable data from the twenty-one supporting producers, their support cannot be relied upon for determining domestic industry standing. This defeats principles of transparency and natural justice.

x. The Authority has not independently verified domestic industry standing by seeking information from non-participating domestic producers or relevant line ministries, as has been the consistent practice of the Authority in past investigations.

xi. Reference was made to past investigations where such independent verification was undertaken. The absence of a similar exercise creates a risk of distorted data being relied upon.

xii. Reliance was also placed on WTO jurisprudence to submit that the Authority is under an obligation to ensure that the definition of domestic industry does not introduce a material risk of skewing economic data and distorting injury analysis.

xiii. Given the existence of a large number of domestic producers in both organised and unorganised sectors, the "major proportion" test is not a purely mathematical exercise and must reflect both quantitative and qualitative aspects.

xiv. Even if the applicants are assumed to meet the major proportion test, the Authority cannot ignore the situation of other domestic producers unless they are legally ineligible to be considered as part of the domestic industry.

xv. Injury analysis must objectively examine the industry as a whole and cannot be limited to only certain parts of the industry.

xvi. With respect to sampling, the other interested parties submitted that they are unable to comment on the appropriateness of the sampling methodology due to the non-disclosure of producer-wise data for the applicant companies for the POI, as required under Trade Notice No. 09/2021.

xvii. It was submitted that, despite sampling having been undertaken and four domestic producers having been selected as sampled companies, the domestic industry has failed to provide non-confidential versions of the mandatory injury formats (Formats VI-1 to VI-5).

xviii. The circulation of only a consolidated non-confidential NIP does not satisfy the requirements of Trade Notice No. 09/2021, as the obligation extends to disclosure of the injury formats themselves.

xix. Without access to the non-confidential injury formats, interested parties cannot meaningfully examine or verify key elements such as cost of production, raw material consumption norms, working capital, capacity utilisation, plant-wise optimum production, and adjustments applied.

xx. Reliance on alleged past practice or the absence of a requirement for a separate sampling notification cannot override the mandatory disclosure obligations prescribed under Trade Notice No. 09/2021.

xxi. The Authority has not disclosed the percentage of total domestic production represented by the sampled producers, which is necessary to assess whether the sample is representative.

xxii. The cumulative effect of non-disclosure of injury formats and non-disclosure of the production share of the sample causes serious prejudice to their rights of defense and violates principles of natural justice.

xxiii. The Authority was requested to disregard deficient supporter data for the purpose of determining standing, direct the domestic industry to file meaningful non-confidential versions of Formats VI-1 to VI-5 for the sampled producers, disclose the production share represented by the sample, and independently examine and pass a reasoned order on domestic industry standing and the sampling methodology.

xxiv. The Petitioners have failed to discharge their burden of establishing standing through verifiable evidence, the present application does not meet the requirements of Rule 6(3) of the CVD Rules and Article 11.4 of the SCM Agreement, and ought not to be permitted to proceed.

D.2 <u>Submissions made by the domestic industry</u>

17. The submissions of the petitioner with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

i. The domestic industry submitted that standing for initiation of a countervailing duty investigation is governed by Article 11.4 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) and the corresponding threshold test under Rule 6 of the CVD Rules.

ii. The domestic industry submitted that the standing test has two conditions: first, domestic producers whose collective output represents more than 25% of the total production of the like product in India; and second, where support and opposition exist, the supporting producers must represent more than 50% of the total production of those producers expressing either support or opposition.

iii. The application for initiation of countervailing duty investigation was filed by two associations namely, CMMAI and MMA on behalf of their members who are domestic producers of PUC in India.

iv. Based on the information available with the CMMAI and MMA, their member companies/entities constitute more than 90% of the total Indian production of PUC in India. CMMAI and MMA are the only two associations representing domestic producers of the PUC in India.

v. The petitioner has provided the list of members of CMMAI and MMA along with their production volumes of the PUC for the injury period including the POI. Additionally, it also provides the status of each such producer (i.e., whether supporter, opposer or neutral). The petitioner has also provided consolidated details of Statement of Indian Production including the estimated production of unknown non-member companies/entities of CMMAI and MMA in the country.

vi. Following twelve applicant domestic producers filed the required information in Annexure-I to Trade Notice 9/2021 comprising more than 35% of the total domestic production of PUC in India during the POI.

S. No.	**Particulars**	**Share in Total Indian Production**
1.	Soltex Petro Products Ltd.	***%
2.	Alok Masterbatches Pvt. Ltd.	***%
3.	Kandui Industries Pvt. Ltd.	***%
4.	Sonali Polyplast Private Limited	***%
5.	Bajaj Polyblends Pvt. Ltd.	***%
6.	Bajaj Plast Pvt. Ltd.	***%
7.	Alok Industries	***%
8.	Bajaj Masterbatches Private Limited	***%
9.	Siddh Chemiplast Pvt. Ltd.	***%
10.	Bajaj Superpack India Ltd.	***%
11.	Blend Colors Private Limited	***%
12.	Shri Ambica Polyfill	***%

vii. Additionally, following twenty-one entities expressly supported the application.

S. No.	**Particulars**	**Share in Total Indian Production**
1.	Sonali Polymers Pvt. Ltd.	***%
2.	Masterplast India Pvt. Ltd.	***%
3.	Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.	***%
4.	S.P. Polymer	***%
5.	365 Plastium Pvt. Ltd.	***%
6.	N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.	***%
7.	Satya Polyalloys LLP	***%
8.	Adex Ployblend Pvt. Ltd.	***%
9.	Rama Vyapaar Pvt. Ltd.	***%
10.	Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.	***%

11.	Swastik Plastoalloys	***%
12.	Manan Polymers Pvt. Ltd.	***%
13.	Aditya Polyspin Pvt. Ltd.	***%
14.	J K Paras Ploycoats Ltd.	***%
15.	Speciality Masterbatches LLP	***%
16.	Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.	***%
17.	Everplus Plastics Pvt. Ltd.	***%
18.	Manhar Polymers Pvt. Ltd.	***%
19.	Dolphin Polyfill	***%
20.	JJ Plastalloy	***%
21.	Prabhu Polycolor	***%

viii. The domestic industry submitted that twelve (12) applicant domestic producers filed the required information in Annexure-I to Trade Notice No. 09/2021 and that these twelve applicants constitute more than 35% of the total domestic production of PUC in India during the POI. The domestic industry submitted that twenty-one (21) entities expressly supported the application and provided the required data in the supporters' format.

ix. The domestic industry submitted that the twelve applicant producers constitute more than 35% of total domestic production, while the applicant producers together with the twenty-one supporting producers constitute more than 55%; accordingly, the statutory standing requirement is satisfied. The domestic industry further submitted that no member company/entity of CMMAI and MMA, and no other domestic producer of PUC, has opposed the petition; hence, the 50% test under the explanation to Rule 6(3) is also satisfied.

x. The term "domestic industry" under Rule 2(b) of the CVD Rules includes either all domestic producers of the like article, or those whose collective output constitutes a "major proportion" of total domestic production. It submitted that the applicants and supporters collectively account for a major proportion of total domestic production and therefore satisfy Rule 2(b).

xi. The domestic industry submitted that a statement depicting the share of production of the applicants, supporters, and other Indian producers in total Indian production has been submitted. Further, the domestic industry submitted the following production and share figures for the POI:

Particulars	**% share in total Indian production**	**Production in POI (A)**
Twelve applicant domestic producers	35	2,50,893 MT
Twenty-one supporting domestic producers	20	1,43,525 MT
Other Indian Producers	45	3,21,306 MT
Total	100	7,15,724 MT

xii. The determination on standing in the present CVD investigation should be the same as the determination already made by the Authority in the recently concluded anti-dumping investigation concerning imports of the same product from the same country.

xiii. Standing was examined and decided after consideration of submissions by exporters, importers, users and the domestic industry in the anti-dumping investigation. In the Final Findings F. No. 06/38/2024–DGTR in Case No. AD(OI)-36/2024, the Authority recorded that the domestic industry satisfied both the 25% standing threshold and the "major proportion" test.

xiv. The legal tests for standing in a CVD investigation are materially the same as those applied in an anti-dumping investigation. It was reiterated that, under Article 11.4 of the

SCM Agreement read with Rule 6(3) of the CVD Rules, standing requires (i) at least 25% support of total production; and (ii) where support and opposition exist, more than 50% support among those expressing support or opposition, and submitted that these principles were already applied and confirmed in the concluded anti-dumping investigation.

xv. There has been no change in the domestic production base, no change in the identity of the applicant producers and supporting producers, and no change in the verified standing computation already accepted by the Authority in the anti-dumping investigation.

xvi. The POI in the present investigation is largely the same, with the addition of three months compared with the anti-dumping investigation.

xvii. Since the factual foundation and legal tests remain the same, the standing determination in the present CVD investigation should follow the concluded standing determination in the anti-dumping investigation, and that attempts to reopen the standing issue should not be entertained.

xviii. On sampling, the domestic industry submitted that sampling of domestic producers was undertaken in accordance with Paragraph 7 of Trade Notice No. 09/2021, which permits the Authority to limit detailed examination of applicant domestic producers to a limited number for injury margin determination. The Trade Notice requires statistically valid sampling methods but does not prescribe issuance of a separate public notification for sampling.

xix. The four sampled producers selected for detailed examination are among the largest producers of PUC in India, making them representative for costing and sales verification, and that they together represent a significant share of total domestic applicants.

xx. The four sampled producers are geographically and operationally diverse, and that diversity ensures the sample is reflective of the broader domestic industry.

xxi. There is no legal requirement under the CVD Rules or the SCM Agreement to issue a separate notification for selection of the sampled domestic industry. For transparency, the domestic industry filed a submission providing updated information in the prescribed formats and that this submission was circulated to all interested parties in line with the procedure and practice of the Authority.

xxii. The Authority in numerous past investigations has selected a representative group of domestic producers without issuing a separate sampling notification, and that the emphasis is on completeness, verifiability, and representativeness of data rather than the form of announcement.

xxiii. The submissions opposing the sampling do not establish any procedural lapse or legal infirmity in the sampling adopted by the Authority.

xxiv. The domestic industry argued that it complied with Trade Notice No. 09/2021, stating that non-confidential disclosure is meant to allow a reasonable understanding of injury claims, not to reveal sensitive plant-wise cost data. Circulating a consolidated non-confidential NIP, instead of disclosing company-wise confidential formats, satisfies this requirement.

xxv. Formats VI-1 to VI-5 contain sensitive information including cost of production, raw material consumption norms, working capital, capacity utilisation, and plant-wise optimum production, and that disclosure at a granular level would reveal business-sensitive information of individual producers and cause irreparable damage.

xxvi. The NIP is computed from confidential data on cost of production, capacity utilisation, raw material consumption, utilities, working capital, and reasonable return, and that this complete data is available to and verified by the Authority. Confidentiality of underlying formats does not affect the correctness or verifiability of the NIP.

xxvii. The interested parties are not prejudiced because they have been provided non-confidential injury information for the twelve applicant domestic producers reflecting

trends in production, capacity utilisation, sales, profitability and other injury parameters. On this basis, interested parties can make submissions on injury and causation, including whether injury, if any, is attributable to subsidized imports.

xxviii. The CVD Rules do not provide interested parties with a right to access confidential costing or production data of domestic producers, and that the domestic industry's obligation is to place complete data before the Authority, which has been complied with. Principles of natural justice are safeguarded through the Authority's examination and verification and through disclosure of meaningful non-confidential summaries.

xxix. The Trade Notice does not require the Authority to disclose the criteria or detailed rationale for sampling or to disclose the precise production share represented by sampled producers. It submitted that representativeness is assessed by the Authority on the basis of confidential data, and the absence of public disclosure does not vitiate the sampling exercise.

xxx. The domestic industry denied the allegation that sampling was driven by the petitioner's discretion and submitted that sampling is undertaken by the Authority in accordance with Paragraph 7 of Trade Notice No. 09/2021, and the domestic industry does not have authority to select the sample.

xxxi. The allegations of non-compliance with Trade Notice No. 09/2021 are without legal or factual basis; that sampling has been undertaken by the Authority in accordance with the Trade Notice and established practice; that disclosure obligations under the CVD Rules have been complied with; and that the requests made by interested parties seek disclosure of confidential business information and should be rejected.

D.3 <u>Examination by the Authority</u>

18. The application was filed by the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as "CMMAI") and the Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter referred to as "MMA") on behalf of the domestic producers in India.

19. The Authority notes that the PUC industry in India is fragmented and consists of an excessively large number of domestic producers located across India, hence the application for countervailing duty investigation was filed by two associations, namely CMMAI and MMA, on behalf of their member entities. All the relevant information in the prescribed format as required under Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 as amended vide Trade Notice No. 11/2021 dated 18th November 2021 was filed by the following twelve (12) applicant domestic producers:

i. Kandui Industries Private Limited
ii. Sonali Polyplast Private Limited
iii. Blend Colors Private Limited
iv. Bajaj Masterbatches Private Limited
v. Bajaj Superpack India Limited
vi. Bajaj Plast Private Limited
vii. Bajaj Polyblends Private Limited
viii. Siddh Chemiplast Private Limited
ix. Shri Ambica Polyfill
x. Soltex Petro Products Limited
xi. Alok Industries
xii. Alok Masterbatches Private Limited

20. Further, the following twenty-one (21) domestic producers supported the application:

i. Sonali Polymers Pvt. Ltd.
ii. Masterplast India Pvt. Ltd.
iii. Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.
iv. S.P. Polymer
v. 365 Plastium Pvt. Ltd.
vi. N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.
vii. Satya Polyalloys LLP
viii. Adex Ployblend Pvt. Ltd.
ix. Rama Vyapaar Pvt. Ltd.
x. Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.
xi. Swastik Plastoalloys
xii. Manan Polymers Pvt. Ltd.
xiii. Aditya Polyspin Pvt. Ltd.
xiv. J K Paras Ploycoats Ltd.
xv. Speciality Masterbatches LLP
xvi. Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.
xvii. Everplus Plastics Pvt. Ltd.
xviii. Manhar Polymers Pvt. Ltd.
xix. Dolphin Polyfill
xx. JJ Plastalloy
xxi. Prabhu Polycolor

21. The issues raised by the other interested parties and the domestic industry with respect to the domestic industry's standing have been examined below:

22. The Authority notes that the standing requirement for initiation of a countervailing duty investigation is governed by Article 11.4 of the SCM Agreement read with Rule 6(3) of the CVD Rules. Rule 6(3) of the CVD Rules requires that domestic producers expressly supporting the application account for more than 25% of total production of the like article by the domestic industry. Additionally, where domestic producers expressly oppose the application, such opposition should not account for more than 50% of total production by domestic producers who have expressed either support or opposition to the application. The relevant extract is reproduced below:

"*(3) The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless –*
(a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like article, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry : Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty-five per cent of the total production of the like product by the domestic industry, and
(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding –
(i) subsidy,
(ii) injury, where applicable; and
(iii) where applicable, a causal link between such subsidized imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation. - For the purpose of this rule, the application shall be considered to have been made "by or on behalf of domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than fifty per cent of

the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be, to the application."

23. The Authority further notes that Rule 2(b) of the CVD Rules defines "domestic industry" as domestic producers as a whole, or those domestic producers whose collective output constitutes a major proportion of total domestic production of the like article. The relevant extract is reproduced below:

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.

24. The Authority notes the contention of certain interested parties that the petition does not disclose producer-wise production volumes and market shares of domestic producers and therefore does not allow verification of standing. The Authority notes that standing determination under Rule 6(3) requires examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like article. The Authority conducts such examination on the basis of information placed on record in the application and subsequent responses, including confidential information submitted by applicants and supporters, along with non-confidential summaries as per the applicable rules.

25. The Authority notes the production and share information placed on record by the domestic industry for the POI:

Particulars	**% share in total Indian production**	**Production in POI (A)**
Twelve applicant domestic producers	35	2,50,893 MT
Twenty-one supporting domestic producers	20	1,43,525 MT
Other Indian Producers	45	3,21,306 MT
Total	100	7,15,724 MT

26. In the Final Findings of the anti-dumping investigation, it was expressly recorded that the twelve applicant domestic producers along with twenty-one supporting producers constituted more than 55% of total domestic production of the product under consideration in India. The Authority further recorded that both the 25% threshold requirement and the "major proportion" test were satisfied on the basis of verified information on record.

27. The Authority notes that the legal tests for standing under Article 11.4 of the SCM Agreement read with Rule 6(3) of the CVD Rules are materially identical to the standing tests applied in the anti-dumping investigation. The Authority further notes that there has been no material change in the identity of applicant producers, supporting producers, or the domestic production base since the conclusion of the anti-dumping investigation.

28. The Authority also notes that the period of investigation in the present countervailing duty investigation substantially overlaps with the period examined in the anti-dumping

investigation, with the addition of only three months. On examination of the information placed on record in the present investigation, the Authority finds no basis to depart from the standing determination already reached after detailed examination in the earlier proceeding.

29. The Authority therefore considers that the issue of domestic industry standing, having been examined in detail and conclusively determined in the anti-dumping investigation after full participation of all interested parties, is a settled issue. In the absence of any material change in facts or legal framework, the Authority considers it appropriate to maintain consistency and rely on the standing determination already reached.

30. The Authority notes that several objections raised by interested parties under the present heading primarily relate to issues of confidentiality, adequacy of non-confidential summaries, and transparency of information placed on record by applicant and supporting producers.

31. The Authority considers that issues relating to confidentiality claims, compliance with Trade Notices, and adequacy of non-confidential disclosures are procedural matters governed by Rule 8 of the CVD Rules and the relevant Trade Notices. Such issues do not, by themselves, negate satisfaction of the standing thresholds under Rule 6(3) or the definition of domestic industry under Rule 2(b).

32. The submissions concerning alleged excessive confidentiality, adequacy of non-confidential summaries, and transparency of disclosures have been examined separately and are addressed in the relevant subsequent sections of these final findings dealing with confidentiality and disclosure obligations.

33. The Authority does not consider that the absence of a separate exercise of seeking information from non-participating producers, by itself, renders the standing determination invalid where the standing thresholds and domestic industry criteria are satisfied on the basis of information on record and examined by the Authority.

34. On sampling, the Authority notes that Paragraph 7 of Trade Notice No. 09/2021 permits the Authority to limit detailed examination to a sample of domestic producers for injury margin determination and requires the sample to be selected using statistically valid sampling techniques. The Trade Notice does not prescribe issuance of a separate public notification setting out detailed sampling rationale.

35. The Authority notes that four domestic producers were selected for detailed examination. The sampled producers are among the larger producers of the PUC and they are geographically and operationally diverse. Representativeness is assessed by the Authority on the basis of the information on record, including confidential information, and the Authority does not find that the sampling undertaken is vitiated merely because a separate formal notification explaining sampling rationale was not issued.

36. The Authority notes that sampling and representativeness are assessed by the Authority on the basis of the record, and that disclosure of precise producer-wise production shares may involve confidential information of individual producers. The Authority considers that due process is ensured through circulation of non-confidential information to the extent permissible and the opportunity to file submissions.

37. The Authority considers that the ability of interested parties to comment on injury and

causal link is preserved through access to consolidated non-confidential trend information, while protecting confidential business information of individual producers. The Authority also notes that the detailed cost data and injury formats remain available for scrutiny and verification by the Authority.

38. The Authority, on the basis of examination, available on record, therefore holds that the initiation and continuation of the investigation are not vitiated on grounds of domestic industry standing or the sampling process, as the standing thresholds under Rule 6(3) / Article 11.4 are satisfied, the domestic industry requirement under Rule 2(b) is met on the basis of the production structure examined, and sampling has been undertaken in accordance with Paragraph 7 of Trade Notice No. 09/2021 and examined by the Authority on the basis of the investigation record.

39. Thus, the following twelve (12) applicant domestic producers constitute domestic industry as per Annexure-I to Trade Notice 9/2021 for fragmented industries:

i. Kandui Industries Private Limited
ii. Sonali Polyplast Private Limited
iii. Blend Colors Private Limited
iv. Bajaj Masterbatches Private Limited
v. Bajaj Superpack India Limited
vi. Bajaj Plast Private Limited
vii. Bajaj Polyblends Private Limited
viii. Siddh Chemiplast Private Limited
ix. Shri Ambica Polyfill
x. Soltex Petro Products Limited
xi. Alok Industries
xii. Alok Masterbatches Private Limited

40. Further, the following twenty-one (21) domestic producers supported the application and provided the required data in the prescribed format:

i. Sonali Polymers Pvt. Ltd.
ii. Masterplast India Pvt. Ltd.
iii. Sri Maniram Synthetics Pvt. Ltd.
iv. S.P. Polymer
v. 365 Plastium Pvt. Ltd.
vi. N.P. Agro (India) Industries Pvt. Ltd.
vii. Satya Polyalloys LLP
viii. Adex Ployblend Pvt. Ltd.
ix. Rama Vyapaar Pvt. Ltd.
x. Bhagyashree Colors Pvt. Ltd.
xi. Swastik Plastoalloys
xii. Manan Polymers Pvt. Ltd.
xiii. Aditya Polyspin Pvt. Ltd.
xiv. J K Paras Ploycoats Ltd.
xv. Speciality Masterbatches LLP
xvi. Sachdeva Polycolor Pvt. Ltd.
xvii. Everplus Plastics Pvt. Ltd.
xviii. Manhar Polymers Pvt. Ltd.
xix. Dolphin Polyfill
xx. JJ Plastalloy
xxi. Prabhu Polycolor

CONFIDENTIALITY & OTHER MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 Submissions by other interested parties

41. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality and other miscellaneous issues:

i. The initiation notification and subsequent proceedings are bad in law as the investigation was initiated with an impermissibly extended POI of 18 months, allegedly in violation of Explanation (ii) to Rule 6 of the CVD Rules.

ii. Explanation (ii) mandates a default POI of twelve months, and permits deviation to a minimum of six months or maximum of eighteen months only "for the reasons to be recorded in writing" by the Designated Authority.

iii. The requirement to "record reasons in writing" is mandatory, as evident from the term "shall". This requirement serves purposes such as consistency in injury analysis, like-for-like comparisons, and procedural fairness, and therefore requires an independent, reasoned justification demonstrating application of mind by the Authority.

iv. The initiation notification merely reproduces the petitioner's statement and does not contain the Authority's independent evaluation.

v. The initiation notification does not record whether the Authority verified or accepted the petitioner's claims regarding MSME status or resource constraints; does not explain why the stated practical difficulties constitute exceptional circumstances warranting deviation from the 12-month norm; and does not address whether reasons for deviation can be supplied after initiation.

vi. Petitioner convenience or administrative hardship cannot substitute for the Authority's statutory obligation to record its own reasons, and that mechanically endorsing the petitioner's averment would render the "reasons to be recorded in writing" requirement meaningless.

vii. The petition is defective for non-compliance with Trade Notice No. 14/2018, which obliges petitioners to furnish detailed non-confidential supporter data to permit meaningful verification and rebuttal.

viii. Supporters' submissions comprise blank formats with substantive information redacted under blanket confidentiality claims, making the data unusable and preventing assessment of volume, market share, injury, and standing claims.

ix. In the absence of compliant non-confidential supporter data, the Authority should disregard the supporters' contributions entirely and treat the petition as lacking support. The initiation should fail for want of demonstrated support and that the proceedings should be dismissed/terminated at the threshold.

x. Trade Notices are binding on the Authority and parties. Reliance was placed on the Supreme Court decision in Steel Authority of India v. Collector of Customs, Bombay (Civil Appeal No. 6600 of 1985) to submit that a trade notice binds customs authorities and, if erroneous, must be withdrawn or amended.

xi. The applicant industry failed to provide complete and updated data corresponding to the POI adopted in the initiation notification. The application was originally filed on the basis of April 2023–March 2024 data, whereas the Authority initiated the investigation for 1 April 2023–30 June 2024.

xii. Once the Authority adopted the extended POI, the applicant was obligated to align its application with the notified POI by furnishing a complete updated set of information and revised injury analysis covering the entire notified period, rather than relying on data only up to March 2024.

xiii. The applicants did not file a complete updated application and, instead, filed only a single-page "updated" Proforma IV-A consolidating information of all applicant producers.

xiv. This does not cure the deficiency because the applicant did not provide company-wise information for the updated POI for all individual applicant companies, as mandated under Trade Notice No. 09/2021, and did not file revised injury tables, trends, or narrative analysis for the notified POI.

xv. This piecemeal updating impedes the rights of interested parties to defend their interests, deprives parties and the Authority of a coherent understanding of injury parameters, and results in the investigation proceeding on an application and injury analysis not corresponding to the POI, thereby undermining the prima facie injury and causation assessment.

xvi. The applicant has not discharged its burden to substantiate injury over the POI adopted by the Authority.

xvii. The absence of certifications/undertakings/declarations/authorizations for the complete POI renders the proceedings illegal. The application was filed with the POI as 1 April 2023–31 March 2024, but the Authority initiated the investigation with 1 April 2023–30 June 2024, and the applicant did not provide certifications corresponding to the POI considered by the Authority in the initiation notification.

xviii. The Authority ought to have sought certifications for the POI adopted in the initiation notification, including certifications regarding relationship with importers/exporters and self-imports, to assess whether the applicant qualifies as domestic industry under Rule 2(b), and that this should have been done prior to issuance of the initiation notification as a pre-condition.

xix. The initiation notification was published without ascertaining pre-conditions under Rule 2(b) and therefore the proceedings are bad in law, including for violation of Rule 5 and Rule 6(3), which provides that the Authority shall not initiate unless pre-conditions are met. Since the defect occurred prior to initiation, it cannot be cured later by providing certifications at the current stage and is a fatal jurisdictional error.

xx. Even the subsequently filed updated injury information for the updated POI does not contain mandatory certifications/undertakings/declarations or authorizations for the updated period. Decisions on eligibility to file the application and prima facie satisfaction as to subsidization, injury, and causal link have been taken without complete POI data and without certifications, casting doubt on the correctness of the data.

xxi. The applicant industry claimed excessive confidentiality on several key economic parameters in the petition, impairing respondents' ability to examine injury parameters and defend their interests. The applicant neither established good cause for confidentiality nor provided adequate non-confidential summaries sufficient for reasonable understanding.

xxii. Where a party claims information is not susceptible to summarization, CVD Rules require a statement of reasons explaining why summarization is not possible, and a bald assertion that summarization is not possible does not satisfy this requirement.

xxiii. In terms of the CVD Rules and Trade Notice, the non-confidential version of the petition must provide indexed and summarized data in sufficient detail to permit reasonable understanding, and that Trade Notice provides that submissions without meaningful non-confidential versions should not be taken on record.

xxiv. Proper non-confidential versions of the petition should be provided and that meaningful non-confidential summaries be made available to enable effective defense.

xxv. Contrary to Trade Notice No. 10/2018, the petition provides trends for sales value, PBIT per unit, total PBIT, domestic sales interest/finance cost, and depreciation/amortization expenses, whereas aggregated actual numbers were required, and that this undermines transparency.

xxvi. Reference was made to the domestic industry's position that Trade Notice No. 10/2018 is guideline-based and permits deviation case-by-case upon showing good cause, and that confidentiality has been claimed accordingly. Interested parties submitted that such reliance is misplaced because deviation is permissible only upon demonstrating good cause, which has not been substantiated in the present case.

xxvii. Disclosure of aggregated actual figures for multiple producers does not reveal individual company information and therefore does not prejudice commercial interests. According to interested parties, the domestic industry has not shown why such aggregated disclosure cannot be made, and therefore no good cause exists for providing only trends.

xxviii. Trade notices are binding and that the domestic industry's justification that similar disclosure was not required in earlier cases is not a valid basis to disregard Trade Notice requirements. The Authority was requested to direct the domestic industry to provide aggregated actual figures in the non-confidential version to ensure transparency and compliance.

xxix. Supporting producers filed only minimal statements with substantive information blacked out, with no indexed or trend-based data, preventing assessment of production, sales, cost trends, profitability, and the extent of support. Domestic industry did not comply with Trade Notice No. 05/2021 and Trade Notice No. 14/2018, and such deficient support be disregarded.

xxx. The import data relied upon by the petitioner is from unreliable secondary/private sources and is not authentic or reliable. The Authority should call for and rely upon DGCI&S import data for examination of imports, as the Authority has relied upon DGCI&S data in past cases.

xxxi. The petitioner claimed excessive confidentiality by not disclosing even the name of the source of the import data used as a basis for initiation, without citing reasons for such confidentiality. The import data pertains to exporters and therefore cannot be claimed confidential from responding exporters.

xxxii. A distinction must be maintained between calcium carbonate filler masterbatch (the PUC) and color masterbatch (NPUC). Calcium carbonate masterbatch is typically priced lower, while color masterbatch has higher prices and higher profit margins.

xxxiii. The Authority was requested to obtain separate production and financial data for PUC and color masterbatch; identify which of the 12 applicants are primarily engaged in producing the PUC; determine what proportion of capacity is dedicated to PUC versus color masterbatch; and ensure that applicant standing and injury evaluation is assessed only with reference to PUC production.

xxxiv. Objections relating to sampling-related disclosure were reiterated, stating that mere disclosure of consolidated NIP does not satisfy Trade Notice No. 09/2021 and that non-confidential versions of Formats VI-1 to VI-5 for sampled producers are required to enable meaningful examination.

xxxv. The injury analysis cannot be reviewed based on NIP alone and requires access to the underlying injury formats, including cost allocation methodologies, consumption norms, utilities, working capital assumptions, capacity utilisation and plant-wise optimum production levels, and adjustments/normalisation.

xxxvi. The Authority has not disclosed the production share represented by sampled producers, which undermines transparency and prevents assessment of representativeness.

xxxvii. No submission filed by the applicant should be taken on record unless a proper non-confidential version has been shared. The applicant should clearly specify which earlier submissions are being relied upon, and that the Authority should verify that each confidential submission is accompanied by a proper non-confidential version and reject submissions that do not meet this requirement.

xxxviii. The supporters did not provide details corresponding to the POI considered in the initiation notification and trade notices must be followed and that non-compliance has been overlooked.

xxxix. Even if certain documents are business sensitive, at least index-based non-confidential information should be provided. Support letters should not be withheld without reasons and, at minimum, information should be provided in percentage form to enable respondents to analyse support in a fair manner.

xl. Excessive confidentiality hinders meaningful submissions, including on injury parameters, and all non-confidential data and meaningful summaries be made available to allow effective defence.

xli. Rule 18 of the Subsidy Rules, 1995 requires that the designated authority, shall, before giving its final findings, inform all interested parties and interested countries of the essential facts under consideration which form the basis of its decision and permit the interested parties to defend their interest. The excerpts of Rule 18 are provided below to substantiate our claim in this context.

Rule 18. Disclosure of information

The designated authority, shall, before giving its final findings, inform all interested parties and interested countries of the essential facts under consideration which form the basis of its decision and permit the interested parties to defend their interest.

xlii. They submitted that the requirements and obligations of Rule 18 have not been complied with, thereby resulting into denial of a fair opportunity to the interested parties to comment upon the same and adequately defend their interests. Therefore, they requested the Hon'ble Authority to issue fresh Disclosure Statement so that the they are able to file their meaningful comments and adequately defend their interests.

E.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>

42. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the confidentiality and other miscellaneous issues:

i. The Authority must assess confidentiality based on various factors including nature of information and whether such information is by law, custom, usage or practice treated as confidential in the relevant field.

ii. The domestic industry denied failure to comply with Trade Notice 09/2021 which recognizes challenges in gathering complete information from all producers in fragmented industries and provides simplified procedures for initial filings. The petitioners filed all required information under Annexure-I for twelve applicant producers supported by requisite production and injury data across the injury period.

iii. The domestic industry denied that only Proforma IV-A and single-page NIP statement was provided, stating that complete confidential data including PCN-wise cost and price data and cost sheets were submitted to the Authority. Non-confidential versions were submitted to extent possible without disclosing information that could harm commercial interests of sampled producers operating in highly competitive market.

iv. The domestic industry denied failure to adhere to Trade Notice 10/2018 and Trade Notice 14/2018, stating that as per the Trade Notice, producers are required to provide reasonable non-confidential summary or explanation where summary is not

possible. In all instances where data was marked confidential, either summary in indexed form was submitted or explanation was provided why disclosure would severely prejudice companies.

v. Non-confidential versions were submitted with data marked with justifiable confidentiality indicators in accordance with Trade Notice. Summary trends in domestic sales, profit margins, interest costs and depreciation were provided in indexed form, fully complying with confidentiality treatment requirements.

vi. Allegations of excessive confidentiality are without basis as the Authority has consistently accepted confidential filings where companies can show risk of significant commercial harm. The market for the PUC is competitive and disclosure of costs and pricing would materially harm sampled producers. Confidentiality claims are made in accordance with Trade Notice and CVD Rules.

vii. There is no legal obligation to disclose actual numbers in public version when such disclosure would lead to commercial harm. The Authority has not raised any deficiency with respect to confidentiality and there is no procedural violation.

viii. The Authority is competent body to assess completeness, confidentiality and procedural compliance. All mandatory information has been placed on record and the Authority retains discretion to verify and evaluate all data on record and direct disclosure of further information if required.

ix. The domestic industry submitted that it has placed on record the list of members of CMMAI and MMA along with their status as supporters or opposers, and a statement depicting the share of production of applicants, supporters, and other Indian producers in total domestic production.

x. The domestic industry submitted that the request to disregard the support of the supporting producers is untenable and that the record contains supporter-wise information in non-confidential form as required under the applicable framework.

xi. Interested parties have misread the Trade Notice by asserting that it mandates disclosure of aggregated actual figures in all cases involving multiple domestic producers.

xii. Trade Notice No. 10/2018 expressly provides that the confidentiality guidelines are not absolute and that the Authority may permit deviation on a case-to-case basis upon demonstration of good cause, consistent with Rule 8 of the CVD Rules.

xiii. Good cause exists in the present case for claiming confidentiality over aggregated sales value and profitability figures. Aggregate sales quantities have been disclosed in the non-confidential version, and disclosure of aggregated sales value and profitability, when read with quantities, would reveal estimated selling prices and profit levels of the domestic producers.

xiv. The domestic market for the PUC is highly competitive and fragmented, with multiple Indian producers competing among themselves and with exporters. Disclosure of consolidated sales value and profitability figures would provide pricing benchmarks to competitors and exporters, enabling undercutting and causing serious commercial harm.

xv. The allegation that aggregated disclosure for multiple producers would not prejudice commercial interests ignores market realities, as aggregated figures can still reveal sensitive pricing and margin information in industries with comparable cost structures and product characteristics.

xvi. The allegation regarding non-disclosure of interest and depreciation data is factually incorrect, as aggregate information relating to interest expenses and depreciation and amortization has been provided in the non-confidential version of the petition.

xvii. Confidentiality has not been claimed through bald assertions. The domestic industry has clearly explained the justification for confidentiality, including risks of price undercutting, loss of bargaining power, and distortion of competition.

xviii. Reliance was placed on past practice of the Authority, including the anti-dumping investigation concerning imports of Soda Ash from Turkey, Russia, USA and Iran, where the Authority accepted disclosure of trends instead of aggregated actual figures for sales value and profitability in view of potential commercial harm.

xix. The Authority, in the Soda Ash Final Findings, expressly recorded that disclosure of actual selling price, cost, and profitability information could cause significant adverse effects and confer undue competitive advantage, and therefore allowed confidentiality on such parameters.

xx. The factual matrix in the present investigation is materially identical to the Soda Ash case, as the domestic industry here also comprises multiple producers competing inter se and with exporters, and disclosure of aggregated actual figures would similarly reveal sensitive pricing and margin information.

xxi. Acceptance of trend-based disclosure does not dilute transparency. The non-confidential trends provide sufficient information to understand injury parameters, examine patterns over the injury period, and make meaningful submissions while protecting confidential business information.

xxii. The Authority has consistently allowed confidentiality of selling price and profitability-related information in investigations involving multiple producers, including investigations concerning printed circuit boards, PVC suspension resins, solar cells, tyres, polyester yarn, and caustic soda.

xxiii. Interested parties are not prejudiced in their right of defense and are able to make submissions on volume effects, price effects, profitability trends, and causation on the basis of the non-confidential information placed on record.

xxiv. With respect to allegations regarding inadequate disclosure by supporting producers, the present investigation concerns a fragmented industry dominated by MSMEs, and that the special procedural framework under Trade Notice No. 09/2021 applies.

xxv. Trade Notice No. 09/2021 requires applicant domestic producers to file basic injury information in Annexure-I and does not require supporting producers to file detailed injury, cost, sales, or financial information.

xxvi. The purpose of Trade Notice No. 09/2021 is to simplify initiation for fragmented industries and avoid procedural barriers that would otherwise prevent such industries from seeking trade remedy protection.

xxvii. In compliance with Trade Notice No. 09/2021, it has already filed and circulated a complete list of members of CMMAI and MMA indicating supporters, opposers, and neutral producers, along with aggregated production data sufficient to understand the production structure of the domestic industry.

xxviii. Without prejudice, it was reiterated that the twelve applicant domestic producers alone account for more than 35% of total domestic production during the POI, independently satisfying the 25% threshold under Rule 6(3), irrespective of supporter data.

xxix. No domestic producer has opposed the application, and therefore the second limb of the standing test under Rule 6(3), requiring supporters to represent more than 50% of those expressing support or opposition, is automatically satisfied.

xxx. Allegations regarding violation of Trade Notice No. 14/2018 must be assessed in harmony with Trade Notice No. 09/2021, which was issued later in time and specifically addresses filing requirements for fragmented industries.

xxxi. The injury determination under the CVD Rules is based on data of the applicant domestic producers, including sampled producers where applicable, and supporting producers are not required to submit detailed injury information.

xxxii. The consolidated Proforma IV-A captures key injury parameters and that interested parties have access to non-confidential injury information sufficient to comment on injury and causation.

xxxiii. No principles of natural justice have been violated and that interested parties have been afforded full opportunity to examine and comment on injury on the basis of information placed on record.

xxxiv. With respect to allegations regarding failure to re-file a complete updated application for the extended POI, the Authority has discretion to determine the POI at initiation and that initiation is based on prima facie evidence. Once the POI was extended, the domestic industry furnished updated information for the additional period in the manner directed by the Authority, and there is no requirement under the CVD Rules to re-file the entire petition.

xxxv. No prejudice has been caused to interested parties, as non-confidential information reflecting trends over the injury period, including the extended POI, has been placed on record.

xxxvi. With respect to allegations regarding absence of certifications or declarations for the extended POI, the application contained the required certifications at the time of filing and that extension of the POI does not invalidate certifications already on record.

xxxvii. Any alleged procedural deficiency is curable and does not render the initiation void or without jurisdiction.

xxxviii. Company-wise information for individual applicant producers was provided at the time of filing in accordance with Trade Notice No. 09/2021 and that updated company-wise information for the extended POI has also been filed with the Authority. The non-confidential versions of individual company-wise information for the updated POI have also been filed and circulated to all other interested parties.

xxxix. The initiation was based on examination of accuracy and adequacy of evidence under Rule 6 of the CVD Rules and Articles 11.2 and 11.3 of the SCM Agreement.

xl. The import trends relied upon show a consistent increase in imports from Vietnam over the injury period, culminating in a surge during the POI, and that these trends have been corroborated by verified import data examined by the Authority.

xli. Reliance on secondary import data at the stage of initiation is an established practice of the Authority where official data is not contemporaneously available, and such data is subsequently verified during investigation.

xlii. With respect to allegations regarding mixing of PUC data with colour masterbatch data, all information furnished relates exclusively to Calcium Carbonate Filler Masterbatch and that consolidated Proforma IV-A reflects only PUC-specific data.

xliii. The fact that some applicant producers may also manufacture colour masterbatch does not invalidate the injury analysis, as long as the analysis is based on PUC-specific data, which is the case here.

xliv. The domestic industry requested that the submissions of the interested parties on confidentiality and miscellaneous procedural issues be rejected.

E.3 Examination by the Authority

43. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality and other miscellaneous issues have been examined as under:

i. The Authority notes the objection that the investigation was initiated with 15-month POI and that Explanation (ii) to Rule 6 of the CVD Rules prescribes a 12-month POI as the norm, permitting a minimum of six months or a maximum of eighteen months only "for reasons to be recorded in writing". Explanation (ii) to Rule 6 of the CVD Rules provides as follows:

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.

ii. The Authority considers that, at the stage of initiation, the Authority is required to record reasons for the POI selected, and such reasons are required to be adequate to explain the basis for the choice made. The Authority that submissions of interested parties that the investigation was initiated with an 18 months POI is wrong and denied. The Initiation notification dated 27.12.2024 clearly records that investigation was initiated with a 15 months POI.

iii. The Authority notes the reasons related to the structure of the domestic industry in the present case and the practical feasibility of compiling data for a fragmented MSME-driven industry. The Authority considers these considerations relevant for selecting an appropriate POI within the range provided under Explanation (ii) to Rule 6 of the CVD Rules.

iv. The Authority considers that selection of an appropriate POI within the permissible statutory range requires balancing comparability and practicality, and that the reasons recorded in the initiation notification are sufficient for the purpose of Explanation (ii) to Rule 6 of the CVD Rules.

v. Accordingly, the Authority has not accepted the submission that the investigation is without jurisdiction on the grounds that the POI is more than 12 months. The Authority further notes that the choice of POI within the permissible statutory range.

vi. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 7(7) of the CVD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of CVD Rules provides as follows:

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule (2) of rule 14, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19, copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information."

vii. The Authority notes the submission of other interested parties that supporters have not provided meaningful non-confidential data on production, capacity, sales, profitability or injury, that the non-confidential versions are heavily redacted, and that supporters'

support should therefore be disregarded for the purposes of standing.

viii. The Authority notes that twelve (12) applicant domestic producers filed the required information in Annexure-I under Trade Notice No. 09/2021 constitute domestic industry, and that twenty-one (21) producers expressly supported the application.

ix. The Authority notes that, in any event, the twelve applicant producers alone constitute more than 25% of total domestic production. The Authority therefore considers that satisfaction of the 25% threshold under Rule 6(3) does not depend on the supporters. Further, the Authority notes that no domestic producer has expressed opposition to the application. In view of the explanation to Rule 6(3), the Authority considers that the standing requirement relating to the degree of support among those expressing support or opposition is satisfied on the facts of the present case.

x. The Authority notes the submission that Trade Notice No. 14/2018 requires detailed non-confidential summaries and that supporters' data is non-compliant. The Authority considers that confidentiality obligations apply to all submissions, and that the adequacy of non-confidential summaries must be assessed in the context of the information required to be filed and the nature of information for which confidentiality is sought.

xi. The Authority notes the submission that Trade Notice No. 10/2018 requires disclosure of aggregated data in actual figures in cases involving multiple domestic producers, and that the domestic industry disclosed only trends for parameters such as sales value, profitability, interest/finance cost, and depreciation/amortization.

xii. The Authority has examined the domestic industry's justification that aggregate sales quantities have been disclosed and that disclosure of aggregated sales value and profitability, when read with quantities, can reveal estimated selling price and profit levels of domestic producers in a competitive and fragmented market. The Authority notes the domestic industry's submission that such disclosure can provide pricing benchmarks to competitors and exporters and may cause commercial harm.

xiii. The Authority considers that the confidentiality regime under the CVD Rules seeks to balance transparency and due process with protection of confidential business information. The Authority considers that trend-based disclosure can be permissible where it permits reasonable understanding of the substance of information while protecting sensitive data, provided the summaries are meaningful and sufficient for interested parties to present their case.

xiv. On the facts of the present case, the Authority considers that the domestic industry has provided non-confidential information in a manner that enables interested parties to understand trends over the injury period and make submissions on injury, price effects, profitability trends, and causation, while protecting information that is confidential by nature.

xv. The Authority has undertaken a thorough examination of the confidentiality claims submitted by both the domestic industry and other interested parties. Upon review, the Authority finds that these claims were, in general, appropriately substantiated and in conformity with the applicable legal provisions.

xvi. Accordingly, on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of

the information filed on a confidential basis.

xvii. The Authority notes the submission of other interested parties that the application was originally filed for April 2023–March 2024, while the Authority initiated with an extended POI of 1 April 2023–30 June 2024, and that the applicant allegedly failed to re-file a complete updated application and revised injury analysis for the notified POI.

xviii. The Authority notes that it may fix the POI at initiation based on prima facie evidence and may later seek updated information or additional evidence during the investigation. The domestic industry has stated that it submitted all required updated POI data in the manner directed, and that the CVD Rules do not require a complete re-filing of the petition for such updates. It also submitted company-wise information in the prescribed formats, including for the updated POI, along with a circulated non-confidential version. Regarding the allegation that fresh certifications were not provided for the extended POI, the domestic industry maintains that the original certifications filed with the application remain valid and are not invalidated merely because the POI was extended.

xix. The Authority considers that the relevant question is whether the information required for examination is available on record for the POI adopted, and whether the Authority has had the ability to examine and verify the information during the investigation. The Authority notes that the investigation process includes opportunities to seek and provide updated information, and procedural requirements are to be applied to ensure a fair process without treating curable procedural aspects as jurisdictional defects in the absence of prejudice.

xx. The Authority notes that interested parties have had access to non-confidential information for the injury period including the extended POI and have been afforded opportunity to file submissions. The Authority therefore does not accept the submission that the proceedings are vitiated at the threshold on account of the form in which updated POI information was provided or on account of the allegations regarding certifications, particularly where information has been placed on record and examined.

xxi. The Authority notes the submission that the petitioner relied on secondary/private sources for import data and that the Authority should have called for DGCI&S data at initiation, and that the source of import data was not disclosed.

xxii. The Authority notes that import trends relied upon for initiation were examined for reasonableness and consistency and that the Authority has access to official import data during investigation for verification.

xxiii. The Authority notes that for the purpose of investigation, it has relied upon the DG Systems data.

xxiv. The Authority notes the submission that sampled companies may manufacture both calcium carbonate filler masterbatch (PUC) and colour masterbatch, and that profitability of colour masterbatch could distort injury analysis unless PUC-specific data is used.

xxv. The investigation concerns only Calcium Carbonate Filler Masterbatch and that all information furnished by applicant domestic producers, including company-wise and consolidated Proforma IV-A data, pertains exclusively to the PUC, and does not include production, sales, costs or profitability relating to colour masterbatch or other non-subject products.

xxvi. The relevant issue is whether the injury analysis is based on PUC-specific data. On the basis of the record, the Authority holds that the applicant domestic producers have filed

product-specific information relating to the PUC in the prescribed formats. The Authority therefore has not accepted the submission that the injury analysis is vitiated merely because certain producers may also manufacture other products, where the data relied upon is product-specific and duly verified by the Authority.

xxvii. The Authority notes that certain interested parties reiterated that non-confidential versions of injury formats VI-1 to VI-5 for sampled producers should be circulated and that mere disclosure of a consolidated non-confidential NIP is insufficient, and that non-disclosure of production share of sampled producers affects representativeness.

xxviii. The Authority reiterates that the injury analysis and NIP are based on complete information placed on record by the sampled producers and examined by the Authority, and confidentiality claims are assessed under the applicable framework to balance transparency and protection of confidential information.

xxix. In view of the above examination, the Authority holds that the above issues have been examined in accordance with the applicable legal framework and do not vitiate the initiation or continuation of the present investigation.

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

F.1. Submissions by other interested parties:

44. The other interested parties have made the following submissions with regard to the subsidies and subsidy margin:

i. The producers/exporters submitted that the allegations of subsidization made in the petition are unfounded and unsupported by evidence.

ii. The producers/exporters contended that the petition lacks "sufficient evidence" of subsidization as required under Articles 11.2 and 11.3 of the SCM Agreement and the corresponding provisions of the Indian CVD Rules. The petition relies on assertions and general descriptions of government policies without establishing the constitutive elements of a subsidy for each alleged programme.

iii. The existence of a subsidy under the SCM Agreement and the CVD Rules requires proof of a financial contribution, benefit, and specificity, and that mere availability or existence of a programme under domestic law is legally insufficient.

iv. Reliance is placed on WTO jurisprudence, including the Panel Report in China – GOES, to argue that the investigating authority must examine the accuracy and adequacy of evidence before initiating an investigation and must filter out applications that do not meet the sufficiency standard. It is contended that "prima facie" evidence is not equivalent to "sufficient evidence" and that the latter requires legally satisfactory substantiation.

v. One of the interested parties submitted that out of the thirteen subsidy programmes alleged in the petition, they have not availed any programme except a minor investment-linked corporate income tax exemption, which is claimed to be a general measure under Vietnamese law and non-specific in nature.

vi. The said corporate income tax exemption was available only for a limited period of six months during the fifteen-month period of investigation and yielded a negligible benefit. Such a limited and general tax measure cannot be treated as a countervailable subsidy.

vii. Few producers/ exporters submitted that they are either not eligible under the respective schemes, have not participated in such schemes, or have engaged in purely commercial transactions conducted at market-determined rates. Documentary evidence has been submitted to demonstrate non-eligibility, non-availment, or absence of any preferential treatment.

viii. The petition and the initiation notification merely list thirteen programmes without demonstrating, with evidence, that any exporter actually received a financial contribution conferring a quantifiable benefit.

ix. The producers/exporters submit that the petition fails to establish: (i) a financial contribution by the Government of Vietnam or a public body; (ii) a benefit conferred; and (iii) specificity of the alleged programmes. The failure to establish these elements vitiates the initiation of the investigation and cannot be cured at a later stage.

x. Vitaplas has submitted that the jurisprudence of the WTO Appellate Body has unequivocally established that domestic prices constitute the primary and preferred benchmark, and that recourse to out-of-country benchmarks is strictly residual in nature. In US – Softwood Lumber IV, Appellate Body Report, WT/DS257/AB/R (adopted 17th February 2004), paras 90–103, the Appellate Body held that private prices in the country of provision are the primary benchmark, and that out-of-country benchmarks may be used only where domestic prices are distorted. The Appellate Body expressly rejected any automatic or presumed rejection of domestic prices. This position was reinforced in US – Countervailing Measures (China) - WT/DS437/AB/R, US – Carbon Steel (India) - WT/DS436/AB/R.

xi. The Authority has not demonstrated that it assessed the adequacy and accuracy of the evidence prior to initiation, as required under Article 11.3 of the SCM Agreement and Section 6 of the Indian CVD Rules. The respondents request the Authority to clarify the basis on which the petition was considered to contain sufficient evidence.

xii. The producers/exporters further relied on WTO Panel findings, including Mexico – Pipes and Tubes and Japan – DRAMs, to submit that countervailing duties can only be imposed where there is evidence of ongoing subsidization and that general assertions, policy descriptions, or unsubstantiated claims do not meet the evidentiary threshold.

xiii. It is further submitted that any determination regarding existence, benefit, or specificity of alleged subsidies must be based on a combined examination of exporters' questionnaire responses and the response filed by the Government of Vietnam. No adverse inference can be drawn without such correlated examination.

xiv. The respondent submitted that rejection of its response on the ground of non-filing of the additional questionnaire response is unwarranted, as it had filed a complete questionnaire response and the information sought by the Authority had either already been furnished in the original questionnaire response or was not applicable to the company.

xv. With regard to $CaCO_3$ details, the applicant submitted that $CaCO_3$ was the only raw material used for manufacture of the subject goods, and details of its consumption and purchase had already been provided in Section I(C) of the original questionnaire response. As regards export promotion incentive, grant or drawback, the applicant submitted that no such benefit was received during the POI for exports of the subject goods, and the same had already been confirmed in Section I(A)(7) of the original response.

xvi. The respondent further submitted that it had not received any exemption on purchase of raw materials. All imported raw materials used by the company were subject to the general import-export tariff schedule under Vietnamese law, and no specific import duty exemption or preferential treatment was granted exclusively to enterprises engaged in manufacture of the subject goods. It was also submitted that import duty concessions

under Free Trade Agreements are not countervailable, as such concessions are generally available to all enterprises satisfying the prescribed origin and FTA requirements and are not industry-specific or exclusive to the subject goods.

xvii. With regard to capital goods and spares, the respondent submitted that it had not imported any capital goods or stores/spares and, therefore, no benefit under any such scheme was availed. As regards land-related benefits, the applicant submitted that it had not purchased land and had not participated in any Government programme providing land at below-market rates or granting land-related exemptions. The premises were stated to have been taken on rent from a private party.

xviii. The respondent also submitted that it does not use water or gas in the manufacture of the subject goods. With regard to electricity, it submitted that electricity is purchased at arm's length prices applicable generally to all companies and that no electricity subsidy has been received.

xix. As regards corporate tax, the respondent submitted that US Masterbatch JSC paid regular corporate income tax at the rate of 20% during the POI. It further submitted that US Masterbatch JSC – Hung Yen Branch availed 50% corporate income tax reduction in 2023, 2024 and 2025, and that copies of the relevant income tax returns of the producer and related trader had already been submitted with the original questionnaire response.

xx. With respect to loans, the respondent submitted that all loans were obtained from commercial banks on arm's length terms and at normal banking rates. It further submitted that no loan was taken from the State Bank of Vietnam and, therefore, the alleged scheme was not applicable to the company. The respondent also stated that details of loans had already been provided at pages 28 to 30 of the original questionnaire response.

xxi. The respondent finally submitted that several alleged schemes, including export incentives, raw material purchase exemptions, capital goods concessions, and water/gas benefits, were not countervailed in the Disclosure Statement dated 20th March 2026.

xxii. The respondent submitted that rejection of the entire questionnaire response is contrary to the consistent practice of the Authority. It was submitted that in several investigations, where part of the information was found deficient or was not accepted, the Authority applied best information available only to the deficient portion and nevertheless granted individual duty margins.

xxiii. In support, the respondent relied on the final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Aluminium and Zinc Coated Flat Products from China PR, Vietnam and Korea RP, wherein the Authority did not reject the complete response of M/s Nam Kim Steel despite non-submission of the practicing accountant's certificate. Instead, the Authority rejected only the claimed normal value and determined the same on the basis of best facts available.

xxiv. Accordingly, the respondent submitted that even assuming there is any missing or deficient information, the complete response of US Masterbatch Group cannot be rejected in totality. The Authority may, at best, apply best information available only to the specific missing information, in accordance with the ASCM, past practice of the Authority and principles of natural justice.

xxv. The respondent further submitted that both US Masterbatch Joint Stock Company and US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch are manufacturers of the subject goods and, therefore, requested that individual duty margins be granted to both companies.

F.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>

45. The domestic industry has made the following submission with regard to the subsidies and subsidy margin:

i. The domestic industry submitted that the determination of countervailable subsidies in the present investigation is governed by the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the domestic legal framework contained in Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with the Countervailing Duty Rules.

ii. In terms of Section 9(1) of the Customs Tariff Act, a subsidy is deemed to exist where a financial contribution is made by the government or a public body of the exporting country and a benefit is thereby conferred on the recipient. For a subsidy to be countervailed, the requirement of specificity must also be satisfied.

iii. Section 9(1) of the Customs Tariff Act expressly provides that a financial contribution may take the form of, inter alia, direct transfer of funds, government revenue foregone or not collected, provision of goods or services other than general infrastructure, purchase of goods, or income or price support that operates to increase exports or reduce imports, provided that a benefit is conferred.

iv. Rule 12 of the CVD Rules provides the methodology for calculation of the amount of countervailable subsidy. The Rule mandates that countervailable subsidies shall be calculated in terms of the benefit conferred on the recipient, as found to exist during the period of investigation.

v. Based on publicly available information, the domestic industry made detailed and programme-specific submissions in the petition seeking initiation of the present countervailing duty investigation. These submissions identified the nature of the alleged subsidy programmes, the legal basis under Vietnamese law, the manner in which financial contribution was made by the Government of Vietnam, and the benefit conferred on the producers/exporters of the subject goods.

vi. The petition and the benchmark submissions were supported by publicly available documents, government notifications, policy documents, and secondary evidence, and were sufficient to establish the existence of financial contribution, benefit, and specificity for the purposes of initiation and investigation.

vii. The investigation has progressed beyond the initiation stage and that the determination of subsidization must now be based on a detailed examination of exporters' questionnaire responses, the response filed by the Government of Vietnam, and verification of information on record, in accordance with the CVD Rules.

F.3 <u>Examination by the Authority</u>

46. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the determination of subsidies and subsidy margin. The Authority notes that under Section 9(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with the CVD Rules, a subsidy is deemed to exist where financial contribution is made by the government, conferring a benefit to the recipient. Further, for a subsidy to be countervailed, it should fulfill the requirements of specificity.

47. The Authority notes that, for the purpose of determining subsidization and subsidy margin, it has relied upon:

(i) the information and evidence filed by the domestic industry in the petition and subsequent submissions, including benchmark submissions;

(ii) the questionnaire responses/additional questionnaire response and supporting documents filed by the participating producers/exporters; and

(iii) the response and information provided by the Government of Vietnam through the Trade Remedies Authority of Vietnam (TRAV), along with the verification and examination carried out by the Authority during the course of investigation.

48. The Authority further notes that the record in the present investigation contains information from all cooperating parties relevant to examination of the constitutive elements of subsidization.

49. The Authority notes that the exporters' contentions regarding programme-wise non-eligibility, non-availment, market-based transactions, and the alleged non-countervailable nature of certain schemes raise issues that require programme-specific examination. The Authority considers that these issues cannot be concluded on the basis of general assertions and must be assessed in light of verified information on record.

50. Accordingly, the Authority has examined the alleged subsidy programmes, the evidence placed on record by the domestic industry, the information filed by the cooperating producers/exporters, and the response filed by TRAV, for the purpose of determining whether countervailable subsidies exist and for quantification of subsidy margin. The Authority's programme-wise examination, including examination of benchmarks and benefit calculations, has been set out in the subsequent paragraphs under the relevant programme headings.

51. The Authority has therefore proceeded to determine subsidization and subsidy margin on the basis of the information available, consistent with the requirements of the CVD Rules.

52. The Authority finds that wherever the level of cooperation by Vietnamese producers/exporters has been satisfactory, the Authority has considered the information provided by cooperating producers/exporters for determination of individual subsidy margins.

53. US Masterbatch Joint Stock Company and US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch (exporters) have submitted that they have filed complete questionnaire response. It is noted that the exporters have filed the information relating to raw material, land, electricity, corporate income tax and loan in their original questionnaire response. The exporters have also claimed in their original questionnaire response that they have not availed any export promotion incentive, not availed specific import duty exemptions on imported raw material / capital goods and not imported capital goods / stores. The Authority has examined the questionnaire response filed by the exporters and notes that the information relevant for the determination of the margins for the schemes countervailed by the Authority were filed by the exporters in the original questionnaire response. Therefore, it is decided to grant individual margin to the exporters.

I. <u>List of schemes identified in the form of provision of goods/services for Less Than Adequate Remuneration ("LTAR")</u>

- **Program 1 -** Supply of Limestone at LTAR
- **Program 12 -** Provision of Natural Gas/Electricity/Coal for Power Consumption at LTAR
- **Program 13 -** Government Provision of Land at LTAR And Exemption/ Reduction of Land and Water Rent

II. <u>List of schemes identified in the form of tax exemptions and rebates</u>

- **Program 3 -** Exemption on Corporate Income Tax for Enterprise
- **Program 4 -** Import Duty Exemption

III. <u>List of schemes identified in the form of interest rate subsidies</u>

- **Program 5 -** Preferential Lending for Investor
- **Program 7 -** Preferential Lending to the Exporter
- **Program 8 -** Interest Rate of Investment Credit Loans

- **Program 9 -** Investment Support on Investors who Invested on establishing small and medium enterprises
- **Program 10 -** Export Credit from Vietnam Development Bank ("VDB")
- **Program 11 -** Financial Guarantee by Vietin Bank

IV. <u>List of schemes identified in the form of other financial incentives</u>

- **Program 2 -**Masterplan For Development of Vietnam
- **Program 6 -**Export Promotion Program

54. Post initiation, the producers/ exporters of the subject goods were advised to file response to the questionnaire and additional questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of the alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

55. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

i) European Plastic Joint Stock Company
ii) Polyfill Joint Stock Company
iii) Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company
iv) Yen Bai European Plastic Joint Stock Company
v) A Dong Plastic Joint Stock Company
vi) Vitaplas Joint Stock Company
vii) An Tien Industries Joint Stock Company
viii) Filler Masterbatch Joint Stock Company
ix) Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company

56. Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 ("**GATT**") read with Article 19 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ("**SCM**") allows importing countries to impose a countervailing duty on subsidized imported goods.

57. Accordingly, Section 9 of the Customs Tariff Act allows the Central Government to impose a countervailing duty on subsidized imports. Section 9(1) of the Customs Tariff Act states as follows:

> *(1) Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any article including any subsidy on transportation of such article, then, upon the importation of any such article into India, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.*

58. The Explanation to Section 9(1) of the Customs Tariff Act contains the same language of Article 1 of the SCM, which defines a 'subsidy' for the purposes of a countervailing duty investigation. It states that a subsidy shall be deemed to exist if:

> *"(a) there is financial contribution by a Government, or any public body in the exporting or producing country or territory, that is, where –*

(i) a Government practice involves a direct transfer of funds (including grants, loans and equity infusion), or potential direct transfer of funds or liabilities, or both;
(ii) Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (including fiscal incentives);
(iii) a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;
(iv) a Government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i) to (iii) above which would normally be vested in the Government and the practice in, no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or
(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase export of any article from, or to reduce import of any article into, its territory, and a benefit is thereby conferred."

59. Additionally, Section 9(3) read with section 9(1) and section 9 (2) of the Customs Tariff Act suggests that for a subsidy to be countervailable, it must be for a limited number of persons engaged in the manufacture, production or export of articles.

60. Rule 7(8) of the CVD Rules allows the Authority to rely on 'facts available' in the event the exporters fail to cooperate in the investigation. In this regard, it states:

"In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstance."

F.3.1 Programs Found to be Countervailable

List of schemes identified in the form of provision of goods/services for Less Than Adequate Remuneration ("LTAR")

Program 1 - Supply of Limestone at LTAR

61. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The allegation of "supply of limestone at less than adequate remuneration" is either not applicable to individual entities on facts or not a countervailable subsidy in law.
ii. The domestic industry has not discharged the burden of establishing the essential elements of a countervailable subsidy, namely financial contribution, benefit, and specificity, and has also proposed an incorrect benchmark for examining adequacy of remuneration.
iii. One responding producer/exporter submitted that the alleged programme does not apply to it because it does not purchase limestone in lump form at all. It submitted that it procures commercially available calcium carbonate ($CaCO_3$) powder from independent suppliers at market prices, supported by purchase invoices, long-term purchase agreements and supplier certificates. It submitted that it does not have any facility to convert limestone into $CaCO_3$ powder and, therefore, the alleged "limestone export tax" cannot be linked to its raw material procurement or production methods.

iv. The said party further submitted that the domestic industry's allegation is factually misplaced because the product purchased by it is $CaCO_3$ powder classifiable under HS 2517.41.00.10, whereas limestone is covered under HS 2521 00 00.

v. It submitted that $CaCO_3$ powder is subject to export tax of 5%, which has remained unchanged during the POI, and contended that it is illogical to assume that such export tax on $CaCO_3$ powder could depress domestic prices to the advantage of downstream producers.

vi. It also submitted that the $CaCO_3$ powder supplied to it is produced from white stone/marble and not from limestone, and therefore the Government of Vietnam has not made available the relevant input at LTAR to it. On this basis, it submitted that the programme should be treated as not applicable to it.

vii. Other parties submitted that the domestic industry has failed to provide any evidence to establish that Vietnam's export tax on limestone constitutes a subsidy under Article 1.1 of the SCM Agreement. They submitted that a subsidy requires (i) a financial contribution by the government or public body and (ii) a benefit conferred, and further that the subsidy must be specific under Article 2 to be countervailable.

viii. They submitted that the domestic industry has not provided evidence satisfying these requirements and, in particular, has not established that an export tax can be equated to a government financial contribution.

ix. They submitted that an export tax or levy is a regulatory fiscal measure and does not involve any transfer of funds, government revenue foregone, or government provision of goods to enterprises. They submit that the theory advanced by the domestic industry that an export tax allegedly creates surplus domestic supply and hence lowers domestic prices cannot be treated as a government "financial contribution" and cannot substitute for proof of governmental action amounting to a financial contribution under the SCM Agreement and CVD Rules.

x. In support, reliance was placed on WTO jurisprudence to submit that the reaction of private entities to a government measure, or the economic effects of regulation (including export restraints/taxes), cannot by itself establish "entrustment or direction" or a "financial contribution" under Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM. They relied on the reasoning in WTO disputes cited by them, including US – Export Restraints (DS194) and US – Softwood Lumber, to submit that export restraints or taxes cannot be treated as government-entrusted or directed provision of goods and that entrustment/direction requires a demonstrable governmental link to private conduct, not merely market effects.

xi. They also relied on WTO panel reports cited by them, including European Union – Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia (DS618) and European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (DS616), to submit that entrustment/direction requires evidence of government action that effectively denies suppliers the freedom to sell freely and that mere regulatory intervention or export measures affecting domestic pricing or supply is insufficient.

xii. They submitted that limestone suppliers in Vietnam retain commercial discretion to sell domestically or export, to sell to multiple sectors, and are not mandated to provide limestone to producers of the product under consideration or at any particular price, thereby failing the "demonstrable link" test.

xiii. The other interested parties further submitted that, even assuming arguendo the existence of a financial contribution, the domestic industry has not demonstrated that any benefit was conferred on producers of the subject goods. They relied on WTO jurisprudence to submit that benefit must be shown to be actually received by a recipient and must be examined both in nature and extent.

xiv. They contended that the domestic industry has not provided evidence showing that any producer procured limestone at below-market prices during the POI compared to an

appropriate benchmark, or that the export tax resulted in actual reduction of input cost for the producers of the subject goods.

xv. With respect to specificity, the other interested parties submitted that limestone is a multi-use mineral used across numerous sectors (including cement, steel, mining, paper, water treatment and other industries) and therefore any export tax measure cannot be presumed to be limited to or designed for the benefit of PUC producers.

xvi. They contended that there is no explicit limitation of access to any alleged benefit to certain enterprises or industries within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement. They further submitted that, in terms of Article 8.1, a non-specific subsidy is non-actionable and cannot be countervailed.

xvii. The Government of Vietnam, through TRAV, has also submitted that the allegation does not constitute a subsidy programme under the SCM Agreement. It submitted that an export tax is a fiscal regulatory measure and does not fall within the exhaustive list of "financial contributions" under Article 1.1(a)(1) and that the Government does not provide limestone, control domestic pricing, or supply limestone at a discount.

xviii. It submitted that, in the absence of a financial contribution, there can be no subsidy, and therefore no countervailing duty can be imposed under the alleged programme. It further submitted that no WTO Member investigating authority has treated an export tax as a subsidy in an anti-subsidy investigation.

xix. Certain producers/exporters submitted that their raw material procurement is from private suppliers at arm's length, at prices determined through competitive negotiations in a competitive market. They submitted that there is no government intervention in purchase transactions and, therefore, the test of benefit under Article 14(d) is not satisfied. They further submitted that DGTR's past practice recognises that market-based purchases cannot be treated as countervailable subsidies.

xx. The other interested parties submitted that the domestic industry's benchmark proposal is flawed. They submitted that the domestic industry proposes to use Malaysia FOB export prices for HS 2521, which covers a heterogeneous basket of calcareous products and not necessarily comparable limestone lumps relevant to the producers' input.

xxi. They submitted that the domestic industry's own benchmark data contains extreme outliers across destinations, which indicates product mix, misclassification, or other distortions, and cannot be treated as "prevailing market conditions" under Article 14(d). They also submitted that the export tax alleged by the domestic industry applies to limestone (HS 2521) and not to processed $CaCO_3$ products (HS 2517 / 3824), and therefore any attempt to benchmark or compute benefit using $CaCO_3$ prices is legally impermissible.

xxii. In place of Malaysia FOB benchmarks, one responding exporter submitted that an appropriate benchmark would be Indian import prices of limestone lumps, stated to be the precise form procured by a responding exporter.

xxiii. For this purpose, interested party has provided a transaction-wise summary of imports into India during the POI, showing an average import price from United Arab Emirates accounting major source of supply with smaller volume from other countries. On this basis, it submitted that UAE prices are representative of prevailing international prices.

xxiv. The interested parties also submitted that the stated rationale for Vietnam's export duty on limestone is resource conservation and prevention of over-exploitation of natural resources, and not to ensure supply at LTAR. They submitted that the Government does not itself supply limestone and that limestone is supplied by private vendors.

xxv. They further submitted that limestone is naturally occurring and is also available in India, and that India imports limestone from several countries, which can serve as a verifiable benchmark, and that reliance on third-country export price data is unwarranted.

xxvi. Certain interested parties submitted that any attempt to infer a pass-through from upstream measures on limestone to downstream pricing of $CaCO_3$ or masterbatch is speculative. They submitted that an export tax could, depending on market conditions, lead to different

price outcomes and that no empirical evidence has been provided demonstrating sustained domestic suppression relative to an undistorted benchmark after appropriate adjustments. They further submitted that any pass-through analysis is not automatic and must be supported by evidence, which is absent.

xxvii. The other interested parties submitted that, for the purpose of benefit computation, it is not permissible to compute benefit against $CaCO_3$ when the alleged measure pertains only to limestone, and that benefit, if any, must be tested only against limestone lumps. They contended that there is no allegation regarding direct provision of $CaCO_3$ by the Government and therefore no benefit can be computed against $CaCO_3$.

xxviii. On the basis of the above, the other interested parties request the Authority to reject the domestic industry's allegations under this programme, to reject the benchmark proposed by the domestic industry, and to determine that the alleged measure does not constitute a countervailable subsidy and/or is not applicable to the responding producers/exporters.

xxix. The GOV respectfully submits that the DGTR's findings are inconsistent with Articles 1, 2, and 14(d) of the SCM Agreement. The GOV respectfully disagrees with the conclusion that the alleged program is specific to downstream industries using limestone or calcium carbonate as principal raw materials. Limestone is a widely used multi-purpose mineral consumed across numerous industries, including cement, steel, paper, plastics, paints, rubber, water treatment, mining, construction, fertilizers, food, pharmaceuticals, and other sectors. Decree No. 26/2023/ND-CP is a generally applicable resource management measure applicable to all entities engaged in the extraction and export of limestone and does not provide any benefit exclusively to the masterbatch or PUC sectors.

xxx. The policy objective of the measure is the conservation of natural resources, the prevention of over-exploitation and depletion of non-renewable resources, environmental protection, and sustainable development, rather than the provision of targeted support to downstream industries. Accordingly, the GOV respectfully submits that the program does not exhibit either de jure or de facto specificity within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement.

xxxi. The GOV further respectfully submits that no "financial contribution" exists within the meaning of Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement. The interpretation adopted by the DGTR appears to equate export duties and regulatory measures with "entrustment or direction" of private bodies and directly contradicts established WTO jurisprudence, including United States – Export Restraints and European Union – Countervailing Duties on Biodiesel from Indonesia. These WTO reports confirm that export restraints or export duties do not constitute government entrustment or direction merely because they may affect market conditions. The GOV further notes that, although the Panel Report in European Union – Countervailing Duties on Biodiesel from Indonesia is currently subject to an "appeal into the void," the report remains the most recent and authoritative interpretation of Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement. Since the Appellate Body is non-operational, such appeals do not invalidate or overturn panel findings, and WTO Members have continued to rely on reports under "appeal into the void" as persuasive legal authority.

xxxii. The limestone suppliers retain full commercial discretion regarding pricing, customers, and sales. Any domestic price effects therefore reflect ordinary market dynamics rather than government delegation or command through evidence-based economic analysis. The DGTR did not conduct a pass-through analysis, regression analysis, cost build-up analysis, or transaction-level comparison demonstrating that export duties on limestone translated into lower prices for processed calcium carbonate powder.

xxxiii. The GOV further respectfully submits that limestone and processed calcium carbonate powder are distinct products with different classifications, production processes, characteristics, cost structures, and end uses. Limestone is a raw natural mineral primarily used in cement and steel industries, whereas calcium carbonate powder is a processed

industrial product requiring crushing, grinding, classification, drying, packaging, surface treatment, and quality control for use in plastics, paints, paper, and masterbatch production. Export duties apply only to raw limestone and not to processed calcium carbonate products. The GOV therefore respectfully submits that the DGTR improperly conflated raw limestone with processed calcium carbonate products and assumed, without sufficient evidentiary basis, that any alleged upstream distortion is automatically transmitted to downstream products. The GOV further notes that the DGTR effectively adopted a multi-layer pass-through theory without conducting any pass-through analysis at any level, contrary to Articles 1.1(b) and 14(d) of the SCM Agreement and established WTO jurisprudence.

xxxiv. The Malaysian benchmark selected by the DGTR concerns chemically processed calcium carbonate products classified under HS code 283650, whereas Vietnamese producers use natural ground calcium carbonate classified under HS code 251741. These products differ materially in production methods, characteristics, cost structures, purity levels, and market uses. The GOV therefore respectfully submits that the selected benchmark does not appropriately reflect prevailing market conditions in Viet Nam and results in a distorted comparison and an inflated calculation of the alleged benefit. The GOV further notes that the DGTR did not sufficiently demonstrate comparability in terms of quality, production conditions, economies of scale, logistics, trade patterns, or competitive conditions between Malaysia and Viet Nam.

xxxv. The GOV also respectfully notes that, given India's formal recognition of Viet Nam as a market economy, the DGTR is not entitled to reject domestic prices and replace them with surrogate out-of-country benchmarks. Such an approach is inconsistent with the recognition of Viet Nam as a market economy and effectively amounts to the application of a surrogate-value methodology, which is not permissible in this context.

xxxvi. The respondents submitted that the alleged export tax on limestone cannot be treated as a countervailable subsidy, as it does not constitute a "financial contribution" under Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement. There is no evidence that the Government of Vietnam entrusted or directed private suppliers to provide limestone or calcium carbonate to producers of the subject goods at a particular price. Mere export restraint or market effect of a regulatory measure cannot be equated with Government direction, as recognised in WTO jurisprudence.

xxxvii. The respondents further submitted that the Authority has not established any "benefit", since no transaction-level analysis, cost analysis or company-specific examination was conducted to show that inputs were procured below prevailing market prices. Companies such as VMI, Vitaplas and ADC stated that their calcium carbonate inputs were purchased from independent private suppliers on arm's length, commercially negotiated terms, without Government involvement or preferential treatment.

xxxviii. A major objection concerns the incorrect treatment of limestone lumps and calcium carbonate powder as the same product. The respondents submitted that limestone lumps are raw mineral rocks, whereas $CaCO_3$ powder is a processed, value-added industrial input, with different HS classifications, characteristics, impurity levels, uses and prices. Since the alleged export tax applies to limestone and not to $CaCO_3$ powder, $CaCO_3$ cannot be used as the relevant benchmark where the producer has used limestone lumps.

xxxix. The Disclosure Statement dated 20.03.2026 is not compliant with Rule 18 of the Subsidy Rules as evidenced from the following facts. The disclosure statement is woefully silent on many of the key issues raised by the respondents. Some of the key issues include:

a) Test of "Entrustment" / "Direction" provided in Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 and Article 1.1(a)(1)(iv) of ASCM to consider export tax as financial contribution has not been carried out.

b) The disclosure statement dated 20.03.2026 has not examined the issue that economic effects cannot be conflated as the government "giving responsibility to

(Entrustment)" or "exercising authority over (Direction)" a private body to provide goods. A reaction of the private entities to a government measure (like export tax) cannot be the basis of a determination of financial contribution by the government.

c) No evidence provided or proposal made in the Disclosure Statement dated 20.03.2026 to show that the Government of Vietnam directed the suppliers of Limestone Lumps to provide Limestone Lumps to the manufacturers of the subject goods or at a particular price.

d) The suppliers of Limestone Lumps have complete freedom to sell their products in the domestic market to the manufactures of subject goods / non-subject goods / downstream industries, captive use or exports.

e) Following WTO Appellate Body and Panel Reports clearly established that entrustment/direction requires more than mere regulatory intervention affecting private behaviour, there must be evidence of government action whose object is to impose a "type of function" on private bodies, denying them freedom to operate commercially. General economic effects, such as export restraints influencing domestic supply or pricing, do not suffice, as "a government would not be considered to entrust or direct a private party in situations where a private party's behavior is merely affected by the regulatory framework in which it operates.

   a) Appellate Body Report in US – Countervailing Duty on DRAMS
   b) WTO Panel Report (WT/DS618/R dated 22 August 2025) - European Union – Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia
   c) WTO Panel Report (WT/DS616/R dated 02 October 2025) - European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia"

f) Findings of the Australian Commission in the case of Aluminium Zinc Coated Steel of a Width Equal to or Greater Than 600 Millimetres from Vietnam has not been examined in the Disclosure Statement dated 20.03.2026, despite the fact that it is directly applicable to the facts and issues involved in this case.

g) "Explicit" test to consider export tax as specific has not been carried out.

xl. Without prejudice to the aforesaid, most of the key issues raised by the respondents have not been properly examined or addressed in the disclosure statement dated 20.03.2026, which the Authority is obligated to do under the Rules.

xli. The respondent submitted that the benchmark adopted by the Authority is fundamentally flawed, as the respondent used limestone lumps for manufacture of the PUC and not $CaCO_3$ powder. Once the Authority itself recognised that benchmarking must be undertaken with reference to the "relevant good" under Article 14(d), the relevant good in the present case ought to have been limestone lumps, particularly when the alleged export restriction / tax is on limestone and not on calcium carbonate.

xlii. It was further submitted that the Disclosure Statement dated 20.03.2026 itself records that where a producer purchases $CaCO_3$ powder, a $CaCO_3$ benchmark may be appropriate, and where a producer uses limestone lumps, a limestone-based benchmark is required. Despite this admitted position, the Authority proposed to apply Malaysian $CaCO_3$ export prices to the respondent, apparently on the incorrect assumption that all participating exporters purchased $CaCO_3$ powder directly. Since the respondent admittedly used limestone lumps, adoption of $CaCO_3$ as benchmark is factually incorrect and legally unsustainable.

xliii. The respondent also submitted that limestone lumps and $CaCO_3$ are distinct products. Limestone is a natural rock containing impurities, whereas $CaCO_3$ is a processed, value-added chemical product. They fall under different HS classifications, have different

characteristics, processing levels and prices, and the domestic industry itself provided separate Malaysian FOB benchmarks for limestone and $CaCO_3$. Therefore, $CaCO_3$ cannot be treated as the relevant benchmark merely because both may contain calcium carbonate.

xliv. Accordingly, since the allegation concerns provision of limestone lumps at less than adequate remuneration and not provision of $CaCO_3$, the subsidy margin, if any, must be determined only with reference to limestone lumps. At the highest, only the limestone component embedded in processed $CaCO_3$, after appropriate adjustment for processing costs, could be considered. The use of $CaCO_3$ benchmark without such adjustment is therefore erroneous in principle, fact and law.

UAE wrongly rejected as benchmark

xlv. Further, in paragraph 121 itself, the Authority observes *"that the import of limestone from UAE is primarily used for steel industry and cement industry and not by the PUC producers"*. It is submitted that the said statement is not based on any concrete information or analysis but it seems that the Authority has chosen to accept the contention of the domestic industry without seeking any substantiation or supporting evidence. The respondent submits as follows in this context:

a) The Imports of Limestone Lumps from UAE is also used in the manufacture of the subject goods. The applicant industry has not provided any evidence to shows that Limestone Lumps imported from UAE is not used for the manufacture of the subject goods.
b) The adjustments claimed in the CIF price to determine the FOB price are either taken based on the application or as per the consistent practice followed by the Authority.
c) The Authority may, at best, apply the best available information on the missing information and cannot totally reject the eight-digit level transaction wise segregated imports data submitted by the respondent which is also validated by the eight-digit level import data available on the website of the Ministry of Commerce.

xlvi. Without prejudice, the Authority may consider average import prices to India of Limestone Lumps from all sources after making appropriate adjustments. The Authority may consider the eight-digit level transaction-wise import data of Limestone Lump duly corroborated with the Ministry of Commerce data for the purpose of benchmarking.

xlvii. Without prejudice, it is submitted that even if the prices from UAE to India are not found acceptable by the Authority for benchmarking purposes of limestone lumps, there is no reason as to why the Authority should ignore the data filed by the respondent with respect to the "relevant good" i.e., limestone lumps on which it is alleged that countervailable subsidy has been provided by the Vietnam government.

xlviii. It may not be out of place to mention that it is clear from the disclosure statement dated 20.03.2026 that the Authority has no difficulty in accepting the specific import data supplied by the exporter for limestone lumps at the 8-digit level for the relevant good i.e., limestone lumps except its apprehension that such data may understate the "true economic value" of the actual input used by the PUC producers in the absence of *"appropriate processing adjustments and verifiable evidence supporting each cost deduction"*. With respect, it is submitted that the above statement is bereft of any factual substance for the following reasons:

a) Malaysia FOB export prices for products classified at the 4-digit HS Code 2521 level, which aggregates limestone, limestone flux and other calcareous stones used, inter alia, for manufacture of lime or cement.
b) The cited FOB prices, range from about USD 28/MT to USD 5143672/MT, relate to a broad, heterogeneous product basket that is neither identical nor even sufficiently comparable to the material relevant to the subject goods

c) Reasons for rejecting the respondent's proposal to consider the eight-digit level segregated transaction wise Indian import data of Limestone Lumps duly validated by the eight-digit level import data available on the website of Ministry of Commerce for determining benchmark are superficial.

d) A comparative summary of the import data procured by the respondent from secondary source, import data available on the website of Ministry of commerce and trade map data filed by the applicant industry vide our submissions dated 10 March, 2026 shows that the raw / unsegregated import data reported on the website of Ministry of Commerce including limestone lump is comparable to the raw / unsegregated import data submitted by the respondent. The average price of major suppliers (countries) is also in the same range.

e) The proposed data is at the 8-digit level as against the data proposed to be used by the Authority which is at the 4-digit level and includes limestone, limestone flux and other calcareous stones used, inter alia, for manufacture of lime or cement.

f) The data provided by the exporter has been fully corroborated by the information available on the website of the Ministry of Commerce & Industry.

g) The Authority's observation that there is no "verifiable evidence in respect of processing adjustments", is completely incomprehensible as the data itself relates to the relevant product namely, limestone lumps and, therefore, there is no question of making any processing adjustments whatsoever.

Four-digit level FOB export price from Malaysia of Limestone Lumps to India claimed by the applicant industry is higher than the CIF import price from Malaysia of Limestone Lumps to India

xlix. It may not be out of place to mention that the Authority's proposal to take the data at the 4-digit level (raw / unsegregated import data from Trade Map) has led to an absurd proposition wherein the proposed benchmark of FOB price from Malaysia to India is USD 43/MT while the segregated transaction wise data for the "relevant good" i.e., Limestone Lumps at the 8-digit level shows the CIF price of imports from Malysia itself as about USD 41/MT. It may be noted that the CIF import price from Malaysia of Limestone Lumps to India claimed by the respondent is based on eight-digit level transaction-wise segregated import data which is duly corroborated with import data from Ministry of Commerce.

l. It also clearly shows that the four digit level raw / unsegregated FOB data taken from Trade Map by the applicant industry is incorrect and cannot be relied upon as it includes heterogeneous products.

Proposal made in the Disclosure Statement dated 20.03.2026 to consider export price from Malaysia as an appropriate benchmark is wrong and misplaced

li. The proposal made in the Disclosure Statement to consider Malaysian export price as appropriate benchmark on the ground that external benchmark most reasonably reflects undistorted prevailing market conditions for the relevant good, after suitable adjustments, is completely misplaced and erroneous. It may be noted that in plethora of investigations, the Hon'ble Authority has considered the international prices and not the prices prevailing in the neighboring country. The list of the illustrative cases is provided below for the ease of reference of the Authority.

Sl. No	Name of Investigation	F. No. & Date	Benchmark Considered	Comment
1	Fiberboards	F. No.	Para 71 of FF - Export price of log	International

	from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and Sri Lanka	06/17/2019-DGTR dated 03 May 2021	from New Zealand has been considered as an appropriate benchmark being the largest exporter.	prices considered and not the price prevailing in the neighboring country of the subject country
2	Atrazine Technical from China PR	F. No. 6/19/2018-DGAD 22 August, 2019	Para 56 – International prices of Cyanuric chloride and Caustic soda considered as an appropriate benchmark price.	
3	Saturated Fatty Alcohol from Indonesia, Malaysia, and Thailand	F. No. 6/18/2021-DGTR dated 07 February 2023	Para 56 - CPKO CIF Rotterdam prices have been considered as an appropriate international benchmark price.	

liii. The Limestone subsidy margin proposed in the disclosure statement dated 20.03.2026 based on the misleading information filed by the applicant industry is incorrect as CaCO3 benchmark has been considered instead of Limestone benchmark.

liii. An Tien has submitted that the Domestic Industry has proposed a Benchmark Price both for Limestone Lumps as well as CaCO3 which happens to be more than three times the purchase price even though the extent of alleged subsidization in the form of export tax is a mere 30%. Even assuming but not accepting that the entire extent of export tax of 30% can be considered as countervailable subsidy (which indeed would be in stark contradiction to the established jurisprudence on the issue), the benchmarking price of more than 300%, would be ex facie absurd. Unfortunately, the disclosure statement dated 20.03.2026 seems to have ignored this basic fact and allowed itself to be completely misled by the Domestic Industry. This reinforces our averment that even if the export tax is to be considered as countervailable subsidy, the benchmarking has to be done only and only for the "relevant good", which in this case is Limestone Lumps and NOT CaCO3. Unfortunately, this position has been enunciated by the Authority itself in paragraph 116 but not followed while proposing the benchmark price.

62. <u>The following submissions have been made on behalf of the domestic industry</u>:

i. The domestic industry submitted that limestone is the primary raw material used for manufacturing calcium carbonate ($CaCO_3$), which constitutes approximately 70–85% of the total raw material input used in the production of the PUC.

ii. It submitted that, as per the WTO Trade Policy Review of Vietnam, the Government of Vietnam levies export taxes on certain products, including minerals. In this regard, Vietnam has imposed export taxes on limestone under Decree No. 26/2023/ND-CP.

iii. Limestones are classified under HSN Code 2521 00 00, covering limestone-based melting agents and other calcareous stones used for the manufacture of lime or cement. The applicable export tax rates imposed by Vietnam on limestone have increased progressively over time and are tabulated as follows:

Period	**Rate of Export Tax**
01-01-2020 to 30-06-2022	17%
01-07-2022 to 30-06-2023	20%
01-07-2023 to 30-06-2024	25%
01-07-2024 onwards	30%

iv. The domestic industry submitted that the imposition of increasing export taxes discourages exports of limestone from Vietnam and restricts its availability in international markets. This results in increased domestic supply and downward pressure on domestic prices of limestone and limestone-derived calcium carbonate in Vietnam.

v. It is submitted that the Government of Vietnam has acknowledged that the objective of the export tax policy is to regulate exports, conserve natural resources, and improve efficiency of downstream industries using limestone domestically. The policy framework is aimed at limiting exports of raw and unprocessed minerals and promoting downstream value addition within Vietnam.

vi. Through the export tax regime and associated regulatory framework, limestone is made available to domestic downstream producers, including producers of the PUC, at prices below international levels. This constitutes provision of goods at less than adequate remuneration within the meaning of Article 14(d) of the SCM Agreement and Rule 12(2)(d) of the CVD Rules.

vii. The domestic industry noted that the Respondents have argued that financial contribution, benefit, and specificity have not been established and have relied on WTO panel reports to contend that export taxes or restraints cannot amount to a financial contribution merely based on market effects. They have also challenged the benchmark proposed by the domestic industry and proposed alternate benchmarks based on Indian import prices or UAE prices with adjustments.

viii. The domestic industry submitted that, under Article 1.1 of the SCM Agreement, a subsidy exists where a government makes a financial contribution and a benefit is conferred. In terms of Article 1.1(a)(1)(iv), a financial contribution may arise where a government entrusts or directs a private body to carry out functions such as provision of goods, even indirectly, where the practice does not meaningfully differ from typical government practices.

ix. It submitted that an export tax discourages exports by increasing their cost, diverts supply to the domestic market, and suppresses domestic prices below international market levels. In such circumstances, the government effectively entrusts or directs private suppliers to supply the product domestically at suppressed prices, resulting in provision of goods at LTAR to downstream users.

x. The domestic industry submitted that export taxes are often instruments of a broader policy framework aimed at retaining raw materials domestically, stabilizing domestic prices, and promoting downstream value-added industries. In Vietnam, limestone is subject to licensing, extraction controls, and export regulation, which collectively influence domestic supply and pricing conditions.

xi. Where government policy is designed, explicitly or implicitly, to promote domestic downstream industries by ensuring availability of raw materials at lower or stabilized prices, the Authority is required to examine whether such intervention results in domestic prices that no longer reflect prevailing market conditions, as required under Article 14(d).

xii. The domestic industry submitted that the reliance placed by the Respondents on WTO jurisprudence to argue that export taxes can never amount to a financial contribution is misplaced. WTO panels have consistently held that subsidy determinations are fact-specific and depend on the design, operation, and effects of the measures concerned.

xiii. The domestic industry relied on the Authority's own settled practice. In the countervailing duty investigation concerning Digital Offset Printing Plates, the Authority examined export restraints on an upstream raw material and held that export tariffs and fiscal measures discouraged exports, increased domestic supply, suppressed domestic prices, and resulted in provision of goods at LTAR to downstream industries.

xiv. In that investigation, the Authority rejected the argument that no subsidy could exist merely because inputs were purchased from private suppliers. The Authority held that

government intervention through export tariffs and fiscal policies can distort domestic pricing and confer a benefit, irrespective of the identity of the supplier.

xv. Similar findings were recorded by the Authority in investigations concerning Saturated Fatty Alcohol and Continuous Cast Copper Wire Rods, where export restraints on upstream raw materials were treated as countervailable subsidies.

xvi. The domestic industry submitted that the same legal principles apply in the present investigation. Vietnam's export tax regime on limestone is designed to retain mineral resources domestically and promote downstream industries, thereby distorting domestic pricing of limestone-derived calcium carbonate.

xvii. The objection raised by certain parties that the program is not applicable because they do not purchase limestone lumps but instead purchase calcium carbonate powder is misconceived.

xviii. The allegation is not limited to direct purchase of limestone lumps but concerns distortion of the downstream input market resulting from government measures affecting the upstream limestone market.

xix. Calcium carbonate is derived from limestone and forms a principal raw material for the PUC. Ground calcium carbonate (GCC) powder is produced by crushing limestone, particularly high-purity limestone deposits with calcium carbonate content exceeding 98%, which are widely available in Vietnam.

xx. Publicly available information from Vietnamese suppliers confirms that ground calcium carbonate is commercially referred to as "limestone powder" and originates from limestone deposits. Limestone and calcium carbonate powder are therefore part of the same mineral value chain and are functionally equivalent inputs for industrial use in the masterbatch sector.

xxi. Consequently, government measures affecting the availability and pricing of limestone logically affect the domestic supply and pricing of limestone-derived calcium carbonate, even where producers procure the processed derivative rather than the raw mineral.

xxii. The domestic industry submitted that reliance on HS classification alone is not determinative for subsidy analysis. The relevant inquiry under the SCM Agreement and the CVD Rules is whether government intervention results in provision of a good at LTAR and confers a benefit, regardless of whether the input is procured under one tariff heading or another.

xxiii. The submission that calcium carbonate is derived from marble or white stone and not limestone is technically incorrect. From an industrial and geological perspective, limestone is the primary source for GCC used in masterbatch production. Marble is a higher-value metamorphic stone and is commercially unsuitable and uneconomical for use as a filler in polymer masterbatch applications.

xxiv. Limestone-derived GCC is preferred in the masterbatch industry due to its suitability for controlled particle size, dispersion, whiteness, and compatibility with polymer matrices. Vietnamese suppliers themselves market GCC products as limestone-derived material.

xxv. The fact that certain parties do not have facilities to convert limestone into calcium carbonate powder is irrelevant. The alleged benefit accrues through the price of calcium carbonate powder purchased in Vietnam, and the relevant inquiry is whether that price reflects prevailing market conditions or is distorted by government intervention in the upstream limestone market.

xxvi. The domestic industry submitted that specificity exists because the alleged benefit accrues predominantly to industries using limestone or calcium carbonate as inputs, including producers of the PUC. Specificity does not require exclusive use by PUC producers but may be established de facto based on predominant beneficiaries and market structure.

xxvii. The domestic industry further submitted that reliance placed by the Respondents on the WTO Panel Report in EU – Biodiesel (DS618) is misplaced, as the report is under

appeal and does not represent a final or settled interpretation of WTO law. In any event, investigating authorities are required to apply the SCM Agreement and domestic law to the facts on record and are not bound to mechanically adopt panel reasoning.

xxviii. In contrast, the Authority's own findings in concluded investigations, including Digital Offset Printing Plates and Saturated Fatty Alcohol, constitute settled domestic practice and are directly relevant to the present case.

xxix. The domestic industry submitted that domestic prices in Vietnam cannot be treated as an appropriate benchmark for determining adequacy of remuneration, as such prices are distorted by government intervention. In circumstances where in-country prices are distorted, WTO law permits the use of an external benchmark.

xxx. For this purpose, the domestic industry submitted that the FOB export prices of limestone or calcium carbonate from Malaysia constitute an appropriate benchmark. Malaysia is a major supplier of comparable material in the same region, has similar geological limestone deposits, and operates under market-oriented conditions without comparable export restraints.

xxxi. The benefit under the program should therefore be calculated as the difference between the benchmark price and the price at which limestone or calcium carbonate is procured or captively consumed by Vietnamese producers of the PUC during the POI.

xxxii. The domestic industry submitted that the benchmark proposed by the other parties based on UAE prices is flawed because $CaCO_3$ production in the UAE is largely based on marble waste rather than sedimentary limestone, resulting in a fundamentally different cost structure and market dynamics.

xxxiii. Malaysia, by contrast, has sedimentary limestone deposits comparable to Vietnam, produces high-purity calcium carbonate from limestone, operates under market-oriented conditions, and is a major exporter of $CaCO_3$ to global markets, including India particularly used by the masterbatch industry. Export prices from Malaysia therefore reflect undistorted market conditions and are suitable for benchmarking.

xxxiv. The selection of Malaysia is the appropriate reference country, taking into account similarity of raw material, product characteristics, processing stage, availability of data, and absence of comparable export restraints.

xxxv. The claim that the alleged program is "not applicable" to certain producers is premature and cannot be accepted without examination of questionnaire responses, verification of input sourcing, pricing, and assessment of whether domestic prices reflect distorted market conditions.

The Authority has examined the submissions below:

Financial Contribution

63. The Authority notes that the Government of Vietnam has imposed export taxes on limestone under Decree No. 26/2023/ND-CP with rates progressively increasing and reaching 30% during the POI. Limestone is a natural mineral resource, extraction and export of which in Vietnam is subject to licensing, regulatory oversight, and fiscal control by the Government.

64. The Authority notes that limestone constitutes the principal upstream raw material for the production of calcium carbonate ($CaCO_3$), which in turn accounts for a substantial proportion of the raw material consumption in the manufacture of the PUC. The Authority further notes that the export tax is expressly designed to discourage exports of raw limestone and retain the mineral within Vietnam.

65. The Authority has examined whether such export tax measures, viewed in isolation or in conjunction with the broader regulatory framework governing mineral resources, can constitute a financial contribution within the meaning of Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 12 of the CVD Rules and Article 1.1(a) of the SCM Agreement.

66. While the Authority notes the submissions of the Government of Vietnam and certain exporters that an export tax is a regulatory measure and does not involve a direct transfer of funds or direct provision of goods, the Authority considers that Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement recognizes that a financial contribution may also exist where the government, through a set of measures, effectively causes private bodies to perform functions that would normally be vested in the government, including provision of goods, where such conduct does not meaningfully differ from normal government practice.

67. In the present case, the Authority notes that limestone is a state-controlled natural resource and that the export tax regime operates in a manner that restricts exports, alters supply conditions, and materially influences domestic availability and pricing of limestone and limestone-derived inputs. The Authority further notes that the Government of Vietnam, in its responses, has acknowledged that the policy objective of the export tax is to regulate exports of limestone and improve efficiency of downstream industries.

68. The Authority considers that such regulatory and fiscal measures, when examined cumulatively, constitute affirmative government action that alters the conditions under which limestone is supplied in the domestic market. The resulting domestic supply conditions are not the outcome of free market forces alone but are shaped by government intervention in the form of export taxation and mineral policy.

69. Export restraints such as export taxes constitute a financial contribution within the meaning of Section 9(1) of the Customs Tariff Act, 1975 because they are an indirect transfer of funds. This position has been affirmed by the Authority in investigations concerning various products such as “Saturated Fatty Alcohol” from Indonesia, Malaysia and Thailand and “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, “Digital Offset Printing Plates” (DOPP) originating in or exported from China PR and Taiwan.

70. With regard to the argument that purchase are made from private suppliers, and not from the government, the Authority notes that the Government of Vietnam exercises its authority over private bodies through its regulatory mechanism specifically, the export restraints imposed by the GOV, such as the 30% export tariff, to compel them to provide limestone to the downstream industries at a cheaper price. By artificially suppressing domestic prices for limestone, these measures significantly distort the limestone market in Vietnam and provides downstream manufacturers of PUC with limestone at LTAR. Consequently, even private suppliers benefit from these state-backed measures.

71. In view of the above, the Authority concludes that the export tax and regulatory framework governing limestone in Vietnam constitute a financial contribution by the Government of Vietnam within the meaning of Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 12 of the CVD Rules and Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement, as the Government, through its measures, effectively influences the provision of a key raw material to downstream industries in the domestic market.

Benefit

72. The Authority notes that, in terms of Article 1.1(b) of the SCM Agreement and Rule 12 of the CVD Rules, a subsidy exists only if a financial contribution confers a benefit on the recipient. Article 14(d) of the SCM Agreement provides that, where goods are provided by the government or through its intervention, the adequacy of remuneration shall be determined in relation to prevailing market conditions in the country of provision.

73. The Authority has examined whether the financial contribution identified above has resulted in limestone or limestone-derived $CaCO_3$ being made available to producers of the PUC at remuneration below what would prevail under undistorted market conditions.

74. The Authority notes the domestic industry's contention that the export tax discourages exports of limestone, increases domestic availability, and suppresses domestic prices of limestone and $CaCO_3$ below international levels. The Authority also notes the exporters' submissions that certain producers purchase $CaCO_3$ powder from private suppliers, that HS codes differ, and that no direct government price control exists.

75. The Authority considers that the relevant inquiry under Article 14(d) is not limited to whether the government directly supplies goods, but whether the price paid for the relevant input reflects prevailing market conditions. The Authority further considers that purchasing inputs from private suppliers does not preclude the finding of benefit where domestic prices are themselves distorted due to government intervention upstream.

76. The Authority notes that $CaCO_3$ used in the manufacture of the PUC is also commercially referred to as "limestone powder" industrially derived from limestone and that the limestone and $CaCO_3$ markets are economically integrated. The Authority further notes that distinctions based solely on HS classification do not negate the upstream-downstream linkage for purposes of benefit analysis under the SCM Agreement.

77. The Authority finds that the export tax regime, by restricting exports of limestone, alters normal supply-demand equilibrium and results in domestic prices that do not reflect undistorted market conditions. Consequently, downstream producers using limestone-derived $CaCO_3$ obtain access to this input at prices lower than would prevail absent the government intervention.

78. In view of the above, the Authority concludes that the financial contribution by the Government of Vietnam confers a benefit on producers of the PUC, as limestone-derived inputs are made available at less than adequate remuneration within the meaning of Article 14(d) of the SCM Agreement and Rule 12(2)(d) of the CVD Rules.

Specificity

79. The Authority notes that, in terms of Article 2 of the SCM Agreement and Section 9 of the Customs Tariff Act, a subsidy is countervailable only if it is specific, either de jure or de facto, to an enterprise, industry, or group of enterprises or industries.

80. The Authority has examined the exporters' submissions that limestone is used across multiple industries and therefore the measure lacks specificity. The Authority notes that specificity does not require that the goods be used exclusively by the subject industry, but requires examination of whether the benefit accrues predominantly to certain industries or

is limited in practice.

81. The Authority notes that limestone and limestone-derived $CaCO_3$ are critical inputs for a defined group of downstream industries, including masterbatch producers. The Authority further notes that the policy objective of Vietnam's export tax regime is to retain mineral resources domestically and promote downstream value addition, which inherently favours industries consuming limestone/CaCo3 as a key input.

82. The Authority considers that industries not dependent on limestone/CaCo3 do not derive any benefit from the export tax regime, whereas industries using limestone/limestone derived inputs directly benefit from increased domestic availability and suppressed prices. The benefit is therefore limited in practice to a group of industries that use limestone and $CaCO_3$ as principal raw materials.

83. In view of the above, the Authority concludes that the subsidy arising from the provision of limestone at LTAR is specific, to industries using limestone-derived inputs, including producers of the PUC, within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement and Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975.

Benchmark

84. The Authority notes that, for determining benefit under Article 14(d) of the SCM Agreement and Rule 12(2)(d) of the CVD Rules, the adequacy of remuneration must be assessed in relation to prevailing market conditions for the goods in question in the country of provision. The Authority further notes that where in-country prices are distorted due to government intervention, an external benchmark may be used, subject to appropriate adjustments to ensure comparability.

85. In the present case, the domestic industry has submitted that domestic prices of limestone and limestone-derived calcium carbonate in Vietnam are not appropriate benchmarks, as the export tax regime on limestone discourages exports and alters domestic demand-supply equilibrium. The domestic industry has therefore proposed an external benchmark based on FOB export prices of $CaCO_3$ from Malaysia, asserting that Malaysia is a proximate, comparable supplier within the same region and that its prices reflect undistorted market conditions.

86. The Authority notes the submissions of the producers/exporters and certain other interested parties opposing the domestic industry's proposed benchmark on grounds that the export tax applies only to limestone, not to $CaCO_3$ powder; that Malaysia data at the 4-digit HS level mixes different stone products, reducing comparability; that Malaysian price data contains extreme outliers; and that the domestic industry has not actually shown distortion in Vietnam's domestic prices. They also propose an alternative benchmark based on Indian import prices of limestone lumps (mainly from the UAE), adjusted to derive an FOB price.

87. The Authority has examined the submissions made by all parties and finds that the benchmark exercise must be undertaken by identifying:

i. the relevant "good" whose remuneration is to be assessed under Article 14(d);

ii. whether domestic prices for that good in Vietnam reflect prevailing market conditions; and

iii. if not, which external benchmark most reasonably reflects undistorted prevailing market conditions for the relevant good, after suitable adjustments.

88. Although the program is described as "supply of limestone at LTAR," the Authority recognizes that the downstream manufacturing of the subject product uses $CaCO_3$ powder, which is itself produced from limestone or similar calcareous feedstock.

89. The Authority also notes that Vietnam's export tax on limestone is substantial and increasing, and aims to regulate exports and promote downstream processing. Based on that, the Authority finds it reasonable to treat Vietnamese domestic prices for limestone-derived inputs with caution and to consider external benchmarks.

90. The Authority evaluates the domestic industry's proposed Malaysian benchmark, noting Malaysia's role as a regional supplier of comparable high-purity $CaCO_3$ having highest exports to India during the POI. Further, the domestic industry is also procuring CaCO3 from Malaysia for producing PUC.

91. The Authority observes that most of the participating exporters purchase $CaCO_3$ powder directly rather than limestone lumps, therefore, the benchmark must assess whether the remuneration for $CaCO_3$ powder is adequate.

92. The Authority observes that the HS chapter difference of limestone and calcium carbonate reflects nomenclature or processing levels, but does not alter the chemical identity ($CaCO_3$) or subsidy analysis. It also examines the exporters' proposed benchmark based on Indian import prices of limestone lumps from UAE. It is noted that the calcium carbonate used for PUC production requires high-purity limestone, with finer particle size with calcium carbonate content exceeding 98%. The Authority observes that the import of limestone from UAE is primarily used by the steel industry and cement industry and not by the PUC producers. Further, the exporters' benchmark focuses solely on limestone lumps but does not account for the additional processing required to convert lumps into $CaCO_3$ powder. Without appropriate processing adjustments and verifiable evidence supporting each cost deduction, the exporters' benchmark may understate the true economic value of the actual input used by PUC producers.

93. The Authority therefore considers that a benchmark approach that relies on a comparative market with active exports of $CaCO_3$ / limestone-derived industrial inputs specifically for production of PUC, and that enables conversion to a comparable price basis, is more suitable for Article 14(d) purposes.

94. The Authority has taken into considering the following submissions made by the interested parties regarding reliability of the benchmark data (trade map) submitted by the applicants:

a) Malaysia FOB export prices proposed as benchmark by the applicants is classified at the 4-digit HS Code level, which includes other heterogeneous products.

b) The FOB prices proposed by the applicants range from about USD 28/MT to USD 5143672/MT, substantiates that the data includes a broad, heterogeneous product basket that is neither identical nor even sufficiently comparable to the material relevant to the subject goods.

c) A comparative summary of the import data procured by the interested parties at eight-digit level from secondary source, import data available on the website of Ministry of

commerce and trade map data filed by the applicant industry shows that the raw / unsegregated import data reported on the website of Ministry of Commerce including limestone lump and $CaCO_3$ is comparable to the raw / unsegregated import data submitted by the respondent. The average price of major suppliers (countries) is also in the same range.

d) The data proposed by the interested parties is at the 8-digit level as against the data initially proposed by the applicants which was at the 4-digit level and included limestone, limestone flux and other calcareous stones used, inter alia, for manufacture of lime or cement.

e) Subsequently, the applicant submitted the 8 digit level data of HSN Code 28365000 pertaining to import of Calcium Carbonate from Malaysia to India, on CIF basis, extracted from the Ministry of Commerce and Industry. The necessary appropriate adjustments have been made in this to arrive at the benchmark rate on FOB basis.

f) The data provided by the domestic industry and interested parties pertaining to $CaCO_3$ has been fully corroborated by the information available on the website of the Ministry of Commerce & Industry.

95. Accordingly, the Authority initially proposed to adopt the Malaysian export price of $CaCO_3$ to India on FoB basis as appropriate benchmark under Article 14(d) based on eight-digit level data available on the website of Ministry of Commerce and the resulting benefit has been quantified for the responding exporters on the basis of verified information.

96. However, in view of the post disclosure comments, wherein the other interested parties requested to adopt the import prices from Egypt into India as an appropriate external benchmark due to the large quantum of imports from Egypt to India and on the other hand, the emphasis of domestic industry to consider only Malaysian import prices into India as an appropriate benchmark, the Authority specifically examined these competing claims regarding consideration of external benchmark. The participating producers / exporters relied on Egypt's substantial production and exports, its significant share in Indian imports, the domestic industry's own procurement from Egypt and the commercial relevance of Egyptian prices. The domestic industry relied on the product-specific and reconcilable Malaysian data under tariff item 28365000. Upon reconsideration, the Authority found that both countries supplied relevant calcium carbonate to India during the POI and that neither source should be discarded merely because the other had a larger volume or more detailed transaction data.

97. The Authority has re-examined the benchmark for calcium carbonate strictly in accordance with Rule 12(2)(d), Annexure IV and Article 14(d) of the SCM Agreement, which require adequacy of remuneration to be assessed against prevailing market conditions, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of sale. Benchmark selection is therefore not governed by the lowest price, the nearest source, the largest supplier or the outcome most favourable to either side. The controlling test is whether the benchmark is reliable, representative, comparable and capable of measuring the benefit on a like-for-like basis

98. Egypt represented the materially larger import volume into India of $CaCO_3$ and its use by the domestic industry confirmed commercial availability for industrial use. Malaysia, however, offered a more detailed product-specific transaction data and useful evidence on

descriptions, price dispersion and shipment conditions. The Authority has, therefore, considered the weighted average CIF prices of both the sources duly adjusted to FOB level, that is, import prices of Egypt as well as Malaysia to India as extracted from website of Ministry of Commerce & Industry, as an appropriate external benchmark, for the purpose of programme no. 1. The Authority has relied on actual 8 digit level HSN code imports into India from Egypt and Malaysia in POI at CIF level, as extracted from website of Ministry of Commerce & Industry, which has been duly adjusted to FOB level.

99. The benchmark has been calculated by weighting each country's adjusted price by its corresponding eligible import quantity. This methodology is not an equitable compromise between competing claims; it is the most representative and legally defensible measure of prevailing market remuneration available on the record. It recognises Egypt's greater commercial presence, preserves the reliability of the Malaysian product-specific data, minimises source-specific distortion and provides a balanced, objective and robust basis for the final recipient-specific benefit and subsidy margin calculations. Objections concerning grade, particle size, purity, coating, whiteness, processing route, end use and tariff classification were duly examined for both countries.

100. It is noted that Malaysian CIF prices have been converted to a FOB-equivalent basis by deducting verified freight and insurance prices based on the contemporaneous, route-specific and product-relevant documentary evidence provided by the domestic industry , whereas the Egyptian CIF prices have been converted to a FOB-equivalent basis by deducting verified freight and insurance prices based on the contemporaneous, route-specific and product-relevant documentary evidence provided by the respondents or producer-exporters. This ensures that the benchmark reflects the value of the input itself and is not distorted by differences in product characteristics, shipment terms or level of trade.

101. The composite benchmark is considered more objective and representative than exclusive use of either country. Exclusive reliance on Egypt would disregard the detailed Malaysian transaction evidence, while exclusive reliance on Malaysia would understate the significance of the larger volume of comparable imports from Egypt. The combined series, after harmonisation of product scope and commercial terms, better reflects prevailing market conditions.

102. The legal basis of this methodology is representativeness, comparability and prevailing market conditions under Rule 12 and Article 14(d). Although it incidentally balances the competing concerns of exporters and the domestic industry, it is adopted because it provides a broader and more reliable external market reference-based benchmark.

103. The weighted benchmark is applied only to producers that purchased or consumed calcium carbonate during the POI. It is compared with each cooperating producer's verified purchase price on a like-for-like basis, with adjustments for freight, insurance, port handling, trading level and other conditions of purchase. The company-specific benefit calculations are contained in the confidential calculation sheets.

104. Specificity was confirmed because the identified mineral-input framework benefits a limited group of downstream enterprises dependent on the affected limestone and limestone-derived input. The fact that these minerals may have other uses does not negate specificity where the design and operation of the programme and the benefit to

investigated producers are established.

105. Accordingly, Program 1 remains countervailable. For calcium-carbonate purchases, the final producer-specific subsidy calculations shall use the quantity-weighted average of adjusted comparable POI import prices from Egypt and Malaysia. Consequential revisions shall be made to the subsidy margins.

Subsidy Margin

106. In accordance with Rule 12 of the CVD Rules, the Authority has quantified the benefit as the difference between the benchmark price determined above and the price at which $CaCO_3$ was purchased by the responding exporters during the POI.

107. Based on verified questionnaire responses submitted by the exporters, information provided by the Government of Vietnam through TRAV, and benchmark data placed on record by the domestic industry, the Authority has calculated the subsidy amount attributable to this program for each responding exporter, which has been included in the net countervailable subsidy margin.

Program 12 - Supply of Natural Gas / Electricity / Coal for Power Consumption at LTAR

108. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The other interested parties submitted that the petition alleges that natural gas, electricity and coal are provided by the Vietnamese authorities at less than adequate remuneration, on the premise that government-set prices are lower than international market prices, thereby conferring a financial benefit on recipient enterprises. The parties categorically denied having received any such benefit.

ii. It was submitted that the producers in Vietnam do not use natural gas or coal for power generation or for their manufacturing operations. Accordingly, the allegation relating to provision of natural gas or coal at LTAR is stated to be factually incorrect and not applicable to them.

iii. With respect to electricity, the parties submitted that electricity is procured through private commercial arrangements and not supplied by the Government of Vietnam. They stated that electricity is purchased from private entities pursuant to duly executed agreements, and that monthly electricity bills evidencing such purchases have been submitted to the Authority.

iv. The parties further submitted that utilities such as water are purchased from the private entities on commercial terms. On this basis, it was contended that electricity and utilities are sourced through private contracts rather than through any government program alleged.

v. The parties contended that electricity prices in Vietnam are not distorted and reflect prevailing market conditions. They reiterated, to the extent applicable, their submissions made in relation to the allegation of limestone being provided at LTAR, and submitted that regulation of prices does not, by itself, render a measure actionable under the SCM Agreement or the CVD Rules.

vi. The parties relied on the findings of the Australian Anti-Dumping Commission in the anti-subsidy investigation concerning imports of Aluminium Zinc Coated Steel from Vietnam. They submitted that the Commission, after examining electricity pricing in Vietnam with reference to World Bank data, concluded that there were no significant

cost distortions in the Vietnamese electricity market and that electricity prices in Vietnam were comparable to, or higher than, prices in several other countries.

vii. The parties emphasized that, although the Government of Vietnam regulates electricity pricing and prescribes different tariff categories such as manufacturing, administrative/governmental, trading and household, all entities within each category are charged uniform and publicly notified rates. They submitted that such categorization is common across jurisdictions, including India, and does not imply targeted benefit, preferential treatment or specificity.

viii. It was further submitted that the petitioner has failed to place any enterprise-specific or industry-specific evidence on record to show that the respondents received electricity, natural gas or coal at prices different from those paid by other industrial consumers in Vietnam, or that any preferential tariff, rebate, discount or financial advantage was extended to them.

ix. The parties argued that government regulation of utilities does not automatically imply LTAR or subsidization. They submitted that electricity and gas sectors are regulated worldwide due to their public utility character, and that regulation for grid stability, safety and consumer protection does not establish that prices are lower than market benchmarks or that a subsidy exists.

x. The parties disputed the petitioner's reliance on earlier DGTR findings, including the Fiberboards investigation, and submitted that such reliance is misplaced. They contended that those findings were based on the specific factual record in those investigations, whereas in the present case complete tariff schedules, invoices, bills and government notifications have been provided, leaving no basis for presuming distortion.

xi. The parties also challenged the benchmarks proposed by the petitioner, including reliance on Global Petrol Prices or prices prevailing in Malaysia, on the ground that such sources reflect retail or consumer-level prices, do not represent industrial tariffs, and do not account for country-specific factors such as fuel mix, transmission and distribution costs, subsidy frameworks and climatic conditions.

xii. In relation to natural gas, the parties reiterated that they do not use natural gas in their manufacturing process. They submitted that the allegation regarding use of natural gas is speculative and unsupported by any documentary or technical evidence on record.

xiii. The parties submitted that oversight by the Ministry of Industry and Trade under Decree 87/2018 relates to safety, licensing and technical standards, and not to price fixation. They contended that natural gas prices in Vietnam are determined by commercial suppliers and fluctuate based on international benchmarks such as PLATTS, CP or FOB prices.

xiv. The parties further submitted that where natural gas is purchased, it is procured from private suppliers under arm's-length commercial contracts with price variation clauses, and that invoices and payment records demonstrate that no concession, subsidy or LTAR exists.

xv. It was also submitted that even assuming, without admitting, that electricity or gas were supplied at a different price, the allegation would still fail for lack of specificity. According to the respondents, tariffs apply uniformly to all industrial users in Vietnam, with no enterprise-specific, sector-specific, regional or conditional preference, thereby failing the requirements of specificity under Article 2 of the SCM Agreement.

xvi. The GOV submits that government involvement in a market does not automatically establish price distortion and that the DGTR has not demonstrated why in-country prices could not serve as appropriate benchmarks. The GOV further submits that the DGTR has not sufficiently demonstrated that the selected external benchmarks appropriately reflect prevailing market conditions in Viet Nam through adjustments relating to quality, transportation, availability, and other conditions of sale.

xvii. European Plastic Joint Stock Company, Polyfill Joint Stock Company, Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company and Yen Bai European Plastic Joint Stock Company submitted that they have not received benefit under this program. The reliance on Malaysian electricity prices is legally untenable, as domestic prices in Vietnam must be used in the absence of proven distortion.

xviii. VMI submitted that electricity was procured from private suppliers at market-determined commercial rates and not from government-owned utilities. VMI argued that the Authority improperly presumed distortion in Vietnam's electricity market without conducting a company-specific analysis of VMI's verified electricity contracts and invoices. VMI also challenged the use of Malaysian electricity prices from Global Petrol Prices as a benchmark, asserting that Malaysia's energy market structure, subsidy regime, and consumer tariff data were not comparable to Vietnam's industrial electricity market conditions.

xix. Vitaplas Joint Stock Company submits that it purchases electricity from private commercial entities pursuant to duly executed electricity supply agreements, that the electricity tariffs paid by Vitaplas are determined in accordance with publicly notified tariff schedules applicable to all industrial consumers in Vietnam, and that there is no evidence that Vitaplas has received electricity at preferential rates, concessional terms, or below-market prices.

xx. Electricity is a public utility service characterized by natural monopoly features in transmission and distribution networks. Virtually all countries, including India, regulate electricity tariffs to ensure grid stability, prevent abuse of monopoly power, protect consumer interests, ensure cost recovery for utilities, and promote efficient resource allocation. Such regulation is a normal and necessary function of government and does not, by itself, constitute a financial contribution or confer a benefit within the meaning of the SCM Agreement.

xxi. ADC procures electricity and other utilities from independent suppliers under commercial arrangements. Such procurement is undertaken on an arm's-length basis and at prevailing market prices, without any involvement of the Government of Vietnam in the provision of such utilities. The Authority has not identified any instance where the Government of Vietnam has directly or indirectly provided electricity, natural gas, coal, or any other utility to the Respondent. In the absence of such evidence, the essential requirement of a financial contribution under Article 1.1(a) of the SCM Agreement is not satisfied.

xxii. The Respondent further submits that the mere existence of regulatory oversight or state participation in the energy sector does not imply that all utilities supplied within the economy are provided by the government or at subsidised rates. The Authority is required to establish a direct nexus between the government and the provision of the goods to the Respondent, which has not been done.

xxiii. The respondent has not availed any LTAR benefit on electricity prices. The proposal made in the disclosure statement dated 20.03.2026, that "The Authority finds, on the basis of the regulatory/tariff-setting framework placed on record and the role of the Government of Vietnam through MOIT, that there exists a financial contribution in respect of provision of electricity within the meaning of the SCM Agreement and the CVD Rules." is completely wrong, misleading, and hence, denied. It is submitted that no evidence has been placed on record that Government of Vietnam has provided any benefit to the manufacturers in any of the following forms:

(i) direct transfer of funds to the manufacturers of the subject goods;

(ii) revenue foregone or not collected i.e., electricity charges waived fully or partly;

xxiv. The Authority has consistently analysed whether any rebate / discount / exemption on electricity tariff is provided by the respective government to the manufacturers of the subject goods *vis-à-vis* normal rates. If yes, the same has been considered as subsidy to the extent of rebate/discount/exemption provided to the manufacturers of the subject goods.

xxv. The Authority has not found LTAR on Electricity in the recent investigations. They have submitted that Authority may cross-check this claim from the recent findings. Illustrative list of the investigations is provided below for the ready reference of the Authority:

a) Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F. No. 7/23/2023-DGTR dated 15 June, 2024] Welded
b) Welded Stainless Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F.No. 6/22/2018-DGAD dated 31 July, 2019]
c) Textured Tempered Glass originating in or exported from Vietnam [F. No. 6/32/2023-DGTR dated 11 February, 2025]

xxvi. Curiously, in this investigation an incomparable benchmark has been considered based on the misleading submissions of the domestic industry to prove a non-existent case of subsidization. It may be noted that the policy of the Government remains the same. In such a case, the respondent is not able to understand the reason for the adoption of an unprecedented methodology in this investigation.

xxvii. The allegations of the Applicant also stands unsubstantiated and invalidated by the determination of the Australian Anti-dumping Commission wherein the commission, in Anti-subsidy investigation against imports of Aluminium Zinc Coated Steel of a Width Equal to or Greater Than 600 Millimetres from Vietnam found the absence of cost distortions in the Vietnamese electricity market. The Australian Commission has noted as follows:

a) Vietnam different rates apply to different sectors and are dependent on voltage;
b) World Bank electricity price adequately reflects electricity prices in Vietnam and aligns with the data the GOV provided.
c) The electricity prices in the Korea, Malaysia and Taiwan are all cheaper than Vietnam.

xxviii. With regard to specificity, it is noted in the Disclosure Statement dated 20.03.2026 that the scheme is specific since retail tariff is set for different categories, including manufacturing, administrative/non-business, business and households. Such differentiation indicates that the tariff mechanism is not uniformly applicable across all users, but is administered through defined user categories, including industrial/manufacturing users that consume electricity as an input for production. It is submitted that the proposal made regarding specificity is completely wrong as tariff is always different based on the factors mentioned above. This practice is being followed around the globe including India. The tariff is applicable to all enterprises and is not specific to any particular enterprise.

109. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. The domestic industry submitted that energy prices in Vietnam, including electricity, natural gas and coal, are set or regulated by government authorities and do not reflect market-determined conditions. It was submitted that such administered pricing results in distortion of energy prices in Vietnam.

ii. According to the domestic industry, the provision of electricity, natural gas and coal at administered prices constitutes provision of goods at less than adequate remuneration within the meaning of Article 14(d) of the SCM Agreement and the CVD Rules. The difference between the government-set prices and international market prices represents a financial benefit conferred on recipient enterprises.

iii. It was further submitted that the provision of electricity, natural gas and coal for power consumption at LTAR by Vietnamese authorities constitutes a countervailable subsidy. The domestic industry submitted that the Government of Vietnam exercises direct control over these sectors through the Ministry of Industry and Trade ("MOIT"), which demonstrates that the program is specific and actionable.

iv. The domestic industry submitted that the benchmark for assessing adequacy of remuneration cannot be domestic Vietnamese prices, as these are distorted due to government intervention. It proposed that energy prices from a comparable external market, such as Malaysia, be used as an appropriate benchmark, based on publicly available data. The benefit, according to the domestic industry, should be calculated as the difference between such benchmark prices and the prices actually paid by producers of the PUC in Vietnam.

v. With respect to electricity, the domestic industry submitted that MOIT sets the electricity retail tariffs within prescribed price frames for four categories of users, namely (i) manufacturing sectors, (ii) administrative and non-business sectors, (iii) business sectors, and (iv) households.

vi. The domestic industry relied on the Authority's findings in the anti-subsidy investigation concerning imports of Fiberboards from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and Sri Lanka, wherein the Authority held that electricity rates in Vietnam were distorted and not reflective of market forces due to government control.

vii. In the Fiberboards investigation, the Authority had relied on 'Global Petrol Prices' as a benchmark source on the basis that it publishes a wide range of reliable and up-to-date information on retail energy prices across countries. The domestic industry submitted that this established practice supports the conclusion that Vietnamese electricity prices are distorted.

viii. On this basis, the domestic industry proposed adoption of electricity prices from another ASEAN country, namely Malaysia, as an appropriate external benchmark. The Malaysian electricity prices, as extracted from 'Global Petrol Prices', were placed on record, and the Authority was requested to compare the actual electricity tariffs paid by responding Vietnamese producers with this benchmark to determine the subsidy margin.

ix. In response to the parties' denial of LTAR, the domestic industry submitted that such denials are incorrect, selective and misleading. It reiterated that electricity pricing in Vietnam is administered, regulated and controlled by the Government of Vietnam and therefore does not reflect prevailing market conditions as required under Article 14(d) of the SCM Agreement.

x. The domestic industry further submitted that reliance by parties on findings of the Australian Anti-Dumping Commission is misplaced, as determinations by foreign authorities are not binding on this Authority and are based on different periods, facts and evidentiary records.

xi. The domestic industry pointed out that even the extracts relied upon by the respondents acknowledge that electricity prices in Vietnam are fixed sector-wise by the government and applied uniformly, rather than being determined through competitive market forces. It was submitted that such administered pricing itself warrants scrutiny under Article 14(d).

xii. The domestic industry submitted that its benchmark submissions demonstrate systematic suppression of electricity tariffs in Vietnam through tariff caps and policy intervention by state-owned or state-controlled entities. Accordingly, it denied the parties' claim that no

LTAR exists in respect of electricity and requested the Authority to assess electricity pricing based on objective external benchmarks already proposed.

xiii. With respect to natural gas, the domestic industry submitted that under Decree No. 87/2018/ND-CP, MOIT has been designated as the administrative authority for the petroleum sector and oversees all business activities relating to LPG, LNG and CNG. The relevant Decree was placed on record.

xiv. The domestic industry submitted that such regulatory oversight demonstrates direct government control over the natural gas sector in Vietnam, resulting in distortion of natural gas prices. It was contended that these prices therefore do not reflect market-determined conditions.

xv. Reliance was placed on the Authority's findings in the anti-subsidy investigation concerning imports of Copper Tubes and Pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam, wherein the Authority held that natural gas prices in Vietnam were distorted due to government control and were not reflective of market forces.

xvi. In that investigation, the Authority had relied on 'Global Petrol Prices' as a benchmark source for natural gas prices. The domestic industry submitted that this constitutes a well-established practice of the Authority in circumstances where domestic prices are distorted.

xvii. Accordingly, the domestic industry proposed adoption of natural gas prices from Malaysia, as extracted from 'Global Petrol Prices', as the appropriate benchmark. The relevant Malaysian natural gas price data was placed on record, and the Authority was requested to compare these benchmark prices with the prices paid by Vietnamese producers to determine the subsidy margin.

110. The Authority has examined the submissions below:

A.1 ***Financial Contribution & Benefit***

111. The Authority notes that the allegation under this concerns the provision of energy inputs, namely electricity, natural gas and coal, for power consumption in Vietnam at administered or regulated prices. However, based on the questionnaire response/additional questionnaire response placed on record by the producers/exporters, the Authority notes that the users/consumers including the producers of the PUC have consumed electricity at less than adequate remuneration.

112. The Authority has examined the material on record regarding the structure of the electricity sectors in Vietnam and the role of the Government of Vietnam, including through the Ministry of Industry and Trade ("MOIT"), in tariff setting and oversight.

113. The Authority finds, on the basis of the regulatory/tariff-setting framework placed on record and the role of the Government of Vietnam through MOIT, that there exists a financial contribution in respect of provision of electricity within the meaning of the SCM Agreement and the CVD Rules.

Specificity

114. The Authority has examined the structure of the electricity tariff regime placed on record, wherein the retail tariff is set for different categories, including manufacturing, administrative/non-business, business and households. However, the same is uniformly applicable across all users within each user categories. The applicants have failed to provide evidence to demonstrate that electricity is provided only to the manufactures of

PUC at a rate lower than the normal rates.

115. Therefore, the Authority notes that this program is not specific. Further, this is also corroborated by the fact that the Authority has also not found LTAR on Electricity in Vietnam in the following investigations conducted by the Authority.

a) Textured Tempered Glass originating in or exported from Vietnam [F. No. 6/32/2023-DGTR dated 11 February, 2025]
b) Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F. No. 7/23/2023-DGTR dated 15 June, 2024] Welded
c) Welded Stainless Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F. No. 6/22/2018-DGAD dated 31 July, 2019]

116. Accordingly, the Authority has not examined the countervailability of this particular program.

Program 13 - Provision of Land at LTAR and Exemptions or Reductions from Land and Water Rents

117. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The producers/exporters submitted that the allegation that the Government of Vietnam provides land at LTAR, water rent exemptions or reductions is unfounded, factually incorrect, and not applicable to the responding producers/exporters.
ii. It submitted that this program refers to exemptions or reductions in land and water rent for periods ranging from three to eleven years, and reductions of up to fifty percent for certain enterprises. The parties submitted that they have not availed any such alleged program during the POI.
iii. The parties submitted that land used by them is not owned or directly allotted by the Government of Vietnam. Instead, land has been obtained through commercial sub-lease arrangements with private industrial park infrastructure development companies.
iv. In this regard, one of the parties submitted that it entered into a land sub-lease agreement with the lease valid until 2065.
v. It submitted that the unit price for sub-leasing land with infrastructure (excluding VAT) under the said agreement is equivalent to approximately USD 75 per square meter, applicable for the entire lease term.
vi. The parties submitted that the land price paid by them is significantly higher than the base land prices prescribed by the People's Committee of Hung Yen Province under Decree No. 40/2019/QD-UBND dated 20 December 2019, which promulgates the land price list for the period 2020–2024.
vii. As per Table 09 of Decree No. 40/2019/QD-UBND, the base price for commercial, service, and non-agricultural production land in industrial parks located in Yen My District is VND 1,200,000 per square meter.
viii. It submitted that the land price paid by the parties exceeds the base price prescribed under the said Decree. This premium demonstrates that the land lease price is not incentivised, concessional, or provided at LTAR.
ix. The parties submitted that the payment of a premium over the provincial base price conclusively establishes that no benefit has been conferred and that the transaction reflects market-based commercial terms.
x. The parties further submitted that the allegation of provision of land at LTAR is not applicable, as they have not purchased land but have only taken land on lease.

According to the parties, the petition incorrectly equates leasing arrangements with government provision of land.

xi. The parties rely on findings of the Australian Anti-Dumping Commission in the anti-subsidy investigation concerning imports of Aluminium Zinc Coated Steel of a width equal to or greater than 600 millimetres from Vietnam, wherein no subsidy was found in relation to land use levy exemptions or reductions.

xii. The parties submitted that the Australian authority found no evidence that exporters of the subject goods had received any financial benefit under land-related programs and consequently terminated the investigation with respect to that program.

xiii. The parties submitted that land rent exemption and reduction policies in Vietnam constitute general investment promotion measures that are uniformly available to all enterprises investing in industrial zones, particularly those located in socio-economically difficult regions.

xiv. It submitted that these measures do not distinguish between sectors, products, sizes of enterprises, export orientation, or localisation requirements, and therefore lack both de jure and de facto specificity.

xv. Eligibility for any land or water rent exemption or reduction is based solely on objective geographical criteria, namely the location of the project in designated industrial zones or economically difficult regions, and not on the nature of the product manufactured.

xvi. One respondent submits that its project, located in Yen Bai Province, qualifies for land rent exemption under Point (b), Clause 3, Article 19 of Decree No. 46/2014/ND-CP, as the project is situated in an industrial zone located in a socio-economically difficult area, with the objective of promoting regional development.

xvii. The parties submitted that such incentives constitute general regional development measures and fall within the category of permissible investment promotion policies, which are not countervailable in the absence of specificity.

xviii. The parties further submitted that similar regional development incentives exist in India and other WTO Members, and therefore Vietnam's land policies should not be treated differently.

xix. The parties denied the allegation that the Government of Vietnam provides land to producers of the PUC at LTAR and submit that the domestic industry has failed to establish any distortion in land prices or any benefit conferred during the period of investigation.

xx. The parties also challenged the domestic industry's proposal to rely on out-of-country benchmarks, including Thailand Board of Investment ("BOI") land rental data, adjusted by inflation indices.

xxi. It submitted that Thailand and Vietnam have fundamentally different land tenure systems, industrial zoning frameworks, real estate markets, land conversion costs, and infrastructure provisioning models, rendering such comparisons invalid.

xxii. The parties submitted that inflation-based adjustments across unrelated real estate markets lack economic justification and do not satisfy the requirements of comparability under Article 14(d) of the SCM Agreement.

xxiii. It further submitted that Thailand BOI rates do not reflect the structure of Vietnamese industrial zone leasing, which typically includes bundled infrastructure, services, and long-term concession arrangements.

xxiv. The parties argued that reliance on precedents from the United States Department of Commerce regarding out-of-country benchmarks is misplaced and not binding on the Authority.

xxv. Even under U.S. practice, use of external benchmarks requires a prior finding of domestic market distortion and a rigorous comparability analysis, neither of which has been demonstrated by the domestic industry.

xxvi. The parties submitted that, for determining adequacy of remuneration, the Authority must consider the nature of land, lease tenure, escalation clauses, included infrastructure, local market conditions, zoning restrictions, and bundled charges.

xxvii. The parties submitted that they have placed on record complete land lease agreements, rent payment schedules, and supporting documentation demonstrating that land was obtained on market-based terms.

xxviii. It submitted that the domestic industry has failed to establish the existence of a financial contribution, benefit, or specificity, and therefore the allegations relating to provision of land at LTAR and exemption or reduction of land and water rent deserve to be rejected in entirety.

xxix. The respondents submitted that no countervailable benefit has been received under the alleged land-related programme. European Plastic Joint Stock Company, Polyfill Joint Stock Company, Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company and Yen Bai European Plastic Joint Stock Company contended that reliance on Thailand land rental benchmarks is legally untenable, as domestic Vietnamese prices must be used unless distortion in Vietnam is first established.

xxx. VMI submitted that the Authority's finding is unsupported, as it incurred substantial commercial costs for acquiring land use rights, constructing factory infrastructure and developing industrial facilities at its own expense. Such costs were capitalised in its audited financial statements and resulted in depreciation expenses exceeding any alleged notional land rent benefit. VMI further objected that the Disclosure Statement dated 20.03.2026 does not disclose essential calculation elements such as benchmark rate, land area, calculation period and adjustments applied. It also challenged the use of Thailand Board of Investment rental rates, as Thailand and Vietnam differ materially in land ownership systems, economic conditions, infrastructure, geography and industrial development.

xxxi. ADC submitted that it acquired land at prices approximately 45% above the applicable benchmark values, thereby establishing absence of any benefit. It further submitted that there is no evidence of exemption, reduction, waiver or preferential treatment in respect of land or water rent, and all payments were made in accordance with applicable laws at commercially determined rates. In the absence of any financial contribution by the Government of Vietnam, the threshold requirement for establishing a subsidy itself is not met.

xxxii. The respondents further submitted that no evidence has been placed on record to show any direct transfer of funds or revenue foregone by the Government of Vietnam, such as full or partial waiver of land charges. The Disclosure Statement also ignores that the Government of Vietnam merely prescribes a floor or circle rate, while actual purchase price is determined by market forces, subject only to the condition that it cannot fall below such floor rate. This is a normal regulatory practice followed in several countries, including India, and does not establish subsidisation.

xxxiii. A major objection concerns the benchmark adopted by the Authority. The respondents submitted that Nakhon Nayok Province, Thailand is not comparable with Van Tien commune, Yen Bai Province, Vietnam, where the factory is located. Van Tien is a developing rural area about 200 km from Hanoi, whereas Nakhon Nayok is a developed province in central Thailand, around 100 km from Bangkok, with mature tourism and infrastructure facilities. The respondents submitted that population density is not the proper basis for comparison; the relevant criterion is level of development. The proposed Thai benchmark is more than 1,000 times the actual rent paid by the respondent, which itself shows that the benchmark is distorted, incomparable and misleading.

	Particulars	**Van Tien commune, Yen Bai Province, Vietnam**	**Nakhon Nayok Province, Thailand**
i	Location	Rural Area	Central Thailand
ii	Distance from capital city	200 km from Hanoi	100 km from Bangkok
iii	Scale	Small administrative unit	Entire administrative province
iv	Level of development	Developing rural area	Mature; international-standard resorts, water parks, and part of a UNESCO World Heritage site (Khao Yai).
v	Benchmark Claimed ($ per M2 per Annum)	-	50.53
vi	Benchmark as no. of times of actual rent	*** Times	No comparable area can have *** times difference in rent

xxxiv. The respondents submitted that the subsidy margin under this scheme has always been assessed less than 0.5%. This can be cross-checked from the recent findings issued by DGTR mentioned below. In this case, the alleged subsidy margin on this account has been calculated as 5%, which is more than 10 times higher than what has been determined earlier by the Authority. Illustrative list of the investigations is provided below for the ready reference of the Authority:

a. Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F. No. 7/23/2023-DGTR dated 15 June, 2024] Welded
b. Welded Stainless Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam [F. No. 6/22/2018-DGAD dated 31 July, 2019]
c. Textured Tempered Glass originating in or exported from Vietnam [F. No. 6/32/2023-DGTR dated 11 February, 2025]

xxxv. On specificity, the respondents submitted that the finding is unsupported because the Disclosure Statement dated 20.03.2026 merely states that the programme is region-specific and limited to encouraged sectors. However, the respondents' project does not fall under any encouraged sector, and no evidence has been provided by the domestic industry to prove otherwise.

xxxvi. Lastly, the respondents relied on the Australian Anti-Dumping Commission's termination of the anti-subsidy investigation concerning Aluminium Zinc Coated Steel from Vietnam, wherein no subsidy was found in respect of the same / similar land-related programme. They submitted that this supports their position that the alleged programme does not confer a countervailable benefit.

118. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. The domestic industry submitted that the Government of Vietnam provides land-use rights to enterprises at less than adequate remuneration through various schemes involving reduced land rents, full or partial exemptions from land rent, and reductions or exemptions from land and water surface rent.

ii. These measures are granted under government frameworks applicable to enterprises investing in identified regions, industrial zones, or projects classified as encouraged industries under Vietnamese law.

iii. The domestic industry submitted that such measures constitute a financial contribution within the meaning of Article 1.1(a)(1)(iii) of the SCM Agreement and Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975, as they involve the provision of goods, namely land, and also

involve government revenue foregone in the form of exemptions or reductions in land and water rent.

iv. The provision of land at reduced rent or with rent exemptions confers a benefit on the recipient enterprises, as the terms and conditions of such land-use rights are more favourable than those prevailing under market-determined conditions.

v. The subsidy is specific within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement, as access to such exemptions or reductions is limited to enterprises located in particular regions, industrial zones, or undertaking projects classified as encouraged under Vietnamese investment policy.

vi. The domestic industry submitted that the parties' contention that the land program is not applicable because land was taken on lease rather than purchased is legally untenable. Article 1.1(a)(1)(iii) of the SCM Agreement covers provision of goods irrespective of the mode of provision, whether by sale, lease, or concession.

vii. The relevant legal inquiry is not whether land was purchased or leased, but whether the terms and conditions of the land lease reflect adequate remuneration as determined by prevailing market conditions.

viii. The domestic industry has alleged the existence of schemes involving preferential land pricing, exemptions, reductions, and administered land-use levies, all of which must be examined by the Authority to determine whether remuneration is adequate.

ix. Where parties claim that no benefit has been availed, the Authority may rely on the confidential questionnaire responses, land lease agreements, and verification records submitted by the participating foreign producers to determine applicability and benefit, if any.

x. The domestic industry submitted that the Government of Vietnam provides land rent exemptions either for the entire lease period or for a limited number of years, as well as rent reductions for certain enterprises, under various decrees governing land administration and investment promotion.

xi. These exemptions and reductions result in government revenue foregone and confer a direct benefit on recipient enterprises, thereby satisfying the definition of a subsidy

xii. The domestic industry relied on the Authority's findings in the countervailing duty investigation concerning imports of Copper Tubes and Pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam, wherein the Authority held that the Government of Vietnam's provision of land at LTAR and exemptions or reductions of land and water rent constituted a financial contribution and conferred a benefit.

xiii. In that investigation, the Authority further held that such land-related measures were specific, as they were limited to enterprises located in particular regions and to projects falling within encouraged sectors.

xiv. The domestic industry submitted that the same reasoning and legal principles apply in the present investigation, as the structure, design, and operation of the Vietnamese land incentive framework remain comparable.

xv. The domestic industry further submitted that investigating authorities in other jurisdictions have also treated similar Vietnamese land programs as countervailable subsidies.

xvi. In this regard, the domestic industry relied on the findings of the United States Department of Commerce in the countervailing duty investigation concerning Frozen Warmwater Shrimp from Vietnam, wherein USDOC determined that Vietnamese domestic land rent data was distorted by state intervention.

xvii. In that investigation, USDOC relied on out-of-country benchmarks published by the Thailand Board of Investment in the "Cost of Doing Business in Thailand 2023" report to determine appropriate market-based land rents.

xviii. The domestic industry submitted that the Thailand Board of Investment data was considered the best available information by USDOC, as it provided market-based industrial land rental rates in a comparable regional context.

xix. In the present case, the domestic industry proposed to adopt rental rates for industrial and logistics properties reported in the "Cost of Doing Business in Thailand 2023" report as the appropriate external benchmark.

xx. The data in the Board of Investment report is presented on a regional basis. To identify the appropriate comparable region, the domestic industry submits that population density of regions in Thailand should be compared with the population density of the locations where the Vietnamese producers' factories are situated.

xxi. The domestic industry submitted that the same methodology was adopted by USDOC in the Frozen Warmwater Shrimp investigation and represents a reasonable and transparent approach to identifying comparable regions.

xxii. As the Thailand Board of Investment has not published a "Cost of Doing Business" report for 2024, the domestic industry submits that the benchmark land rents for 2024 should be derived by adjusting the 2023 BOI rental rates using Vietnam's inflation index.

xxiii. The benefit should be quantified as the difference between the land rent that would have been payable at these benchmark rates and the rent actually paid by the producers of the PUC in Vietnam after accounting for any exemptions or reductions.

xxiv. In cases where full land rent exemption has been granted, the domestic industry submits that the entire benchmark rent amount should be treated as the benefit conferred during the relevant period.

The Authority has examined the submissions below:

Financial Contribution & Benefit

119. The Authority considers that the form of provision (sale, lease, concession, sub-lease) is not determinative for the purpose of examining a financial contribution. Where land-use rights are made available within a government-administered framework and/or where exemptions/reductions in land and water rents are granted pursuant to legal instruments, the Authority has examined whether such measures involve provision of land-use rights by or at the direction of the Government and/or involve foregone revenue that is otherwise due.

120. The Authority notes that land is owned by the Government of Vietnam and price of land is determined by them. The Authority further notes that the land rent exemption/reduction measures relied upon by the domestic industry constitute government revenue foregone. The Authority in its past Anti-subsidy investigation concerning namely "Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes" and "Continuous Cast Copper Wire Rods" has already determined that countervailing duty should be imposed against these programs.

121. The issue of program-wise applicability to the individual responding producers/exporters is examined on the basis of their questionnaire responses and supporting documents.

Specificity

122. The Authority considers that measures limited to enterprises operating in identified regions, industrial zones, or designated investment-incentive areas. In view of the

aforesaid, the Authority notes that this program is also specific because it is region specific and is limited to certain encouraged sectors. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

Benchmark

123. In the present investigation, the Authority has examined the documentary evidence placed on record by the responding producers/exporters, including lease agreements, payment schedules, and details of any exemptions/reductions. The Authority noted that the government of Vietnam granted rebate in land rates to the manufactures of the PUC.

124. Accordingly, for the purpose of the present program, the Authority considered the normal rates prevailing in Vietnam i.e., without rebates as appropriate benchmark.

Subsidy Margin

125. The Authority notes that, in terms of Rule 12 of the CVD Rules, countervailable subsidies are calculated in terms of the benefit conferred on the recipient which is found to exist during the period of investigation.

126. Accordingly, for the responding producers/exporters found to have availed land-related benefits during the POI, the Authority has computed the benefit by comparing (i) the benchmark rentals based on normal land rates that would have been payable under market-consistent conditions for comparable industrial land-use rights, with (ii) the rent actually paid after accounting for any exemptions or reductions.

List of schemes identified in the form of tax exemptions and rebates

Program 3 - Exemption on Corporate Income Tax for Enterprise

127. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The other interested parties submitted that the corporate income tax ("CIT") exemptions or reductions alleged by the domestic industry are general policy measures under Vietnamese law and are available to all enterprises that meet objective statutory criteria. It is submitted that such measures do not satisfy the requirement of specificity under Article 2 of the SCM Agreement.
ii. ADC Plastic JSC submitted that the only incentive availed by it during the POI was a general investment-linked CIT exemption applicable for a limited period of six months. This exemption arises automatically under the Law on Corporate Income Tax No. 32/2013/QH13 and the Law on Investment No. 61/2020/QH14, which confer eligibility based on objective investment thresholds, without regard to export performance, industry, region, foreign ownership, or enterprise size.
iii. The parties submitted that the CIT incentive is wholly non-specific, as confirmed by the Investment Registration Certificate and tax records.
iv. The parties submitted that the domestic industry has failed to establish de jure or de facto specificity. The statutory instruments governing the CIT incentives apply horizontally across the Vietnamese economy and are neither directed at the plastics industry nor contingent upon exportation, localization, or foreign investment. It further submitted that

no discretion is exercised by the administering authority to favour certain enterprises, as eligibility is determined solely on the basis of objective legal criteria.

v. Reliance was placed on the Appellate Body report in United States – Softwood Lumber IV, wherein it was held that general government policies that incidentally affect market conditions cannot be treated as financial contributions or as entrustment or direction. The parties submitted that economic effects alone, absent evidence of targeted transfer of economic resources or preferential treatment to particular enterprises, are insufficient to establish the existence of a subsidy under the SCM Agreement.

vi. It further submitted that, even assuming arguendo that the Authority were to treat the CIT incentive as specific, the quantum of benefit conferred during the POI is minimal.

vii. The parties submitted that the Authority must consider only the actual benefit accrued during the POI and cannot annualize or extrapolate benefits beyond the investigation period.

viii. The parties further submitted that the CIT incentives are not contingent upon export performance and therefore cannot be treated as export subsidies under Article 3.1(a) of the SCM Agreement. It submitted that the benefit applies at the enterprise level and is not linked specifically to the production or export of the product under consideration.

ix. It submitted that similar general tax incentive frameworks exist in several jurisdictions, including India. Both Vietnam and India apply a standard corporate tax rate supplemented by generally available investment-linked incentives such as tax holidays, reduced rates, and R&D deductions. There is no evidence to show that Vietnamese enterprises receive a systematically more favourable tax regime compared to Indian enterprises.

x. The parties relied on past determinations of the Authority, including Polyester Yarn from China PR and Cold Rolled Flat Steel Products from Korea, where it was held that general tax benefits available under national law do not constitute countervailable subsidies in the absence of enterprise-specific or industry-specific targeting.

xi. Any assessment of benefit must be recipient-specific and based on actual tax liability, taking into account taxable income, depreciation, loss carry-forwards, and applicable tax credits. The domestic industry's approach of presuming the statutory tax rate as the benchmark without examining the actual tax base and effective tax rate is legally unsustainable.

xii. Certain parties submitted that they have not availed any CIT exemption or reduction during the POI and that they paid corporate income tax at the standard rate of 20% and did not receive any tax benefit. Other parties similarly submitted that they neither applied for nor received any benefit under the alleged CIT exemption schemes.

xiii. The GOV submits that the relevant policies form part of a generally applicable legal framework and are not specific to certain enterprises or industries.

xiv. VMI stated that it paid corporate income tax at the standard statutory rate of 20% throughout the period of investigation and did not receive any tax exemption or preferential reduction. VMI submitted that its tax filings and payment records confirmed the absence of any countervailable tax benefit.

xv. European Plastic Joint Stock Company, Polyfill Joint Stock Company, Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company and Yen Bai European Plastic Joint Stock Company submitted that the CIT-related incentives are not countervailable, as they are not linked to inputs consumed in the production of the exported product.

xvi. ADC has submitted that while it has disclosed the availment of a limited corporate income tax exemption for a portion of the POI, the Authority's treatment of this measure as a countervailable subsidy is legally unsustainable and contrary to the framework of the SCM Agreement. The corporate income tax regime in Vietnam is a general fiscal measure applicable across sectors and industries. The exemption relied upon by the Authority is part of a broader, economy-wide tax framework and is not limited to a specific enterprise or industry. Accordingly, the requirement of specificity under Article 2 of the SCM

Agreement is not satisfied. The Respondent reiterates that the alleged benefit is minimal and, when properly allocated, is de minimis in nature. The Authority has not engaged with this submission, nor has it demonstrated that the quantum of benefit is sufficient to warrant countervailing measures. Further, the Authority has not undertaken any analysis to examine whether the tax treatment received by ADC deviates from the normal taxation regime applicable in Vietnam. In the absence of such benchmark analysis, it cannot be concluded that any benefit has been conferred. The treatment of a general tax measure as a countervailable subsidy, without establishing specificity and without quantifying a meaningful benefit, is contrary to settled principles under the SCM Agreement and the CVD Rules**.**

xvii. An Tien has submitted that its submissions regarding corporate income tax has not been examined properly. The respondent has not availed any income tax benefit as evidenced from the following facts. Therefore, the proposal to impose the corporate income tax subsidy on the respondent is completely wrong and misleading.

a) 20% is the normal / regular corporate income tax rate in Vietnam during the period of investigation as also confirmed by the Government of Vietnam in its questionnaire response.
b) The company has paid the corporate income tax at the normal rate of 20% during the POI as evidenced from the Income Tax Return filed with the Authority as part of the verification documents.
c) The proposed corporate income tax subsidy is misleading and incorrect as evidence as the company overpaid income tax in both FY 2023 / FY 2024 as evidenced from the Income Tax Return filed with the Authority.

xviii. Without prejudice to the above, it is submitted that the Authority has not even mentioned the program of the Government of Vietnam under which corporate income tax has been countervailed. It is submitted that delay in the payment of income tax cannot be countervailed as no subsidy provided by the Government of Vietnam.

128. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. The domestic industry submitted that Vietnam provides preferential CIT rates and tax holidays to certain enterprises under the Law on Enterprise Income Tax. The statutory corporate income tax rate in Vietnam is 20%. Enterprises qualifying under incentive schemes are either exempt from payment of CIT for an initial period or are taxed at reduced rates.
ii. It submitted that such preferential treatment results in foregone government revenue that would otherwise have been collected at the statutory rate of 20% and thereby confers a benefit on the recipient enterprises. This constitutes a financial contribution in terms of Article 1 of the SCM Agreement and Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975.
iii. The said subsidy is specific, as access to such exemptions or reduced rates is limited to enterprises meeting defined eligibility conditions relating to particular sectors, regions, project characteristics, or government-prioritised activities. These conditions result in the benefit being available only to a limited set of enterprises in practice.
iv. The domestic industry denied the parties' contention that CIT exemptions are general and non-specific. It submitted that even investment-linked tax exemptions framed in neutral statutory language may be de facto specific under Article 2.1(c) of the SCM Agreement if, in practice, they are limited to certain enterprises, sectors, or regions.
v. The parties' own admission of having availed CIT exemption or reduction during the POI establishes the existence of both a financial contribution and a benefit. The existence of a subsidy does not depend on the magnitude of the benefit, and arguments that the benefit is small or time-limited are irrelevant for determining whether the program is countervailable.

vi. The Authority is required to examine the actual benefit accrued during the POI based on verified tax records. Where parties claim that the benefit is de minimis, such claims must be assessed and confirmed by the Authority on the basis of confidential financial and tax data.

vii. Under Law No. 14/2008/QH12, the standard CIT rate in Vietnam was initially 25%, which was subsequently reduced to 20% with effect from 1 January 2016 pursuant to Law No. 32/2013/QH13. This statutory rate of 20% applies to all enterprises that do not qualify for preferential treatment.

viii. The Government of Vietnam has introduced schemes under which certain enterprises are granted complete exemption from CIT for an initial period of two to four years, followed by reduced CIT rates ranging between 10% and 20% for extended periods that may last up to 30 years. Eligibility for these schemes is based on criteria such as sectoral focus, regional location, project size, and alignment with government priorities including high technology, infrastructure, research, and agriculture.

ix. Where enterprises pay CIT at a rate below the statutory rate of 20%, the government foregoes revenue otherwise due, and a benefit is conferred on such enterprises. This interpretation is consistent with Article 1 of the SCM Agreement and Annexure IV of the CVD Rules.

x. The Authority was requested to calculate the amount of countervailable subsidy by comparing the actual tax paid with the tax that would have been payable at the statutory rate.

xi. Similar approach has been adopted by investigating authorities in other jurisdictions. Reference was made to the investigation on Frozen Warmwater Shrimp, wherein the statutory corporate tax rate was treated as the benchmark and preferential rates were compared against it to determine the benefit.

129. **The Authority has examined the submissions below:**

Financial contribution

130. Based on the verified tax records and questionnaire responses of the participating producers/exporters, the Authority finds that, to the extent a participating producer/exporter has availed CIT exemption or reduction resulting in payment of CIT below the normal statutory treatment during the POI, the program involves a financial contribution in the nature of foregone government revenue otherwise due.

Benefit

131. The Authority finds that, to the extent the participating producers/exporters have paid CIT at a rate lower than the normal statutory CIT rate of 20%, or have paid no CIT during the relevant part of the POI due to an incentive, a benefit is thereby conferred, measurable as the difference between the CIT payable under normal statutory treatment and the CIT actually paid during the POI.

Specificity

132. Based on the operation of the incentive schemes as evidenced on record, the Authority finds that the CIT exemption/reduction program is specific, as access to the benefit is limited to enterprises meeting defined eligibility criteria linked to identified

regions/industrial zones and/or qualifying project categories, and the benefit is not available to all enterprises under identical conditions.

Benchmark

133. The Authority holds that the appropriate benchmark for measuring benefit under this program is the normal statutory CIT rate of 20%, applied to the verified taxable income/tax base for the POI, with due consideration of recipient-specific tax computations reflected in the verified tax records.

Subsidy *Margin*

134. The subsidy amount for this program has been computed for each participating producer/exporter on the basis of verified tax filings, tax computation statements, and supporting accounting records for the POI, by determining (i) the benchmark tax liability at the normal statutory treatment, (ii) the actual tax liability and tax paid during the POI, and (iii) the difference between the two as the benefit.

Program 4 - Exemptions from import duties on raw materials, machinery and equipment

135. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The allegation relating to import duty exemption on raw materials under is not applicable to the responding producers/exporters. None of the respondents applied for, or availed, any import duty exemption or reimbursement for raw materials or capital goods/machinery during the POI or the injury period. All imports of raw materials and capital goods were already subject to nil customs duty under various Free Trade Agreements, upon submission of valid certificates of origin. Duty foregone under an FTA does not constitute a countervailable subsidy.

ii. The parties did not receive any separate or additional import duty exemption linked to their operations. Item-wise import duty screenshots, bills of entry, and duty-free import records were submitted to demonstrate that imports were cleared at zero duty solely by operation of FTAs and not under any subsidy scheme.

iii. The Government of Vietnam submitted that import duty exemption on inputs used in the manufacture of exported products does not, per se, constitute a countervailable export subsidy. Reliance is placed on Annex I(i) of the SCM Agreement, which clarifies that remission or drawback of import charges on inputs consumed in the production of exported products is not countervailable, provided such remission does not exceed the duties actually levied on the imported inputs.

iv. The Government of Vietnam further submitted that earlier determinations alleging lack of an effective tracking system in Vietnam are no longer valid. Vietnam has established a comprehensive customs control and verification mechanism to track the import, consumption, and use of duty-free raw materials for export production. Reference was made to Decree 08/2015/ND-CP, Circulars 38/2015/TT-BTC and 39/2018/TT-BTC, and Decree 59/2018/ND-CP, which prescribe obligations on producers and customs authorities.

v. The Government of Vietnam submitted that producers importing raw materials for export production are required to (i) notify customs authorities of production facilities

and storage locations, (ii) maintain norms of material consumption for each product, (iii) keep detailed records of stock-in, stock-out, and leftovers of imported materials, and (iv) reconcile such records with accounting documentation. Importers are stated to bear legal responsibility for the accuracy of such records and declarations.

vi. It further submitted that customs authorities are empowered to receive and examine these records, conduct facility inspections, verify inventories, and undertake post-clearance audits based on risk management criteria. Where irregularities or trade fraud are suspected, customs authorities may impose duties and penalties in accordance with law. It contended that this system enables customs authorities to verify whether duty-free imported inputs are actually used in exported products.

vii. The Government of Vietnam submitted that this customs verification framework is comparable to systems adopted in other jurisdictions. It argued that, if the domestic industry disputes the effectiveness of Vietnam's system, it must demonstrate how Vietnam's system materially differs from or is less effective than India's customs system. In the absence of such proof, the program should not be treated as countervailable.

viii. Individual responding producers/exporters submitted that they have not availed any import duty exemption or remission on raw materials during the POI. Since no exemption or remission was availed by them, the essential elements of a subsidy, financial contribution and benefit, are absent in their case.

ix. The parties further submitted that the petitioner's allegation that import duty exemptions constitute revenue foregone is incorrect. The petitioner's proposal to treat statutory duty rates as benchmarks, and to allocate benefits on a recurring basis for inputs or over an assumed average useful life (AUL) for capital goods, is hypothetical and unsupported by evidence in the absence of any actual exemption availed.

x. With respect to capital goods, it was submitted that allocation over an AUL may be relevant only if an exemption is actually availed. Even otherwise, the petitioner's assumption of a uniform AUL of eight years for all machinery is arbitrary and inconsistent with DGTR practice. AUL must be asset-specific and supported by evidence such as audited records or applicable depreciation schedules.

136. **The domestic industry has made the following submissions with respect to this:**

i. Under Decree No. 134/2016/ND-CP, the Government of Vietnam provides exemptions from import duties on raw materials, machinery, and equipment used for production and export. Such exemptions involve foregone government revenue that would otherwise have been collected in the form of customs duties and therefore constitute a financial contribution within the meaning of the SCM Agreement and the CVD Rules.

ii. Import duty exemptions on raw materials constitute recurring subsidies, as raw materials are imported on a continuous and repetitive basis for production. Each instance of duty-free import of raw materials results in revenue foregone by the government and confers a benefit on the recipient enterprises.

iii. Under WTO law and DGTR practice, import duty exemptions on inputs consumed in the production of exported goods may be treated as non-countervailable only where there exists a properly implemented and verified system ensuring that duty-free inputs are limited strictly to the quantities consumed in exported goods. In the absence of such a verified system, or where its implementation is inadequate, the entire duty exemption must be treated as countervailable.

iv. It is incumbent upon the participating producers/exporters of the PUC in Vietnam to demonstrate, through their questionnaire responses and supporting evidence, the specific raw materials imported, the quantities consumed in production, and the manner in which any duty exemption was applied. Where such evidence is absent, incomplete, or

unverifiable, the Authority must treat the entire duty foregone as a countervailable subsidy.

v. Reliance was placed on DGTR's past practice, including the countervailing duty investigation concerning imports of "Fiberboards" from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and Sri Lanka, wherein import duty exemptions on raw materials were treated as countervailable in the absence of effective verification of consumption of duty-free inputs in exported goods.

vi. For raw materials the appropriate benchmark is the statutory import duty rate applicable to the relevant raw material during the POI. The benefit should be calculated as the difference between the statutory duty payable and the duty actually paid. Where no duty is paid, the entire statutory duty foregone should be treated as the benefit.

vii. With respect to machinery and equipment, import duty exemptions constitute non-recurring subsidies, as machinery and equipment are typically imported once and then used over their useful life. Although the exemption occurs at a single point in time, the benefit continues to accrue over the period during which the asset is used in production.

viii. WTO law and DGTR practice recognize that import duty exemptions on capital goods are countervailable even if such goods are used for production of exported products. The benefit conferred is the duty foregone at the time of import, which must be allocated over the Average Useful Life (AUL) of the machinery or equipment.

ix. The benchmark for machinery and equipment should be the statutory customs duty applicable at the time of import. The benefit is the difference between the duty that would have been payable at the statutory rate and the duty actually paid.

x. The DGTR's Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations expressly provides that benefits from non-recurring subsidies, such as duty exemptions on capital assets, should be considered over the AUL of the relevant tangible or intangible assets used in production.

xi. The domestic industry has proposed an AUL of eight years, consistent with established DGTR practice, including in the Fiberboards investigation. Accordingly, any benefit arising from import duty exemptions on machinery and equipment should be allocated over an eight-year period to determine the portion of the benefit attributable to the POI.

xii. The Authority must examine whether any such non-recurring subsidies on machinery and equipment were availed by producers of the PUC in Vietnam during the period from 1 April 2016 to 31 March 2024, as non-recurring subsidies received in earlier years but continuing to yield benefits during the POI remain countervailable.

xiii. The Authority may rely on confidential import data, bills of entry, duty payment records, and questionnaire responses to verify whether any import duty foregone constitutes a financial contribution and benefit.

The Authority has examined the submissions below:

137. The Authority notes that none of the respondents applied for, or availed, any import duty exemption or reimbursement for raw materials or capital goods/machinery during the POI or the injury period. All imports of raw materials and capital goods were already subject to nil customs duty.

138. Accordingly, the Authority has not examined the countervailability of this particular program.

List of schemes identified in the form of interest rate subsidies

Program 5 - Preferential Lending for Investor
Program 7 - Preferential Lending to the Exporters
Program 8 - Interest Rate of Investment Credit Loans
Program 9 - Investment Support on Foreign Investors Establishing SMEs
Program 10 - Export Credits from the Vietnam Development Bank (VDB)
Program 11 - Financial Guarantees by Vietin Bank

139. The other interested parties have made the following submissions with respect to above programs:

i. The producers/exporters submitted that the allegation regarding preferential lending for investors is not applicable to them, as none of the responding producers/exporters have availed any loans from the Vietnam Development Bank ("VDB").
ii. Some of the interested parties have submitted that they have not availed any concessional or export-linked loans from state-owned banks, SBV, or VDB during the POI. SBV's interest-rate ceilings and related measures are general monetary policy tools of economy-wide application and do not constitute subsidies or demonstrate specificity.
iii. Some of the interested parties submitted that they are not eligible under the SME framework, as their capital investment exceeds the thresholds for classification as small or medium enterprises. Consequently, the program does not apply to them.
iv. The parties submitted that they have not availed any export credit or export-linked financing from the VDB during the POI or at any other relevant period. The other interested parties also submitted that they have not availed any financial guarantees from Vietin Bank or any other state-owned bank during the POI. There is no lending or guarantee relationship with Vietin Bank.
v. Some of the interested parties submitted that the loans availed during the POI were obtained from private commercial banks at market-determined interest rates on arm's length terms. Documentary evidence of such commercial borrowings has been placed on record to demonstrate the absence of any concessional or government-directed lending.
vi. The existence of a policy framework for preferential lending does not, by itself, establish countervailability. A benefit can arise only where a loan is provided on terms more favourable than those available on the market, which has not been demonstrated in the present case.
vii. The GOV submits that the investigated exporters did not receive any actual measurable benefit and that subsidy findings should be based on verified evidence demonstrating the existence of a real and measurable benefit to the enterprises concerned, rather than assumptions or theoretical calculations.
viii. VMI maintained that it had not received any loans from state-owned banks, the Vietnam Development Bank, or any preferential government financing program during the period of investigation. VMI stated that all financing arrangements during the relevant period were obtained from private commercial banks at market interest rates and that documentary evidence supporting these facts had already been submitted to the Authority during verification. VMI therefore argued that no financial contribution or benefit existed under these programs and requested the Authority to assign a zero subsidy margin accordingly.
ix. An Tien stated that it did not receive any preferential loans or interest-rate benefit. It argues that the Disclosure Statement dated 20.03.2026 has not properly examined the evidence showing that no direct transfer of funds was made by Vietnamese state-owned banks, and that treating ordinary loans from state-owned banks as financial contribution would wrongly imply that loans from public sector banks in India, such as SBI, are also subsidies. An Tien further submits that its projects/products are not covered under Decree No. 32/2017/ND-CP, and that its local currency loans were obtained from both state-owned and private foreign

banks at market-driven interest rates. The comparable rates charged by both categories of banks demonstrate that no preferential rate or countervailable benefit was conferred.

x. The rate of interest of the foreign currency (USD) loans is determined by the international benchmark (LIBOR) and not by the regulations / decree of Government of Vietnam. This is the reason that no interest subsidy is determined by the Authority on foreign currency loans in the past investigations like Fiberboard.

xi. As regards benchmark, it is proposed in the disclosure statement dated 20.03.2026 that "Authority proposes to adopt interest rate provided by Bank of India branch in Vietnam which is not a state-owned bank in Vietnam." It means that interest rate of foreign private bank is proposed to be considered as a benchmark. It is submitted that interest rate of Vietnam branch of Bank of India as a benchmark is arbitrary and does not take in to account parameters like whether the loan is secured or not, tenure of loan, credit rating, industry risk etc. It may also be noted that that the supporting documents provided for the Bank of India interest rate clearly mentions that "The above rates are for reference and negotiable from case-to-case basis". Therefore, the same cannot be considered as a benchmark

xii. Without prejudice to the submission of the respondent that it has not availed any interest subsidy, it is submitted that the respondent has also taken loan from *** (Private Foreign Bank) and *** (Private Foreign Bank). Therefore, the actual interest rate of the same shall be considered for the determination of the subsidy margin of the respondent as the interest rate varies on account of above-mentioned factors.

140. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. Lending by a government-owned or government-directed financial institution constitutes a financial contribution in the form of direct transfer of funds. Where such loans are extended at concessional interest rates, they confer a measurable benefit on the recipient enterprises.

ii. The Government of Vietnam provides preferential lending to investors through the VDB under Decree No. 75/2011/ND-CP. Under this program, eligible enterprises can obtain loans at interest rates lower than those available from commercial banks. The state-owned banks in Vietnam extend export-linked loans to exporters at concessional interest rates under the policy direction and regulatory control of the State Bank of Vietnam.

iii. Plastic manufacturing is classified as a support industry. Consequently, producers engaged in plastic manufacturing are eligible to access investment credit loans under this program, and the program is applicable to producers of the PUC.

iv. The Government of Vietnam provides investment support to enterprises establishing small and medium-sized enterprises under the Law on Assistance for Small and Medium-Sized Enterprises. These legal instruments lay down the framework for granting financial assistance to eligible SMEs, irrespective of whether such enterprises are owned by domestic or foreign investors.

v. The Government of Vietnam operates an export credit program. Under this program, eligible exporters are provided loans of up to 85% of the value of export contracts, thereby directly linking the availability of credit to export activity.

vi. The financial guarantee program offered by Vietin Bank constitutes a countervailable subsidy. By providing guarantees on loans, Vietin Bank assumes credit risk that would otherwise be borne by commercial lenders. Such guarantees improve the creditworthiness of recipient enterprises producing the PUC and enable them to access financing at lower interest rates, or on terms that may not have been available in the absence of such guarantees.

vii. The difference between the concessional interest rate charged and the market-determined commercial interest rate represents the benefit conferred, and the foregone interest revenue constitutes revenue forgone by the government.

viii. For determination of the benefit, the appropriate benchmark is the interest rate charged by private commercial banks in Vietnam for comparable loans. Only by comparing the concessional lending rate with such commercial rates can the Authority determine what the recipient would have paid in the absence of government intervention.

ix. The Authority was requested to examine evidence of commercial lending rates in Vietnam, including rates charged by private banks operating in Vietnam and publicly available indicators such as World Bank interest rate data, to establish a reliable benchmark for benefit calculation.

The Authority has examined the submissions below:

Financial Contribution

141. Authority notes that VDB and other state-owned banks in Vietnam are a public body because it is owned and controlled by the Government of Vietnam and exercises Governmental authority. Loans granted by VDB or any other state-owned bank are in the nature of financial contribution in the form of direct transfer of funds.

142. When a financial institution that is owned or controlled by the government provides loans, this amounts to a financial contribution through the direct provision of funds. If these loans are offered at below-market interest rates, they give the receiving companies a quantifiable advantage.

143. The Authority in the past Anti-subsidy investigation against Vietnam concerning "Welded Stainless Steel Pipes and Tubes", "Continuous Cast Copper Wire Rods", "Copper Tubes and Pipes" and "Fiberboards", have held these programs as countervailable. The question of whether a given producer/exporter has received such a financial contribution during the POI is examined on the basis of verified company-specific records.

Benefit

144. The Authority considers that, where loans are availed and are at rates more favourable than comparable commercial lending available in the Vietnamese market to the recipient, such lending confers a benefit within the meaning of Annexure IV of the CVD Rules and Article 14(b) of the SCM Agreement. The existence and quantum of benefit for each responding producer/exporter is determined on the basis of verified loan documentation and comparison with an appropriate commercial benchmark.

Specificity

145. The Authority considers that these programs are specific within the meaning of Rule 9 and Article 2, since access to the program is limited to enterprises/projects meeting the eligibility conditions prescribed in the related project lists and related criteria, and is therefore not generally available to all enterprises across the economy without restriction.

Benchmark

146. The Authority considers that the appropriate benchmark for determining the benefit is the interest rate on a comparable commercial loan available in Vietnam to the recipient during the POI. The applicants proposed to adopt interest rate provided by Bank of India branch in Vietnam which is not a state-owned bank in Vietnam. However, it is noted from the supporting evidence provided by the applicants that the proposed rates are for reference purposes only and are negotiable on case-to-case basis. The proposed rate does not consider parameters like whether the loan is secured or not, tenure of loan, credit rating, industry risk etc. Therefore, the same is not considered as a benchmark.

147. It is noted from the questionnaire response filed by the producers / exporters that they have taken loan from both state-owned banks and private foreign (non-Vietnam) banks during the POI. Accordingly, the Authority adopts the actual interest rate (pertaining to POI) of private foreign banks operating in Vietnam as an appropriate benchmark.

Subsidy Margin

148. The Authority determines that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB and other local banks of Vietnam. The Authority proceeds to compute company-specific subsidy margins under Preferential Lending based on the verified loan data of each responding producer/exporter and the benchmark determined above, and includes the resulting margins in the subsidy computation tables.

List of schemes identified in the form of other financial incentives

Program 2 - Master Plan for Development of Vietnam's Plastic Industry

149. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The parties submitted that they have not availed any benefit under the alleged Master Plan for Development of Vietnam's Plastic Industry. The Master Plan is described as a planning document outlining the Government of Vietnam's long-term vision to develop a coordinated plastic industry from raw material production to finished goods. The Master Plan identifies certain priority or beneficiary projects, none of which cover the respondents or the product under investigation. This is also evident from their Investment Registration Certificates, which do not record any benefit or linkage to the Master Plan.

ii. The Master Plan is a high-level industrial policy or strategy document and does not, by itself, constitute a subsidy program. It does not contain any operative mechanism for granting financial contributions, such as budgetary allocations, grants, preferential loans, tax incentives, guarantees, or reimbursements. A policy framework cannot be treated as a countervailable subsidy unless it establishes a concrete scheme involving financial contribution and confers a measurable benefit on identifiable enterprises. In the absence of such operative provisions, the Master Plan cannot be considered a subsidy within the meaning of the CVD Rules or the SCM Agreement.

iii. Master Plan does not mandate or provide for any direct or indirect transfer of funds, revenue foregone, provision of goods or services, or price/income support. The parties submitted that they have not received any preferential loans, tax benefits, trade promotion assistance, training support, infrastructure support, or any other form of financial

assistance pursuant to the Master Plan. The petitioners are stated to have produced no evidence of any disbursement, transaction, or measurable advantage. Consequently, both the elements of financial contribution and benefit are asserted to be absent.

iv. The Master Plan applies broadly to the entire plastic industry value chain in Vietnam, including raw materials, intermediate inputs, finished products, additives, and ancillary industries. Such a sector-wide policy does not meet the requirement of specificity, as it is not limited to certain enterprises, groups of enterprises, regions, or products, nor does it involve discretionary selection of beneficiaries. On this basis, the Master Plan is claimed to be non-specific and therefore not countervailable.

v. Reliance by the domestic industry on prior DGTR findings concerning other countries' market development or industrial plans is misplaced. Those cases involved clearly defined schemes with actual budgetary allocations and reimbursable grants, unlike the Vietnamese Master Plan, which merely sets out policy objectives without any automatic or operational financial assistance mechanism.

vi. Even if any downstream initiatives were hypothetically linked to the Master Plan, the parties have not availed any such initiative during the POI. In line with DGTR practice, where a program is not used by a party, the benefit attributable must be treated as nil.

150. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. The Government of Vietnam has introduced a Master Plan for the Development of Vietnam's Plastic Industry with the stated objective of building and developing a synchronous plastic industry, progressing step by step from raw material production to final product processing. The Master Plan aims to transform the plastic industry into a strong economic sector with sustainable growth. Its objectives include mobilising domestic and foreign investment for production of raw materials, semi-finished products, chemicals and additives; producing high-quality plastic materials and products; and encouraging investment in plastic material manufacturing.

ii. The Master Plan envisages and provides for multiple forms of support to plastic industry participants. These include preferential loans from the government, establishment of development and technology support funds for priority projects, enhanced trade promotion and market research support, partial state support for training of technical personnel, and strengthening of export promotion activities. The Master Plan also contemplates eligibility of plastic industry projects for investment incentives similar to those granted to key mechanical engineering industries, including access to investment credit covering up to a significant portion of total investment costs. Further, it provides for government-backed guarantees, support for infrastructure development in industrial zones, and adjustment of import duties on raw materials and finished plastic products to promote industry growth.

iii. The measures outlined in the Master Plan involve direct transfers of funds, provision of services, and foregone government revenue in the form of tax and duty incentives. These measures, taken together, constitute financial contributions by the Government of Vietnam. The benefit to recipient enterprises arises from access to concessional finance, grants, guarantees, tax relief, training subsidies, trade promotion assistance, and infrastructure support, which reduce production and investment costs compared to market conditions.

iv. The PUC is an important raw material used in plastic products and therefore falls squarely within the scope of encouraged products under the Master Plan. The production of such raw materials is specifically promoted through incentives relating to investment, finance, infrastructure, and import tariff adjustments. As a result, producers of the PUC are eligible to receive, and benefit from, the support measures contemplated under the Master Plan.

v. The support measures under the Master Plan are limited to identified sectors and activities within the plastic industry value chain. By targeting the plastic industry and its upstream raw materials, including PUC, the program is sector-specific and therefore, meets the specificity requirement for countervailability.

vi. The Authority has, in prior countervailing duty investigations, treated similar market development or industry-specific plans as countervailable subsidies, even where respondents claimed non-availment. In such cases, the Authority has examined the design and scope of the program and held the measures to be countervailable where they involved financial contribution and benefit to a defined sector. On this basis, the domestic industry submits that the Master Plan for Development of Vietnam's Plastic Industry constitutes a countervailable subsidy program.

vii. The benefit under this program should be measured as the actual amount of financial assistance received by producers of the PUC or, where applicable, the amount of government revenue foregone through tax and duty incentives, guarantees, or concessional financing provided pursuant to the Master Plan.

The Authority has examined the submissions below:

151. The Authority notes that none of the participating producer/exporters have availed benefit under this program. Therefore, the Authority has not examined the countervailability of this program.

Program 6 - Export Promotion Program

152. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:

i. The responding producers/exporters submit that although the Government of Vietnam operates an Export Promotion Program providing support for export-related activities, the parties have not participated in, applied for, or availed any assistance under this program during the period of investigation. It is stated that the Petitioner has sought investigation of this program without placing prima facie evidence on record demonstrating actual receipt of benefits by any party.

ii. It is acknowledged that the Export Promotion Program is stated to provide partial cost support for export promotion activities, including reimbursement of up to 50% of expenses for hiring experts for export development, participation in trade fairs, consultancy, and related promotional initiatives. The Petitioner has also alleged the existence of an export-related tax incentive of 6% on exports of the PUC, though the Respondents contend that the Petitioner itself admits to having limited information and has not substantiated this claim with documentary evidence or statutory provisions demonstrating such an incentive in practice.

iii. No financial contribution exists in their case, as no grants, reimbursements, subsidies, tax incentives, refunds, or other financial inflows from the Government of Vietnam have been received. It is emphasized that audited financial statements, accounting records, bank ledgers, and statutory filings of the Respondents for the POI do not contain any entries reflecting receipts or benefits under any export promotion or national trade promotion scheme. They did not engage in activities such as export consultancy, trade fair participation, or advisory services that would qualify for reimbursement under the alleged program.

iv. National trade promotion programs in Vietnam are general government functions aimed at enhancing the country's overall trade profile and international visibility. Such measures

include market studies, trade fairs, branding initiatives, dissemination of information, and export-related advisory support, which are available across sectors and are not limited to exporters of the product under consideration. Such general promotional activities, even where undertaken by the government, do not constitute specific subsidies and are not targeted at any particular enterprise, industry, or group of enterprises.

v. Export Promotion Program is not specific within the meaning of the SCM Agreement or the CVD Rules, as access to the program is based on broad, economy-wide criteria and is not limited to a particular industry, product, or group of exporters. The mere fact that certain enterprises may choose to participate does not render the program specific, and the Petitioner has not demonstrated either de jure or de facto specificity in respect of exporters of the PUC.

vi. The alleged program is not contingent upon export performance in the sense required under WTO law. Participation in trade promotion activities does not depend on achieving export volumes, export values, or export targets, and does not automatically confer financial rewards linked to export performance. There is no evidence of any linkage between exports of the PUC and receipt of financial assistance.

vii. All applicable taxes were paid in accordance with statutory requirements, and no reduction in tax liability or export-linked fiscal benefit was received. In the absence of any tax concession, there is no revenue foregone by the Government of Vietnam in relation to the Respondents.

viii. The discussions on benchmarking are premature and academic, as benchmarking under the CVD framework arises only after the existence of a financial contribution and benefit is established. Since no benefit has been received by the Respondents under the Export Promotion Program, there is no basis for undertaking any benchmark comparison.

ix. The burden lies on the Petitioner to demonstrate actual disbursement, receipt of benefit, and specificity. The Petitioner has relied on generalized references to government programs without producing transaction-level evidence showing that any Respondent received support under the Export Promotion Program.

153. The domestic industry has made the following submissions with respect to this:

i. The Government of Vietnam operates export promotion measures under the National Trade Promotion Program, established by Decision 279 and governed by Decision 80. These measures are designed to support exporters, including exporters of the PUC, and therefore, constitute countervailable subsidies.

ii. Export Promotion Program involves direct transfers of funds by the Government of Vietnam in the form of financial assistance for export promotion activities. This includes reimbursement of up to 50% of expenses incurred by enterprises for hiring experts to advise on export development and related services. Such reimbursements constitute direct transfers of funds within the meaning of Annexure IV of the CVD Rules and Article 1 of the SCM Agreement.

iii. The program also entails foregone government revenue, as exporters are provided tax-related incentives linked to export activity. By reducing the tax liability of exporters based on the value of their exports, the Government of Vietnam forgoes revenue that would otherwise have been due under the statutory tax framework. This reduction in tax liability confers a benefit by lowering operating costs and enhancing export competitiveness.

iv. The benefit under the Export Promotion Program arises in two forms:
(a) in cases of direct transfers of funds, the benefit is equal to the actual amount of financial assistance received by the enterprise; and
(b) in cases of foregone revenue, the benefit is the difference between the statutory tax liability and the reduced liability after application of the export-linked incentive.

v. The export promotion programs are, by their very nature, contingent upon export activity and are therefore specific. The availability of benefits is linked to engagement in export promotion and export-related activities, satisfying the specificity requirement under the SCM Agreement and the CVD Rules. Such programs are export-contingent and thus countervailable.

vi. While certain parties have claimed that they did not participate in any export promotion schemes or receive benefits, the domestic industry submits that non-participation is a matter of verification. The Authority is requested to rely on confidential records, government disbursement data, and verification findings to determine whether any financial assistance or tax benefit was in fact received during the POI.

vii. Annexure IV of the CVD Rules provides clear guidance on benchmarking. For direct transfers of funds, the benchmark is the actual amount of financial assistance received by the enterprise. For measures involving foregone revenue, the benchmark is the statutory tax liability that would have been payable in the absence of the incentive. The benefit is the difference between the statutory liability and the reduced liability after application of the export promotion measures.

The Authority has examined the submissions below:

154. The Authority notes that none of the participating producer/exporters have availed benefit under this program. Therefore, the Authority has not examined the countervailability of this program.

CVD Schemes in Vietnam

155. In view of the foregoing, the Authority concludes that the Vietnamese producers are benefited from countervailable subsidies. On the basis of the investigations conducted, facts on record, and the investigations conducted in the past, and considering absence of full cooperation from few of the Vietnamese participating producers/ exporters of PUC, Authority quantified various subsidy schemes and margin of subsidies therein as shown in table below. It is seen by the Authority that the quantum of CVD margins is above de-minimis.

156. With respect to Filler Masterbatch Joint Stock Company ("FMJSC"), the Authority notes that the producer/exporter has furnished the details/information in the questionnaire format/additional questionnaire format for the calendar year January 2023 to December 2023 instead of Period of investigation i.e., April 2023 to June 2024. The Authority notes that FMJSC did not provide information in the given format and has failed to co-operate with the Authority. Therefore, the Authority has not granted an individual subsidy margin to FMJSC.

157. Additionally, Authority notes that following producers/exporters of PUC from Vietnam namely, GCC Minerals, JSC, Viet Trung Plastic Chemical Joint Stock Company and Megaplast Joint Stock Company have failed to furnish relevant information in the original as well as additional questionnaire response issued by the Authority during the course of investigation and have failed to co-operate with the Authority. Therefore, the Authority has not granted the individual margins to above mentioned producers/exporters.

SUBSIDY MARGIN TABLE

Sl No	Producer	Program. No. 1 - Supply of Limestone at LTAR			Program 3 - Exemption on Corporate Income Tax for Enterprise			Program. No. 5, 7, 8, 10,11 - Preferential Lending			Program. No. 13 Government Provision of Land at LTAR And Exemption/ Reduction of Land and Water Rent			Total		
		Subsidy margin			Subsidy margin			Subsidy margin			Subsidy margin			Subsidy margin		
		USD/ MT	%	Range	USD/ MT	%	Range	USD/ MT	%	Range	USD/ MT	%	Range	USD/ MT	%	Range
1	European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast"),	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
2	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
3	Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
4	Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
	W Avg for Euro Plast Group	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
5	ADC Plastic.,JSC	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
6	An Tien Industries Joint Stock Company	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
7	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
8	Vietnam Industrial Minerals Joint Stock Company	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
9	US Masterbatch Joint Stock Company	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10

10	US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
	(collectively referred to as "US Masterbatch Group")	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10
11	Others	***	***	10-20	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	0-10	***	***	20-30

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions made by other interested parties

158. The following submissions have been made by the other interested parties on the issue of injury and causal link:

i. The other interested parties submitted that the petition does not establish material injury to the domestic industry or the existence of a causal link between alleged subsidisation and the condition of the domestic producers. It was submitted that the Authority must undertake a causation and non-attribution analysis before recommending countervailing duties.

ii. Rule 13 of the CVD Rules mirrors Article 15.5 of the SCM Agreement, which requires demonstration that subsidised imports are causing injury "through the effects of subsidies" based on examination of all relevant evidence and further requires the Authority to examine other known factors injuring the domestic industry and ensure injuries from such factors are not attributed to subsidised imports.

iii. The petition does not satisfy these mandatory requirements and should therefore be rejected.

iv. Although the petition alleges price undercutting, price suppression, and volume-based injury, it does not provide reliable evidence that imports from Vietnam exerted significant price pressure on the domestic industry.

v. The domestic industry itself acknowledges that the PUC varies considerably in composition, including calcium carbonate content, polymer base, and additive structure. The price comparisons require "like-for-like" adjustments for grade, functionality, and specifications, which the petition does not undertake.

vi. The price undercutting methodology in the petition is simplistic and does not meet the evidentiary threshold because it does not account for product differences. The price undercutting has consistently shown positive trends, and despite this, the domestic industry has not changed its behaviour to avert losses. This indicates losses are driven by internal competition among domestic producers rather than imports from Vietnam.

vii. The petition does not demonstrate significant price depression. There is no data showing domestic prices fell during the injury period, and no evidence that domestic producers attempted to raise prices but were prevented from doing so by imports.

viii. The petition itself states that PUC forms only a miniscule share of cost for downstream plastics products and that polymer/resin costs are dominant determinants of pricing. The stability or modest increases in domestic prices aligned with input cost trends cannot constitute price depression.

ix. Price suppression cannot be established without showing that domestic prices would have increased "but for" imports. The petition provides no such counterfactual analysis.

x. The petition fails to show a direct or consistent correlation between import prices and domestic pricing behaviour. The petition itself acknowledges substantial influence of raw material price fluctuations, including resin and calcium carbonate inputs, on costs during the injury period, and these factors are independent of imports and must be excluded from injury attribution.

xi. The petition does not establish displacement of domestic sales by imports from Vietnam. The market for PUC has been expanding, providing room for both domestic producers and imports.

xii. Annexure IV-A in the petition does not show a precipitous decline in output over the years that would normally indicate injury caused by import surges. Many domestic producers maintained or increased production levels.

xiii. Where imports rose, this coincided with increases in nationwide demand rather than loss of domestic market share. The petition itself refers to operational constraints faced by domestic producers, including the fragmented structure of the industry and shutdowns during the COVID-19 period.

xiv. The imports are filling a supply gap that domestic producers could not meet, whether due to capacity constraints or commercial decisions, cannot constitute injury.

xv. The petition acknowledges imports under HS Code 3824 99 00 from other countries, but attributes the alleged injury entirely to Vietnamese imports. Without analysing the price and volume effects of non-subject imports, the Authority cannot satisfy the non-attribution requirement under Rule 13 of the CVD Rules and Article 15.5 of the SCM Agreement.

xvi. The petition identifies certain non-import factors but does not analyse and exclude their effects from the injury narrative. The factors identified by interested parties included internal competition among numerous domestic producers, pricing strategies adopted by domestic firms, changes in demand patterns, variations in production efficiency, downstream market fluctuations, contraction in demand or changes in patterns of consumption, developments in technology, export performance, and productivity.

xvii. The Indian market is fragmented with significant inter se domestic competition, and that aggressive price competition among domestic producers can influence pricing behaviour, profitability, and capacity utilisation independent of imports.

xviii. The domestic producers operate with excess capacity and low-capacity utilisation, creating oversupply and downward pressure on prices independent of imports.

xix. The product segmentation, including the price differential between calcium carbonate masterbatch (PUC) and colour masterbatch, and higher margins in colour masterbatch, can distort profitability and injury assessment if not properly segregated.

xx. The smaller producers, including MSMEs, are vulnerable to aggressive domestic competition, and any financial strain may arise from these structural conditions rather than from imports.

xxi. The petition shows price undercutting by subject imports remained consistently positive across all years, including during the POI, and that despite stable undercutting levels the domestic industry allegedly reported increased losses during the POI. It was contended that this disconnect indicates injury is not attributable to Vietnamese imports.

xxii. Reliance was placed on WTO and domestic jurisprudence to submit that the Authority must "separate and distinguish" the injurious effects of other known factors and quantify or explain their nature and extent relative to subject imports.

xxiii. Even in the domestic industry's own data, most injury parameters show improvement from the base year and preceding years, and therefore the applicants have not established injury.

xxiv. Based on the injury information, the domestic industry's capacity increased from 415,302 MT in the base year to 475,748 MT in the POI (annualised).

xxv. The production increased from 252,179 MT in the base year to 303,862 MT in the POI (A), and that productivity also increased.

xxvi. capacity utilisation increased from 61% in the base year to 64% in the POI (A).

xxvii. Domestic sales increased from 190,683 MT in the base year to 223,632 MT in the POI (A).

xxviii. Domestic selling price per unit increased from an index of 100 in the base year to an index of 112 in the POI (A).

xxix. Where some factors may have declined, such declines cannot be attributed to imports from Vietnam and are instead due to internal factors such as inefficiencies of domestic producers and increased depreciation and interest costs.

xxx. The petition does not provide positive evidence of subsidisation in the subject country and consequential injury to the domestic industry, and therefore no injury finding can be made.

xxxi. The petitioner's injury analysis is legally inadequate because it relies predominantly on import volume trends without establishing the mandatory causal link between alleged subsidisation and injury, contrary to the requirement to examine all relevant economic factors.

xxxii. The import volumes may change for various commercial reasons not related to subsidies, including buyer procurement strategies, inventory adjustments, seasonal or cyclical demand, temporary domestic supply shortages, exchange rate movements affecting landed price parity, shifts in demand for quality or cost-efficient imports, and downstream demand fluctuations.

xxxiii. The petitioner has not provided transaction-level evidence showing that alleged subsidies translated into lower export prices or any pass-through from subsidy to export pricing.

xxxiv. One interested party submitted that its exports are too small to cause injury and claimed that, even on the petitioner's estimates, its exports represent 0.98% of India's demand and 5.15% of Vietnam's exports to India and therefore cannot materially affect a domestic industry of the scale alleged in the petition.

xxxv. One interested party claimed that its export price to India is higher than its domestic price and higher than its export prices to other destinations, indicating no price pressure on the domestic industry.

xxxvi. Due to incoherent, uneven, and allegedly non-compliant data and excessive confidentiality claimed by the domestic industry, they are not in a position to offer meaningful comments on injury and causal link at this stage. It was submitted that meaningful comments can be offered only after proper information for the proper period is provided in line with Trade Notices.

G.2. <u>Submissions made by the domestic industry</u>

159. The following submissions have been made by the domestic industry on the issue of injury and causal link:

i. The domestic industry submitted that the determination of injury and causal link in a countervailing duty investigation is governed by Rule 13 read with Annexure I of the CVD Rules, which requires an examination based on positive evidence and an objective evaluation of (a) the volume of subsidised imports and their effect on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers.

ii. The domestic industry provided the data on imports from the subject country, Indian demand, Indian production, and import share.

iii. The domestic industry submitted that the data shows a consistent increase in imports from the subject country in absolute terms and an increase in their share in the Indian market both relative to demand and relative to Indian production.

iv. Imports increased from 48,155 MT in 2020–21 to 63,043 MT in 2021–22 and further to 1,00,122 MT in 2022–23 and then increased to 2,20,912 MT during the POI. Indian demand increased from 6,30,693 MT in 2020–21 to 10,87,076 MT in the POI, but Indian production increased from 6,06,939 MT in 2020–21 to 8,94,395 MT in the POI.

v. The growth in domestic production was lower than growth in demand, indicating displacement by imports from the subject country.

vi. Subject imports' share in demand increased from 8% to 20% and their share relative to production increased from 8% to 25% over the injury period, reflecting increasing penetration and replacement of domestic production.

vii. The volume effect is evident because incremental demand was increasingly captured by imports from the subject country, limiting the domestic industry's ability to supply Indian consumers despite expanding demand.

viii. The domestic industry submitted the data showing significant and positive undercutting throughout the injury period and the POI, indicating that landed prices of subject imports undercut domestic selling prices.

ix. The domestic industry was forced to sell below cost of sales in all years, resulting in losses throughout the injury period. The persistent gap between landed prices and domestic selling prices, together with sales below cost, demonstrates price suppression and price depression.

x. In accordance with Paragraph 7 of Trade Notice No. 09/2021 as amended by Trade Notice No. 11/2021, the Authority selected the following entities as sampled domestic producers for determination of injury margin:

(i) Soltex Petro Products Ltd.;
(ii) Alok Masterbatches Pvt. Ltd.;
(iii) Alok Industries; and
(iv) Kandui Industries Pvt. Ltd.

xi. The sampled domestic producers filed the information required for determination of non-injurious price. It was submitted that the weighted average combined non-injurious price for PCN A, PCN B and PCN C has been claimed to be in the range of 400–550 USD/MT.

xii. The domestic industry expanded capacity to meet increasing demand from the plastics industry. During the POI, actual production and sales declined compared to the previous year due to increased low-priced subsidised imports from the subject country.

xiii. The capacity utilisation fell in the POI and that despite increasing demand, a significant portion of capacity remained unused. Over the injury period the domestic industry operated at around 60%–70% capacity.

xiv. The applicant domestic industry's market share declined from 30% in the base year to 26% in the POI, while the subject country's market share increased from 8% to 20% over the same period.

xv. The imports from other countries were negligible, and the increase in import share was mainly from the subject country. This increase is linked to the large volume of subsidised imports from the subject country, which became more aggressive in the last few years and during the POI.

xvi. The lost market share and could not sell at reasonable prices despite having sufficient capacity to meet the entire demand in India.

xvii. The profit, cash profit and return on investment remained negative throughout the injury period and losses increased with the highest losses in the POI. Losses increased sharply due to aggressive subsidisation of subject imports.

xviii. The average inventory increased consistently over the injury period and rose sharply in the POI.

xix. All volume parameters show negative growth in the POI, and all price parameters show negative growth over the injury period and the POI. Increasing inventory and declining market share show adverse impact of subsidised imports.

xx. Although domestic industry expanded capacities, it is unable to utilise the existing capacities and is incurring losses due to aggravated subsidisation. The industry is therefore reluctant to make fresh investments in the subject goods unless existing capacities are fully utilised.

xxi. Threat of material injury must be based on facts and not on allegation, conjecture, or remote possibility, and reliance was placed on Article 15.7 of the SCM Agreement and Clause (3) of Annexure I of the CVD Rules.

xxii. There are specific facts indicating a threat of material injury due to subsidies provided by the Government of Vietnam to Vietnamese producers/exporters, including export promotion schemes and policies that make raw materials (including limestone/calcium carbonate) available at subsidised prices, and also include utilities at less than adequate remuneration, tax incentives, cheaper land and electricity and similar support.

xxiii. These subsidies enable exports to India at subsidised prices, causing material injury and threat of material injury to the domestic industry in India.

xxiv. The domestic industry submitted that increasing export tax rates on limestone, reaching 30% from July 2024, indicate that the threat is likely to intensify.

xxv. The Master plan for development of Vietnam's plastic industry focuses on trade promotion in export markets and adjustment of import tax rates to boost the plastics industry indicates likelihood of increased subsidised exports to India, creating a foreseeable and imminent threat of material injury.

xxvi. The data shows a significant rate of year-on-year increase in subsidised imports from the subject country during the injury period, indicating likelihood of substantially increased importation in the future.

xxvii. Vietnamese manufacturers have production capacities exceeding Vietnam's domestic demand and therefore surplus production is intended for export. These excess capacities are far in excess of India's total demand and create a likelihood of substantially increased exports to India.

xxviii. India represents a significant market, and following are the installed capacities of major Vietnamese producers:

a) European Plastics Joint Stock Company – 8,00,000 MT
b) US Masterbatch Joint Stock Company – 2,30,000 MT
c) Mega Plast Joint Stock Company – 1,40,000 MT
d) An tien Industries Industry Joint Stock Company – 96,000 MT
e) Pha le Plastics Manufacturing – 4,50,000 MT
f) Vitaplas Joint Stock Company – 48,000 MT

xxix. These producers are likely to target India to utilise surplus capacity, and that the influx of subsidised imports at suppressing/depressing prices threatens the existence of the domestic industry.

xxx. The domestic producers were forced to sell below cost and that domestic prices fell in the POI as compared to the previous year on account of imports entering at undercutting prices. The trend of landed prices vis-à-vis domestic prices and cost shows imports are entering at prices with significant depressing/suppressing effect and therefore imports are likely to increase further.

xxxi. The inventory levels of foreign producers are not publicly available and requested that the Authority verify exporters' inventory levels based on questionnaire responses.

xxxii. The domestic industry undertook a structured analysis of other factors, including: (a) volume and prices of non-subsidised imports; (b) contraction in demand or changes in patterns of consumption; (c) competition between foreign and domestic producers; (d) developments in technology; (e) export performance; and (f) productivity.

a) The imports from other countries did not cause injury because imports from the subject country account for about 99% of total imports into India and imports from other countries constitute about 1%.

b) The demand increased over the injury period and therefore injury cannot be attributed to demand contraction.

c) The customer negotiations are benchmarked to imported prices and domestic producers are forced to match prices of subject imports; if exporters offer better prices, customers shift to imports.

d) There is no injury due to technological changes.

e) Exports are insignificant compared to domestic sales and export performance was not considered in determining injury, and therefore injury cannot be attributed to exports.

f) The injury analysis pertains only to PUC and excludes profitability of other products, and therefore injury cannot be attributed to performance of other products.

xxxiii. The injury is not due to other known factors and is caused by subsidised imports from the subject country. Imposition of countervailing duty is necessary.

xxxiv. The contention that injury is attributable to inter se competition among domestic producers is misplaced, and that fragmentation does not negate injury caused by subsidised imports where the data shows significant increase in import volumes coupled with adverse price effects.

xxxv. The increased import volume coincides with deterioration in key parameters including market share, profitability, cash flows and inventories, establishing injury through volume effect.

xxxvi. The contention that price undercutting is "stable" is misleading, as persistent and significant undercutting itself indicates price pressure, and injury is aggravated when such undercutting operates over substantially increased volumes.

xxxvii. The price undercutting reached 25–30% during the POI, which suppresses domestic prices and prevents recovery of costs.

xxxviii. The arguments on unused capacity and low-capacity utilisation ignore displacement, and the relevant issue is whether capacity could be utilised in the presence of subsidised imports. It was submitted that incremental demand was captured by low-priced imports, preventing proportionate increase in production and utilisation.

xxxix. The objections on inability to comment due to confidentiality are unfounded, as sufficient non-confidential information including indexed trends and injury parameters has been disclosed to enable reasonable understanding, confidentiality has been claimed in accordance with Trade Notices and the CVD Rules, and the Authority has power to verify confidential information. Confidentiality does not vitiate the injury analysis and does not warrant restarting investigation timelines.

G.3. <u>Examination by the Authority</u>

160. Rule 13 of the CVD Rules read with Annexure I to the CVD Rules provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry,

"(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material

injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.
(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidised import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.
(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if - (i) there is a concentration of subsidised imports into an isolated market, and (ii) the subsidised imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.".

161. Further, in considering the effect of the subsidized imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, return on investment, the magnitude and margin of subsidization, etc. have been considered in accordance with Annexure I of the CVD Rules.

162. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

163. As regards the various arguments of other interested parties based on the statements and data provided by the domestic industry, the Authority has relied upon the verified data of the domestic industry for the purpose of the present final findings.

G.3.1. <u>Volume effect of the subsidized imports</u>

a) <u>Assessment of demand/apparent consumption</u>

164. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. For determination of demand/apparent consumption of the product in India, the Authority has considered the sum of the domestic sales of the applicants, other producers and imports from subject country and imports from other countries. The demand/apparent consumption so calculated is as under:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Imports from Vietnam	MT	48,182	62,228	94,458	1,81,824
2	Imports from other counties	MT	207	27	969	5,702
3	Domestic Sales (Applicant)	MT	1,90,683	2,40,084	2,32,183	2,23,632
4	Domestic Sales (Other producers including supporters)	MT	3,91,758	4,19,307	4,37,761	4,64,831
5	Indian Demand	MT	6,30,830	7,21,645	7,65,372	8,75,988

165. It is seen that the demand of the PUC has increased significantly during injury period.

b) Import volume from the subject country relative to production and consumption in India

166. With regard to the volume of the subsidized imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of subject imports during the injury investigation period are as follows:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Imports from Vietnam	MT	48,182	62,228	94,458	1,81,824
2	Imports from other countries	MT	207	27	969	5,702
3	Indian Demand	MT	6,30,830	7,21,645	7,65,372	8,75,988
4	Indian Production	MT	6,06,939	6,78,391	6,96,823	7,15,516
5	Subject country import in relation to -					
A	Indian Demand	%	8%	9%	12%	21%
B	Indian Production	%	8%	9%	14%	25%

167. It is seen that imports of subject goods from Vietnam have increased in absolute terms throughout the injury period while there are negligible imports from other countries. The imports from Vietnam in terms of Indian demand and Indian production have also consistently increased during the injury period.

A.2 **G.3.2. Price effect of the dumped imports**

168. In terms of Annexure I (ii) of the Rules, with regard to the effect of the subsidized imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

169. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the POI. The table below shows the same-

Particular	UOM	POI (A)
Net Selling Realisation	Rs. / MT	***
Landed Price	Rs. / MT	25,760
Price Undercutting	Rs. / MT	***
Price Undercutting	%	***
Price Undercutting	Range %	25-35%

170. The Authority notes that the price undercutting is not only positive but also significant.

b) Price suppression/depression

171. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has compared the cost of sales & net sales realization of the domestic industry with the landed price of subject goods.

172. The table below shows the cost of sales, selling price and the landed price of imports of PUC-

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	119	113
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	115	109
Landed Price	Rs/MT	23,926	29,808	29,695	25,760
Trend	Indexed	100	125	124	108

173. It can be seen from the above table that the domestic industry has been selling PUC in the domestic market below its cost of sales thereby incurring losses. The landed prices have been below the domestic selling prices, and sales price is below the cost of sales which exhibiting that domestic industry has suffered price suppression.

G.3.3 <u>Economic parameters of the domestic industry</u>

174. Annexure I to the CVD Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of subsidization; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) <u>Production, capacity, capacity utilization and sales volumes</u>

175. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Capacity	MT	***	***	***	***
Production PUC	MT	***	***	***	***
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Domestic sales	%	1,90,683	2,40,084	2,32,183	2,23,632

176. It is noted that the domestic industry expanded its capacities. There has been an increase in demand of the subject goods in India. The domestic industry increased its capacity utilization marginally in the POI when compared to base year. The domestic industry is operating at ***% in the POI.

177. Further, the domestic sales and production level of the domestic industry have shown an improvement in the POI when compared to base year.

b) Market share

178. The market share of the domestic industry and of imports is shown in the table below:

Particulars	**Unit**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI (A)**
Share of Applicant Domestic Industry	%	30 %	33 %	30 %	26 %
Share of other Indian producers including Supporters	%	62 %	58 %	57 %	53 %
Share of subject country	%	8%	9%	12 %	21 %
Share of Other Countries	%	0.03 %	0.00 %	0.13 %	0.65 %

179. It can be seen from the above table that the market share of the domestic industry has declined in the POI (A) as compared to base year, despite having the capacity to meet a much higher share in the Indian demand. Furthermore, the share of other Indian producers including the supporter has also declined throughout the injury period.

180. On the contrary, the market share of the subject country has been consistently increasing throughout the injury period. Further, it is also evident that the market share of imports from other countries is insignificant.

c) Inventories

181. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI (A)**
Average	MT	***	***	***	***

182. It can be seen that the average inventory of the domestic industry consistently increased during the injury period.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

183. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Profit/ (loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-260	-319	-306
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-557	-718	-661
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-363	-402	-349

184. The profit, cash profits and ROI of the domestic industry have been consistently declining throughout the injury period and the domestic industry is suffering financial losses.

e) <u>Employment, wages and productivity</u>

185. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Employees	Nos	***	***	***	***
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Salaries and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***

186. The salary and wages paid by the domestic industry have increased over the injury period. The productivity per employee has also declined in the POI.

f) <u>Growth</u>

187. All the price parameters of the domestic industry show negative growth over the injury period and POI. The average inventory has also increased over the injury period. The market share of the domestic industry also shows negative growth. The domestic industry is in losses during the injury period.

g) <u>Impact on the ability to raise capital investments</u>

188. The Authority notes that, even though the domestic industry has made new investments to increase its capacities to cater to the increasing demand for the PUC in India, it has been unable to utilise its capacities and is facing losses due to subsidised imports. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investments is significantly impaired.

h) <u>Factors affecting prices</u>

189. The Authority notes that the volume of imports during the POI was significant and such imports were at prices significantly below the cost of sales of the domestic industry. Net Sales Realisation of the domestic industry has been severely affected by the subject imports. Thus, the landed value of the subject goods from the subject country is the main

factor affecting domestic prices.

i) Margin of Subsidy

190. The margin of subsidy is an indicator of the extent to which the subsidized imports can cause injury to the domestic industry. The Authority notes that the subsidy margin is positive for Vietnam.

G.3.4 Threat of material injury

191. The Authority has examined the submissions made by various interested parties regarding the scope of investigation concerning threat of material injury.

192. The Authority notes that Rule 13 of the CVD Rules provides that the Authority shall determine whether subsidized imports have caused or are threatening to cause material injury to the domestic industry.

193. The Authority observes that the initiation notification stated that the investigation would examine whether subsidized imports have caused or are threatening to cause material injury to the domestic industry. The scope of investigation as defined in the initiation notification encompasses both material injury and threat of material injury, and the Authority is empowered to examine both aspects based on evidence that emerges during the investigation.

194. The Authority observes that Para (3) of Annexure I to the CVD Rules requires that no determination of threat of material injury shall be made on the basis of mere allegation, conjecture or remote possibility and that the change in circumstances which would create a situation in which the subsidization would cause injury must be clearly foreseen and imminent.

195. The Authority has examined the import data on record and notes that there has been a consistent and significant increase in imports of the subject goods from Vietnam throughout the injury period. The import volumes have more than tripled from the base year to the POI, demonstrating a substantial rate of increase.

196. The data on record shows that Vietnamese producers have substantial production capacity that exceeds domestic demand in Vietnam.

197. The Authority notes that the existence of surplus production capacity in Vietnam, combined with the export orientation of Vietnamese producers as evidenced by increasing exports to India, creates conditions conducive to further substantial increases in exports to the Indian market.

198. The Authority has also examined the price analysis on record and notes that the subject imports have been entering the Indian market at prices that undercut domestic prices, leading to price suppression in the domestic market.

199. The Authority observes that the combination of factors including significant rate of increase in imports, surplus production capacity in Vietnam, price undercutting and suppression, and deteriorating performance of domestic industry creates conditions where threat of material injury is clearly foreseen and imminent.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

200. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the CVD Rules.

a. Volume and price of imports from third countries

201. The Authority notes that imports from non-subject countries are almost negligible. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b. Contraction of demand

202. The demand for the product under consideration has seen an increase. Therefore, decline in demand cannot be a cause of injury. Thus, the domestic industry has not suffered any injury due to a possible contraction in demand.

c. Changes in pattern of consumption

203. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

204. The sales of the subject goods are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

e. Developments in technology

205. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f. Export performance

206. The Authority has considered the injury data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

207. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

208. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of the CVD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

Injury Margin Table

S. No.	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range %
1.	European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast")	***	***	***	***	20-30
2.	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai")	***	***	***	***	20-30
3.	Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe")	***	***	***	***	20-30
4.	Polyfill joint stock company ("Polyfill")	***	***	***	***	20-30
5.	ADC Plastic.,JSC	***	***	***	***	25-35
6.	An Tien Industries Joint Stock Company	***	***	***	***	20-30
7.	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	***	***	***	***	25-35
8.	Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company	***	***	***	***	55-65
9	US Masterbatch Joint Stock Company	***	***	***	***	10-20
10	US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch	***	***	***	***	10-20
11	Others	***	***	***	***	60-70

J. USER IMPACT ANALYSIS (INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES)

J.1 Submissions made by other interested parties

209. The other interested parties have made the following submissions regarding the public interest / Interest of the Indian industry:

i. The levy of countervailing duty in the present investigation would be contrary to public interest within the meaning of Article 19.2 of the SCM Agreement.
ii. Article 19.2 recognizes that the decision to impose countervailing duty, and the level at which it is requested, is discretionary and must take into account representations made by domestic interested parties, including consumers and industrial users, whose interests may be adversely affected.
iii. The Authority has already recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch originating in or exported from Vietnam with the recommended duty ranging from 0 to 75 USD per MT.
iv. The imposition of countervailing duty in addition to the anti-dumping duty would result in a cumulative and excessive trade-restrictive burden, far exceeding what is necessary to address any alleged injury to the domestic industry.
v. Trade remedial measures are intended to remedy injury and not to provide over-protection or double protection to the domestic industry. The cumulative imposition of anti-dumping duty and countervailing duty would substantially increase the landed cost of imports and

would artificially inflate domestic prices, reduce the availability of competitively priced raw materials, and distort market competition to the detriment of downstream users. Such an outcome would be inconsistent with the principles of proportionality and public interest underlying trade remedy law.

vi. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a critical industrial input used extensively across a wide range of downstream industries, including plastic packaging (rigid and flexible), woven sacks and packaging materials, consumer goods and household products, agricultural films and pipes, automotive and electrical plastic components, and construction and infrastructure-related plastic applications.

vii. The product is used to reduce raw material costs, improve processing efficiency, and enhance physical properties of plastic products. Any increase in the cost of this input would have a direct and immediate cascading impact across multiple sectors of the economy.

viii. The downstream industries in India are highly sensitive to input cost fluctuations. Imposition of anti-dumping duty has already increased cost pressures on downstream users, and that an additional countervailing duty would further increase production costs, reduce the competitiveness of Indian manufacturers in both domestic and export markets, lead to higher prices for end consumers, and potentially result in reduced production, layoffs, or closure of businesses.

ix. Given the widespread use of the subject goods, the adverse effects would extend beyond the domestic masterbatch producers and impact the broader manufacturing ecosystem.

x. The Indian market for PUC is highly fragmented, with a large number of domestic producers operating alongside imports. Imports play a crucial role in ensuring supply stability, providing price discipline, and meeting specific quality and consistency requirements of downstream users. Excessive trade remedial measures would restrict supply options and undermine healthy competition in the market, which would be contrary to public interest.

xi. Public interest analysis under trade remedy law requires a balancing of interests between domestic producers on the one hand and downstream industries, consumers, and the broader economy on the other. In the present case, any marginal benefit accruing to the domestic industry from the imposition of countervailing duty would be outweighed by the adverse impact on downstream industries and consumers, and such additional costs would ultimately be passed on to consumers in the form of higher prices.

xii. The imposition of countervailing duty would be disproportionate and excessive, result in an undue cumulative burden when combined with the anti-dumping duty, and have a significant adverse impact on downstream industries as well as on consumers.

xiii. Certain interested parties further contended that the claims made by the applicant domestic industry on issues relating to user impact and public interest are based on assertions, conjectures, and surmises without supporting evidence. No evidence has been provided by the applicant to substantiate its submissions, and that such unsubstantiated claims should not be relied upon for adjudicating the merits of the case.

J.2 <u>Submissions made by the domestic industry</u>

210. The domestic industry has made the following submissions regarding the Public interest / Interest of the Indian industry:

i. The objective of countervailing duty is to remove injury caused by unfair subsidization practices and to restore conditions of fair and open competition in the Indian market, which is in the overall interest of the country. The imposition of CVD is not intended to restrict imports, but to neutralize the unfair advantage arising from subsidization.

ii. The imposition of CVD may have an impact on price levels, but it does not reduce competition in the Indian market. On the contrary, CVD ensures that competition is based

on market forces rather than subsidization, prevents further decline of the domestic industry, and helps maintain long-term availability and choice for consumers.

iii. Assessment of public interest requires the Authority to examine the impact of CVD on availability of the goods, on downstream users, on the domestic industry, and on the general public. Such an assessment must be based on evidence placed on record during the investigation.

iv. As a matter of established practice, the Authority relies on information filed by interested parties through User Questionnaires and Economic Interest Questionnaires ("EIQ") to assess downstream impact. Similar approaches are followed internationally, including in the European Union, where user responses form the basis of the union interest analysis.

v. In the present investigation, the Authority issued User Questionnaires and EIQs and invited participation from all interested parties, including users and consumers. However, no downstream user has filed any response to the User Questionnaire or the EIQ.

vi. No downstream user has provided any quantified or verifiable information demonstrating adverse impact of CVD on cost of production, pricing, employment, or competitiveness. In the absence of such data, the submissions made by exporters and foreign producers on alleged downstream impact are speculative and unsupported.

vii. WTO jurisprudence recognizes the right of investigating authorities to impose strict timelines and to disregard belated submissions. In the present case, no downstream user has availed the opportunity provided during the investigation to place its concerns on record, and any submissions made at a later stage should therefore be rejected.

viii. Downstream users of the subject goods are understood to be members of the All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA). However, no representation has been filed by AIPMA or by any of its members. The lack of participation indicates that the submissions made by exporters are not representative of the interests of Indian downstream users.

ix. The complete absence of responses to the EIQ demonstrates that downstream users do not consider the imposition of CVD to have any material adverse impact on their operations. No quantified information has been placed on record to show that CVD would render downstream industries inefficient or uncompetitive.

x. The only quantified and verifiable impact assessment on record is the one provided by the domestic industry itself, which shows that the impact of CVD on downstream users would be minimal. The Authority was requested to rely on this evidence.

xi. India has sufficient domestic capacity to meet the entire demand for Calcium Carbonate Filler Masterbatch. The total installed capacity of the Indian industry is estimated at approximately 12–15 lakh MT, while domestic production during the POI (A) was 7,15,516 MT, indicating significant underutilization of capacity.

xii. Given the availability of surplus domestic capacity, imports from the subject country are not required to ensure supply stability. The contention that imposition of CVD would restrict availability or disrupt supply is therefore factually incorrect.

xiii. It was submitted that public interest analysis must balance the interests of all domestic stakeholders. The domestic industry is highly fragmented and predominantly composed of MSMEs, which play a critical role in employment generation, regional development, and value-chain resilience in India.

xiv. The domestic industry submitted that continued subsidized imports threaten the survival of MSME producers. Allowing such imports to erode domestic manufacturing capacity would be contrary to India's industrial and economic policy objectives and would adversely affect public interest.

xv. Subsidized imports from Vietnam have already led to adverse structural changes in the Indian market, with several domestic producers either shutting down operations or being compelled to act as white-label manufacturers/suppliers for Vietnamese producers, thereby undermining domestic manufacturing capability.

xvi. Such developments result in long-term dependence on imports and defeat the objective of fair competition and are contrary to public interest.

xvii. The subject goods constitute only a small proportion of the total cost of downstream plastic products. No evidence has been placed on record to show that any increase in cost would lead to inflationary pressure or consumer harm.

xviii. By restoring fair competition and ensuring the viability of domestic producers, imposition of CVD would promote long-term price stability and reliable availability of the product in the Indian market.

xix. The imposition of countervailing duty would not be contrary to public interest and is necessary to safeguard domestic manufacturing (comprising primarily MSME producers), employment, and long-term market stability.

J.3 Examination by the Authority

211. The Authority notes that the submissions of certain producers/exporters have relied upon Article 19.2 of the SCM Agreement to contend that the levy of countervailing duty would be contrary to public interest, particularly in view of the anti-dumping duty already recommended in the anti-dumping investigation concerning the same product from Vietnam.

212. The Authority has examined the contention that the imposition of countervailing duty in addition to anti-dumping duty would result in an excessive and disproportionate trade-restrictive burden. In this regard, the Authority notes that the trade remedial framework applicable in India incorporates the principle of the lesser duty rule, which acts as an in-built safeguard against excessive protection.

213. The Authority notes that, in accordance with the applicable rules and consistent practice, the quantum of duty recommended is restricted to the level necessary to remove the injury suffered by the domestic industry. Accordingly, the cumulative impact of anti-dumping duty and countervailing duty is capped by the injury margin determined for the domestic industry and cannot exceed the level required to neutralize the injurious effect of dumping and subsidization.

214. The Authority further observes that anti-dumping duty and countervailing duty address distinct unfair trade practices, namely dumping and subsidization, respectively. However, the application of the lesser duty rule ensures that the combined remedial effect does not go beyond the injury margin established on the basis of verified data. This mechanism prevents over-compensation to the domestic industry and ensures proportionality in the imposition of trade remedial measures.

215. The Authority considers that public interest/user impact analysis must be undertaken on the basis of evidence and information placed on record by domestic stakeholders whose interests may be affected, including users/consumers/importers, and not on the basis of broad assertions.

216. For this purpose, the Authority notes that, in the present investigation, User Questionnaires and Economic Interest Questionnaires were issued, and the initiation notification an opportunity to all interested parties, including downstream users and consumers, to place relevant data on record regarding any adverse impact of duties on their operations.

217. The Authority notes that no downstream user has filed any response to the User Questionnaire or the Economic Interest Questionnaire. The Authority further notes that no downstream user or user association has provided quantified information regarding the share of the subject goods in their cost structure, the expected impact of duties on cost of production, pricing, employment, or competitiveness, or any other verifiable evidence to substantiate the claim that the levy of countervailing duty would cause material adverse impact.

218. In the absence of such quantified and verifiable information from users, the Authority considers that the claims of injury to downstream industries remain unsubstantiated on the record of the present investigation.

219. The domestic industry provided a quantified impact analysis demonstrating that imposition of countervailing duty would have a negligible impact on downstream users of the product.

i. HDPE woven sack is one example where PUC is used.
ii. As per IS 11652:2017, the ash content in an HDPE woven sack (downstream product) is 5%, which indicates that the finished product has 5% calcium carbonate content.
iii. The PUC has approx. 75-85% of the Calcium Carbonate.
iv. Therefore, a HDPE woven sack of 1 kg, will have 0.0625 kg (6.25%) of PUC.
v. Imposition of any countervailing duty will have negligible impact **of 0.001%** on the end product.

220. The Authority notes the argument that duties may restrict availability and supply stability. On this aspect, the Authority notes that the domestic industry has stated that total installed capacity of the Indian industry is estimated at approximately 12–15 lakh MT, while total Indian production during the POI (A) is stated to be 7,15,516 MT, indicating underutilization of capacity.

221. In the absence of quantified evidence from users demonstrating that imports from the subject country are indispensable for supply stability, the Authority considers that the contention of supply disruption due to CVD is not supported by evidence on record.

222. The Authority has noted the submissions that the subject goods are used across multiple downstream applications and that any increase in input cost may be passed through to consumers. However, the Authority also notes the domestic industry's submission that the subject goods constitute a small proportion of total cost of downstream plastic products, and that no downstream user has placed evidence on record to demonstrate the likely cost pass-through, inflationary impact, or loss of competitiveness attributable to countervailing duty. In the absence of such evidence, the Authority considers that the claimed downstream cost impact remains unquantified.

223. The Authority also notes the domestic industry's submissions regarding the structure of the Indian industry and the potential broader implications of continued subsidized imports, including underutilization of capacity, stress on MSME producers, and alleged structural changes such as closures or conversion to white-labelling. The Authority considers that public interest analysis requires balancing the interests of domestic producers and domestic users, and that the interests of a fragmented domestic manufacturing base, including MSMEs, are also relevant considerations where injury is found due to subsidized imports.

224. The Authority considers that the record indicates availability of domestic production and capacity in India and that no downstream user has demonstrated, with data, that countervailing duty would cause material adverse impact on downstream industries or the general public. Accordingly, the Authority has not accepted the request to refrain from recommending countervailing duty solely on the basis of the public interest submissions made by the producers/exporters.

225. The Authority notes the submission of the domestic industry that the Indian producers of PUC are predominantly MSMEs. The Authority further notes that the fragmented structure of the domestic industry, with a large number of small and medium-scale producers, has already been acknowledged in the initiation of the present investigation and in the application of the procedural framework applicable to fragmented industries.

226. The Authority observes that MSME producers typically operate with limited financial resilience, constrained access to capital, and lower ability to absorb sustained price pressure arising from subsidized imports. Unlike large integrated producers, MSMEs are particularly vulnerable to prolonged price undercutting and price suppression, as such conditions directly affect their viability, cash flows, and ability to continue operations.

227. The Authority considers that protection of MSME producers is a relevant consideration in public interest analysis, particularly where the domestic industry provides employment, supports regional industrial development, and contributes to value addition within the country. The erosion of such an industry due to subsidized imports would have broader economic implications extending beyond the immediate product market.

228. The Authority observes that the submissions made by the producers/exporters have primarily focused on alleged downstream impact, without addressing the consequences of continued injury to the domestic MSME producers. Public interest analysis requires a balanced assessment of the interests of all domestic stakeholders, including the sustainability of domestic manufacturing and employment.

229. In the absence of quantified evidence from downstream users demonstrating material adverse impact, and in view of the evidence on record regarding injury to an MSME-dominated domestic industry, the Authority considers that recommendation of countervailing duty is a necessary and proportionate measure to protect domestic MSME producers from the injurious effects of subsidized imports and to restore conditions of fair competition in the Indian market.

230. Accordingly, the Authority considers that, far from being contrary to public interest, the imposition of countervailing duty serves the public interest by safeguarding domestic MSME manufacturing capability, promoting fair competition, and preventing long-term dependence on subsidized imports.

231. The Authority has considered all submissions regarding public interest and notes that the fundamental purpose of countervailing duties is to eliminate injury caused to the domestic industry by unfair trade practices so as to establish fair competition in the Indian market.

232. **Quantification of duty impact analysis**:

Impact of Duty on Calcium Carbonate Filler Masterbatch Users & Consumers in India

Illustrative downstream impact analysis

Illustrative Duty Rate = USD 10/MT = approx. ₹0.97 per kg of filler masterbatch

Assumptions: Exchange rate ₹96.84/USD | Filler masterbatch loading in end products assumed at 10%–20%

#	Product	Indicative Product Value	Article Weight	Filler Masterbatch Content	Impact at Illustrative Duty (₹ increase per unit & % impact)	Impact status
1	HDPE woven sack	Packed goods value ₹800	80 g	10%	₹0.008 per sack (0.001%)	Low Impact
2	Small T-shirt carry bag	Goods value ₹300	8 g	15%	₹0.001 per bag (0.0003%)	Low Impact
3	Garbage bag	₹15 per bag	20 g	20%	₹0.004 per bag (0.03%)	Low Impact
4	Nursery / plant bag	Plant value ₹20	12 g	20%	₹0.002 per bag (0.01%)	Low Impact
5	Courier / packing bag	Shipment value ₹500	25 g	15%	₹0.004 per bag (0.001%)	Low Impact
6	25 kg woven sack / liner	Packed goods value ₹1,000	70 g	10%	₹0.007 per sack (0.001%)	Low Impact
7	Industrial liner / heavy duty bag	Packed goods value ₹1,125	100 g	10%	₹0.010 per bag (0.001%)	Low Impact
8	PE film / packaging pouch	Packed goods value ₹80	10 g	15%	₹0.001 per pouch (0.002%)	Low Impact
9	Shopping / carry bag	Goods value ₹500	15 g	15%	₹0.002 per bag (0.0004%)	Low Impact

Absolute impact per unit at illustrative duty

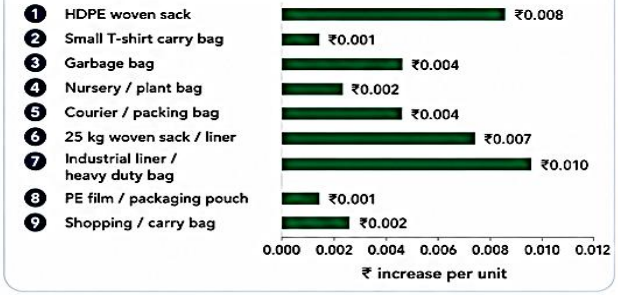

Consumer Applications mostly **0.0003%** to **0.03%** of product value

Industrial Applications around **0.001%** of packed product value

Analysis

At an illustrative duty of USD 10/MT, the impact works out to only about ₹0.97 per kg of filler masterbatch. Since filler masterbatch is used only in limited proportions, typically 10%–20% of the end product, the duty impact per downstream article remains extremely small. Across the examples shown, the increase ranges from about ₹0.001 to ₹0.010 per unit and generally remains well below 0.03% of product value. This demonstrates that the duty burden is highly diluted in downstream products and is unlikely to materially affect users or consumers.

For most consumer and industrial applications, the impact of duty on calcium carbonate filler masterbatch is generally below 0.03% of product value.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions by the Government of Vietnam and Other Interested Parties

233. The Government of Vietnam, the participating producers/exporters and other interested parties have, inter alia, made the following post-disclosure submissions:

i. The issuance of a revised Disclosure Statement, after the earlier disclosure dated 20 March 2026, was challenged as procedurally impermissible. It was submitted that the

Authority could not materially alter the disclosed methodology or margins without disclosing the complete revised calculations and granting sufficient time to comment.

ii. The time available for filing comments on the revised Disclosure Statement was stated to be inadequate. Certain parties also objected to consideration of any fresh information filed by the domestic industry after disclosure unless the same was placed in the public file and an effective opportunity to rebut it was granted.

iii. The participating producers/exporters alleged excessive confidentiality in respect of the domestic industry's production, standing, sampling, injury data, non-injurious price, benchmark data and subsidy calculations. It was contended that indexed or consolidated disclosure did not permit an effective defence.

iv. The standing of the applicant associations and the applicant domestic producers was disputed. It was submitted that the Authority had not disclosed the production shares necessary to establish compliance with Rule 6(3), and that the sampling of four domestic producers was not shown to be representative.

v. The fifteen-month period of investigation was challenged as exceptional and unsupported by adequate reasons. It was also alleged that the injury analysis could be distorted because some sampled producers manufacture products other than the product under consideration.

vi. The interested parties did not seek any change to the product scope or the PCN methodology; however, they maintained that all comparisons and margin determinations must remain PCN-specific and based on verified product-specific data.

vii. The substantial reduction in subsidy margins between the earlier and revised disclosures was relied upon to contend that the first disclosure was based on unreliable benchmarks and assumptions. Certain exporters nevertheless submitted that the revised calculations still did not disclose the complete workings, denominator, allocation basis, exchange rates and adjustments.

viii. With respect to Program 1, it was submitted that the export tax on limestone is a general fiscal and resource-conservation measure and does not constitute entrustment or direction of private suppliers within Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement.

ix. The Government of Vietnam and the exporters submitted that the mere effect of an export tax on domestic availability or price cannot establish a financial contribution. It was argued that the Authority must identify an affirmative governmental act compelling or authorising private bodies to provide limestone or calcium carbonate to the producers of the subject goods.

x. The respondents contended that they procure calcium carbonate powder from independent private suppliers on arm's-length terms and do not purchase limestone from the Government. Limestone and processed calcium carbonate were stated to be distinct goods, falling under different tariff headings and having different physical characteristics and processing costs.

xi. It was argued that no pass-through or company-specific benefit analysis was carried out. According to the exporters, any upstream effect on limestone cannot be attributed to a downstream purchaser of processed calcium carbonate unless the Authority establishes, on verified transaction-specific evidence, that the alleged benefit passed through to that purchaser.

xii. Specificity under Program 1 was disputed on the ground that limestone and calcium carbonate are used across numerous sectors. The respondents submitted that a widely available input or a generally applicable export-tax measure cannot be treated as specific merely because producers of the subject goods use the input.

xiii. The use of Malaysian export prices of calcium carbonate as an external benchmark was challenged. The respondents questioned comparability in terms of whether the traded

material was ground or precipitated calcium carbonate, tariff classification, particle size, purity, coating, whiteness, end use, quantity, level of trade and other commercial conditions.

xiv. It was submitted that tariff item 28365000 may include chemically defined, precipitated, coated or refined calcium carbonate, whereas several Vietnamese producers use ground calcium carbonate or stone powder. The benchmark was therefore alleged to be product-mismatched and inflated.

xv. An Tien, US Masterbatch and Vitaplas requested adoption of Egypt as the benchmark source. They submitted that Egypt is a major producer and exporter of calcium carbonate, represents an arm's-length and undistorted market, and supplies calcium carbonate used by the Indian industry.

xvi. The respondents relied on the alleged shares of Vietnam, Egypt and Malaysia in Indian imports of calcium carbonate during the POI, stated to be approximately 45%, 37% and 13%, respectively. On that basis, Egypt was claimed to be substantially more representative than Malaysia, which was characterised as a comparatively minor source.

xvii. It was further contended that the domestic industry had acknowledged in the connected anti-dumping investigation that it procures calcium carbonate from Egypt, Vietnam and India. The omission of Egypt from the proposed benchmark exercise was alleged to be selective and intended to produce a higher subsidy margin.

xviii. Certain respondents stated that the average purchase price of CaCO3 by Vietnamese producers is USD 35 per MT. However, the applicant industry has proposed FOB benchmark price of around USD 130 per MT. Benchmark Price both for Limestone Lumps as well as CaCO3 which happens to be more than three times the purchase price even though the extent of alleged subsidization in the form of export tax is a merely 30%. Even assuming but not accepting that the entire extent of export tax of 30% can be considered as countervailable subsidy (which indeed would be in stark contradiction to the established jurisprudence on the issue), the benchmarking price of more than 300%, would be ex facie preposterous.

xix. The respondents submitted that Egyptian prices, when properly adjusted, demonstrate absence of benefit. They proposed deductions from Egyptian CIF prices for ocean freight, inland freight, port charges, insurance and trader margin, including indicative adjustments of 3% for port charges, 0.05% for insurance and 3% for trader margin. In support of their argument, vide their email dated 23.06.2026, they have submitted the documentary evidence pertaining to ocean freight charges from Alexandria port in Egypt to Nhava Sheva port in India. The ocean freight provided by them is in the range of 45-55 USD/MT.

xx. It was argued that the benchmark country need not be geographically proximate and should instead reflect a reliable international market price at a comparable level of trade. Reliance was placed on the Authority's earlier determinations concerning Fiberboards, Atrazine Technical and Saturated Fatty Alcohol, where international or third-country price references were used.

xxi. The respondents also challenged the conversion of Malaysian CIF values to FOB. They submitted that the difference between the Malaysian CIF price and the alleged local price largely represented freight, port, insurance and trading costs; that calcium carbonate is a high-volume, low-value product; and that only actual, contemporaneous and product-specific freight should be used.

xxii. Without prejudice, the Government of Vietnam and certain exporters requested reliance on verified in-country Vietnamese prices. They submitted that recognition of Vietnam as a market economy and the existence of private transactions required the Authority to use domestic prices unless material distortion was established through positive evidence.

xxiii. With respect to Program 12, the respondents supported the Authority's proposal not to countervail electricity, natural gas or coal. It was submitted that the participating producers did not use natural gas or coal and purchased electricity under ordinary commercial arrangements at published tariff rates applicable to broad categories of consumers.

xxiv. The respondents submitted that differences in electricity tariffs based on voltage, time of use or consumer category are normal utility-pricing features and do not establish specificity or a preferential benefit to producers of the subject goods.

xxv. With respect to Program 13, the exporters submitted that they acquired or sub-leased land-use rights from industrial park developers on commercial terms and, in some cases, paid amounts above provincial base rates. It was argued that a sub-lease from a private entity does not constitute government provision of land.

xxvi. The respondents disputed the specificity of land incentives, submitting that exemptions and reductions are based on objective regional-development criteria and are available to all eligible enterprises located in designated areas. ADC Plastic further claimed that its land price was approximately 45% above the relevant benchmark and that no land or water-rent concession was received.

xxvii. The use of Thailand Board of Investment data or built-factory/warehouse rental rates was opposed as non-comparable. One respondent submitted, without prejudice, that if a Thailand benchmark were used, an industrial-estate land rate rather than a factory-rental rate should be adopted.

xxviii. With respect to Program 3, the respondents submitted that corporate income tax incentives form part of a general fiscal regime based on objective statutory criteria. It was argued that the incentives are neither export-contingent nor limited to the plastics industry and are therefore not specific.

xxix. ADC Plastic acknowledged a limited tax exemption during part of the POI but argued that any benefit was minimal and de minimis. The respondents also requested that the benefit be confined to the actual period of exemption and calculated against the company-specific taxable income and normal statutory liability.

xxx. With respect to Program 4 and Programs 2 and 6, the participating exporters stated that they had not availed any import-duty exemption, Master Plan assistance or export-promotion benefit. They submitted that the legal existence or potential availability of a programme cannot support a margin in the absence of verified receipt of a benefit.

xxxi. With respect to Programs 5, 7, 8, 9, 10 and 11, the respondents submitted that their loans were obtained from private commercial banks or on market terms. They disputed treating every state-owned bank as a public body and requested that any benefit be tested against comparable loans in the same currency, with due regard to maturity, security, creditworthiness and borrower-specific conditions.

xxxii. An Tien and other parties submitted that actual rates charged by private foreign banks in Vietnam should be preferred over the indicative rates of Bank of India, Vietnam Branch. They further submitted that foreign-currency loans linked to international benchmarks require separate treatment.

xxxiii. US Masterbatch Joint Stock Company and its Hung Yen Branch submitted that they had filed the relevant programme information in their original responses and were correctly granted an individual margin in the revised disclosure. Other parties sought company-specific treatment based on the degree of cooperation and verified data.

xxxiv. VMI contended that its injury margin range was materially higher than those of other participating exporters despite a similar subsidy-margin range. It requested re-examination of the PCN-wise landed value, NIP comparison and weighted-average methodology.

xxxv. The respondents disputed the findings on material injury, threat and causal link. They relied on demand growth, capacity additions, internal competition, raw-material costs, product mix, fragmented industry structure and other factors as possible causes of the domestic industry's performance.

xxxvi. The interested parties submitted that any countervailing duty must be limited to the lesser of the subsidy margin and injury margin. In view of the existing anti-dumping duty on the same product from Vietnam, they requested protection against double remedies and, in some submissions, contended that the combined incidence of anti-dumping and countervailing duties should not exceed the injury margin.

xxxvii. The users and exporters submitted that the subject goods are an important input for plastic products and that additional duty would increase downstream costs. They requested termination of the investigation or, alternatively, a narrowly calibrated duty that would not disrupt supplies or downstream competitiveness.

K.2 Submissions by the Domestic Industry

234. The domestic industry has, inter alia, made the following post-disclosure submissions:

i. The revised Disclosure Statement was stated to be procedurally unwarranted insofar as it materially reduced the subsidy margins disclosed earlier. The domestic industry requested restoration of the earlier margins or complete disclosure of the revised benchmark values, adjustments, calculations and reasons for the change.

ii. The domestic industry submitted that it was effectively allowed only three working days to respond and that requests for disclosure of the revised calculation sheets and benchmark adjustments were not fully accepted. It nevertheless placed additional supporting material on record within the permitted time.

iii. The domestic industry supported the product scope and PCN methodology adopted by the Authority, which are identical to those finalised in the related anti-dumping investigation concerning the same product from Vietnam.

iv. The application and standing were stated to satisfy the CVD Rules and Trade Notice No. 09/2021. Twelve applicant producers furnished the prescribed information and twenty-one additional producers expressly supported the application.

v. Sampling of four domestic producers was defended as valid and representative of a fragmented, predominantly MSME industry. The sampled producers were stated to be among the larger producers and to reflect geographical and operational diversity.

vi. The fifteen-month POI was defended as legally permissible and appropriate in the circumstances of a fragmented industry. The domestic industry also submitted that all injury and cost data relied upon by the Authority are specific to the product under consideration.

vii. The confidentiality claims were stated to be justified because disclosure of producer-wise sales value, profitability, cost, finance cost, depreciation, plant data, capacity utilisation and consumption norms would cause commercial harm. Indexed and consolidated trends were said to provide a reasonable understanding.

viii. The domestic industry supported the finding that the Vietnamese producers/exporters received countervailable subsidies above de minimis levels, but strongly objected to the substantial reduction in the margins of almost all participating producers and the residual category.

ix. With respect to Program 1, the domestic industry supported the finding of countervailability. It submitted that limestone is the principal upstream raw material for ground calcium carbonate and that calcium carbonate is the major input for the subject goods; the effect of measures retaining and depressing the price of limestone is therefore transmitted to limestone-derived calcium carbonate.

x. The domestic industry submitted that the programme is not confined to producers directly purchasing limestone lumps. Where a producer purchases calcium carbonate powder, the relevant comparison is with a comparable calcium-carbonate benchmark; where it consumes limestone lumps, the benchmark must correspond to limestone. The form of the immediate purchase does not sever the identified mineral value chain.

xi. The UAE limestone benchmark was stated to be unsuitable because the underlying transactions predominantly concerned steel, cement and metallurgical-flux applications, including flux-grade material, and were not comparable with the input used in filler masterbatch.

xii. Malaysia was stated to be the appropriate external source because the calcium carbonate exported from Malaysia to India was commercially comparable in particle size, purity, whiteness and industrial characteristics and because a consistent POI price series was available at the product-specific tariff level.

xiii. The domestic industry clarified that its benchmark evidence was not confined to a four-digit heterogeneous basket. It relied on HS 283650 data, corresponding Indian tariff item 28365000 data, Trade Map information, TradeStat data, purchase records and material from the connected anti-dumping investigation.

xiv. The domestic industry accepted conversion of Malaysian CIF import data to FOB only if freight and insurance are removed on the basis of actual calcium-carbonate freight. It filed POI invoices, bills of entry, purchase registers, accounting extracts and third-party supplier freight evidence and submitted that these corroborated the FOB series earlier placed on record. The domestic industry vide its mail dated 23.06.2026 has provided the documentary evidence pertaining to the ocean freight charges from Malaysia to India of the subject goods.

xv. The domestic industry further submitted that freight data for a dissimilar product or period could not override contemporaneous calcium-carbonate freight evidence. It requested disclosure of the CIF base price and adjustments and restoration of the Program 1 margin after using verified, product-specific freight and insurance.

xvi. The domestic industry requested countervailing of Program 12. It submitted that electricity prices in Vietnam are centrally regulated through the Ministry of Industry and Trade and EVN, that tariff differentiation favours manufacturing users, and that the benefit is sector-specific.

xvii. With respect to Program 13, the domestic industry supported the findings on financial contribution and specificity but requested use of an external market benchmark, including comparable Thailand industrial land data, rather than Vietnamese rates stated to be distorted by the government-administered land regime.

xviii. The domestic industry supported countervailing Program 3. It submitted that the normal statutory CIT rate of 20% is the appropriate benchmark and that the benefit is the difference between the verified normal tax liability and the tax actually paid during the POI.

xix. The domestic industry requested countervailing of import-duty exemptions wherever a participating exporter received a specific exemption or excess

remission. It accepted that quantification must be based on the verified amount of revenue foregone during the POI.

xx. The domestic industry supported countervailing preferential lending by VDB and state-owned or government-directed banks. It submitted that the benefit should be measured against comparable private commercial lending rates in Vietnam.

xxi. Programs 2 and 6 were stated to be sector-specific or export-contingent by design. The domestic industry submitted that claims of non-availment must be tested against verified records and government disbursement information.

xxii. The domestic industry objected to grant of an individual margin to US Masterbatch Joint Stock Company and its Hung Yen Branch and requested application of the non-cooperative residual rate, alleging material deficiencies in the responses and absence of complete programme information.

xxiii. The domestic industry supported the Authority's injury findings. It submitted that subsidised imports increased significantly, captured market share, undercut and suppressed domestic prices and caused deterioration in profits, cash flow and return on capital employed.

xxiv. The domestic industry submitted that the injury analysis is based on verified PUC-specific records of the sampled producers and that no substantiated alternative cause severed the causal link between subsidised imports and injury.

xxv. The domestic industry supported application of the lesser-duty rule and submitted that the duty should be the lower of the subsidy margin and the injury margin for each producer/exporter. It also requested appropriate treatment of overlap with the anti-dumping measure in accordance with the Act and the Rules.

xxvi. The domestic industry submitted that countervailing duty would restore fair competition rather than restrict imports. The impact on downstream products was stated to be limited, while non-imposition would perpetuate injury to a large fragmented domestic industry.

K.3 Examination by the Authority

I. Procedural and Preliminary Issues

235. The Authority examined the post-disclosure submissions of the Government of Vietnam, participating producers/exporters, the domestic industry and other interested parties. Repetitive submissions which have already been dealt with in the revised Disclosure Statement were not reproduced; only new issues, alleged computational errors and matters requiring clarification were examined.

236. Rule 18 of the CVD Rules requires disclosure of the essential facts under consideration before final findings and a meaningful opportunity to defend interests. A disclosure statement is not a final determination and does not create a vested right in a provisional benchmark, calculation or margin. The Authority may reconsider comments, correct errors and refine the methodology to be used in working of the relevant calculations.

237. The revised Disclosure Statement dated 16 June 2026 superseded the earlier disclosure dated 20 March 2026 after reconsideration of countervailability, benchmark selection, specificity, company-specific benefit and cooperation. Comments filed within time were considered on merits, while fresh information was used only where it was capable of verification.

238. The product scope and PCN methodology based on calcium-carbonate content was retained.

The standing of the domestic industry was also confirmed: the application was filed by two associations on behalf of twelve producers and was supported by twenty-one additional producers. Sampling of four representative producers was considered justified in view of the fragmented structure of the industry. The Authority relied on verified PUC-specific cost, production, sales and profitability data.

239. The fifteen-month POI was found consistent with the Rules and suitable for representative analysis. Confidentiality claims were examined under Rule 8. Commercially sensitive data such as raw-material purchase prices, tax records, loan terms, land agreements, production costs and producer-wise profitability were protected, while non-confidential summaries, indexed trends and ranges were disclosed wherever practicable.

II. Subsidy Methodology

240. The change in subsidy margins between the earlier and revised disclosures arose from programme-wise re-examination, use of more product-specific benchmarks, correction of certain programme treatments and examination of company-specific information. A changed margin is not evidence of arbitrariness; it reflects the working of the disclosure process.

241. Under Rule 12, the countervailable amount is the benefit conferred on the recipient during the POI. Accordingly, only verified recipient-specific benefits were quantified. Benefits were allocated to the subject goods using appropriate verified turnover or sales denominators. No benefit was attributed merely because a programme existed in law.

III. Program 1 - Supply of Limestone/Calcium Carbonate at Less Than Adequate Remuneration

242. The Authority re-examined Program 1 with reference to the distinct requirements of financial contribution, benefit, specificity and countervailability. The determination is not based merely on Vietnam's export tax on limestone or on a difference between domestic and external prices. It is based on the cumulative design and operation of Vietnam's mineral-policy framework governing extraction, export retention and domestic availability of limestone and limestone-derived calcium carbonate.

243. Under Article 1.1(a)(1)(iv) of the SCM Agreement, a financial contribution may arise where the government entrusts or directs private bodies to provide goods. Such entrustment or direction cannot be inferred from price effects alone. In the present case, the Authority considered the legal framework, export-tax treatment, policy objective of retaining minerals for domestic downstream use and the conduct of suppliers, and found that these factors, taken together, went beyond an incidental market response.

244. Verified purchases / consumption of limestone / calcium carbonate powder were compared with a calcium-carbonate benchmark. Since the investigated producers were the direct purchasers or consumers of the input, no separate pass-through test was required. The benefit was determined by comparing the price actually paid with an appropriate benchmark reflecting prevailing market conditions, including quality, availability, transportation and other conditions of purchase or sale.

245. The import data pertaining to imports of Calcium Carbonate into India was extracted from website of Ministry of Commerce & Industry, and it was noted that the imports of Calcium Carbonate into India were highest from Vietnam (44%), followed by Egypt (37%) and Malaysia (12%) during the period of investigation. Since, this investigation is being

undertaken against the alleged subsidy programmes of Vietnam and the related issues of alleged price distortion therein, therefore, the import prices from Vietnam to India cannot be adopted as an appropriate benchmark. Further, it was noted that the import prices of next largest exporters of Calcium Carbonate to India, that is, Egypt and Malaysia when combined together accounted for 49% of total imports into India and was found to be considered as a representative sample for adopting the same as a benchmark for this programme. Therefore, the possibility of considering the import prices of both Egypt and Malaysia into India together in the form of weighted average, has been examined and was found to be suitable for considering it as an appropriate benchmark for this subsidy programme.

246. The Authority specifically examined competing claims regarding consideration of Egypt and Malaysia for benchmark. The participating producers / exporters relied on Egypt's substantial production and exports, its significant share in Indian imports, the domestic industry's own procurement from Egypt and the commercial relevance of Egyptian prices. The domestic industry relied on the product-specific and reconcilable Malaysian data under tariff item 28365000. Upon reconsideration, the Authority found that both countries supplied relevant calcium carbonate to India during the POI and that neither source should be discarded merely because the other had a larger volume or more detailed transaction data.

247. The Authority has re-examined the benchmark for calcium carbonate strictly in accordance with Rule 12(2)(d), Annexure IV and Article 14(d) of the SCM Agreement, which require adequacy of remuneration to be assessed against prevailing market conditions, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of sale. Benchmark selection is therefore not governed by the lowest price, the nearest source, the largest supplier or the outcome most favourable to either side. The controlling test is whether the benchmark is reliable, representative, comparable and capable of measuring the benefit on a like-for-like basis

248. Egypt represented the materially larger import volume into India of $CaCO_3$ and its use by the domestic industry confirmed commercial availability for industrial use. Malaysia, however, offered a more detailed product-specific transaction data and useful evidence on descriptions, price dispersion and shipment conditions. The Authority has, therefore, considered the weighted average CIF prices of both the sources duly adjusted to FOB level, that is, import prices of Egypt as well as Malaysia to India as extracted from website of Ministry of Commerce & Industry, as an appropriate external benchmark, for the purpose of programme no. 1. The Authority has relied on actual 8 digit level HSN code imports into India from Egypt and Malaysia in POI at CIF level, as extracted from website of Ministry of Commerce & Industry, which has been duly adjusted to FOB level.

249. The benchmark shall be calculated by weighting each country’s adjusted price by its corresponding eligible import quantity. This methodology is not an equitable compromise between competing claims; it is the most representative and legally defensible measure of prevailing market remuneration available on the record. It recognises Egypt’s greater commercial presence, preserves the reliability of the Malaysian product-specific data, minimises source-specific distortion and provides a balanced, objective and robust basis for the final recipient-specific benefit and subsidy margin calculations. Objections concerning grade, particle size, purity, coating, whiteness, processing route, end use and tariff classification were duly examined for both countries.

250. It is noted that Malaysian CIF prices have been converted to a FOB-equivalent basis by deducting the verified freight and insurance prices as provided by the domestic industry, whereas the Egyptian CIF prices have been converted to a FOB-equivalent basis by

deducting the verified freight and insurance prices provided by the respondents or producer-exporters. This ensures that the benchmark reflects the value of the input itself and is not distorted by differences in product characteristics, shipment terms or level of trade.

251. The composite benchmark is considered more objective and representative than exclusive use of either country. Exclusive reliance on Egypt would disregard the detailed Malaysian transaction evidence, while exclusive reliance on Malaysia would understate the significance of the larger volume of comparable imports from Egypt. The combined series, after harmonisation of product scope and commercial terms, better reflects prevailing market conditions.

252. The legal basis of this methodology is representativeness, comparability and prevailing market conditions under Rule 12 and Article 14(d). Although it incidentally balances the competing concerns of exporters and the domestic industry, it is adopted because it provides a broader and more reliable external market reference based benchmark.

253. The weighted benchmark is applied only to producers that purchased or consumed calcium carbonate during the POI. It is compared with each cooperating producer's verified purchase price on a like-for-like basis, with adjustments for freight, insurance, port handling, trading level and other conditions of purchase. The company-specific benefit calculations are contained in the confidential calculation sheets.

254. Specificity was confirmed because the identified mineral-input framework benefits a limited group of downstream enterprises dependent on the affected limestone and limestone-derived input. The fact that these minerals may have other uses does not negate specificity where the design and operation of the programme and the benefit to investigated producers are established.

255. Accordingly, Program 1 remains countervailable. For calcium-carbonate purchases, the final producer-specific subsidy calculations shall use the quantity-weighted average of adjusted comparable POI import prices from Egypt and Malaysia. Consequential revisions shall be made to the subsidy margins.

IV. Other Subsidy Programmes

256. The Authority examined Program 12 concerning the alleged provision of natural gas, electricity and coal at less than adequate remuneration. The participating producers did not establish use of natural gas or coal in the production of the subject goods during the POI. As regards electricity, the tariff differences were found to arise from ordinary commercial factors such as voltage level, consumption category, time of use and supply conditions. No evidence showed that producers of the subject goods received electricity on preferential terms compared with similarly situated industrial consumers. Accordingly, no countervailable benefit was determined under this programme.

257. Under Program 13, the Authority examined land-use rights, lease and sub-lease agreements, payment records, investment certificates and relevant provincial instruments. A benefit was not presumed merely because a producer was located in an industrial park or investment zone. It was quantified only where verified records established that the producer received land-use rights, or an exemption or reduction in land or water rent, on terms more favourable than those normally applicable in Vietnam.

258. For determining the benefit under Program 13, the Authority compared the rent actually paid by the producer with the normal rate applicable in Vietnam in the absence of the concession. The proposed use of rental prices of factories or industrial properties in Thailand was rejected because such prices were not sufficiently comparable in terms of location, tenure, legal framework and nature of the property. A countervailable benefit was therefore determined only for producers that received a verified land-related concession during the POI.

259. Under Program 3, exemptions or reductions in corporate income tax were treated as government revenue foregone. The normal statutory corporate income-tax rate of 20% was used as the benchmark. The benefit was determined as the difference between the tax that would ordinarily have been payable and the tax actually payable after availing the concession. The calculation was confined to the verified period and amount of tax relief.

260. The corporate income-tax programme was considered specific where eligibility was restricted to enterprises located in specified regions or industrial zones, or to enterprises undertaking identified categories of investment. Accordingly, a countervailable benefit was determined only to the extent of the verified tax relief received by the concerned producer during the POI.

261. Under Program 4, the Authority examined whether the participating producers had actually availed exemptions from customs duty on imports of raw materials, machinery or equipment. The mere existence of such an exemption under Vietnamese law was not considered sufficient. In the absence of verified company-specific availment and a corresponding amount of duty foregone during the POI, no separate subsidy margin was assigned under this programme.

262. With respect to preferential lending, export credit and loan guarantees under Programs 5, 7, 8, 9, 10 and 11, the Authority did not presume that every loan granted by a state-owned bank constituted a subsidy. Each loan was examined with reference to the lender, currency, tenure, security, interest rate and other borrowing terms. A benefit was determined only where the verified terms were more favourable than those available under a comparable commercial loan. Where a participating producer had obtained a comparable arm’s-length loan from a private commercial bank in the same currency and on similar terms, that loan has been used as the benchmark.

263. Under Programs 2 and 6, relating to the Master Plan for Development of the Plastics Industry and the Export Promotion Program, no verified financial contribution or benefit was found to have been received by the participating producers during the POI. The existence of a government policy or programme was not considered sufficient in the absence of actual receipt of a measurable benefit. Accordingly, no subsidy margin was assigned under these programmes.

V. Cooperation, Injury, Lesser-Duty Rule and Conclusion

264. US Masterbatch and its Hung Yen branch were granted individual treatment because their responses contained the material information required for the programmes ultimately countervailed and were capable of verification. Entities that failed to furnish complete POI information remained subject to the residual or facts-available approach.

265. The Authority reaffirmed material injury and causal link after examining import volumes, market share, PCN-wise price undercutting, suppression and depression, and the domestic

industry's production, sales, profitability, cash flow and return on capital employed. Other factors such as demand movement, capacity additions, raw-material prices, product mix and competition among domestic producers were examined and were not found to sever the causal link.

266. The NIP was determined from verified costs of sampled domestic producers after prescribed adjustments and a reasonable return. Exporter-specific injury margins were based on PCN-wise comparison of NIP with landed value and could differ because of product mix, transaction prices, freight and export quantities.

267. The lesser-duty rule was applied. The recommended countervailing duty for each producer/exporter cannot exceed the lower of the positive subsidy margin and injury margin. The existence of an anti-dumping duty does not bar a countervailing measure, but the recommendation must avoid double counteraction of the same export-subsidy benefit.

268. The Authority concluded that the interests of users and importers were adequately considered. A calibrated duty is intended to neutralise injurious subsidisation, not to restrict fair imports. The final recommendation therefore confirms the essential approach of the revised Disclosure Statement, with the principal modification that the calcium-carbonate benchmark under Program 1 shall be the quantity-weighted average of the adjusted, comparable POI import prices from Egypt and Malaysia into India. The post-disclosure comments do not justify termination of the investigation.

L. CONCLUSIONS

269. After examining the submissions made by all interested parties and issues raised therein and the facts available on record, the Authority comes to the following conclusions:

a) The product under consideration in the present investigation is Calcium Carbonate Filler Masterbatch having CaCO3 as major constituent i.e., more than 50% in content.

b) The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of CVD Rules, 1995.

c) The applicant domestic producers constitute domestic industry within the CVD Rules, 1995.

d) The domestic industry has suffered material injury as a result of the subsidized imports. The injury margin is significant.

e) Governments of Vietnam is providing subsidies to the producers of the PUC in the form of tax benefits, interest concessions, land rebates and provisions of goods and services at less than adequate remuneration.

270. The imposition of countervailing duty is in public interest. This is evident from the following:

i. The impact of duties on the cost of the user industry is not expected to be significant.

ii. The trade remedial measures do not prohibit imports into the country, but ensures a level playing field between imports and domestic manufacturing. A viable domestic industry ensures that the user industry is not fully dependent on the imports.

iii. The imposition of countervailing duty would only be to the extent of the injury caused to the domestic industry. Therefore, the imposition of duties does not provide any extra protection but only offsets the injury caused by unfair trade practices.

M. RECOMMENDATIONS

271. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the governments of the exporting country, exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of subsidization, injury and causal link.

272. Having concluded that there is positive evidence of subsidization, injury and causal link between them, the Authority is of the view that a countervailing duty is required to be imposed on the PUC from the subject country. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder. The Authority has recommended imposition of the anti-dumping duties in the investigation concerning the subject goods *vide* its Final Findings F. No. 6/38/2024-DGTR dated 27.09.2025.

273. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty less than or equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury to remove the injury to the domestic industry. The Authority has noted the fact that the PUC is already attracting anti-dumping duty.

274. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No. 7 of the duty table is recommended to be imposed for five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject country.

DUTY TABLE

S. No	Heading/Sub heading/ Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	3824 99 00	Calcium carbonate filler masterbatch	Vietnam	Any country including Vietnam	European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast")	15.16	MT	USD
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai")	15.16	MT	USD
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe")	15.16	MT	USD
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Polyfill joint stock company ("Polyfill")(collectively referred to as "Europlast Group")	15.16	MT	USD
5	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	ADC Plastic., JSC	14.20	MT	USD

6	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	An Tien Industries Joint Stock Company	13.42	MT	USD
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	9.11	MT	USD
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company	16.03	MT	USD
9	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	US Masterbatch Joint Stock Company	22.52	MT	USD
10	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	US Masterbatch Joint Stock Company – Hung Yen Branch	22.52	MT	USD
11	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any Producer	69.19	MT	USD
12	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any Producer	69.19	MT	USD

(a) For serial no. 1 to 8, and 11, 12, since the sum of countervailing duty mentioned above and the anti-dumping duty imposed vide Customs notification no. 37/2025-Customs (ADD) dated 24th December, 2025 for the subject goods, does not exceed the respective injury margin of the producers, therefore, the countervailing duty mentioned in Column no. 7 of the above duty table shall be collected.

(b) For serial no. 9 and 10, since the sum of countervailing duty mentioned above and the anti-dumping duty imposed 'under residual category' vide Customs notification no. 37/2025-Customs (ADD) dated 24th December, 2025 for the subject goods, exceeds the respective injury margin of the producers, therefore, the countervailing duty mentioned in Column no. 7 of the above duty table shall not be collected.

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

> "I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.' If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations."

N. Further procedure

275. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.16 14:42:12 +05'30'